

राजस्थान सेवा नियम (Rajasthan Service Rules)

सम्पूर्ण दोनों खण्ड (पेंशन नियमों सहित)

बुद्धपालचन्द भण्डारी
प्रधोसक
महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान
एवम्
रणवीरसिंह गहलोत

यूनिक ट्रेडर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

प्रकाशक :
ग्रैनिक ट्रेडर्स,
चोडा रास्ता, जयपुर-३.

संस्करण : 1976

© मण्ढारी एव महलोत

मूल्य : १४.०० रुपये मात्र

: एलोरा प्रिण्टर्स,
जयपुर

- 22 क प्रशिक्षण काल में दी गई घनराशि वापिस जमा कराना
 23 एक राज्य कर्मचारी के सेवा में न रहने की शर्त
 23 क घस्याई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का नाटिश

भाग 3

अध्याय ४

वेतन (Pay)

- 24 वेतन, पद के वेतन से ज्यादा न हो
 25 प्रशिक्षण काल धारि में वेतन
 26 से 26ख किसी समय वेतन-मान (Time Scale) वाले पद पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक (Initial) मूल वेतन को नियमित करना
 27 घटाई गई वेतन को समय शृंखला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन को पुनः नियमित करना (Regradation)
 27 क परिवर्धन काल में वेतन
 28 एक पद के वेतन परिवर्धित होने पर वेतन को नियमित करना
 29 जब तक वार्षिक वृद्धि (Increment) रोजी न जाय, वह प्राप्त की जाती रहनी चाहिए
 30 दक्षतावर्ग (Efficiency Bar) पार करना
 31 टाइम स्केल (समय-वेतन-मान) में वेतन वृद्धि (Increments) के लिये सेवा की गिना जाना
 32 निर्धारित लिये में पूर्व वार्षिक वृद्धियाँ (Pre-mature Increments)
 33 निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरण करने पर वेतन
 34-34 ए. निम्न श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) करने पर वेतन
 35-35 क स्थानान्तरण राज्य कर्मचारी का वेतन
 36 निम्न दर पर कार्यवाहक वेतन निर्दिष्ट करने की शक्ति
 37 कार्यवाहक वेतन का नियमन जब पद पर वेतन ऐसी दर पर घुकरें हो जो दूसरे राज्य कर्मचारी की निज़ि हो
 38 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिये नये राज्य कर्मचारियों के स्थान पर कार्यवाहक उपस्थिति
 39 निजी वेतन का भटना
 40 से 41 घस्याई पद का वेतन

अध्याय ५

वेतन के अतिरिक्त अन्य मते (Addition to Pay)

- 42 क्षतिपूर्क मत्ता (Compensatory Allowance)
 43 (क) कार्य करने व उपका शुल्क स्वीकार करने की स्वीकृति
 43 (ख) शुल्क (फोन) स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक

वे परिस्थितियों तिनमें पारिश्रमिक (Honorarium) स्वीकृत किया जा सकता है	75
दुन्क एवं पारिश्रमिक की स्वीकृति के कारकों को मिला जाये	78
चिरिगा अधिकाारियों द्वारा पीछ स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति	80
सरकार के नाम दुन्क बक जमा बनाना चाहिये	80
बिना विशेष आज्ञा के स्वीकार किया जाने वाला अनुदान	82
अनुदान कार्य में निवृत्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकार (Patent) प्राप्त करने में रोक	84

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

नियुक्तियों का समन्वय	84
-----------------------	----

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनिधित्व

भारत के बाहर प्रतिनिधित्व पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता पैन्डीय सरकार के नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा	85
--	----

अध्याय ८

उन्नी, हटाना या निलम्बित करना (Dismissal, Removal & Suspension)

वर्धितगी की शारीर, वेतन एवं भत्तों का बन्द करना	93
निर्वाह अनुदान (Subsistence Grant)	93
पुनर्नियुक्ति (Reinstatement)	94
निलम्बन काल में व्यवसाय की स्वीकृति	97
वर्धितगी, हटाये जाने के बाद व्यवसाय की स्वीकृति	97

अध्याय ९

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

अधिकारिकी आयु प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति	98
---	----

भाग ४

अध्याय १०

अवकाश (leave)

- ५७ (क) दूगरे नियमों के मसूह में नियमित एक रात्र कर्मचारी द्वारा इन नियमों में शामिल पद पर काम करने पर उनके अवकाश का नियमन का प्रसार
- ५८ पुनर्निधोक्ता (Re-employment) या पुनर्निधुक्ति होने पर वर्गीकृत होने से पूर्व की गई सेवाओं का अवकाश
- ५९ अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है ।
- ६० अवकाश का प्रारम्भ व अन्त
- ६० क अवकाश के समय में पता
- ६१ अवकाश के साथ अवकाशों (Holidays) का सम्मिश्र (Combination)
- ६२ मुक्त (Exempt) करने की शक्ति
- ६३ अवकाश के साथ छुट्टियों के सम्मिश्र होने पर अनुवर्गी व्यवस्थाओं का प्रभावशील होना
- ६४ अवकाश में नौकरी स्वीकार करना
- ६५ निवृत्ति-पूर्व-अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) पर राज्य कर्मचारियों की पुनर्निधुक्ति
- ६६ अवकाश में वापिस बुलाना
- ६७ अवकाश के लिये आवेदन पत्र जितने प्रस्तुत किया जाये
- ६८ विदेशी सेवा में स्थानान्तरित राज्य कर्मचारियों की पहले अवकाश नियमों से अवगत कराना चाहिए
- ६९ विदेशी सेवा में निधुक्ता राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना
- ७० राज्यान्तर अधिकारियों के लिए विरिष्ठा सम्बन्धी प्रमाण पत्र
- ७१ मेडिकल कमेटी के सामने उपस्थित होना
- ७२ मेडिकल कमेटी का प्रमाण पत्र
- ७३ अश्वि मानसी में व्यवसायात्मक परीक्षा के लिए रोकना
- ७४ मेडिकल कमेटी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना
- ७५ विरिष्ठा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार प्रदान नहीं करता है
- ७६ अराज्यपति कर्मचारियों की विरिष्ठा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध का तरीका
- ७७ अनुप्रेषणी कर्मचारियों के लिए विरिष्ठा प्रमाण पत्र पर अवकाश
- ७८ व ७९ सेवा पर उपस्थित न हो सकने योग्य राज्य कर्मचारियों की विरिष्ठा प्रमाण पत्र

खण्ड २—अवकाश की स्वीकृति

- ८० अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता
- ८१ राज्य सेवा में वापिस लौटने के योग्य राज्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति

वर्खास्त किये जाने वाले राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकार न करना	124
राजपत्रित अधिकारियों के लिए अवकाश	124
अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय योग्यता का प्रमाण पत्र	125
राजपत्रित कर्मचारियों को मेडिकल कमेटी से कब स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये	125
नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना	126
अवकाश समाप्त होने पर अनुपस्थिति	127

अध्याय ११

अवकाश (Leave)

खण्ड १—सामान्य

प्रयोग्यता	128
अवकाश का लेखा (Leave Account)	128
राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा	128
अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश वेतन	128
विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय	129
अधिवारिकी प्रायु की तिथि के बाद का अवकाश	129

खण्ड २—उपार्जित अवकाश आदि

प्राप्त उपार्जित अवकाश की सख्या	136
विश्राम कालीन विभागों (Vacation Departments) में अधिकारियों के लिये विशेष नियम	138
प्राप्त धर्द्ध वेतन अवकाश की मात्रा	139
प्राप्त रूपान्तरित अवकाश (Commuted leave) की मात्रा एवं उसे स्वीकार करने की शर्तें	139
बिना बकाया अवकाश (Leave not due) कब स्वीकार किया जाता है	140
अस्थाई राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश	143
विश्राम काल (Vacation)	145
सेवा भंग किए बिना एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की स्थाई रूप में नियुक्ति होने पर उसका अवकाश	147
असाधारण अवकाश	147
प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए प्राप्त अवकाश वेतन	149

खण्ड ३—विशेष अस्तमर्थता अवकाश

विशेष अस्तमर्थता अवकाश कब स्वीकार किया जाता है	152
विशेष अस्तमर्थता अवकाश की अवधि	152
अस्तमर्थता अवकाश पेन्शन के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है	154

- 99 (7) असमर्थता अवकाश में अवकाश वेतन
 100 असमर्थता के लिए क्षतिपूर्ति (Compensation) स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौती
 101 व 102 विभिन्न वर्ग-चारियों पर विनियम असमर्थता अवकाश नियमों का लागू होना

खण्ड ४—प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)

- 103 प्रसूति अवकाश
 104 प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाश का समन्वय

खण्ड ५—अस्पताल अवकाश

- 105 अस्पताल अवकाश (Hospital Leave) स्वीकृत किये जाने की सीमा
 106 अस्पताल अवकाश में अवकाश वेतन
 107 अस्पताल अवकाश की अवधि
 108 अस्पताल अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का समन्वय

खण्ड ६—अध्ययन अवकाश (Study Leave)

- 109 प्रयोग्यता
 110 अध्ययन अवकाश किन्को स्वीकृत किया जाय
 111 व 112 अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें
 113 अन्य अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का समन्वय
 114 समय से कम के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में तरीका
 115 अध्ययन अवकाश के लिए प्राप्ति पत्र प्रस्तुत करना
 116 अन्य अवकाश की अध्ययन अवकाश में परिवर्तित करना
 117 अध्ययन भत्ता (Study allowance)
 118 विद्यालय काल का अध्ययन भत्ता
 119 अध्ययन के पाठ्यक्रम का शुल्क
 120 पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
 121 इन्प्रि एव वेन्सन के लिए अध्ययन अवकाश की गणना
 121 (क) राज्य सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (Bond) भरा जाना

खण्ड ७—प्रोवेशनर तथा नवसिखुओं के लिए अवकाश

- 122 प्रोवेशनरों के लिए अवकाश
 123 नवसिखुओं (Apprentices) के लिए अवकाश

खण्ड ८—अंशकालिक सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश

- 124 शिक्षण संस्थाओं में पाठ्य-शास्त्र राज्यकीय प्राध्यापक (Lecturers) एवं कानून अधिकारियों (Law Officers) के लिए अवकाश
 125 स्वीकृत किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय

६—पारिश्रमिक या दैनिक भजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा द्वारा उपाजित अवकाश

पारिश्रमिक या दैनिक भजदूरी द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त सेवा का अवकाश 165

अध्याय १२

सेवा में कार्य ग्रहण करने का समय (Joining Time)

कब स्वीकृत होगा (When admissible)	165
स्थान का परिवर्तन न होने पर ज्वाइनिंग टाइम	169
प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम की अवधि	170
किस रास्ते द्वारा ज्वाइनिंग टाइम गिना जावेगा	171
मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यभार संभालने पर ज्वाइनिंग टाइम	171
प्रस्थान समय में नये पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम	171
एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान काल में अवकाश लेने पर राज्य कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम	171
उपाजित अवकाश काल में नये पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम	171
सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाया जाना	171
अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम जो स्वीकृत किया जा सकता है	172
अन्य सरकार में स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम का विनियमन	172
ज्वाइनिंग टाइम सेवा के रूप में गिना जाता है	172
ज्वाइनिंग टाइम के बाद दण्ड	174
राज्यकीय सेवा में नियुक्त होने पर गैर सरकारी (Private) कर्मचारियों को ज्वाइनिंग टाइम	174

भाग ५

अध्याय १३

विदेशीय सेवा (Foreign Service)

विदेशी सेवा में स्थानांतरित करने पर कर्मचारी की सहमति आवश्यक	175
विदेशी सेवा में स्थानान्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है	175
अवकाश काल में विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने के परिणाम	176
विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करने की तारीख	176
(क) विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें	177
अवकाश एवं वेतन में अंशदान	177
(क) वेतन भत्ते आदि का भार	177
(ख) भारतीय राज्यों एवं 'बी' श्रेणी के राज्यों के बीच में आपस में की गई सेवा	

	की परीक्षा	178
146	अंशदान की दर	178
147	अंशदान किस प्रकार निवामा जाता है	181
148	अंशदान माफ करना	182
149	बकाया अंशदानों पर व्याज	182
150	विदेशी सेवा में अंशदान राज्य कर्मचारी द्वारा नहीं रोजा जा सकता	184
151	विदेशी नियोजक कि पेन्शन या प्रोव्यूटी स्वीकार करने में स्वीकृति लेना आवश्यक	184
152	विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश	184
153	भारत के बाहर विदेशी सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने के विशेष प्रावधान	184
154	राज्यकीय सेवा में कार्यवाहक उम्मीद हो जाने पर विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारी के वेतन का नियमन	185
155	विदेशी सेवा से मोटने की तारीख	185
156	विदेशी नियोजक द्वारा वेतन एवं अंशदान बन्द कर देने की तारीख	187
157	नियमित स्थापन जिसका कि भ्रम सरकार को देय है, के सम्बन्ध में अंशदान की वसूली	187

अध्याय १४

स्थानीय निधियों के अर्धन सेवा

158	सरकार द्वारा प्रचालित स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली सेवाएँ किस प्रकार नियमित होती हैं	187
-----	---	-----

भाग ६

अध्याय १५

सेवा के अभिलेख (Records of Service)

159	राजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख	195
160	मराठपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख	195
161	सेवा पुस्तिका (Service Book) में इन्द्राज	197
162	सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की जाँच	199
163	आडिट आफिस द्वारा विदेशी सेवा में स्थानान्तरण पर इन्द्राज किया जाना	200
164 व 164 (क)	सेवा सूचियाँ (Service Rolls)	200

भाग ७

अध्याय १६

शक्तियों का प्रदत्तीकरण (Delegations)

165	अधीनस्थ अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का उपयोग करते हैं	202
-----	--	-----

जिन अधिकारियों को शक्तियाँ सौंपी गई हैं उनके उपयोग करने में	
वित्त विभाग की अनुमति दी हुई मानी जावेगी	202
प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के नियमन सम्बन्धी सामान्य शर्तें	202

भाग ८

अध्याय १७

सामान्य नियम

खण्ड १—सामान्य

ब 168 (क) छात्र होने की सीमा	203
पेन्शन की स्वीकृति के लिए उत्तम चरित्रवान होना आवश्यक	209
ब 170 (क) पेन्शन से नुकसानों की बसूली	211

खण्ड २—वे मामले जिनमें मांगें (Claims) स्वीकार नहीं की जा सकती

पेन्शन का हक कम प्रस्वीकृत होता है	214
क्षतिपूर्क भत्ता	214
(क) प्रतिवाद्य सेवा निवृत्ति दण्ड के रूप में	216
विधवा के हक	216
प्रतिबन्ध	222
सिविल नियमों के अन्तर्गत पेन्शन के लिए मिलेटी सेवा को गिना जाना	222
सिविल नियमों के अन्तर्गत मिलेटी सेवा को उच्चतर या बतुर्प थोड़ी सेवा में गिना जाना	224

अध्याय १८

योग्य सेवा की शर्तें (Conditions of qualifying service)

खण्ड १—योग्य सेवा की परिभाषायें

योग्य सेवा प्रारम्भ होने की सन्न	224
योग्यता की शर्तें	225
किसी भी सेवा को योग्य सेवा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार की शक्ति	225

खण्ड २—पहली शर्त

सरकार द्वारा नियुक्ति पेन्शन के लिए आवश्यक शर्त	233
अनुबन्ध भत्तों से मुक्तान की जाने वाली सेवा	234
राजाघों के निजी कोषों (प्रिवीपट्सों) से मुक्तान की जाने वाली सेवा	234
ठिकानों द्वारा मुक्तान की गई सेवा	234

खण्ड ३—दूसरी शर्त

सामान्य सिद्धान्त

185	सेवा वच योग्य होनी है	234
186	निरन्तर स्थापन (Non Continuous establishment)	234
187	अस्थायी सेवा को गिना जाना	235
188	वायव्याहक नियुक्ति को शामिल किया जाना	238
188 (क)	अस्थायी सेवा स्थायी हो जाने पर गिनी जाती है	239
189	नवमिनुषा	240
189 (क)	परिशोषाधीन व्यक्ति	240
190 व 191	अस्थायी सेवा पर प्रतिनिधित्व स्थायी अधिकारी	240
192	समाप्त किया गया स्थायी पद	241
193	फुटकर कार्यों के लिए नियुक्त मृदगुणाय का बर्तव्यारी	241
194	सर्वे एवं सू प्रबन्ध विभाग	242
195	पारिश्रमिक का स्रोत योग्यता का आधार	242
196	संचित निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा को शामिल किया जाना	243
197	स्थानीय निधि एवं ट्रस्ट निधि से भुगतान की जाने वाली सेवा केवल योग्य नहीं गिनी जाती है	243
198	फीस एवं कमीशन से भुगतान की गई सेवा	244
199	कमीशन के पट्टे आदि से भुगतान की गई सेवा	244

अध्याय १६

खण्ड १—अवकाश एवं प्रशिक्षण की अवधियां

203	योग्य सेवा के लिए गिनी जाने वाली अवकाश की अवधियां	244
204	भर्तों सहित अवकाश पर विज्ञाया गया समय	244
205	प्रशिक्षण में विज्ञाया गया समय	248

खण्ड २—सेवा में निलम्बन, त्याग पत्र, सेवा मंग एवं कमियां

206	निलम्बन में विज्ञाया गया समय	248
208 व 209	त्याग पत्र, वनस्तिगी या दुराचरण के कारण हटाया जाना	249
210	सेवा में व्यवधान मत सेवा की समाप्ति करता है—अपवाद	249
211	बिना अवकाश की अनुमति के समय का भर्तों सहित अवकाश में व्याप्त	251
212	व्यवधानों का बन्दोबस्त	251
213-	कमियों की बन्दोबस्त	253

अध्याय २०

पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें

खण्ड १—पेंशनों का वर्गीकरण

उच्च सेवा के लिए पेंशनों का वर्गीकरण 254

खण्ड २—क्षतिपूरक पेंशनें (Compensation Pensions)

5	क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें	255
6 व 217	स्थापना की कटौती पर तरीका	256
8 से 221	क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध	256
2 व 223	सेवा की किस्म में परिवर्तन करने पर सेवा से हटाने के लिए विशेष मामला	256
4	सेवा से हटाने का नोटिस	257
5	अनुबन्ध के समय में सेवा से हटाया जाना	258
6	पुनर्नियुक्ति का अवसर देना	258
7	नये पद की स्वीकृति	258

खण्ड ३—अयोग्य पेंशनें

8	स्वीकृत करने की शर्तें	259
9	चिकित्सा प्रमाण पत्र का आवश्यक होता है तथा किसका आवश्यक होता है	259
10 व 231	मामले का इतिहास संलग्न किया जाता	260
12	चिकित्सा प्रमाण पत्र का फार्म	260
13	पुलिस सेवा में विशेष सावधानी	261
14	चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश	262
15	प्रतिबन्ध	262
16	प्राप्ति की सेवा से हटाये जाने का तरीका	262

खण्ड ४ अधिवापि की पेंशन (Superannuation Pension)

19	स्वीकृत करने की शर्तें	263
13	सेवा निवृत्ति पेंशन	265
14 (1)	30 साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के बाद वैकल्पिक सेवा निवृत्ति	265
14 (2)	25 साल की योग्य सेवा पूर्ण करने के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति	265
15	समन्वित नियुक्तियाँ	266
16	चतुर्थे वर्ष की सेवा के लिए पेंशन	266

अध्याय २१

पेंशनों की धनराशि (Amount of Pensions)

खण्ड १—सामान्य नियम

247	धनराशि किस तरह नियमित होती है	266
248 व 249	अनुमोदित सेवा के लिए ही पूर्ण पेन्शन की स्वीकृति	267

खण्ड २—पेन्शन के लिए गिने गए भत्ते

250 व 250	(क) कुल राशि (Emoluments) की परिभाषा	269
251	औसतन कुल राशि (Average emoluments)	277
252	वे भत्ते जो शामिल नहीं किये जाते हैं	285
253 व 254	(क) वास्तविक कुल राशि जो गिनी जाती है	285
255	एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य करने से पेन्शन में कृद्धि नहीं होती	286

अध्याय २२

खण्ड १—पेन्शन

256	पेन्शन का परिमाण (Scale of Pension)	289
-----	-------------------------------------	-----

खण्ड २—मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपदान

(Death-Cum-Retirement Gratuity)

257	मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति प्रच्युती कब स्वीकार्य होती है (when admissible)	300
258	मृत्यु की हालत में	308
259	कुल राशि की परिभाषा (Emoluments defined)	308
260 (1)	परिवार की परिभाषा (मनोनयन हेतु)	308
260 (2)	कब आवश्यक है	309

अध्याय २३

परिवार पेन्शन (Family Pension)

261	स्वीकृति की शर्तें	317
262	राशि (Amount)	318
263	परिभाषा	320
264	प्रतिबन्ध	320
265	वितरण का नम	321
266	मनोनयन का विरूप	322
267	पेन्शन पुरस्कार का भुगतान	322

268	परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन या क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त चातू रहने योग्य	322
-----	--	-----

अध्याय २३ क.

नई परिवार पेंशन (New Family Pension)

268 (क)	लागू होने की सीमा	322
268 (ख)	पेंशन स्वीकृत करने योग्य	323
268 (ग)	परिवार पेंशन की राशि	323
268 (घ)	परिभाषा	324
268 (ङ)	स्वीकृति की शर्तें	325
268 (च)	वितरण का क्रम	325
268 (छ)	प्रोटो को हिस्सा छोड़ना	326
268 (ज)	इस अध्याय के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विवरण	326

अध्याय २३ ख. पेंशन सम्बन्धी लाभों के बदले पुरस्कार (अवार्ड)

268	अ-प्रयोग्यता	339
268	अ-अवार्ड की प्रयोग्यता	339
268	अ-अवार्ड की राशि	340
268	अ-परिवार में कौन शामिल होंगे	340
268	अ-स्वीकृत करने की शर्तें	341
268	अ-प्रक्रिया	341

अध्याय २४

असाधारण पेंशनें (Extraordinary Pensions)

269	लागू होने की सीमा	343
269 (क)	परिभाषाएँ	344
270 से 272	पुरस्कार की शर्तें	346
273	घोटों का वर्गीकरण (Classification of injuries)	347
274	घोटों के लिए पुरस्कार (Award in respect of injuries)	347
275	राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा पति एवं बच्चों को पुरस्कार	349
276	मृत कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को पुरस्कार	351
277	प्रभावशील होने की तारीख (Date from which effective)	352
278	शरीर	352

अध्याय २५

पेंशन स्वीकार करने हेतु आवेदन पत्र

अनुभाग-१- सामान्य

279	प्रयोग्यता	353
280	भगले बरफ माहों के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना	354

281	पेंशन के लिए धीरधारिण आदेशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया	354
282	पेंशन स्वीकृत करने में गलत प्रक्रियाएँ	354
283	हेतुबोध रूप का पत्र मनने के कारण पेंशन का पुनरीक्षण	354
284	पेंशन वागवालों की संशयों का समाधान करना	355
285	राज पत्रिका अधिकाधिकों की पेंशन हेतु धीरधारिण आदेशन पत्र का प्रपत्र भेज दिया जाना	355
286	जब पेंशन के अन्तिम रूप में निर्धारित एवं निगमित किए जाने की सम्भावना न हो या निर्धारित जाँच करने के बाद अन्तिम पेंशन (प्रोबेशनल पेंशन) के लिए प्राधिकार देना	356
287	पेंशन वागवालों में बिमरुह न करना	357
288	गैरा सम्पादित करने के बाद सेवा विवरण संसार करना	357
289	पेंशन सम्बन्धी वागवालों पूरे करना	358
290	प्रपत्र पी-३ में पेंशन स्वीकृत प्राधिकारों के आदेश	358
291	उन तथ्यों की सूचना जो महालेखाकार के पास पेंशन वागवालों के भेज दिए जाने के बाद पेंशन की राशि पर प्रभाव डालने वाले पाए जाएँ	359
292	अन्तिम पेंशन एवं उद्दान (प्रोबेशनल पेंशन एन्ड पेंशुटी) का मुग्तान	359
293	पेंशन आदेशन पत्र पर अंशेष्टा द्वारा सुगन्धन	360
294	प्रपत्र पी-२ के भाग II में क्लेम की गई सेवा के आसोहन करने के कारणों का महालेखाकार उत्प्रेषण करेगा	361
295	सरकारी बकायों का मुग्तान करना सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य	361
296	बकाया ऋणों की वसूली के लिए रखी सरकारी कर्मचारी की जमीन को या उपयुक्त नकद धन को स्वीकार करना या अमानत के रूप में उपदान के एक भाग को रोकना	362

अध्याय २६

पेंशनों का मुग्तान (Payment of Pensions)

301	साधारण मामलों में मुग्तान की तारीख	377
302	विशेष मामलों में मुग्तान की तारीख	378
303	असाधारण पेंशन के मुग्तान की तारीख	378
305	एक मुदत मुग्तान करने योग्य पेंशुटी	378
306	पेंशन के मुग्तान का तरीका	378
307	पट्टिचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति	378
308	व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट	378
309	जीवन प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर्ता प्राधिकारी	379
309 (क)	एक ऐजेंट द्वारा पेंशन प्राप्त करना	379
310	साल में एक बार पेंशनर के जीवित रहने का सत्यापन करना	380

311-	पुलिस पेन्शनर की पहिचान	380
312	एक प्राधिकृत एजेंट द्वारा पेन्शन प्राप्त करना	380
313 व 314	भारत में एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का हस्तान्तरण	381
315	एक जिला ट्रेजरी के बचीन एक ट्रेजरी से दूसरी ट्रेजरी में भुगतान का स्थानान्तरण	382
316	सेवा नहीं करने का प्रमाण पत्र	382
317	पेन्शन पेमेंट ग्राहक का नवीनीकरण	383
318	सो जाने पर नया पेन्शन पेमेंट ग्राहक जारी करना	383
319	भुगतान कब बन्द किया जावे	383
320 व 321	पेन्शन के बकायों का भुगतान	383
322	मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को पेन्शन का भुगतान	383
323	मृत पेन्शनर की बकायों का उसके उत्तराधिकारियों के लिए भुगतान	384
324	जब सेवा, निवृत्ति या डिस्चार्ज-किए जाने के पूर्व ही राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाये	384

अध्याय २७

पेंशन का रूपान्तरण (Commutation of Pension)

325	पेन्शन के रूपान्तरण की आज्ञा	385
326	तरीका	386
327	रूपान्तरण पर भुगतान करने योग्य एक मुक्त राशि	389
328	मृत पेन्शनरों के उत्तराधिकारियों के लिए रूपान्तरित राशि का भुगतान	389
329 व 330	पेन्शन के रूपान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र	389
331	महालेखाकार के कार्यालय का तरीका	390
332 व 333	रूपान्तरण के लिए प्रदासनात्मक स्वीकृति	391
334 व 335	स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Examination)	391
336	रूपान्तरित राशि का भुगतान	393

अध्याय २८

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति (Re-employment of Pensioners)

खंड १—सामान्य

337	पुनर्नियुक्त पेन्शनरों का वेतन	393
338 व 339	पेन्शनर को नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के पेन्शन की राशि की घोषणा करना	396

340 पुनर्नियुक्ति के समय में प्रसाधारण पेन्शन स्वीकार्य

खंड २—सिविल पेंशनर्स

- 341 पुनर्नियुक्ति पर प्रोब्युटी वापिस सोटाना
 342 प्रोब्युटी सोटाने के लिए माहवारी बिस्ते
 343 क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति
 344 तीन माह के भीतर बिस्ते दिया जाना
 345 अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति
 346 अविवाहिकी आयु या सेवा निवृत्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति
 347 पेंशन स्थगित करने की शक्ति
 348 पेंशन रूपान्तरित होने पर पुनर्नियुक्ति पर बेटन
 349 व 349 (क) पेंशन रूपान्तरित कर की जाती है

खंड ३—मिलिट्री पेंशनर (Military Pensioner)

350 व 351 मिलिट्री पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति

खंड ४—नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

- 352 नई सेवा के लिए पेंशन प्राप्त नहीं करेगा
 353 से 355 बाद की सेवाओं के लिए पेंशन या प्रोब्युटी की सीमा

खंड ५—सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा

- 356 राज्य सरकार की पूर्वाभूमति आवश्यक
 357 पेंशनर द्वारा भारत के बाहर नियुक्ति पर अनुपति लेना

राजस्थान सेवा नियम

संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने, राजस्थान के काम काज के सम्बन्ध में राज्य पदों पर राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के बारे में निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अध्याय १

लागू होने की सीमा (Extent of Application)

नियम १. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—ये नियम राजस्थान सेवा नियम कहलायेंगे। ये नियम १ अप्रैल, 1951 से प्रभावशाली समझे जायेंगे।

टिप्पणी—यदि कोई व्यक्ति 1-4-51 की अवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

नियम २. लागू होने की सीमा—ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे:—

(1) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में या उसके कार्य के सम्बन्ध में पदों या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(2) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके बाद में प्रसंविधान्तर्गत राज्यों की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किए गए हों।

+(3) उन समस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या प्रसंविधान्तर्गत राज्य की सरकार द्वारा, समझौते के आधार पर, ऐसे पदों पर या सेवाओं पर इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हों जो कि नियुक्ति हेतु उनकी संविदा में विशेष रूप से प्रावहित न किये हों।

परन्तु धार्त यह है कि खण्ड (2) में उल्लेख किये गये श्रेणी के व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने से या जब एकीकरण के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति होने से दो माह के भीतर, इनमें से जो कोई बाद में हो उस तक, सेवा-निवृत्त (रिटायर) होने के लिये प्राप्यता पत्र देंगे तथा उन्हें पेन्शन या उपदान (ग्रैजुटी) उन नियमों के अनुसार मिलेगा जो उस एकीकरण के प्रारम्भ होने या उनकी नियुक्ति के पूर्व में लागू थे।

परन्तु इसके साथ ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:—

(क) भारत सरकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत की किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर भेजे गये अधिकारियों पर, क्योंकि उन पर उनकी मूल नियुक्तियों के नियम ही लागू होंगे।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(104) वित्त वि./नियम 66 दि० 20-4-67 द्वारा संशोधित।

340	पुनर्नियुक्ति के समय में असाधारण पेन्शन स्वीकार्य	397
-----	---	-----

खंड २—सिविल पेंशनर्स

341	पुनर्नियुक्ति पर प्रेच्युटी वापिस सोटाना	398
342	प्रेच्युटी सोटाने के लिए माहवारी बिस्ते	398
343	क्षतिपूर्ति पेंशन के बाद पु न्नियुक्ति	398
344	छीन माह के भीतर बिस्तर दिया जाना	400
345	अयोग्यता पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति	400
346	अधिकाधिकी काम या सेवा निवृत्ति पेंशन के बाद पुनर्नियुक्ति	401
347	पेंशन स्थगित करने की शक्ति	403
348	पेंशन रूपान्तरित होने पर पुनर्नियुक्ति पर वेतन	404
349 व 349 (क)	पेंशन रूपान्तरित बब की जाती है	404

खंड ३—मिलिट्री पेंशनर (Military Pensioner)

350 व 351	मिलिट्री पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति	405
-----------	------------------------------------	-----

खंड ४—नई सेवा के लिए पेंशन (Pension for New Service)

352	नई सेवा के लिए पेंशन प्राप्त नहीं करेगा	406
353 से 355	बाद की सेवाओं के लिए पेंशन या प्रेच्युटी की सीमा	406

खंड ५—सेवा निवृत्ति के बाद व्यापारिक सेवा

356	राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक	407
357	पेंशनर द्वारा भारत के बाहर नियुक्ति पर अनुमति सेना	408

राजस्थान सेवा नियम

मंत्रिधान की धारा 309 के परन्तुक के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने, राजस्थान के काम काज के सम्बन्ध में राज्य पदों पर राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के बारे में निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

अध्याय १

लागू होने की सीमा (Extent of Application)

नियम 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—ये नियम राजस्थान सेवा नियम कहलायेंगे। ये नियम 1 अप्रैल, 1951 से प्रभावशील समझे जायेंगे।

टिप्पणी—यदि कोई व्यक्ति 1-4-51 को अवकाश पर हो, तो ये नियम उस पर अवकाश से लौटने की तारीख से लागू होंगे।

नियम 2. लागू होने की सीमा—ये नियम निम्न व्यक्तियों पर लागू होंगे—

(1) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में या उसके कार्य के सम्बन्ध में पदों या सेवाओं पर राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों।

(2) उन समस्त व्यक्तियों पर, जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके बाद में प्रसंविधानान्तर्गत राज्यों की सेवाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप ऐसे पदों या सेवाओं पर नियुक्त किए गए हों।

+(3) उन समस्त व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार द्वारा या प्रसंविधानान्तर्गत राज्य की सरकार द्वारा, समझौते के आधार पर, ऐसे पदों पर या सेवाओं पर इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हों जो कि नियुक्ति हेतु उनकी संविदा में विधेय रूप से प्रावहित न किये हों।

परन्तु शर्त यह है कि खण्ड (2) में उल्लेख किये गये श्रेणी के व्यक्ति, इन नियमों के प्रारम्भ होने से या उक्त एकीकरण के परिणामस्वरूप उनकी नियुक्ति होने से दो माह के भीतर, इनमें से जो कोई बात में हो उस तक, सेवा-निवृत्त (रिटायर) होने के लिये प्रारम्भ पर प्रवेश तथा उन्हें वेतन या उपदान (ग्रैज्युटी) उन नियमों के अनुसार मिलेगा जो उक्त एकीकरण के प्रारम्भ होने या उनकी नियुक्ति के पूर्व में लागू थे।

परन्तु इसके साथ ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:—

(क) भारत सरकार या राजस्थान के अतिरिक्त भारत की किसी अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति (deputation) पर भेजे गये अधिकारियों पर, क्योंकि उन पर उनकी मूल नियुक्तियों के नियम ही लागू होंगे।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1(104) वित्त वि./नियम 66 दि० 20-4-67 द्वारा संशोधित।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे ।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे ।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में धरनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रस्तावदन (रिजुमेन्टेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके प्रस्तावदन (रिजुमेन्टेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्णय ले सकती है कि परन्तुक्त में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके प्रस्तावदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे ।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम । अप्रैल, 1951 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं । इसका प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है ।

निर्णय—इन विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) धार 51 दिनांक 22-8-51, नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के तत्पश्चात् दिए गए परन्तुक्त के एवं के सम्बन्ध में कुछ संशेद स्पष्ट किए गए हैं । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काज में सम्मिलित एक पद पर प्राविक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार धानीय होना) भी शामिल है । इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो । चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो ।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा नियुक्ति तक ही सीमित है । उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस सम्बन्ध का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण अवस्था में किसी पद, क्रेटर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है । यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, इन्डियन पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुक्रम श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी ;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (2) धार/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है ।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रह नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में भ्रम्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करते हैं।

नियम संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 12 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए भ्राप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों में सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं को एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये भ्राप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए भ्राप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सर्वस्टान्डिग एपॉइन्टमेंट) राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद भ्राप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस भ्राप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के भ्राप्सन का प्रयोग में लाने में कोई प्रतिवन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई भ्रम्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके भ्रम्यावेदन पर प्राप्ति के फसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

नियम संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या एक 35 (2) भार 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूर्क पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोषपुर के भ्रम्यावेदनी भविष्य निधि नियमों (फान्डीयूटरी प्रोविडेंट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में भ्रम्यावेदनी भविष्य निधि (फान्डीयूटरी प्रोविडेंट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाए जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एस्टाब्लिशमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे ।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे ।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) देना है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) के तब होने पर सरकार यह निर्णय दे सकती है कि परन्तुक्त में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे ।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम । अप्रैल, 1951 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं । इसका प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है ।

निर्णय—इस विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) धार/51 दिनांक 22-8-51, नियम 2 के नीचे दो गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के ब तद्धीन दिए गए परन्तुक्त के एवं के सम्बन्ध में कुछ सुन्दर व्यक्त किए गए हैं । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके काम काम में सम्मिलित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार अधीन होना) भी शामिल है । इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो । चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही बना या रहा हो ।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है । उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रावधान का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केटर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है । यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, अतिपूरक पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी ;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (2) धार/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया गया है ।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रद्द नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बाद में शम्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करते हैं।

नियम संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए श्राप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर प्रावश्यक रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये श्राप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए श्राप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के तथ्य, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (संस्टान्टिव एपॉइन्टमेंट) राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद श्राप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस श्राप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के श्राप्सन का प्रयोग में लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई शम्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके शम्यावेदन पर प्राप्ति के फल होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

नियम संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या एफ 35 (2) भार 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, क्षतिपूर्क पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोषपुर के श्रमदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले में श्रमदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाए जायेंगे। ये मामले स्थापन वगैरे (एस्टाब्लिशमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ख) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे ।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे ।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रस्ताव (रिप्रेजेंटेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके प्रस्ताव (रिप्रेजेंटेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्णय सकती है कि परन्तुक में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके प्रस्ताव के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होनी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होनी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे ।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रैल, 1951 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं । इसका प्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है ।

निर्णय—इन विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) धार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) में तदधीन दिए गए परन्तुक के एवं के सम्बन्ध में कुछ मन्देश व्यक्त किए गए हैं । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन या उसके नाम मात्र से सम्बन्धित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार आसीन होना) भी शामिल है । इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो । चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो ।

प्रावधान में बतलाया गया विकल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है । उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रावधान का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, क्रेटर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है । यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, क्षतिपूर्ति पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुकूल श्रेणी) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी ;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (2) धार/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया गया है ।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एफ 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रह नहीं सम्झी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में भ्रम्यावेदन (रिप्रजेन्टेशन) पेश करते हैं।

नियम संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 12 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए भ्राप्सन के प्रयोग में धीर भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों में सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये भ्राप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में भूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए भ्राप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में भूल नियुक्ति (सर्वेस्टामेंट एपोइन्टमेंट) राजस्थान सेवा नियमों के चालू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद भ्राप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही हो। अन्य मामलों में भी भूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस भ्राप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के भ्राप्सन का प्रयोग में लाने में कोई प्रतिवन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई भ्रम्यावेदन (रिप्रजेन्टेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके भ्रम्यावेदन पर आखिरी कैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

नियम संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या एफ 35 (2) भार 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिशा दिया है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, सतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल थैली) के रूप में उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले प्रशंदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाए जावेगे। ये मामले स्थापन वर्ग (एटान्सिशनमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवामुक्ति (डिस्चार्ज) मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

(ल) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय में उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे; या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से शासित होंगे ।

(ङ.) अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सदस्यों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे ।

टिप्पणी—यदि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खण्ड (2) लागू होता हो और वह एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को एक अभ्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) देता है, तो ऐसी दशा में उसके अभ्यावेदन (रिप्रिजेंटेशन) के तय होने पर सरकार यह निर्देश दे सकती है कि परन्तुक्त में उल्लेख की गई दो माह की अवधि, उसके अभ्यावेदन के अन्तिम निर्णय की तारीख से लागू होगी चाहिये या ऐसी तारीख से लागू होगी चाहिये जिसे सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तय करे ।

आदेश—राजस्थान सेवा नियम 1 अग्रेज, 1951 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू कर दिए गए हैं । इसका प्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 के साथ पठित अनुच्छेद 229 (2) से है ।

निर्णय—इन विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) धार 51 दिनांक 22-8-51, नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) के साथ पठित, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के अन्तर्गत दिए गए परन्तुक्त के एवं के सम्बन्ध में कुछ मन्देश व्यक्त किए गए हैं । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार कर दिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि खण्ड (2) में राज्य सरकार के प्रशासनिक निदेशों के अधीन या उसके काम काज से सम्बन्धित एक पद पर प्राविधिक (Provisional) नियुक्ति (या उस पद पर लगातार धामीन होना) भी शामिल है । इस पद पर नियुक्ति चाहे एकीकरण की तिथि के बाद एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुई हो । चाहे ऐसा पद एकीकरण के कारण किसी विभाग या सेवा या अन्य प्रकार से नया सृजित (created) किया गया हो या चाहे राजस्थान के एकीकरण के पूर्व से ही चला आ रहा हो ।

प्रावधान में बतलाया गया विवल्प (option) सेवा निवृत्ति तक ही सीमित है । उसका सेवा नियमों के अन्य पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्राप्ति का उपयोग राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से दो माह के भीतर अथवा एकीकरण व्यवस्था में किसी पद, केहर या सेवा में मूल नियुक्ति से इसी समान अवधि के भीतर तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है । यदि कोई राज्य कर्मचारी सेवा से निवृत्त होना चाहता हो तो उसकी पेन्शन, क्षतिपूर्ति पेन्शन (Compensation pension) (या पेन्शन की तदनुक्रम अंशों) के रूप में, उस पर पूर्व में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, दी जाएगी ;

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (2) धार/52 दिनांक 12 फरवरी, 1952 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) और उसके अधीन दिए गए प्रावधान के सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियम 2 ।

इससे वित्त विभाग के पत्र संख्या एक 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) रह नहीं समझी जावेगी; यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में है जो एकीकृत सेवा में अपनी नियुक्ति के बारे में भ्रमविदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करते हैं।

निर्णय संख्या 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के खण्ड (2) के प्रावधान में बतलाए गए भ्राप्सन के प्रयोग में और भी सन्देह व्यक्त किए गए हैं। मामले पर सरकार ने विचार किया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त प्रावधान, यह निश्चय करने के लिए बनाया गया है कि राजस्थान सेवा नियम उन सब पर आवश्यकीय रूप से लागू होंगे जो राज्य सेवाओं की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी नियुक्ति को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को मानने को तैयार नहीं हो तो वह प्रावधान (Provision) में दिये गये भ्राप्सन का प्रयोग कर, सेवा से निवृत्त होने का पात्र हो सकेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के प्रारम्भ होने से या एकीकरण व्यवस्था में मूल नियुक्ति होने से (इनमें से जो कोई भी बाद में हो उससे) दो माह की अवधि के भीतर प्रावधान में दिए भ्राप्सन का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त अवतरण 1 के लिये, इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों में मूल नियुक्ति (सर्वटान्तिव एपोइन्टमेंट) राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने के पूर्व ही हो चुकी हो, उन मामलों में नियमों के जारी होने के बाद भ्राप्सन देने की अवधि, केवल दो माह तक ही थी। अन्य मामलों में भी मूल नियुक्ति से दो माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व इस भ्राप्सन को कभी भी प्रयोग में लिया जा सकेगा। परन्तु यदि कोई राज्य कर्मचारी इन नियमों से अनुशासित नहीं होना चाहे तो उसके लिए स्थायी नियुक्ति होने से पूर्व भी सेवा से निवृत्त होने के भ्राप्सन को प्रयोग में लाने में कोई प्रतिवन्ध नहीं है।

यदि एक व्यक्ति एकीकृत व्यवस्था में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई भ्रमविदन (रिप्रिजेंटेशन) पेश करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान में बतलाई गई दो माह की अवधि, उसके भ्रमविदन पर भाषिणी कैसला होने की तारीख से गिनी जाएगी या ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 35 (8) भार/51 दिनांक 22-8-51 (नियम 2 के नीचे दी गई टिप्पणी) में पहिले ही किया जा चुका है।

निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के मेमोरेण्डम संख्या एक 35 (2) भार 52 दिनांक 12-2-52 (राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के अनुसार सेवा से निवृत्त होने की इच्छा करता हो तो पेन्शन, सतिपूरक पेन्शन (या पेन्शन की तदनुकूल थैली) के रूप में उसे पर पूर्व से लागू होने वाले नियमों के अनुसार दी जाएगी। ऐसी ही परिस्थितियों में उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक प्रदन उत्पन्न हुआ है जो पेन्शन के स्थान पर जोधपुर के अंशदायी भविष्य निधि नियमों (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) से शासित होते हैं।

मामले पर विचार कर लिखा गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फण्ड) नियमों के अनुसार निपटाए जायेंगे। ये मामले स्थापन वर्ष (एस्टाब्लिशमेंट) में कटौती के कारण सेवा निवृत्ति या सेवानिवृत्ति (डिस्चार्ज) मामलों के समान निपटाए जाएंगे।

नियम संख्या 5—जोधपुर की पूर्व स्टेट के कुछ राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के जारी होने की तारीख 1-4-51 की या उनके बाद अधिकाधिकी धातु प्राप्त करने आदि के कारण (न कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 2 के प्रावधानों के अन्तर्गत) सेवा से निवृत्त हो चुके थे। लेकिन उनके सेवा निवृत्त होने से पहिले विभाग का अन्तिम रूप से एकीकरण नहीं हो चुका था। अब कुछ संदेह इस सम्बन्ध में उठाए गए हैं कि क्या ऐसे व्यक्तियों के पेंशन के मामलों को रियासत के नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए अथवा राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि क्योंकि राज्य कर्मचारी ने रियासत के नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त होने के अपने आपन का प्रयोग नहीं किया है, अतः उनके पेंशन के मामले राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निपटाए जाने चाहिए।

नियम 3. वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना—इन नियमों के अनुसार वित्त विभाग की सलाह के बिना कोई भी दलित या न उपभोग की जा सकती है और न प्रदत्त हो की जा सकती है। यह उस विभाग को छूट होये कि यह, सामान्य या विदेश आदेश द्वारा, ऐसे मामलों को निरिक्त कर सकता है जिनमें कि वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की हुई मान ली गई है। यह यह भी अवस्था करेगा कि किसी भी मामले में ली गई उसकी सहमति को सलाह प्राप्त करने वाला विभाग, राजप्रमुख को पेश करेगा।

नियम 4. परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति—सरकार इन नियमों या आदेशों के बनाने की शक्ति की सीमा तक, उचित ढंग से इन नियमों के प्रावधानों में रियायत कर सकती है।

+ निर्णय सं० 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारी जो 55 वर्ष या इससे अधिक के हैं एवं जो 58 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष की अधिकाधिकी धातु पर सेवा निवृत्त किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 1 जुलाई 1967 से सेवा-निवृत्त होते हों, निम्नलिखित रूप में नौगनल सेवा के प्रतिरिक्त वनों की ध्यान में रखकर दिनांक 1 जुलाई 1967 को वर्तमान नियमों के अनुसार संगठित सेवा निवृत्ति लाभों को उन्हें स्वीकृत किया जाएगा:—

(1) सेवा-निवृत्ति लाभों की अर्हकारी सेवा (स्वातोपादंग सविष) नौगनल सेवा में तीन वर्ष जोड़कर, बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) नौगनल सेवा की उक्त वृद्धि की रोकने पर सेवा की कुल अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नहीं होगी जिसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी 21 वर्ष तक की धातु में सेवा निवृत्त होने पर मिला सकता था।

• (2) जहाँ उपरोक्त पैरा 1 के अधीन सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा बढ़ा दी गई हो वहाँ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 के साथ पठित नियम 250 में यथापारि-नायित परिस्थितियों, जिन्हें सरकारी कर्मचारी 1-7-67 के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, प्रतिरिक्त प्रकल्पित सेवा (एडीनल नौगनल सविष) की अवधि में उसके द्वारा प्राप्त की हुई समानो जाएगी

+ वित्त विभाग की अधिमूर्चना सं० एड1(42) वित्त वि० (नियम) 67 III दि० 13-6-67 द्वारा पामिल किया गया

• अन्तिम पदे के स्थान पर प्रतिस्थापित

दि० 30-9-67

(यद्यपि वह उन्हें वास्तव में प्राप्त नहीं करेगा) तथा उक्त नियम 251 के अधीन भौत परिलब्धियाँ ऐसी प्रकल्पित परिलब्धियों के आधार पर संगणित की जाएगी ।

(3) उपर्युक्त पैरा 2 में अन्तर्बिष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन दि० 1-7-67 के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम 3 वर्षों के दौरान उसके द्वारा वास्तव में माहुरित 'परिलब्धियों' के आधार पर निश्चित की जाएगी यदि वह परिलब्धि उपर्युक्त पैरा 2 के अधीन संगणित की गई परिलब्धियों से अधिक निकलती हो ।

ये आदेश दिनांक 1-7-67 से प्रभावी होते हैं । अन्य प्रकार से निर्णय किए गए मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा उन्हें इन आदेशों के अधीन निर्णीत किया जाएगा ।

+ निर्णय सं० 2— यह आदेश दिया जाता है कि जो दि० 1-7-60 को या उसके बाद, किन्तु 30-6-70 से पूर्व 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होते हैं/होंगे तथा जिनके मामले में राजस्थान सेवा नियमों के सामान्य प्रावधानों के अधीन मुग्तान योग्य पेंशन एवं/या उपदान उक्त पेंशन सम्बन्धी लाभों की राशि से कम आती हो ओ यदि वह 1-7-67 को सेवा निवृत्त होता तो उसे दि० 30-5-70 द्वारा यथा संशोधित वित्त विभाग के आदेश दि० 13-6-67 (उक्त राजस्थान सरकार के निर्णय सं० 1 के रूप में प्रयुक्त) के अधीन स्वीकार्य होती, तो उसे उक्त आदेशों के अनुसार संगणित पेंशन/उपदान दिया जाए ।

इन आदेशों के जारी किए जाने के पूर्व अन्यथा प्रकार से निर्णय किए गए पेंशन क्लेमों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा उन्हें उन आदेशों के अनुसार निपटाया जाएगा ।

× निर्णय सं० 3—विषय—उन सरकारी कर्मचारियों को जो स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होना चाहते हैं, सेवा निवृत्ति लाभ स्वीकृत किया जाना ।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (1) के अधीन स्वेच्छा से जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त होना चाहते हैं, उन्हें उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख की निम्नानुसार प्रकल्पित सेवा (नोशनल सर्विस) अतिरिक्त वर्षों को गिने जाने के बाद विद्यमान नियमों के अनुसार संगणित किए गए सेवा निवृत्ति लाभ, दिये जा सकते हैं:—

1. पेंशन नियमों द्वारा शासित सरकारी कर्मचारियों के लिए:—

(1) सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अर्हकारी सेवा को उक्त मामले में 5 वर्ष जोड़ कर बढ़ाया जाना चाहिए ।

(2) प्रकल्पित सेवा को उक्त अवधि को जोड़े जाने के बाद सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा में 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा से या उस सेवा से जिसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी यदि अधिकाधिकी आयु प्राप्त करने तक करता तो गिनी जाती, इनमें से जो भी कम हो, ज्यादा नहीं होगा ।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक1(42) वित्त वि० (नियम) 67 III दि० 30-5-67 द्वारा निदिष्ट

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक1('99') वित्त वि/नियम/66 दि० 27-12-69 द्वारा निदिष्ट

(3) जहाँ पर सेवा निवृत्ति सामो के लिए अर्हकारी सेवा उक्त (1) व (2) के अधीन बढ़ाई जाती है तो परिलक्षिण्या, जो कि नियम 250 से भी परिभाषित है, एवं जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त की हुई सम्पत्ती जाएगी (यद्यपि वह वास्तव में प्राप्त नहीं की गई है) तथा उपर्युक्त नियम 251 के अधीन योग्य परिलक्षिण्या उक्त प्रकल्पित परिलक्षिण्या के आधार पर संगणित की जाएगी।

(4) उपर्युक्त (3) में किसी बात के अन्तर्निष्ठ होने हुए भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवा निवृत्ति के पूर्व उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के भीतर उसके द्वारा वास्तव में अतिरिक्त परिलक्षिण्या के आधार पर निर्दिष्ट की जाएगी यदि वह उपर्युक्त (3) के अधीन स्वीकार्य पेंशन से अधिक होती हो।

2. अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा प्राप्त कर्मचारियों के लिए—

सरकारी कर्मचारियों को उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख को वर्तमान जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान नियमों के अनुसार उत्तम प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद भविष्य निधि लाभ निम्न प्रकार दिए जाएंगे :—

(1) सरकारी अंशदान (सामांश एवं विशेष अंशदान) उन राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए जो कि पाँच वर्ष की अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़े जाने के बाद उसे उद्भूत हुई होती।

(2) उपर्युक्त तरीके से की गई परिणामी वृद्धि, उस अंशदान (सामांश एवं विशेष अंशदान) जो कि यदि वह 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने पर या अधिवापि की प्राप्ति करने तक सेवा में रहता तो अपने भविष्य निधि लेख में जमा हो गई होती, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(3) प्रकल्पित अंशदान, सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व किए गए अंशदान की राशि के आधार पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख तक या उनके बाद तक, निधि में अंशदान किए बिना ही बढ़ाया जाएगा।

2. वित्त विभाग की भाषा सं० एफ 1 (99) वित्त वि (अध्य-नियम), 66 दि० 31-12-66 एतद्वारा वापिस लिया जाना है।

3. ये आदेश दि० 1-12-69 से प्रभावी होंगे।

+ निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (71) वित्त वि/नियम/69 दिनांक 19-11-69 द्वारा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष के या इससे अधिक की आयु के हो गए हैं, उक्त दिनांक से उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया है। चूँकि इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया अतः उन्हें अवकाश का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया था। अतः राज्यपाल ने आदेश दिया है कि उन्हें निम्नलिखित अवकाश सम्बन्धी रियायतें प्रदान की जाएँ :—

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1(80) वित्त वि. नियम/69 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

(1) सरकारी कर्मचारी जिनके लेखे में दिनांक 1-12-69 से ठीक पूर्व जितना उपाजित अवकाश बकाया है, वह उस अवकाश के लिए आवेदन करेगा। आवेदित अवकाश को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देते हुए, अधिकतम 120 दिन की सीमा के अधीन रहते हुए, अस्वीकृत अवकाश के रूप में समझा जाएगा। अस्वीकृत अवकाश की स्वीकृति मागे भी इस शर्त पर ही दी जाएगी कि वह उस तारीख के बाद तक का नहीं होगा जिसको कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता।

(2) उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1-12-69 के बाद किन्तु 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते हैं/हूए हैं, उन्हें बकाया एवं आवेदित उपाजित अवकाश निम्नलिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सता है :—

(क) 1-12-69 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में समस्त बकाया उपाजित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, जिसे वह सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप में उपाजित कर सकता था, उसमें से उसके द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की काट कर, अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 1-1-70 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा निवृत्ति के पूर्व बकाया उपाजित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जाएगा परन्तु उसमें से (1) दिनांक 31-12-69 तक वास्तव में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की (2) तथा दिनांक 1-1-70 से उसके सेवा निवृत्त होने के ठीक पूर्व की तारीख तक की अवधि को, घटा दिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त (1) व (2) के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन नियम 89 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (48) वित्त वि. (अध्य-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा निविष्ट किया गया था) के अनुसार निकाला जाएगा तथा हर माह के अन्त में भुगतान योग्य होगा। जहाँ पेंशन या उपदान के समस्त पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं हों वहाँ अवकाश वेतन का भुगतान सामान्य रूप में किया जाना चाहिए तथा अधिक भुगतानों की रेशन या प्रॉच्युटी या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में से, जब वे स्वीकृत हों, काट लिया जाएगा। इस बात की सुनिश्चित करने के लिए कि अवकाश वेतन का अधिक भुगतान वसूल किया जा सके, आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन कागजातों के साथ साथ सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की भुगतान की गई अवकाश वेतन की राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार पर महालेखाकार अधिक राशि को पेंशन से वसूल करने के लिए एक टिप्पणी लिखेगा।

× निर्णय संख्या 5:—विषय—चतुर्थ श्रेणी सेवा कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 4 द्वारा प्राप्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा का सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 1-12-69 को या उसके बाद किन्तु 31-12-71 तक अधिवापिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1(80) वित्त वि. नियम 69-1 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

होता है, उसे प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद सेवा निवृत्ति के समय विद्यमान नियमों के अनुसार, संगणित जो लाभ दिए जाएंगे वे निम्न होंगे :—

(1) पेंशन नियमों द्वारा शासित चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी के लिए

(1) सेवा निवृत्ति लाभों के लिए ग्रहणीय सेवा की 2 वर्ष जोड़कर बढ़ाया जाना चाहिए ।

(2) उक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़ने पर सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा में उस सेवा से अधिक नहीं होगी जिसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने पर गिनता ।

(3) जहाँ सेवा निवृत्ति लाभों के लिए ग्रहणीय सेवा उक्त (1) व (2) के अधीन बढ़ाई जाए वहाँ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 250 ख में यथा परिभाषित परिलक्ष्यियाँ, जिसे सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, उक्त नियमों के नियम 251 के अधीन अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा की अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त की हुई समझी जाएगी । (यद्यपि वास्तव में प्राप्त नहीं की गई है) तथा उक्त नियमों के नियम 251 के अधीन प्राप्त परिलक्ष्यियाँ उक्त प्रकल्पित परिलक्ष्यियों के आधार पर निकाली जाएगी ।

(4) उपर्युक्त (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की पेंशन सेवा निवृत्ति के पूर्व उनकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों की अवधि के भीतर उसके द्वारा वास्तव में आहरित परिलक्ष्यियों के आधार पर निर्दिष्ट की जाएगी यदि वह उपर्युक्त (3) के अधीन स्वीकार्य पेंशन से अधिक होती है ।

(2) सामान्य भविष्य निधि योजना द्वारा शासित चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख को वर्तमान जोधपुर भविष्य निधि एवं उपदान नियमों के अनुसार समझे प्रकल्पित सेवा के अतिरिक्त वर्षों को जोड़े जाने के बाद भविष्य निधि लाभ निम्न प्रकार दिए जाएंगे—

(1) सरकारी भण्डान, (लानाथ एवं विशेष भण्डान) उस राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए जो कि 5 वर्ष की अतिरिक्त प्रकल्पित सेवा को जोड़े जाने के बाद उसे उद्भूत हुई होती ।

(2) उपर्युक्त तरीके से की गई परिणामी वृद्धि किसी भी दशा में उस भण्डान (लानाथ एवं विशेष भण्डान) से, जो कि यदि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने भविष्य निधि लेख में जमा कराई गई होती, अधिक नहीं होगी ।

(3) प्रकल्पित भण्डान, सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व किए गए भण्डान की राशि के आधार पर उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख को या उसके बाद तब निधि में भण्डान किए बिना ही, बढ़ाया जाएगा ।

अधिमूचना (नोटिफिकेशन)—संविधान की धारा 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज प्रमुख ने निम्नलिखित नियम बनाया है :—

जहाँ सरकार इस बात से मनुष्ट हो कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों या ऐसे राज्य कर्मचारियों के किसी विनियम वर्षों की सेवा की गतों से सम्बन्धित किसी नियम को प्रयोग करने से किसी विनियम मामले में अनुचित कठिनाई पैदा होती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम को उस सीमा तक एवं ऐसी गतों के साथ समाप्त कर सकता है या उसमें रियायत कर सकती है जब तक कि उन मामले को उचित एवं न्यायोचित ढंग से गव करने के लिए आवश्यक न समझा जावे ।

1. इस नियम में प्रयुक्त "राजस्थान राज्य बर्मेचारी" शब्द का तात्पर्य उन सब व्यक्तियों से है जिनकी सेवा की शर्तें भारतीय संविधान की धारा 309 के प्रावधानों के अनुसार राज प्रमुख द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होती है।"

उचित एवं न्यायोचित ढंग से मामले को निपटाने के लिए संघीय राज्य बर्मेचारीयों की सेवाओं को शासित करने वाले किसी नियम को समाप्त करने या उसमें रियायत देने में केन्द्रीय सरकार की शक्ति से सम्बन्धित नियम का स्पष्टीकरण—

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अधीन सौकर सेवा में नियुक्त एवं राजस्थान के कार्य में लगे व्यक्तियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या ऐसे व्यक्ति में निहित है जिसे वह निश्चित करे। यह स्वयं सिद्ध है कि जो अधिकारी नियम बनाने के लिए सक्षम है वही नियम में संशोधन करने अवकाश उनकी व्याख्या करने के लिए सक्षम है। उच्चतम राज्य अधिकारी भी शक्तिशाली मामलों में कठिनाई पैदा करने वाले किसी सेवा नियमों के प्रावधानों में रियायत करने में सक्षम है। वह ऐसे मामलों में भी रियायत प्रस्तुत करता है जिनमें नियमों की कठोरता के कारण किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती है।

संविधान में इस तरह के प्रावधान को शामिल न किए जाने के फलस्वरूप कुछ संदेह ऐसे पैदा हो गए हैं जैसे कि क्या इन आन्तरिक (Inherent Power) का प्रयोग राज्यपाल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी प्रकार के संदेह को मिटाने के लिए तथा इस सम्बन्ध में स्थिति को सुस्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग ने विनियम संख्या एफ 7 (5) धार 55/ए दिनांक 16-7-55 द्वारा एक नियम बनाया है जिसमें कि इस सम्बन्ध के स्पष्ट प्रावधान का समावेश किया गया है।

यह नियम किसी एक ऐसे नए सिद्धांत को धमका पड़ति को प्रारम्भ नहीं करता है जो पूर्व से ही प्रचलन में न हो। लेकिन यह नियम केवल उस स्थिति को ही स्पष्ट करता है जिसे पूर्व से ही प्रचलित हुई समझी जाती रही है। राज्य सरकार को किसी विशेष मामले में न्यायोचित ढंग से किसी नियम में मानव्यता पड़ने पर, रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग, मूलकाल में केवल बिरले अवसरों पर तथा अपवादस्वरूप मामलों में ही, किए जाने की इच्छा थी। इस प्रकार के मामलों को निपटाने समय स्वीकृत पद्धति के अनुसार ही ऐसा कार्य किया जाना था। किसी भी मामले में रियायत सम्बन्धी कोई भी रियायत बरतने से पूर्व रियायत करने के नियम प्रस्तावित करने वाले विभाग एवं अन्य विभाग जैसे नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग इनमें से प्रत्येक मामले के विषय को ध्यान में रखते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रमंग से, जो भी संबंधित हो, उससे राय प्राप्त करनी चाहिये। इसके अलावा राजकीय सचिवालय के इस सम्बन्ध के वर्तमान कोई भी नियम का पुरा पालन किया जाना चाहिये।

किसी भी मामले में यदि इससे सम्बन्धित विभाग एक मत हो जायें कि यह एक उचित मामला है जिसमें कि नियम में रियायत बरतने की शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिये। इस प्रकार की रियायत किए जाने के कारणों को तबित पत्रावली (फाइल) पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की जाने वाली इसे औपचारिक भाषा के रूप में नहीं माना जाना चाहिये।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सरकार का कोई भी आदेश जो किसी विशिष्ट मामले में किसी नियम को समाप्त करने के लिए या उसमें रियायत बरतने के लिए जारी किया

जाता है, उसे गविवधान की धारा 238 व धारा 166 की आवश्यकतानुसार राज प्रभुत्व की धारा के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिये।

उक्त राज्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सम्बन्धित नियमों के एक नए समूह के प्रारम्भ में, जो सविषय में निम्नलिखित हैं, उनमें किसी विशेष मामले में नियमों के प्रावधानों में रियायत करने की शक्ति राज प्रभुत्व को दी हुई होनी चाहिये परन्तु यह है कि किसी भी मामले का निर्णय प्रावधानों के प्रतिष्ठित रूप में न किया जावेगा।

निर्णयः—यह निर्णय किया गया था कि उपरोक्त विज्ञप्ति केवल राजस्थान सेवा नियमों व अन्य नियमों के समूह जैसे धारा अक्षा नियम, वेतन मान एकीकरण नियम एव वेतन मान मधीकरण नियम (यूनीफिकेशन धारा) स्कैल रूल्स, रेशनलाइजेशन धारा व स्कैल रूल्स) आदि पर ही लागू होगी जो कि (ये नियम) भारतीय गविवधान की धारा 309 के अन्तर्गत वित्त विभाग में जारी किए गए थे, एवं यह विज्ञप्ति भारतीय गविवधान की धारा 309 के अन्तर्गत सरकार के निर्णय एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी किए गये विभिन्न सेवाओं पर की गई नियुक्ति, उन्नति आदि के नियमों पर लागू नहीं होगी।

नियम ४ क. सरकार अपनी स्वेच्छानुसार वेतन, कार्यवाहक भत्ता (Acting allowance) अवकाश व पेन्शन के नियमों में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। एक अधिकारी का वेतन व भत्ते का एक उच्च अंकित किए गए वेतन व भत्ते के समय प्रचलित नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जावेगा। अवकाश का वेतन उन नियमों द्वारा तय दिया जावेगा जो उस समय अवकाश के सम्बन्ध में लागू हों एवं अवकाश पेन्शन वेतन ऐसे नियमों द्वारा नियमित किया जावेगा जो अधिकारी के त्यागपत्र देने के समय या उसे सरकार की सेवा से हटाने के समय प्रचलित थे।

निर्णय—यह प्रश्न कि क्या किसी विनिष्ट कार्यलय या विभाग में की गई सेवा पेन्शन के योग्य है प्रत्यक्ष नहीं, उन्हीं नियमों द्वारा तय किया जाता है जो कि उस सेवा के करने के समय प्रभावी थे एवं बाद में तब सेवा की पेन्शन के योग्य माने जाने के आदेश निकले हैं, वे आदेश तब तक समय में की गई सेवा पर लागू नहीं होंगे।

पूर्व गविवधानान्तर्गत रियायतों (former covenanting states) के सम्बन्धीकरण जो राजस्थान सेवा में एकीकृत हो चुके हैं, उनके एकीकरण के पूर्व रियायती राज्य में स्थाई एवं/या अस्थायी रूप से की गई सेवाओं की राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थाई एवं/या अस्थायी सेवा माना जावेगा। सरकार के पृथक् आदेशों से राजस्थान सरकार द्वारा ठिकानों में तब गये कर्मचारियों के मामले नियमित होंगे।

स्पष्टीकरण—जहाँ पर कि किसी विनिष्ट रियायत के नियमों के समूह के अनुसार कोई सेवा वाल विशेष रूप से पेन्शन के अयोग्य समझा गया हो एवं यदि वही सरकार के किसी विनिष्ट आदेश द्वारा पेन्शन के योग्य घोषित हो गया हो तो वह सेवा इस प्रकार पेन्शन योग्य समझी जावेगी—

(1) कि जहाँ पर रियायत के नियमानुसार कोई एक पद पेन्शन के अयोग्य था एवं यदि वही अब राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के योग्य घोषित कर दिया गया हो, तो 1-4-51 के पूर्व की गई सेवा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पेन्शन के अयोग्य समझा जावेगा।

(2) कि वहाँ रियासत के नियमों के अनुसार कोई सेवा, पेन्शनयुक्त भी पर बाद में मत्स्य भ्रमवा पूर्व राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार पेन्शन के भ्रमवा कर दी गई तथा पुनः राजस्थान सेवा नियमों के तहत पेन्शन के योग्य हो गई तो दो पेन्शन योग्य सेवामों के बीच के सेवाकास की पेन्शन के योग्य गिना जाना चाहिये क्योंकि मध्यवर्ती सरकार (Intermediary-Government) की इच्छा कमी यह नहीं थी कि उन कर्मचारियों की उनके पेन्शन की सुविधा से वंचित कर दिया जावे ।

नियम 5—शक्ति प्रदान करने की शक्ति—सरकार किन्हीं ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह लगाना उचित समझे किसी भी अपने अधिकारी की इन नियमों के अन्तर्गत निम्न अपवादों (Exceptions) के साथ शक्तियाँ प्रदान कर सकती है :—

(क) नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।

(ख) अन्य शक्तियाँ भी नियम 5, 42, 56 (क), 81, 135, 140, 148, 151 एवं 157 (ग) द्वारा प्रदत्त की गई हैं ।

निर्णय—प्रती सरकार के प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों की उवाहनिंग टाइप बनाने, पद पर नियुक्त किये जाने तक इन्तजार करने के समय की छुट्टी के रूप में मानने, पुनर्नियुक्ति स्वीकृत करने, प्राप्ति सीमा के प्रतिबन्ध को मिटाने, प्रादि की एवं सेवा नियमों से सम्बन्धित इसी तरह के मामलों में, शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या उनको दी गई शक्ति का प्रयोग आदेश के जारी होने की तारीख से किया जाना है या विचाराधीन मामले भी उन्हीं शक्तियों के अनुसरण में लिये किये जा सकते हैं । प्रश्न की जाँच करती गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि इस प्रदत्त शक्ति का उपयोग शक्ति के हस्तान्तरण के पूर्व के मामलों में भी किया जा सकता है । केवल उन मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जावेगा जो पहिले ही उस अधिकारी द्वारा रद्द कर दिये गये हैं भ्रमवा उसे प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिसकी कि यह शक्ति पूर्व से ही प्राप्त थी ।

नियम 6—व्याख्या—इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राज प्रमुख को है ।

अध्याय २ परिभाषायें

नियम 7—जब तक कि विषय या प्रसंग में कुछ विपरीत दिया हुआ न हो इस अध्याय में नियमों में काम में लिए गये परिभाषित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से स्पष्ट किये गये अर्थों में होगा—

(1) प्राप्ति—जब कोई राज्य कर्मचारी को विशिष्ट प्राप्ति प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त (रिटायर), प्रत्यावर्तित (रिबर्ट) या अवकाश पर रहना बन्ध करना आवश्यक हो, तो जिस दिन वह उस विशिष्ट प्राप्ति को प्राप्त करता है, वह अकार्य दिवस (Non working day) गिना जाता है एवं राज्य कर्मचारी को उस दिन से सेवा-निवृत्त, प्रत्यावर्तित (रिबर्ट) या अवकाश पर रहने से बन्ध (जैसी भी स्थिति हो) हो जाना चाहिये ।

टिप्पणी-1. यदि किसी राज्य कर्मचारी की वास्तविक सही जन्म तिथि ज्ञात न हो तो सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के निम्न उद्धृत विद् गए अवतरण 63 में दी गई पद्धति को काम में लेना चाहिये—

(1) यदि कोई राज्य कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं बतला सके बल्कि केवल जन्म का साल या साल धीरे मात्र ही बतला सके तो उसकी जन्म तिथि क्रमशः उस वर्ष की 1 जुलाई या उस माह की 16 तारीख समझी जावेगी।

(2) अगर वह केवल अपनी अनुमानित आयु ही बतलावे तो उसकी जन्म तिथि उसकी नियुक्ति की तारीख से, उसका सेवाकाल अनुमानित आयु में से काटकर, निश्चित की जानी चाहिये।

ऐसे मामले, जिनमें जन्म तिथि नियुक्ति या अन्य प्रकार से अनुमानित आयु में से काटी गयी है, पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी-2. सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि एक अधिकारी ने एक पदचारी की जन्म तिथि को जो उसकी सविस्तर बुक में दर्ज हो, उसे सही न मानकर उसके पदचारी स्कूल सर्टिफिकेट में दी गई जन्म तिथि को सही जन्म तिथि माना। इसका सही तरीका यह है कि जहाँ तक जन्म तिथि का प्रश्न है, सविस्तर बुक में दर्ज की गई आयु ही मान्य होनी चाहिये। सविस्तर बुक में आयु का इन्तजाम न होने की दशा में, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली (परसनल फाइल) में दी गई उम्र को मान्य समझना चाहिये। यदि सविस्तर बुक या व्यक्तिगत पत्रावली न हो या उनमें उसकी आयु का प्रमाण न मिलता हो तो उसके स्कूल प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को प्रमाणित सही जन्म तिथि माना जाना चाहिये। अगर यह भी उपलब्ध न हो, तो नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को मान्य समझना जाना चाहिये। यदि प्राप्यवश नगरपालिका के रेकार्ड में भी इसका उल्लेख न मिले तो जन्म कुन्डली में दी गई जन्म तिथि पर विचार प्रकट करना चाहिये बल्कि वह कथित जन्म तिथि के बाद यौग्य ही तैयार की गई हो।

निर्णय—यह ध्यान में लाया गया है कि बहुत से मामलों में अधिकारीयों अपनी दर्ज की गई जन्म तिथि में परिवर्तन करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। मामले की जांच करती गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि आमतौर पर कोई भी अधिकारी अधिकारपत्र की आयु (Superannuation age) प्राप्त करने में 5 वर्ष से कम समय रह जाने पर, अपनी दर्ज की गई जन्म तिथि को बदला नहीं सकता। राजस्थान में मौजूदा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह धारा 1954-55 में उन अधिकारियों को दी गई थी जो सन् 1957-58 या उसके बाद सेवा निवृत्त होने की थे। इसी प्रकार सन् 1955-56 में भी उन अधिकारियों को अपनी जन्म तिथि परिवर्तित करने की धारा दी जा सकती है जो 58-59 में या उसके बाद रिटायर होने की हों।

(2) नव सिद्धांत (एपेरेन्टिस)—का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यापार या कारोबार में राजकीय सेवा प्राप्त करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो एवं जो ऐसे प्रशिक्षण काल में सरकार से मासिक वेतन प्राप्त करता हो परन्तु जो किसी विभाग के पद पर या उस पर (केडर में) स्पाई रूप से नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) संबिधान—का तात्पर्य भारत के संबिधान से है।

(4) संवर्ग (केटर)—का तात्पर्य किसी सेवा की या सेवा के एक अंग की मंजूरी से है जिसे अलग इकाई के रूप में रखा गया हो।

(4क) चतुर्थ श्रेणी सेवा—का तात्पर्य राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1950 की अनुसूची 4 (चतुर्थ श्रेणी सेवा) में वर्णित पदों की सेवा से है अथवा उससे है जिसका वेतन (यदि निर्दिष्ट किया हुआ हो) या अधिकतम वेतन (यदि वह अनिर्दिष्ट हो या वेतन मान पर हो) 55 रु. मासिक हो एवं जिसका उत्तरेख इन नियमों के परिशिष्ट 12 भाग 2 में वर्णन नहीं किया गया हो। (परिशिष्ट 12 भाग 1, चतुर्थ श्रेणी सेवा का है।)

(5) क्षतिपूर्ति भत्ता—(Compensatory Allowance)—वह भत्ता है जिसे राज्य कार्य में विदेश परिस्थितियों में व्यक्तिगत धन्य के रूप में खर्च किया जाता है। इसमें पाना भत्ता भी शामिल है। परन्तु इसमें न तो निम्पब्युरी भत्ता ही शामिल है और न भारत के बाहर समुद्र द्वारा जाने का एवं भारत में बाहर से समुद्र द्वारा आने का भत्ता ही शामिल है।

(6) सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)—किसी शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य राज्यपाल या अन्य ऐसे प्राधिकारी हैं है जिसे इन नियमों द्वारा या इनके अधीन, शक्ति प्रदान की जावे।

को प्राधिकारी विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनकी एक सूची इन नियमों के परिशिष्ट 9 में दी हुई है।

(7) संघित निधि (Consolidated Fund)—का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन स्थापित की गई धनराशि से है।

(7क) स्थापित (कम्पुटेड) अवकाश—का तात्पर्य नियम 93 के उपनियम (ग) के अधीन लिए गए अवकाश से है।

(8) सेवा (Duty)—(क) दायित्व में निम्नलिखित समय शामिल है—

(i) परिधीनाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) या नव विद्युता (एप्रेन्टिस) के रूप में की गई सेवा, बशर्ते कि उसके याद की, की गई सेवाएं स्थाई कर दी गई हों।

(ii) कार्यग्रहण काल (आइनिंग टाइम)

+ (iii) अवकाश से लौटने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिस पर से वह अवकाश पर रवाना हुआ था उसी पर का कार्यभार संभालने का दिन।

अववाद—जयपुर एवं जोधपुर के जिला कोषागारों का कार्यभार संभालने के मामले में इस सप्ताह के प्रयोजनार्थ अधिकतम 7 दिन तथा अन्य जिला कोषागारों के मामले में 3 दिन होंगे।

(ख) सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश जारी कर सकती है कि निम्न परिस्थितियों में या उनके समानाधिकार परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी की सेवा में लगा हुआ माना जाएगा—

(1) भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण का काल।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (50) वित्त वि. (नियम) 70 दिनांक 3-8-70 द्वारा निविष्ट।

+ राजस्थान सरकार का निर्णय - यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ ट्रेंनिंग इन्स्टीट्यूट, नागपुर एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किये जाते हैं उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ग) (1) के अधीन सेवा (ड्यूटी) पर समझा जाएगा तथा वह वेतन एवं भत्ता पाने के हकदार होंगे जिन्हें वे यदि प्रशिक्षण पर रहना न होतें तो प्राप्त करते ।

यह और आदेश दिया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने व समाप्त होने के स्थान से जाने की यात्राओं का यात्रा भत्ता केवल दोनों पर वो गई यात्रा की दर पर पाने के हकदार होंगे । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान वे राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के परिशिष्ट 2 में आदेश सं. 3 (वित्त विभाग के शासन सं. एक 7 (प) (25) वित्त वि./नियम/60 दि. 19-9-62 समय समय पर संशोधित अनुसार, में दी गई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार होंगे —

पाठ्यक्रमों के नाम

1. सिविल डिपेंडेंट इन्सट्रुक्टर्स के लिए बैसिक एसीमेन्ट्री कोर्स ।
2. वरिष्ठ अधिकांशियों के लिए वार्षिक सेमिनार
3. सिविल डिपेंडेंट स्टाफ कोर्स
4. सिविल डिपेंडेंट इन्सट्रुक्टर्स कोर्स
5. सिविल डिपेंडेंट केडी आफिसर्स कोर्स
6. इन्डस्ट्रियल सिविल डिपेंडेंट कोर्स

(2) यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करता हो या अन्यथा प्रकार से कुछ प्राप्त करता हो एवं जो भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने पर राजकीय सेवा में लिए जाने का अधिकारी है, तो उनके प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक समाप्त करने एवं सेवा में नियुक्त होने के समय के समय को, सेवा काल समझा जाना चाहिए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय नियम केन्द्र पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार कार्यभार नहीं संभालता है तथा बाद में किसी विशिष्ट पद के कार्यभार को संभालने का आदेश प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी पर प्रथम रिपोर्ट देने तथा अपने पद का कार्यभार संभालने के बीच का समय सेवा काल समझा जावेगा ।

टिप्पणी—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार संभाला कर या अवकाश से लौटने के बाद, उसे किसी पद पर लगाने के लिए सरकारी आदेश का इन्तजार करता है तो वह समय भी इसी के अन्तर्गत आता है ।

(4) यदि किसी राज्य कर्मचारी को किसी विभागीय परीक्षा में बैठना हो या उसे किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई हो तथा उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उस राज्य कर्मचारी के विभाग या कार्यालय के साधारण क्षेत्र में उसे राजकीय सेवा में महत्ता दी जाती हो, तो परीक्षा का समय तथा परीक्षा स्थल तक आगे जाने का उचित समय, सेवा में गिना जाएगा ।

(5) किसी ऐच्छिक परीक्षा में जिसमें बैठने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी हो तो उसका परीक्षा समय तथा परीक्षा स्थल तक आने जाने की यात्रा का उचित समय, सेवा में गिना जाएगा।

9. शुल्क (Fees)—का तात्पर्य राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान किया गया आवर्तक (Recurring) या अनावर्तक (non-recurring) वह व्यय है जो राज्य कर्मचारी को प्रायस्स रूप से या किसी सरकारों माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाये।

लेकिन शुल्क में निम्न शामिल नहीं होंगे;—

(क) अनुपाजित आय जैसे सम्पत्ति से प्राप्त आय (मकान किराया आदि), लाभार्जन एवं समानता पर दयाज से आमदनी, एवं

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयत्नों से प्राप्त आय, यदि ऐसे कार्यों में सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवाकाल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग न किया गया हो।

स्पष्टीकरण:—साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयत्नों में यदि सेवाकाल में प्राप्त किये गये ज्ञान की सहायता मिलती है तो उनमें पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी पड़ेगी तथा उससे प्राप्त होने वाली कोई भी आमदनी 'शुल्क' गिनी जावेगी लेकिन रिपोर्ट लिखना या अन्तर्राष्ट्रीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूनेस्को आदि जुने हुए विषयों पर अध्ययन करना, एवं भारतीय एवं विदेशी पत्रिकाओं में साहित्यिक योगदान देना आदि खण्ड (ख) में नहें गये अनुसार माने जायेंगे, यदि वह सेवा काल में उपलब्ध किये गये ज्ञान द्वारा सहायता प्राप्त किया हुआ न हो।

(9 क) प्रथम दस/बीस वर्ष की सेवा, 'अन्व दस वर्ष की सेवा' सेवा के पूर्ण वर्ष (Completed years of service) एवं एक साल की लगातार सेवा का तात्पर्य राजस्थान सरकार या एकीकृत किसी राज्य के अधीन उक्त निर्दिष्ट अवधि में लगातार सेवा से है तथा उसमें ड्यूटी पर विताये गये समय तथा असाधारण अवकाश सहित अवकाश का समय भी शामिल है।

निर्णय:—राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित 'सेवा के पूर्ण वर्ष' में असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर विताया गया समय भी शामिल है।

एक सन्देह व्यक्त किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी जो पहले से ही अवकाश पर है, अपने अवकाश के क्रम में (In continuation) अर्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) भी ले सकता है, यदि वह अर्ध वेतन अवकाश उसी अवकाश के बीच में अपनी सेवा का वर्ष पूरा करने के कारण, उपार्जित करता हो।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसा अर्ध वेतन अवकाश जो राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश काल में सेवा का पूरा वर्ष होने के कारण उपार्जित किया गया हो, उसे राज्य कर्मचारी अपने अवकाश के क्रम में ले सकता है या वह उसे अपने अवकाश को बुद्धि कराने के साथ में भी ले सकता है जिसमें कि उसके सेवा का पूरा वर्ष होने की तिथि आती है।

(10) विदेशी सेवा (Foreign Service) — का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें राज्य कर्मचारी अपना मूल वेतन सरकार की स्वीकृति से संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों (साधनों) से प्राप्त करता है।

(10 क)—एक राजपत्रित अधिकारी वह है जो या तो—(1) अखिल भारतीय सेवा (All India Service) का एक सदस्य हो, या (2) राजस्थान सिविल सर्विसेज (ब्रह्मोसफिसेज, कन्ट्रोल एवं अरील) नियम, 1950 की अनुसूचि 1 (राज्य सेवा) में बतलाए गये पदों में से किसी एक पर कार्य करता हो। या (3) शर्न या समझौते के आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति हो तथा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा राजपत्रित मान ली गई हो। या (4) ऐसे पद पर काम करने वाला राज्य कर्मचारी हो जो (पर) राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित कर दिया जाये। (परिशिष्ट 12 भाग 2, राज्य सेवा)।

(10 ख) "अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave)—रा तात्पर्य सेवा के पूर्ण वर्षों के कारण उपाश्रित किए हुए अवकाश से है। अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay leave due) का तात्पर्य उस अर्ध वेतन अवकाश की संख्या से है जो कि नियम 93 में निर्धारित किए गए अनुसार पूर्ण सेवा काल में से निजि कार्यों के लिए पूर्व चिन्हित प्रमाण पत्र (सेटिफिकेट प्रमाण-पत्र) पर या 1-4-51 से पूर्व अन्य किसी किस्म के अर्ध वेतन पर लिए गए अवकाश एवं अर्ध वेतन (औसतन अर्ध वेतन) अवकाश, जो 1-4-51 या उसके बाद लिया हो, को काट कर निकाला जाता है।

(11) बिभागाध्यक्ष का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इन नियमों के उद्देश्य के लिए बिभागाध्यक्ष घोषित कर दे।

(12) अवकाश (Holiday) का तात्पर्य (क) नेगोसिएबल इन्सट्रुमेंट्स एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अवकाश से है, एवं

(ख) किसी विदेशी कार्यालय के सम्बन्ध में उस दिन से है, जिसको कि ऐसा कार्यालय सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए राजपत्र में राज्य सरकार की विनयि द्वारा बन्द घोषित कर दिया जाता है।

(13) पारिश्रमिक (Honorarium) का तात्पर्य एक राज्य कर्मचारी की आवर्तक या अनावर्तक राशि के भुगतान से है जो कि राज्य की संचित निधि या भारत या अन्य राज्य की संचित निधि से किसी आकस्मिक कार्य के लिए अथवा अमानुष प्रकृति (इन्टरमिटेन्ड करेक्टर) के कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है।

टिप्पणियाँ.—(1) यदि कोई कार्य सम्बंधित राज्य कर्मचारी की वंश सेवाओं का अर्ध माना जाता हो तो उस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए।

(2) अवकाशस्वरूप समय एवं परिस्थितियों में कार्यालय के समय के बाद भी कार्य करना एक तरह से राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी है। इसके लिए साधारणतया कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लगातार कार्यालय समय के बाद भी काम करते रहने के कारण पारिश्रमिक या विशेष वेतन का कभी उचित ठहराया जा सकता है।

(14) ज्वाइनिंग टाइम—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी को दिए गए उस समय से है जो उसे अपने नए पद का कार्यभार सम्भालने के लिए या यात्रा करने के लिए अपना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, जहाँ पर कि वह लगाया गया है, स्वीकृत किया गया हो।

(15) अवकाश (Leave)—में उपाजित अवकाश (Privilege leave) अथं वेतन अवकाश, स्थापनाित (कम्प्यूटेड) अवकाश, विशेष अयोग्यता अवकाश, मध्ययन अवकाश, प्रसूति अवकाश एवं अस्पताल अवकाश, अवकाशा अवकाश (Leave not due), एवं असाधारण अवकाश शामिल है।

(16) अवकाश वेतन (Leave Salary) का तात्पर्य राज्य कर्मचारी की अवकाश पर ही जाने वाली मासिक धनराशि से है।

(17) लीयन (पूर्वाधिकार)—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी द्वारा एक स्याई पद पर स्याई रूप से काम करने के हक से है जिसे वह अवधि ध्यतीत होने पर या अनुपस्थिति की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त करता है। इसमें टेन्डोर (समराधधि) पद भी शामिल है जिस पर कि वह स्याई रूप से नियुक्त किया जा चुका है।

(18) स्थानीय निधि (Local Fund) का तात्पर्य—

(क) निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व से है जो कानून या कानून की शक्ति रखने वाले नियम द्वारा सरकार के नियन्त्रण में जाता है। चाहे वे (राजस्व) किसी साधारण या विशेष मामले में कार्यवाही करने के मध्यम में हो बर्न न हों जैसे कि उनका खजान स्वीकार करना, विशिष्ट पक्षों का सुजन करने अथवा उन्हें भरने की स्वीकृति देने या अवकाश, पेन्शन आदि के समान नियम बनाना, और

(ख) किसी भी संस्था के राजस्व से है जो विशेष रूप से राजप्रमुख द्वारा उस संस्था की, घोषित कर दी गई हो।

(19) लिपिक वर्ग कर्मचारी (Ministerial Servant)—का तात्पर्य किसी अधीनस्थ सेवा में राज्य कर्मचारी से है जिनका कि मुख्य कार्य लेखन सम्बन्धी हो है। एवं ऐसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों से है जो सरकार के सामान्य एवं विशेष आदेशों द्वारा विशेष रूप से इस श्रेणी में घोषित कर दिए गए हों।

(20) माह (Month)—का तात्पर्य एक कलेंडर माह से है। इसमें माह एवं दिनों की संख्या गिनने में, हर माह के दिनों की संख्या का ध्यान न रखते हुए, पहले पूरे माह गिन लेने चाहिए तथा, इसके बाद दिनों की संख्या गिनी जानी चाहिए।

टिप्पणी—25 जनवरी से 3 माह 20 दिन की अवधि गिनते समय 3 माह 24 मर्चल को समाप्त हुए समझना चाहिए एवं 20 दिन तारीख 14 मर्च को समाप्त हुए समझने चाहिए। इसी प्रकार 30 जनवरी से 2 माह तक का समय 1 माह और 2 दिन गिना जाना चाहिए क्योंकि 30 जनवरी से 1 माह 28 फरवरी को समाप्त हो जाता है। 1 जनवरी से 1 माह 29 दिन का समय एक साधारण वर्ष (जब कि फरवरी 28 दिनों की हो) में फरवरी की आखिरी तारीख को समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि 29 दिनों का समय एक पूर्ण कलेंडर माह से ज्यादा का नहीं

हो सकता एवं 1 जनवरी से लिया गया दो माह का अवकाश फरवरी के अंतिम दिन समाप्त हो जाएगा। यही दो माह को अवधि उस समय भी गिनी जाएगी जब कि फरवरी 29 दिन की हो या अवकाश की अवधि 1 माह 28 दिन की हो (माघारण वर्ष में)।

(21)—विलोपित किया गया

(22) स्थाई सेवा के कर्मचारी—(Official in Permanent employ)—का तात्पर्य ऐसे राज्य कर्मचारी से है जो किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता हो या जो किसी स्थाई पद पर अपना पूर्वाधिकार (लीयन) रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित न किया गया होना तो वह स्थाई पद पर अपना लीयन रखता।

(23) स्थानापन्न (Officiate)—एक राज्य कर्मचारी किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य उस समय करता है जब वह एक ऐसे पद का कार्य करता है जिस पर कि अन्य कर्मचारी का लीयन हो। यदि सरकार उचित समझे तो किसी राज्य कर्मचारी को ऐसे रिक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकती है जिस पर कि किसी अन्य कर्मचारी का लीयन न हो।

(24) वेतन-का तात्पर्य राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक वेतन से है जन्मे:-

(1) वेतन, स्पेशल पे के अलावा या वह वेतन जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर स्वीकृत हुआ है एवं जो कि उसके द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या स्थानापन्न रूप में धारण किए गए पद के लिए स्वीकृत किया गया है या तथा जिस पद के लिए वह अपनी स्थिति के कारण अधिकारी है; एवं

(2) स्पेशल पे (विशेष वेतन) एवं व्यक्तिगत वेतन (परसनल पे), एवं

(3) अन्य राशि जो राजप्रमुख द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हो।

टिप्पणियाँ—(1) राजकीय मुद्रणालय में फुटकर कार्य करने वालों के सम्बन्ध में जब वह किसी समय वेतन मान (टाइम स्केल पे) पर किसी पद पर नियुक्त किया जावे तो उनका वेतन 200 घंटे काम करने के वेतन के बराबर समझा जावे।

(2) पुलिस सिपाही एवं अन्य स्टाफ को जो साक्षरता भत्ता (Literacy allowance) स्वीकार किया जाता है वह वेतन में गिना जावेगा।

+ (3) राजस्थान सिविल सेवा (रिवाइज्ड पे) नियम 1961 की अनुसूची 5 (वित्त विभाग की अधिमूचना स. एक 2 (ख) (18) वित्त विभाग (नियम) 65 I दि. 28-7-66 द्वारा निविष्ट) के अधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राद्वित प्रेक्टिस बन्दी भत्ता (नॉन प्रेक्टिसिंग एलाउंस) या नान-क्लिनीकल भत्ता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वेतन गिना जाएगा—

(1) पेंशन एवं उपदान

(2) अवकाश वेतन

• (3) विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति, यदि विदेशी सेवा / प्रतिनियुक्ति में पद पर प्राक्टेड प्रेक्टिस की कोई गुंजाइश न हो।

(4) नियम 7 (8) (ख) के अधीन प्रशिक्षण

(5) राजस्थान सिविल सेवा (घावासीय सुविधा के किराए का निश्चयन एवं वसूली) नियम 1958 के नियम 35 में यथा पारिभाषित परिलब्धियां ।

(6) राजस्थान सेवा नियम भाग II के परिशिष्ट 17 में प्रन्तविष्ट मकान किराया भत्ता नियम ।

(7) मंहेगाई भत्ता (8) यात्रा एवं दैनिक भत्ता + (9) कार्य ग्रहण काल

§ (4) विक्रित्ता अधिकारी जिसे समय समय पर प्रेक्टिस बन्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है, किसी भी रूप में कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करेगा । वह उस वेतन जिस में निम्न रूप में एक प्रमाण पत्र प्रामितिलिखित करेगा जिसमें कि प्रेक्टिस बन्दी भत्ते का कन्नेम किया गया है—

"यह प्रमाणित किया जाता है कि उस अवधि में, जिसके लिए इस बिल में प्रेक्टिस बन्दी भत्ते का कन्नेम किया गया है, कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं की गई है ।"

(25) पेन्शन—लिखावट इसके कि जब पेन्शन शब्द का प्रयोग "ग्रेजुटी" एवं/या "डेय-कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी" के विपरीत रूप में किया जावे, पेन्शन में "ग्रेजुटी" एवं या डेय-कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी" (मृत्यु व सेवा निवृत्त उपदान) दोनों शामिल हैं ।

(26) स्थाई पद (Permanent Post)—का तात्पर्य बिना समायावधि के स्वीकृत वेतन को निश्चित दर वाले पद से है ।

27) निजि वेतन (Personal Pay)—का तात्पर्य राजकीय कर्मचारी को स्वीकृत किए गए अतिरिक्त वेतन से है । इसकी स्वीकृति दो कारणों से दी जाती है:—

(क) जब कोई राज्य कर्मचारी टेम्पोर (सावधिक) पदों के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर कार्य करता है परन्तु वेतन में संशोधन (Revision) करने के कारण या अनुशासनारमक कदमों के रूप में उठाए गए कदमों के अतिरिक्त अग्यथा रूप से ऐसे मूल वेतन (मस्टान्टिब पे) में कटौती करने के कारण यदि उसे कोई हानि होती हो तो उसे पूरा करने के लिए निजि वेतन (परसनल पे) स्वीकृत किया जाता है; या

(ख) अन्य वैयक्तिक कारणों को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है ।

(28) उपाजित अवकाश (Privilege Leave)—का तात्पर्य सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर उपाजित अवकाश से है ।

बकाया उपाजित अवकाश (Privilege leave due) का तात्पर्य नियम 91, 92 या 94 द्वारा विनियमित अवकाश के दिनों की संख्या से है । अवकाश की संख्या निकालते समय सेवा में बितने समय का अवकाश भोगा जाता है उतना समय काट दिया जाता है ।

+ वित्त विभाग की अधिनियमन सं. एक 2 (ख) (18) वित्त वि० (व्यय नियम) 65 दिनांक 6-8-70 द्वारा निविष्ट ।

§ वित्त विभाग की अधिनियमन सं. एक 1 (47) वित्त विभाग (नियम) 68 दिनांक 16-9-68 द्वारा निविष्ट ।

(29) पद का सम्भावित वेतन (Presumptive pay of a post)—जब इसका प्रयोग किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए किया जाता है तो इसका तात्पर्य उस वेतन से है जिसे यदि वह उस पद को स्थाई रूप से धारण करता तो पाने का अधिकारी रहता एवं अपना कार्य करता रहता परन्तु इसमें विशेष वेतन उस समय तक शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य कर्मचारी कार्य या कर्तव्य नहीं करता या वो जिम्मेदारो नहीं लेता, या ऐसी अवस्था परिस्थिति में नहीं पड़ा हो, जिसको कि ध्यान में रखकर विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था ।

(30) परीक्षाधीन व्यक्ति (Probationer)—का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी सेवा के संवर्ग (केडर) में या स्थाई रूप से रिक्त पद पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है ।

टिप्पणियाँ—1) यह परिभाषा, फिर भी, उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जो एक संवर्ग (केडर) में स्थाई पद पर स्थाई रूप से कार्य करता है एवं सिर्फ दूसरे पद पर परीक्षा के तौर पर (on probation) नियुक्त किया जाता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी एक केडर में स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है, वह परीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) नहीं है जब तक कि उसको नियुक्ति के साथ परीक्षा (प्रोबेशन) की निश्चित शर्तें सलान नहीं कर दी गई हों जैसे यह शर्त कि प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय तक वह प्रोबेशन (परीक्षा) पर सम्मत्ता जायेगा ।

(3) जब तक किसी मामले में नियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, एक प्रोबेशनर (परीक्षाधीन व्यक्ति) का स्तर (status) उसी प्रकार से समझा जाता है जैसे कि मानों स्तर के व्यक्ति के सब अधिकार रहता है ।

जांच निर्देशन—उपरोक्त टिप्पणी संख्या (1) व (2) में दिए गए निर्देशनों को एक दूसरे को पूरक के रूप में समझी जानी हैं न कि इन्हें एक दूसरे के भिन्न समझी जानी चाहिए । दोनों को मिलाकर इन टिप्पणियों में यह जांच करने की बात है कि किस समय एक राज्य कर्मचारी, इस जांच का ध्यान रखे बिना ही कि वह पहिले से ही स्थाई राज्य कर्मचारी है या बिना किसी स्थाई पद पर धनरा लीयन रखे ही राज्य कर्मचारी है, 'प्रोबेशनर' के रूप में है या सिर्फ 'प्रोबेशन पर' है । जब कि एक प्रोबेशनर व्यक्ति वह होता है जो प्रोबेशन की निश्चित शर्तों के साथ स्थाई रूप से रिक्त किसी पद पर या उस पद के विनरोध नियुक्त किया गया हो तथा प्रोबेशन पर व्यक्ति वह होता है जो किसी पद पर (यह आवश्यक नहीं कि वह पद मूल रूप से रिक्त हो) प्रविष्ट में नियुक्त किये जाने की निश्चितता करने के लिए नियुक्त किया जाता हो । इन जांच निर्देशनों में किसी एक राज्य कर्मचारी को किसी एक केडर में स्थाई रूप से 'प्रोबेशनर' के रूप में किसी एक पद पर या उसके विपरीत नियुक्त करने से नहीं रोका जा सकता है जब कि कुछ निश्चित शर्तें जैसे कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना यदि उसके साथ निर्धारित की गई हो । इस प्रकार के मामलों में राज्य कर्मचारी को 'प्रोबेशनर' के रूप में समझा जाना चाहिए एवं जब तक इस विषय में कोई विशेष, विपरीत नियम न हों केवल उसे आरम्भिक एवं बाद के वेतन उठी वेतन दर से स्वीकृत किये जाने चाहिए जो कि परीक्षण काल की प्रवृत्ति के लिए निर्धारित की जाये । इसमें यह ध्यान न रखा जाना चाहिए कि क्या उन दरों की वस्तुतः सम्बन्धित सेवाओं के समय क्रम में शामिल किया हुआ या प्रत्येक किया हुआ बतलाया गया है या नहीं । एक ही विभाग के कर्म-

चारियों का सलेक्शन द्वारा प्रमोशन होने का मामला कुछ भिन्न है। (उदाहरणार्थ एक भारतीय जांच विभाग का एस. ए. एस. (केन्द्रीय सेवा, श्रेणी III) सुपरिन्टेन्डेंटों या ए. ए. भी. जो कि इस प्रकार की पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्दिष्ट संख्या के भीतर सलेक्शन द्वारा भारतीय जांच एवं लेखा सेवा में पदोन्नति किया जाय) यदि भारतीय सरकार के सम्बन्धित विभाग इसे उचित समझे तो इन 'पदोन्नत व्यक्तियों' को 'प्रोवेंशन पर' किसी एक समय के लिये यह देखने हेतु रखा जा सकता है कि क्या वे वास्तव में प्रथम श्रेणी अधिकारी का कार्य प्रबन्धी तरह कर सकते हैं और उनके लिये (पूर्वाधिकार) उनके पुराने पदों पर रखे जावें। इसी बीच में शायद उनके पुनरावर्तन की सम्भावना हो। चाहे प्रोवेंशन के समय में उनकी योग्यता आदि की परीक्षा करने का कुछ भी प्रबन्ध हो पर उनका आरम्भिक वेतन उस समय प्रभावी वेतन किन्तसेन सम्बन्धी सामान्य नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए।

+ (31) विशेष वेतन (Special pay) से तात्पर्य निम्न बातों को दृष्टि में रखते हुए किसी पद या किसी कर्मचारी की परिस्थितियों में उसके वेतन के स्वरूप की अतिरिक्त वृद्धि से है।

(क) विशेष रूप से कठिन प्रकृति का कार्य करने के लिए,
या

(ख) कार्य या उत्तरदायित्व के विशेष रूप से बढ़ जाने पर,

टिप्पणी—कोई राज्य कर्मचारी जो किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया हो उनका संविदा में यह प्रावधान है कि 'उसे वे सारे कार्य करने होंगे जिनको कि उसे करने के लिए कहा जाय।' परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उससे यदि दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कहा जायेगा तो उसे उसका पारिश्रमिक न दिया जायेगा।

"टिप्पणी—किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी की संविदा में यह प्रावधान है कि उसे वे समस्त कार्य भी करने चाहिये जिन्हें उससे कराने के लिए कहा जाए, इस बात पर जोर नहीं देना है कि उससे अन्य पद के अतिरिक्त मार स्वरूप कार्यों को बिना पारिश्रमिक के करने हेतु कहा जाए।"

[32] उच्च सेवा (Superior Service):—का तात्पर्य चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार की सेवा से है। (परिशिष्ट 12 भाग 2)

[33] निर्बाह अनुदान [सबसिस्टेंस ग्रांट] का तात्पर्य उस राज्य कर्मचारी की दो पंद्रह मासिक सहायता से है जिसे वेतन या अवकाश वेतन कुछ भी नहीं दिया जा रहा हो।

[34] मूल वेतन (Substantive pay):—का तात्पर्य नियम 7 (24) (3) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उस वेतन से है जो विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य वेतन के अतिरिक्त है और जो उनी स्थायी पद पर नियुक्त होने के कारण या उसकी किसी संवेग (केडर) से स्थायी स्थिति होने के कारण, पाने का अधिकारी है।

टिप्पणियाँ—(1) जब कोई राज्यकीय मुद्रणालय का फुटकर काम करने वाला व्यक्ति समय श्रद्धालु वाले किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है तो प्राया मूल वेतन उसके प्रति घण्टे की दर के हिसाब से 200 घण्टे के कार्य के बराबर होगा।

(2) मूल वेतन में प्रोवेंशनर द्वारा किसी ऐसे पद पर प्राप्त किया गया वेतन भी शामिल है, जिस पर कि वह प्रोवेंशन पर नियुक्त किया गया है।

+ वित्त वि. की अधिसूचना सं. एफ 1 (64) वित्त वि. (नियम) 68 दि. 22-2-69 द। निर्दिष्ट

(3) यदि कोई राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन किसी स्थाई पद पर घपना सीपन रखता है तो उसके सम्बन्ध में 'मून वेतन का तात्पर्य' उस 'मून वेतन' से है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के सम्बन्धित नियमों द्वारा परिभाषित किया जावे ।

÷[34 क.] 'स्थायी नियुक्ति' हो तात्पर्य सरकारी कर्मचारी की उस स्थायी पद पर नियुक्ति है जिस पर वह सीपन प्राप्त करता है ।

[35] अस्थाई पद (Temporary post):—का तात्पर्य एक ऐसे पद से है जिसका वेतन निश्चित दरों से किसी समय की अवधि तक निश्चित है ।

टिप्पणी सं० (1) व (2) विलोपित की गई ।

टिप्पणी(3) एक अस्थाई पद की अवधि की, उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वीकृत प्रवर्तन की अवधि तक बढ़ाना उची सनय प्रावश्यक है जबकि उच्च प्रवर्तन की स्वीकृति प्रदान करने से सरकार को कोई व्यय न करना पड़ता हो लेकिन इस प्रकार की अवधि बढ़ाने की अनु-वस्थिति में वह अनुचित दिखाई देता हो ।

[36] सावधिक पद (Tenure post):—का तात्पर्य एक स्थाई पद से है जिससे एक स्वयं राज्य कर्मचारी एक सीमित अवधि से ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी—सन्देह होने पर सरकार ही तय करेगी कि एक धर्मक पद सावधिक पद है या नहीं ।

37. समय वेतन मान (Time scale वे):—का तात्पर्य उस वेतन से है जो इन नियमों में दी गई दरों के आधार पर, समय के अवधि के अनुसार वृद्धि के साथ साथ ग्यूनतम से अधिकतम तक पहुँच जाता है ।

टाइम स्केल अनुक्रम (आइडेण्टिकल) उसी समय बही जानी है जब टाइम स्केल की निम्नतम, अधिकतम, वेतन वृद्धि का समय, व वृद्धि की दर व समय समान हों ।

एक पद की दूसरे पद के समय वेतन मान के समान उसी समय कहा जाता है जबकि दोनों पदों का टाइम स्केल समान हो तथा दोनों पद एक केडर में आने हों या किसी केडर में एक क्लास में आते हों । ऐसे केडर या क्लास इन दृष्टि से सूचित किये गये हों कि उची प्रवृत्ति या समान उत्तरदायित्व के कार्य के लिये किसी सेवा में या स्थापन में या स्थापन वर्ग में पदों की भरती के लिए उर्ह नियुक्त किया जा सके ताकि किसी भी पद की धारण करगे वाले व्यक्ति का वेतन उसके केडर या क्लास में होने के कारण तय किया जा सके, न कि इस तथ्य से कि वह उस पद की धारण करता है ।

(38) स्थानान्तरण (Transfer):—का तात्पर्य किसी राज्य कर्मचारी का जहाँ पर वह नियुक्त है, उस स्थान से दूसरे ऐसे स्टेशन पर निम्न कारणों से जाना—

(क) नये पद का कार्य भार संभालने के लिए, या

(ख) उसके मुरदात्म के परिवर्तन के फलस्वरूप ।

(39) विधामकालीन विभाग (Vacation Department):—वह विभाग है या विभाग का हिस्सा है जिनमें कि नियमित रूप से छुट्टियाँ दी जाती हैं । उन छुट्टियों के बीच में राजस्वीय कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की इजाजत होती है ।

÷ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (14) वित्त वि (अय-नियम 66 दिनांक 18-5-66 द्वारा निविष्ट

+ अपवाद—विलोपित

÷ (40) पेंशन न देने योग्य स्थापना (नान पेंशनेबिल एस्टाब्लिशमेंट) का तात्पर्य ऐसी स्थापना से है जिनका कि वेतन (सेलेरी)—आय व्ययक (बजट), में 'अधिकारियों के वेतन' एवं 'स्थापना के वेतन' के प्रावधानों में से नहीं चुकाया जाता है, बल्कि अन्य तरीके से चुकाया जाता है।

भाग २

अध्याय ३ सेवा की सामान्य शर्तें

नियम ८—प्रथम नियुक्ति के समय आयु (Age on first appointment)—जब तक कि सो पद पर या पदों की श्रेणी पर नियुक्ति करने सम्बन्धी सरकार के नियमों या आदेशों में अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हुआ हो, सरकारी सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम व अधिकतम उम्र क्रमशः 16 साल एवं 28 साल होगी।

अपवाद-1 मल्प बयस्क (Minors), या वे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की हो, उन्हें ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जिसके लिए कि जमानत की जरूरत होती हो।

अपवाद 2—किसी विशेष पद/या पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी नियमों में जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ न दिया हो, महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश पाने की अधिकतम आयु 35 साल होगी।

नियम सं० 1—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आयु की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है।

नियम संख्या 2—जामीनदारों के मामले में (इसमें वे जामीनदारों के पुत्र भी शामिल हैं जिनके पास अपने जीवन निर्वाह हेतु कुछ भी जमीन नहीं है) जो कि जामीनों के पुनर्ग्रहण के बाद राजकीय सेवा में से लिए गए हैं तथा अन्य सब बातों में योग्य पाये गए हैं तो उनकी आयु 40 वर्ष तक की जा सकती है। यह रियायत केवल 5 वर्ष तक ही काम में आयेगी। इस रियायत को 31-12-63 तक बढ़ाया जाएगा।

नियम संख्या 3—अधिक उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति के अवसरों को कम करने के शक्तिशाली से यह निर्णय किया गया है कि सभी नई नियुक्ति के आदेशों में उनको जन्म तिथि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये।

नियम संख्या 4—यह आदेश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न पदों पर भारतीय पुलिस सेवाओं के सुरक्षितता प्राप्त (रिजर्विस्ट) व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (62) वित्त वि (भार) 68 दिनांक 17-12-68

द्वारा निविष्ट तथा इसी क्रम सं० अन्य आदेश दिनांक 18-3-69 द्वारा विलापित किया गया।

+ वित्त विभाग आदेश संख्या एक 1 (14) एक. जी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21-3-67 द्वारा शामिल किया गया।

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (62) वित्त वि/ (नियम) 69 दिनांक 15-10-69 द्वारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

× नियम सं० 5—राज्य कर्मचारियों के नामों में परिवर्तन करने के लिए कोई समान तरीका नहीं है। मामले की जांच करती गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो नया नाम रखना चाहता है या अपने वर्तमान नाम में कोई संशोधन करना चाहता है, उसे अपने नाम में परिवर्तन का एक बन्ध पत्र (डोड) भर कर औपचारिक रूप से परिवर्तन करना चाहिए। दस्तावेज के निष्पादन में कोई संदेह न रहने के लिए, यह बांझनीय है कि वह दो साक्षियों द्वारा, विशेष तौर पर उन लोगों द्वारा जो उस कार्यालयध्यक्ष को ज्ञात हों जिसमें कि राज्य कर्मचारी सेवा कर रहा है, अनुमोदित होना चाहिए। बन्ध पत्र के प्रथम (डीड फार्म) का एक नमूना संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है। बन्ध पत्र (डोड) का निष्पादन परिवर्तन का प्रकाशन किसी प्रसिद्ध स्थानीय समाचार-पत्र तथा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कर दिया जाएगा। दोनों मामलों में राज्य कर्मचारी द्वारा प्रकाशन अपने स्वयं के खर्च पर कराया जाएगा। राजस्थान राजपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए राज्य कर्मचारी को अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के पाम पहुँचने का निदेश देना चाहिए।

पूर्वोक्त अवसरों में वर्णित औपचारिकताओं की अनुपालना होने के बाद तथा राज्य कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई पहिचान की समीक्षाजनक साक्ष्य एवं दस्तावेजों का निष्पादन हो जाने के बाद ही, नया न म रखने या वर्तमान नाम में परिवर्तन करने की सरकारी रूप से स्वीकृत किया जाएगा तथा सरकारी अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सम्बन्धित दस्तावेजों की सही प्रतिनिधियाँ राज्य कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखी जाएंगी तथा तदनुसार महालेखाकार को सूचित कर दिया जाएगा।

नाम/उपनाम (सरनेम) परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र

इस बन्ध-पत्र (डोड) द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता क स ग (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व क ग (पुराना नाम) कहलाता था, एवं जो (सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए पद का नाम) के रूप में स्थान (स्थान जहाँ राजस्थान सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, ऐतद्द्वारा—

(1) स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया भागित हों, मेरे पूर्व नाम क स, उपनाम ग (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उनके स्थान पर उम्मी तारीख से नाम क स ग, तथा उपनाम स ग ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे ऐतद्पश्चात् मेरे पूर्व उप नाम ग (केवल) से न जाने जाएँ तथा पहिचाने जाएँ बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किए गए उपनाम स ग द्वारा जाने जाएँ।

(2) उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं ऐतद्पश्चात् सभी समय, प्राईवेट या सार्वजनिक, सभी अभिलेखों, बन्ध पत्रों (डोड), लेखों एवं समस्त कार्य-वाहियों में, व्यवहारों (विलियम) एवं लेनदेनों (ट्रान्जेक्शन्स) में तथा सभी अवसरों पर, अपने पूर्व नाम क ग तथा उपनाम ग (सिर्फ) के स्थान पर एवं उनके परिवर्तन मे क स ग नाम के रूप में तथा स ग उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूँगा एवं हस्ताक्षर करूँगा।

(3) स्पष्टतः ऐतद्पश्चात् सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर

× वित्त विभाग के आदेश संख्या 1 (12) एक डी (अवय-नियम) 67 दिनांक 10 अप्रैल 1967 द्वारा शामिल किया गया)

के बच्चे को तदनुसार नए रखे गए नाम क स ग, उपनाम स ग के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता है तथा उसके लिए निवेदन करता है।

इसकी साक्षी में मैंने अपने पूर्व नाम ए नए नाम क स, तथा क स ग का वर्णन किया है तथा दिनांक वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए ।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम द्वारा जो पूर्व में } क स
क स ग क स कहलाता था, हस्ताक्षर किए एवं भेजा गया । } क स ग

1.....

2.....

—निर्णय सं. 6—महालेखाकार, राजस्थान ने सरकार के यह ध्यान में लाया है कि प्रायः दिनांक 7-4-49 से 5-5-61 को भववि के बीच अधिकार्यु (मोवरएज) पर नियुक्तियों को विनियमित करने की कार्यवाही की कमी के कारण, पेशान के मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में पर्याप्त देर लग जाती है।

2—मामले पर विचार कर लिया है तथा राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि चूंकि नियुक्तिर्त्ता प्राधिकारीगण, नियमों/आदेशों से परिचित नहीं थे एवं राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सेवाओं के विलीनीकरण की प्रक्रिया में, नियमों की अज्ञानता के कारण, उनके द्वारा अधिकार्यु (मोवरएज) पर नियुक्तियों को गई थी, अतः 7-4-49 से 31-3-53 तक, जिस तक कि विलीनीकरण का बहुत सा काम हो चुका था, की भविष्य के भीतर अधिकार्यु पर की गयी नियुक्तियों को इस आदेश के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई हुई समझी जायेगी।

3—31-3-53 के बाद से 5-5-61 तक अधिकार्यु पर की गयी सभी नियुक्तियों के मामलों को, राज्य-कर्मचारी की सेवा नियुक्ति तक की प्राप्ति प्राप्त करने तक की इन्तजार किए बिना ही सक्षम अधिकारियों द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए। तथा समस्त ऐसे मामलों को सरकार के पास प्रशासनिक विभाग में विनियमित कराने हेतु नियुक्तिर्त्ता की उमे अधिकार्यु पर नियुक्ति के स्पेन्डीकरण के साथ भेजे जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ प्रशासनिक विभाग सबसे सन्तुष्ट है कि अधिकार्यु वाले व्यक्ति की नियुक्ति न्यायोचित थी तो वे उक्त नियुक्ति को विनियमित करने की स्वीकृति जारी करने के लिए वित्त विभाग को सहमति प्राप्त करेंगे।

+ निर्णय सं. 7.—“वित्त विभाग में समय समय पर विघटित जिला बोर्डों के कर्मचारियों के मामले प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें उनकी अधिक आयु (Over-age) में की गई नियुक्ति को नियमित करने हेतु वित्त विभाग को स्वीकृति मांगी जाती है। चूंकि अधिक आयु में नियुक्ति भविष्य में जिला बोर्डों द्वारा की गई थी और वे विघटित हो चुके हैं, अतः ऐसे अधिक आयु की नियुक्तियों के कारण मात्सुम करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस मामले पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिया जाता है कि ऐसे समस्त मामलों को जिनमें कि जिला बोर्डों के कर्मचारियों की अधिक आयु ने नियुक्ति हुई और जिन्हें जिला बोर्डों के विघटित हो जाने के कारण राज्य सेवा में ले लिया गया उनकी नियुक्ति नियमित मानो जावे।”

— वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (78) एक वी (अध-नियम) 62-1 दिनांक 29-4-67 द्वारा लागू किया गया।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (13) वित्त विभाग नियम/68 दिनांक 21-5-1968 द्वारा निष्पत्ति।

+ निर्णय सं. 8—“प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में अंकित सीमा से अधिक के व्यक्तियों/महिलाओं की नियुक्ति करली जाती है और इसके पश्चात् ऐसी अनियमित नियुक्तियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार को लिखा जाता है।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में नये नियुक्त कर्मचारी के प्रथम वेतन के बिल के साथ नियुक्ति आज्ञा-पत्र को कोषाधिकारी देखेंगे व यह ध्यान में रखेंगे कि उक्त नियुक्ति आज्ञा-पत्र में कर्मचारी की जन्म तिथि अंकित है। यदि जन्म तिथि के अनुसार उक्त कर्मचारी की नियुक्ति अनियमित है व सेवा में रहने योग्य आयु से बाहर है, तो उसका वेतन पारित नहीं किया जावेगा। ऐसे कर्मचारी राज्य सेवा में नहीं रह सकेंगे तथा उनका बड़ा हुआ बेटन का भुगतान नियुक्ति अधिकारी स्वयं अपने द्वारा करेंगे। यह निर्देश उन कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा या सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत अधिक आयु में की गई हो।

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति-कर्त्ता अधिकारियों को कृपया सूचित करें कि निर्धारित आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति भविष्य में नहीं की जाने। यदि निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत की गई है तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नियुक्त आज्ञा-पत्र में किया जावेगा, ताकि जिसा कोषाधिकारी को वेतन बिल पारित करने या न करने में कठिनाई नहीं हो।”

✽ निर्णय सं. 9—राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा में रहते हुए मेट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करते हैं जिसके प्रमाण-पत्र के जन्म तिथि अंकित होती है और वे परीक्षा पास करने के पश्चात् उस प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि, जो प्रथम नियुक्ति के समय अंकित की गई थी बदलवाने का प्रयत्न करते हैं।

इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सेवा में रहते हुए मेट्रिक या अन्य समकक्ष परीक्षा पास करें जिसके प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि अंकित होती है, उनकी सेवा पुस्तिका में पूर्व अंकित जन्म तिथि उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं बदली जावे।”

△ निर्णय सं. 10—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, राजकीय सेवा में प्राविष्ट होने की न्यूनतम व अधिकतम आयु 16 व 25 वर्ष है। सरकारी कर्मचारियों की कम आयु में की गई नियुक्तियों को निमित्त करने के मामले सरकार के ध्यान में लाये गए हैं। ये नियुक्तियां प्रसंविदान्तर्गत राज्यों को सरकारों/राजस्थान पुनर्गठन के पूर्व के राज्यों द्वारा की गई थी।

मामले की जांच करली गई है तथा राज्यपाल ने आदेश दिया है कि प्रसंविदान्तर्गत राज्यों

+ (वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (16) वित्त विभाग (नियम)/68 दिनांक 16-7-68) द्वारा निविष्ट।

✽ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक 1 (16) वित्त विभाग (नियम)/68 दिनांक 21-9-68 द्वारा निविष्ट।

△ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक 1 (15) वित्त वि (नियम)/69 दि. 17-4-69 द्वारा निविष्ट।

की सरकारों/राजस्थान के पुनर्गठन के पूर्व के राज्यों द्वारा कम आयु में की गई नियुक्तियों के मामलों में इस आदेश के अधीन सरकार की स्वीकृति दी हुई मानना चाहिये ।

+ **नियम 9.** नियुक्तियों के लिए डाक्टरों प्रमाण पत्र (Medical certificate) प्रस्तुत करना— सिवाय इस नियम में दिए गए प्रावधानों के, किसी भी राज्य कर्मचारी को राज्य सेवा में उसके स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना नियुक्त नहीं किया जा सकता है । व्यक्तिगत मामलों में, सरकार प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत को समाप्त कर सकती है या वह राज्य कर्मचारियों की किसी विशिष्ट श्रेणी को इस नियम के भाग होने से मुक्त कर सकती है ।

निर्णय सं० 1—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या पार्टटाइम कर्मचारी को शारीरिक स्वस्थता के लिए डाक्टरों जांच कराना जरूरी है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को अपनी शारीरिक स्वस्थता का उसी प्रकार से एवं उन्ही शर्तों के अनुसार डाक्टरों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जैसा कि पूर्ण समय के लिए नियुक्त राज्य कर्मचारियों को करना पड़ता है ।

ॐ निर्णय सं० 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 (वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक 1 (26) वित्त विभाग/(नियम) 67-1 दि० 21-6-68 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न नहीं किया जाना है । डाइट की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ डाइट की यह एक प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध का प्रस्तुत करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया गया है । राजपत्रित एवं भराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी—

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में उस सक्षम अधिकारी द्वारा जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रथम वेतन बिल में दर्ज किया जाना चाहिए ।

(2) भराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में माहुरण एवं वितरण अधिकारियों को ऐसा प्रमाण पत्र अभिलिखित करना चाहिए तथा उसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल के साथ संलग्न करना चाहिए ।

+ **नियम 10.** राज्य सेवा के लिए योग्यता का डाक्टरों प्रमाण पत्र निम्न प्रपत्र में होगा—
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

मैं, एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने को कि विभाग में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार है, उसकी जांच की है तथा मुझे सिवाय इनके ऐसी कोई बीमारी (बतलाने योग्य या अन्यथा प्रकार की) शारीरिक कमजोरी या शारीरिक दोष नहीं मालूम दिया है । मैं विभाग में नियुक्त किए जाने में इसे नियुक्ति के लिए उपयोग नहीं समझता ।

+ वित्त वि. की अधि. सं० एक (26) वित्त वि. (नियम) 67 I दि० 21-6-68 द्वारा संशोधित ॐ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक 1 (26) वित्त विभाग (नियम) 67-II दिनांक 21-6-68 द्वारा निविष्ट ।

नियम 11. नियम 10 में निर्धारित प्रमाण पत्र पर जिला चिकित्सा अधिकारी या उससे ऊँचे स्तर के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, परन्तु यह है कि—

(क) महिलाओं के विषय में सक्षम अधिकारी किसी महिला चिकित्सक का डाक्टरों प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में जिनका वेतन, उनकी स्याई बनाने के समय तक 50 रु. से अधिक न पड़े, सक्षम प्राधिकारी किसी राज्यकीय सेवा में नियुक्त मेडिकल प्रेज्युट या लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक के प्रमाण पत्र की स्वीकृत कर सकेगा। या इनके प्रमाण पत्र न देने पर अन्य मेडिकल प्रेज्युट या लाइसेंस प्राप्त डाक्टर का प्रमाण पत्र स्वीकृत करेगा।

(ग) एक उम्मीदवार जो कि अस्थाई रूप से लगातार तीन माह तक या इससे अधिक समय तक नियुक्त किया जाना है, तो उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से पूर्व या उससे एक सप्ताह के भीतर किसी अधिकृत चिकित्सक (मेडिकल अडेण्ट) ने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु यदि यह चिकित्सक इसमें सदेह करे कि उम्मीदवार राज्य सेवा के लिये योग्य है अथवा नहीं, तो वह उस मामले को प्रमाण चिकित्सक (प्रिमरिपल मेडिकल आफीसर) के पास प्रस्तुत करेगा। फिर भी यदि जब एक राज्य कर्मचारी की प्रारम्भ में किसी अधिकारी में तीन माह से कम समय के लिये अस्थाई रूप में नियुक्त किया जाये तथा बाद में उसी कार्यालय में रोक लिया जाये या सेवा में व्यवधान डाले बिना ही दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा राज्यकीय सेवा में कुल सेवा काल तीन माह या इससे अधिक होने की धारा हो तो उसे उस कार्यालय में रहने अथवा नये कार्यालय में उपस्थित होने की स्वीकृति के आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर एक ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी जिसने अपने प्रथम अस्थाई रूप में नियुक्त होने पर एक अधिकृत मेडिकल अडेण्ट (चिकित्सक) का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं जो बाद में उसी कार्यालय में या अन्य स्थान पर बिना अपनी सेवा भंग कराये एक स्थाई रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे, अपने स्याई किए जाने पर, बिना चिकित्सा अधिकारी या उसने ऊँचे चिकित्सा अधिकारी ने पुनः स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक कि उसने अपनी प्रथम अस्थाई नियुक्ति के समय ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र न दे दिया हो। फिर भी यह प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनका वर्णन इन नियम के (क) व (ख) भाग में किया गया है।

नियम 12. डाक्टरों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त हुए राज्य कर्मचारी — निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य कर्मचारी अपने स्वास्थ्य का डाक्टरों प्रमाण पत्र देने से मुक्त किये गये हैं—

(1) एक राज्य कर्मचारी जो प्रतिस्पर्धिता परीक्षा (Competitive Examination) द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा जिने राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार डाक्टरों जचि के लिए जाना पड़ता है।

(2) एक राज्य कर्मचारी जो तीन माह से कम समय के लिये अस्थाई रिक्त स्थान पर उच्च सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(3) एक राज्य कर्मचारी जो अस्थाई रिक्त स्थान पर 6 माह से कम समय के लिए अल्पकालीन सेवा में नियुक्त किया गया हो।

(4) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी जिसको कि डाक्टरों जान पहिले से ही किसी एक कार्यालय में को जा चुको हो, यदि वह बिना सेवा भंग किए दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित हो जाय ।

(5) एक सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) राज्य कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति के बाद शोध हो पुनः नियुक्त किया गया हो ।

(6) एक शारीरिक हट्टि से असमर्थ (Handicapped) राज्य कर्मचारी जो कि विशिष्ट नियोजन विभाग (Special Employment Exchange) के द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे राजकीय अस्पतालों के सुपरिटेन्डेंट/प्रधान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (Principal Medical & Health officer) के एक मेडिकल बोर्ड को सक्षम स्वास्थ्य जांच के लिए जाना पड़ा था ।

टिप्पणी :—] निम्न परिस्थितियों में डाक्टरों प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है :—

(क) जब एक राज्य कर्मचारी स्थानीय निधि में भुगतान किए जाने वाली अयोग्य सेवा में सरकार के अधीन उच्च सेवा में एक पद पर पदोन्नत किया जाये ।

(ख) एक व्यक्ति जो त्याग पत्र देने के बाद या उसकी पूर्ण सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद पुनः नियुक्त किया जाता है ।

(ग) जब कोई व्यक्ति उपरोक्त सण्ड (ख) में बही गई परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में पुनः नियुक्त किया जाये । इसमें नियुक्ति करने वाला अधिकारी निर्णय करेगा कि क्या एक डाक्टरों प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए अथवा नहीं :—

2—जब किसी राज्य कर्मचारी को राजकीय सेवा में प्रवेश पाने के लिए स्वस्थता का डाक्टरों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय, चाहे वह नियुक्ति स्थाई या अस्थाई रूप में हो क्यों न की जा रही हो, परन्तु जब वह एक बार वास्तविक रूप में जांचा जा चुका है तथा अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो नियुक्ति करने वाले अधिकारी के द्वारा उन प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो एक बार प्रस्तुत किया जा चुका है ।

नियम 13. सेवा की मौलिक शर्तें :— जब तक किसी मामले में अस्थाई रूप से साफ साफ प्रावधान न किया जावे, एक राज्य कर्मचारी को सम्पूर्ण समय सरकार की इच्छा पर रहेगा तथा यह उचित अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पारिश्रमिक का एक मांगे दिया हो, किसी भी ढंग से लगाना जा सकता है । चाहे उसकी चाही गई सेवाएं ऐसी हों जिनको पारिश्रमिक संवित निधि या स्थानीय निधि से दिया जावे या एक निकाय से दिया जाये जो निर्गमित हो या न हो और जो पूर्णतः या मूलतः सरकार द्वारा स्वीकृत या नियन्त्रित हो या जिसे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 37) के अन्तर्गत निर्मित पंचायत समिति/जिला परिषद् निधि से दिया जावे ।

नियम 14. (क) — एक ही समय एक स्थाई पद पर दो या दो से अधिक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति स्थाई रूप में नहीं की जा सकती है ।

(ख) एक राज्य कर्मचारी एक ही समय सिवाय अस्थाई रूप के, दो या दो से अधिक स्थाई पदों पर स्थाई रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

(ग) एक राज्य कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पर कि किसी अन्य व्यक्ति का लीयन हो।

नियम 15. पूर्वाधिकार (लीयन)—जब तक इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान न रखा गया हो, एक राज्य कर्मचारी किसी स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किए जाने पर उस पद पर अपना लीयन प्राप्त कर लेता है तथा बाद में किसी अन्य स्थाई पद पर उसका लीयन हो जाता है तो वह अपने पूर्व पद का लीयन रखना बन्द कर देता है।

नियम 16. जब तक किसी राज्य कर्मचारी का लीयन नियम 17 के अन्तर्गत निलम्बित नहीं कर दिया जाता है या नियम 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता है, तब तक स्थाई पद को धारण करने वाला वह उस पद पर अपना लीयन निम्न शर्तों में रखेगा :—

(क) जब तक वह उस पद का कार्य पूरा कर रहा हो,

(ख) जब वह विदेशी सेवा में हो या किसी दूसरे पद पर अस्थाई या कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो,

(ग) दूसरे पद पर स्थानान्तरण के समय (ज्वाइनिंग टाइम) में यदि वह निम्न वेतन वाले पद पर स्थाई रूप से स्थानान्तरित नहीं कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में जिस दिन वह अपने पुराने कार्यभार से मुक्त होगा उसी दिन से उसका लीयन नए पद पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

(घ) जब तक वह अवकाश पर रहे; एवं

(ङ) जब तक वह निलम्बित रहे।

नियम 17. (क) लीयन निलम्बित करना—यदि कोई राज्य कर्मचारी निम्न परों में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो जाता है तो सरकार उसका लीयन उस स्थाई पद में समाप्त कर सकती है जिस पर कि वह कार्य करता है—

(1) किसी सावधिक (टेम्पोर) पद पर,

+ (2) [विलोपित]

(3) अस्थाई रूप से (Provisionally) किसी एक पद पर जिस पर कि अन्य राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन इस नियम के अन्तर्गत निलम्बित न किया गया होता।

× (ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्त (ड्यूटी) पर दिया जाता है या विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है या इस नियम के (क) में के अधीन नहीं आने वाली परिस्थितियों में किसी दूसरे केन्द्र में स्थानापन्न रूप में एक पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं यदि इन मामलों में से किसी मामले में उसे यह विद्वान्त हो मके कि वह जिस पद पर अपना लीयन रखता है उस पद से कम से कम तीन साल की अवधि तक अनुपस्थित रहेगा तो सरकार उस राज्य कर्मचारी का उस पद का लीयन, त्रिम पर वह अपना पूर्वाधिकार रखता है, अपनी इच्छानुसार, निलम्बित कर सकती है।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (94) वित्त वि० (नियम) 66 दिनांक 15-10-69 द्वारा विलोपित किया गया।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (94) वित्त वि० (नियम) 66 दिनांक 15-10-65 द्वारा विलोपित किया गया।

(ग) इस नियम के खण्ड (क) या (ख) में कुछ दिये होने पर भी, एक राज्य कर्मचारी का किसी सांघिक (टेन्डोर) पद पर से लीयन किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकेगा। यदि वह किसी अन्य स्थाई पद पर स्थाई रूप से नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका टेन्डोर पद से लीयन समाप्त किया जा सकता है।

(घ) यदि किसी राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार (लीयन) इस नियम के खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया जाता है तो वह पद स्थाई रूप से भरा जा सकता है तथा इस पद पर स्थाई रूप से नियुक्त किया गया राज्य कर्मचारी उस पद पर अपना पूर्वाधिकार (लीयन) रख सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही निलम्बित किया हुआ पूर्वाधिकार पुनः प्रवर्तित हो जाएगा वैसे ही यह व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी।

टिप्पणी—जब इस खण्ड के अन्तर्गत पद स्थाई रूप में भरे जाते हैं तो वह नियुक्ति प्रस्थाई नियुक्ति (Provisional appointment) कहलाएगी एवं राज्य कर्मचारी उस पर अपना प्रस्थाई (Provisional) लीयन रखेगा एवं वह लीयन इस नियम के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा सकता है।

(ङ) निलम्बित लीयन का पुनः स्थापन (Revival of suspended lien) —एक राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित किया जा चुका है जैसे ही वह कर्मचारी उस खण्ड के उप खण्ड (1) (2) या (3) में वर्णित प्रकृति के पद पर अपना लीयन समाप्त कर देता है।

(च) एक राज्य कर्मचारी का पूर्वाधिकार जो कि इस नियम के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निलम्बित किया जा चुका है, उसी समय पुनः स्थापित हो जाएगा जैसे ही वह राज्य कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रहना बन्द कर देता है या विदेशी सेवा में रहना बन्द कर देता है या दूसरे केन्द्र में पद पर कार्य करना बन्द कर देता है। परन्तु शर्त यह है कि एक निलम्बित लीयन पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा यदि राज्य कर्मचारी अवकाश लेता है, यदि यह पुनर्विश्वास किया जा सके कि अवकाश से लौटने पर वह भारत के बाहर या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर चलता रहेगा ता अन्य केन्द्र में एक पद पर कार्य करता रहेगा तथा सेवा से अनुपस्थिति का कुल समय तीन साल से कम न होगा या वह खण्ड (क) के उप खण्ड (1) (2) या (3) में वर्णित प्रकृति के पद पर स्थाई रूप से कार्य करता रहेगा।

टिप्पणी—जब यह बात हो जाय कि एक राज्य कर्मचारी जो अपने केन्द्र के बाहर किसी पद पर स्थानान्तरित हो, यदि वह अपने स्थानान्तरण से तीन साल की अवधि के भीतर अधिवापि की प्राप्ति करने के कारण वेतन (सुपरग्र्युएन्स पेन्शन) पर सेवा नियुक्त किया जाता हो तो स्थाई पद से उसका लीयन समाप्त नहीं किया जा सकता।

नियम 26 (क)—लीयन समाप्त करना (Termination of lien)—एक राज्य कर्मचारी के लीयन जो किसी पद से किसी परिस्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह लीयन उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता यदि इसका परिणाम उसे बिना पूर्वाधिकार (लीयन) के रखे या वह एक स्थाई पद पर अपना लीयन निलम्बित रखे।

+ (ख) सरकारी कर्मचारी का किसी पद पर सीयन उपरक द्वारा जिस सवर्ग में वह नियुक्त हुआ है उसके अनिश्चित अन्य सवर्ग में (चाहे सरकार, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार के अधीन) किसी स्थाई पद पर सीयन प्राप्त करने पर गमाम्न (टर्मिनेट) हो जाएगा।

+ टिप्पणी सं० 1 (बिलोपित)

निर्णय संख्या 1—विभिन्न एकीकृत राज्यों के स्थाई कर्मचारी जो राजस्थान के निर्माण के समय अस्थाई पदों पर लगाए थे या जो बाद में एकीकरण की प्रगति में लगाए गए थे एवं जिनका सीयन किसी भी स्थाई पद पर नहीं रखा गया था, उनके सीयन, वेतन, पेन्शन आदि के वर्तव्य के प्रदन पर सरकार ने विचार किया है तथा राजपमुन ने निम्न आदेश दिया है—

(1) उन राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो बिना सीयन रहे या बिना किसी स्थाई पद पर एवं बिना 'सरप्लस' घोषित किए अस्थाई (या कर्बन्दाहक) नियुक्तियों पर स्थानान्तरित कर दिये गए थे, उनका सीयन उमी वेतन शृंखला एवं मर्तों की अधिकांश पदों (Superannumerary Posts) का सूचन कर रखा जा सकता है जिसमें कि सम्प्रतिष्ठ राज्य कर्मचारी एकीकृत राज्यों में अपने अन्तिम पद के स्थाई सीयन पर कार्य कर रहा था एवं जो कि स्थाई पदों पर नियुक्ति के मामले की विचाराधीन रहते हुये, वेतनमान एकीकरण (युनिफाइटे स्केल) द्वारा संघोषित की गई।

उपरोक्त पद वर्तमान में 31-6-56 तक सूचन (created) किए हुए समके जावेंगे। ये पद जैसे 2 सम्प्रतिष्ठ कर्मचारी स्थाई पदों पर लगते जावेंगे वैसे वैसे ही कम होते जावेंगे। सभी ऐसे व्यक्तियों को इस समय तक स्थाई पदों पर लग जाना चाहिए या सरप्लस कर हिस्सा में किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो अस्थाई रूप में उन्हें पुनर्नियुक्त किया जाना चाहिए। इस श्रेणी के व्यक्तियों को स्थाई पदों पर नियुक्त करने के मामलों में, मुद अस्थाई कर्मचारियों के बजाए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2 (क)—इस श्रेणी के राज्य कर्मचारी जो पूर्व में सरप्लस घोषित कर दिये गए थे लेकिन पास्तक में हटाए (हिस्सा में) नहीं किए गए थे तथा उन्हें अस्थाई पदों पर काम करने के लिए स्वीकृति दे दी गई या उन्हें किसी स्थाई पद पर अस्थाई रूप में काम करने की स्वीकृति दे दी गई, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वे चाहे उमी पद पर या उसके समान पद पर नियुक्त हो रहे हों या नहीं, उन्हें अपना अन्तिम मूल वेतन तथा वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है। कोई कर्बन्दाहक या अस्थाई वेतन सुरक्षित नहीं किया जावेगा। यदि उनके पूर्व पद का मूल वेतन काम करने के लिए स्वीकृत पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा हो तो उसका वेतन उस पद के अधिकतम वेतन के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा तथा पहिले के मूल वेतन तथा वर्तमान पद के अधिकतम वेतन से जो भी राशि अधिक उबेगी वह व्यक्तिगत वेतन (Personal Pay) के रूप में स्वीकृत की जावेगी।

ऐसे राज्य कर्मचारियों की सेवाओं की पेन्शन के लिए गिनने हेतु उसी वेतन शृंखला में

+ वित्त विभाग की अभिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि० नियम 66 दि० 15-6-69 द्वारा नियम (ख) प्रतिस्थापित व टिप्पणी सं० 1 बिलोपित की गई।

अधिकांश पद (Supernumerary posts) सृजित किये जाने चाहिये जिसे कि ऐसे राज्य कर्म-चारी एकीकृत राज्यों में स्थाई रूप में उनके द्वारा धारण किए गए पद पर प्राप्त कर रहे थे ।

(ख)—जो व्यक्ति सरप्लस के रूप में हटा (डिस्चार्ज) दिये गए थे, उनके मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे । यदि उनमें से किसी व्यक्ति के मामलों पर पुनर्विचार किया गया हो या उसे पुनर्नियुक्त कर दिया गया हो तो उसको वेतन उसके द्वारा अन्तिम रूप में प्राप्त किए गये मूल वेतन से अधिक नहीं दिया जायेगा और उस पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा नहीं होगा जिस पर कि वह पुनर्नियुक्त किया गया है ।—

(ग)—यदि उन व्यक्तियों में से जो किसी भी स्थाई पद पर अपना लीयन नहीं रखते हैं लेकिन जिन्होंने 25 साल की सेवा करली है या 50 वर्ष के हो गए हैं, तो उन सम्बन्धित व्यक्तियों को सरप्लस के रूप में रिटायर किया जा सकता है एवं यदि आवश्यक हो तो पुनर्नियुक्त किया जा सकता है ।

+ निर्णय संख्या 2 (विलोपित) -

÷ निर्णय सं० 3—अधिसंख्यक पदों का सृजन—इस पक्ष पर कुछ समय पूर्व से विचार किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अधिसंख्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए तथा ऐसे पदों को विनियमित करने का क्या सिद्धान्त होना चाहिए । मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर लिया गया है तथा ऐसे पदों के सृजन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं:—

(i) सामान्यतया अधिसंख्यक पद किसी ऐसे अधिकारी को लीयन प्रदान करने हेतु सृजित किया जाता है जो, ऐसे पद को सृजित करने में सक्षम प्राधिकारी की राय में, नियमित स्थायी पद पर लीयन रखने का हकदार है लेकिन जो नियमित स्थायी पद की अनुपलब्धता के कारण ऐसे पद पर अपना लीयन नहीं रख सकता । -

(ii) यह एक काल्पनिक (शैडो) पद है अर्थात् ऐसे पद के साथ कोई छूटी लगी नहीं होती है । अधिकारी, जिसका लीयन ऐसे पद पर रखा जाता है, सामान्यतया किसी अन्य रिक्त प्रस्थायी या स्थायी पद पर कर्तव्यों को पूरा करता है ।

(iii) यह केवल उसी समय सृजित की जा सकती है जब कि उस व्यक्ति के लिए, जिसका लीयन अधिसंख्यक पद का सृजन कर रखा जाता है, कार्य करने हेतु अन्य रिक्त स्थायी या प्रस्थायी पद उपलब्ध हो । दूसरे शब्दों में, यह ऐसी परिस्थितियों में सृजित नहीं किया जाना चाहिए जो पद के सृजन के समय या उसके बाद, विद्यमान पदों की संख्या से अधिक हो जाए ।

(iv) यह हमेशा स्थायी पद होता है । फिर भी चूंकि इसका सृजन किसी स्थाई अधिकारी को जब तक वह किसी नियमित स्थायी पद पर उसे लीयन प्रदान नहीं किया जाता तब तक के लिए किया जाता है इसलिए इसे अन्य स्थाई पदों की तरह अनिश्चित अवधि के लिए सृजित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन सामान्यतया प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निश्चित अवधि तक सृजित किया जाना चाहिए ।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (94) वित्त वि (नियम) 66 दि० 15-10-65 द्वारा विलोपित ।

÷ वित्त विभाग अधिसूचना सं० एफ 1 (38) वित्त वि/ए/नियम/61 दि० 26-10-61 द्वारा निर्रिक्त ।

(v) यह उस अधिकारी के लिए वैयक्तिक पद होता है जिसके लिए यह सृजित किया जाता है तथा ऐसे पद पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह उनी समय समाप्त हो जाता है जब अधिकारी, जिसके लिए यह सृजित किया गया था, सेवा निवृत्ति प्रपत्र किसी अन्य नियमित स्थायी पद पर स्थायीकरण या अन्य किसी कारण से इसे रिक्त करता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे पद पर कोई स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जा सकती है। चूंकि अधिसूचक पद एक कार्यकारी पद (वर्किंग पोस्ट) नहीं है अतः किसी मकान में कार्यकारी पद इसी रूप में विनियमित होते रहेंगे कि यदि नियमित पदों में से किसी एक पद का स्थायी धारक सर्वग्न जाता है तथा सभी पदों पर आदमी कार्य करते हैं तो उस संवर्ग के किसी एक अधिकारी को उसके लिए स्थान रिक्त करना होगा। उसे अधिसूचक पद पर नहीं दिलाया जा सकता है।

(vi) वृद्धि वेतन एवं भत्ते, पेंशन सम्बन्धी लाभ आदि के रूप में ऐसे पदों के सृजन में कोई प्रतिरिक्त वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है।

पहिले कुछ मामले ऐसे हो चुके हैं जिनमें वरिष्ठता, पान्त्रता आदि के परिवर्तन के कारण यह महसूस किया गया कि किसी एक व्यक्ति को पदोन्नति प्राप्त नहीं हो सकी जिसे वह प्राप्त करता यदि बाद में लिया गया निर्णय पहिले ले लिया गया होता तथा ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचक पदों की पूर्ण प्रभाव से सृजित कर उन पर उनकी पूर्ण प्रभाव से नियुक्ति कर उच्चतर वेतन का लाभ दिया गया है। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए ऐसे पदों का सृजन भविष्य में नहीं किया जाए। अधिकतम उस वेतन मान में जिसके लिए वह आधा करता, उस स्टेज तक लाने हेतु अधिम वेतन वृद्धि देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

सभी प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे केवल उपरोक्त परिस्थितियों में ही अधिसूचक पदों के सृजन के लिए मामले भेजें।

यह आदेश पूर्व में उपर्युक्त तरीके के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार से निपटाए गए मामलों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

× निर्णय:—सं० 4 (विलोपित किया गया)

÷ निर्णय सं० 5—वित्त विभाग के ज्ञापन दि० 26-10-61 (उपयुक्त निर्णय सं० 3) के पैरा (vi) के रूपान्तरण में यह आदेश दिया जाता है कि उच्चतर अधिसूचक पद सृजन कर या पदों को प्रप प्रैड कर पूर्ण प्रभाव से पदोन्नतियों निम्नलिखित मामलों में वित्त विभाग की विनियम अनुमति से दी जा सकती है—

(क) किसी न्यायालय के निर्णय के अनुशासना में या कनस्वरूप

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन भारत सरकार के निर्देशन के पालन में यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्देशन मान लिया गया हो।

(ग) सरकार या सरकार के अधीनस्थ सशस्त्र प्राधिकारी की ओर से पान्त्रता के निर्धारण में या वरिष्ठता के निर्धारण में वास्तविक गलती बहा हो जहां वह वास्तविक प्राधिकारों से सम्बन्धित "भ्रंश" पर निश्चित की जाती हो।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (34) वित्त वि./ए (नियम) 66 दि० 15-10-69 द्वारा विलोपित।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (101) वित्त वि./ए/नियम/66 दि० 17-7-67 द्वारा निविष्ट।

(घ) सेवा के एकीकरण की प्रक्रिया में चयन से सम्बन्धित नियमों या भादेशों का गलत प्रयोग या अनुपालना

किर भी निम्न प्रकार के मामलों में पूर्व प्रभाव से पदों की सूचित/अप ग्रेड कर पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए—

(क) जहाँ प्रथम बार वरिष्ठता निर्धारित की जाती हो

(ख) जहाँ मिश्रान्तों में परिवर्तन कर वरिष्ठता पुनः निर्दिष्ट की जाती हो

(ग) जहाँ मेरिट के पुनर्निर्धारण द्वारा वरिष्ठता पुनः निर्दिष्ट की जाती हो।

(घ) जहाँ मेरिट के पुनर्निर्धारण द्वारा उच्चतर पद पर बाद में चयन किया हो।

• नियम सं० 6—वित्त विभाग के आदेश दि० 17-7-67 (नियम सं० 5) के अनुसार वित्त विभाग की अनुमति से उक्त आदेश के पैरा 1 में वर्णित मामलों में अविलम्ब पदों का सूजन कर या पदों की अपग्रेड कर पूर्व प्रभाव से पदोन्नति दी जा सकती है।

एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामले जो उक्त आदेश जारी होने से पूर्व हुए हैं तथा जिनमें पूर्व प्रभाव से पदोन्नति नहीं दी गई थी एवं/वा पुनः स्थिरकरण का लाभ ही स्वीकृत/प्रस्वीकृत किया गया था, पुनः विचार जा सकते हैं तथा उक्त आदेश के अनुसार तय किए जा सकते हैं। मामले की जांच करती गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि चूंकि पूर्व प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय सरकार द्वारा दि० 8-7-66 को लिया गया था (यद्यपि आदेश दि० 17-7-67 को जारी किया गया है) अतः उक्त सभी कर्मचारियों के मामले जो दि० 8-7-66 की या उनके बाद सेवा निवृत्त हो गए हैं, उक्त आदेश के अनुसार पुनः विचार कर निपटाए जाएं बशर्त कि इस हेतु निवेशन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा विशिष्ट रूप में लिखित में किया जाए।

• नियम 19. लीयन का परिवर्तन (Transfer of lien)—नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी के लीयन को समान के दर के दूसरे स्थाई पद में बदल सकती है यदि वह उस पद पर कार्य नहीं कर रहा है जिस पर कि उसका लीयन है, चाहे वह लीयन बिलम्बित हो क्यों न किया गया हो।

• नियम 20. (क) राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण (Transfer)—सरकार एक पद से दूसरे पद पर, (विशेष निम्न शर्तों के) राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर सकती है—

(1) कार्य में अक्षमता (Inefficiency) के कारण या दुर्बलता के कारण, या

(2) उसके लिखित रूप में प्राप्ति पत्र देने पर।

एक राज्य कर्मचारी नियम 50 के अन्तर्गत किसी कार्यवाहक पद पर नियुक्त किये जाने के अनिवार्य स्थाई रूप से किन्हीं ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका वेतन उसके उस स्थाई पद के वेतन से कम हो, जिस पर कि उसका लीयन है या यदि नियम 17 के अन्तर्गत उसका लीयन निवर्धित नहीं किया जाता तो उस पद पर उसका लीयन होता।

+ टिप्पणी—नियम 215 के खण्ड (ख) के अनुसार पद की समाप्ति पर किसी निम्न पद की स्वीकृति के मामलों को छोड़कर, स्थायी पद के जिस पर कि राज्य कर्मचारी अपने पूर्वोक्तिकार

• वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (101) वित्त वि०/ए/नियम/66 दि० 10-6-68 द्वारा निविष्ट

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (65) एफ डी (ई धार) 66 दिनांक 23 सितम्बर 1966 द्वारा अधिल किया गया।

(सीयन) रगता है, वे वेतन से कम से कम वेतन वाले किसी पद पर स्थानान्तरण किया जाना एक प्रकार से उसके पद (रेक) में बर्फी लिए जाने की गारंटी (पेनेन्टी) देना समझा जाता है एवं इस प्रकार कि गारंटी (पेनेन्टी) केवल राजस्थान सिविल सर्विस (गवर्नर, नियन्त्रण एवं प्रोड) नियम, 1958 में निर्धारित प्रतिया के अनुसार ही दी जा सकती है ।

नियम संख्या 1- विषय पर सम्मोचता पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय दिया गया है कि उस सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में स्थाई पदों की अनुपलब्धि होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्तियों का सीयन रगने हेतु ऐसे पदों का सूचन निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में करना उचित रहेगा । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखा जावे कि जहां तक निम्न सेवा/ग्रेड/टाइम स्केल आदि में अधिकांश पदों (मुख्यतः मेररी पद) पर खाली किए गए अधिकांश का सीयन रगता आवश्यक है, तो उच्च पद जिसको कि उसके द्वारा रिक्त किया गया है, उसे स्थाई रूप से या अल्पकालिक प्रकार में नहीं भरा जाना चाहिए तथा उस उच्च पद पर नियुक्ति या उन्नति उसी समय की जा सकेगी जबकि वह राज्य कर्मचारी उस निम्न ग्रेड में प्रायः स्थाई पद पर नियुक्त किया जा सके, जिस पर कि वह खाली किया गया है या रिप्लेस किया गया है ।

नियम संख्या 2-वित्त विभाग के आदेश दिनांक 2-1-61 में (निर्णय संख्या 1) प्राधिक संगोपन करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि जब एक राज्य कर्मचारी की कटौती के कारण एक स्थाई पद रिक्त कर दिया जाता है तो उसे कटौती दिये जाने की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने के पूर्व स्थाई रूप में नहीं भरा जाना चाहिये ।

जब एक साल की अवधि सम्पन्न हो जाए तथा ऐसा पद स्थाई रूप में भर दिया जावे, तथा मूल राज्य कर्मचारी उससे बाद पुनः राज्य सेवा में ले लिया जावे तो उसे पर ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो कि उसी वेतन श्रेणी में स्थाई रूप में खाली हो जिसमें कि उसका पूर्व स्थाई पद था । यदि स्थान खाली न हो तो उसे एक मुख्यमेररी (अधिकांश) पद पर लगाया जाना चाहिये जो उचित स्वीकृति द्वारा सूचित किया जा सकता है एवं जिसे उसके समान वेतन श्रेणी वाले अन्य स्थाई पद के रिक्त होने पर समाप्त किया जा सके ।

(क)-इस नियम के लच्छ (7) में या नियम 7 के लच्छ (17) में वर्णित कुछ भी किसी एक राज्य कर्मचारी को किसी एक ऐसे पद पर बदली करने में नहीं रोक सकेगा जिस पर कि यदि उसका सीयन नियम 17 के लच्छ (क) के अनुसार नियमित न किया गया होता तो वह अपना सीयन रखता ।

नियम-21- एक राज्य कर्मचारी को ऐसे नियमों के अनुसार जिसे कि सरकार आदेशों द्वारा निर्धारित करे, आवश्यक जीवन बीमा योजना में धन जमा कराना पड़ेगा । जहां राजस्थान राज्य कर्मचारी जीवन बीमा नियमों में निर्धारित उम्र से अधिक उम्र होने के कारण तथा मेरीकल आधार पर अयोग्य होने के कारण कोई प्रथम या अंतिम आयुमान नहीं स्वीकृत किया जा सके तो उनको सामान्य मरिष्य विधि में अंशदान जमा कराना पड़ेगा ।

नियम 22- वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने की शर्त- इस नियमों में रखे गये विविध अवधारणों के अनिवार्य जिस दिन से राज्य कर्मचारी अपने पद का कार्यभार संभालेगा, वह उस दिन से नियमानुसार वेतन व भत्ता प्राप्त करेगा और जैसे ही वह उन सेवाओं की करने में बन्द हो जाएगा उसे वेतन व भत्ता मिळना बन्द हो जाएगा ।

टिप्पणी :—‘वापिस के चार्ज’ एवं अधिकार क्षेत्र छोड़ने के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देशनों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें ।

जांच निर्देशन :—एक राज्य कर्मचारी पद के धारण करते समय उसके साथ संलग्न वेतन एवं भत्तों की उसी दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा जिस रोज से वह कार्य भार धारण करता है। यदि उस दिन कार्यभार उसे मध्यमह-पुर्व संभलाया गया हो। यदि कार्य भार (चार्ज) मध्यमह के बाद संभलाया जाये तो वह अपना वेतन व भत्ता अगले दिन से प्राप्त करना शुरू करेगा ।

नियम 22 क. प्रशिक्षण काल में बी गई धनराशि वापिस जमा कराना—(1) जब किसी राज्य कर्मचारी को नियुक्ति राजपत्रित पद पर हो जाने पर यदि उसे अपने पद का स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यभार संभालने के पहिले किसी विशिष्ट निर्धारित समय के लिये प्रशिक्षण में जाना पड़ता हो, यदि ऐसा राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो घण्टे के भीतर हजाग पत्र दे देता है अथवा अन्य जगह नियुक्ति पर चला जाता है तो वह उसे प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई धनराशि को ऐसे प्रशिक्षण में सरकार द्वारा खर्च किए गए अन्य व्यय सहित, सरकार को लौटा देगा। लेकिन सम्बन्धित नियमों के अनुसार जो दैनिक एवं यात्रा भत्ता उसे मिलेगा, यह धनराशि शामिल नहीं की जाएगी ।

लेकिन शर्त यह है कि यह धनराशि उस समय वापिस करना जरूरी नहीं होगा जब सरकार को राय में राज्य कर्मचारी को दिया गया प्रशिक्षण उसकी नई नियुक्ति में भी लाभदायक सिद्ध हो सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उसके प्रशिक्षण के खालू होने से पूर्व एक अनुसन्ध पत्र (बोर्ड) परिशिष्ट 18 क. में दिए गए प्रपत्र (फार्म) में भरना पड़ेगा ।

नियम 23. (1) किसी भी राज्य कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक समय का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

+ (2) एक राज्य कर्मचारी के सरकारी सेवा में न रहने की शर्त—जब कोई राज्य कर्मचारी 5 साल तक लगातार अवकाश पर रहने के बाद सेवा पर उपस्थित नहीं होता है या जब कोई राज्य कर्मचारी अवकाश व्यतीत हो जाने पर सेवा (ड्यूटी) में अनुपस्थित रहता है तबय इसके कि वह कुछ ऐसे समय के लिए विदेशी सेवा में हो या निलम्बित हो जो कि उसको स्वीकृत किए गए अवकाश के समय की गिनकर पांच वर्ष से ज्यादा हो, तो वह, जब तक कि राज्यपाल मामले की अववाद स्वरूप परिस्थिति में अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 में दी गई प्रक्रिया को अपनाने के बाद सेवा से हटा (रिमूव) दिया जाएगा ।

निर्णय :—यह आदेश दिया गया था कि नियम 23 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है जिनमें एक राज्य कर्मचारी, उसे निलम्बित किए जाने के आदेश के कारण, अपने पद के कार्यभार को संभालने से रोका जा रहा है। इसलिए ऐसे मामलों में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 की शर्तों के अनुसार सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार एवं सम्ब-

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं०. एक । (66) वित्त वि (नियम) 66 दि० 8-4-70 द्वारा संशोधित ।

नियत राज्य कर्मचारी के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि निम्नलिखित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए तथा यथाशीघ्र घनिष्ठ आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए ।

23. क. (1) उप नियम (2) में दिये गए के विधाय, एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाये किसी भी समय राज्य कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा राज्य कर्मचारी को लिखित में नोटिस दिया जाकर समाप्त की जा सकती है । इस प्रकार के नोटिस की अवधि, अब तक राज्य कर्मचारी एवं राज्य सरकार एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते हैं एक माह होगी ।

परन्तु यदि यह है कि किसी भी ऐसे राज्य कर्मचारी की सेवा नोटिस की अवधि के समय की राशि के समान राशि का भुगतान कर, सरकार इमकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है, या वह नोटिस की अवधि में जिनके दिन बाकी रहे उतने दिन का या अनुव्यय किए गए किसी लम्बे समय की राशि का भुगतान कर, उनको सेवाओं को तत्काल समाप्त कर सकती है । भर्तों का भुगतान उन शर्तों के अनुसार होगा जिनके कि अन्तर्गत ऐसे भर्ते स्वीकृत हों ।

(2) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाये—

(क) जो लातार तीन साल से अधिक समय से सेवा में चला आ रहा हो, एवं

(ख) जो पद के लिए निर्धारित उम्र तथा योग्यता में पूर्णतया योग्य ठहरता हो तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सलाह से, जहाँ यह सलाह आवश्यक हो, नियुक्त हुआ हो ।

समाप्त की जा सकेंगी—

(i) उन्हीं परिस्थितियों में एवं उन्हीं तरीकों में जिसमें कि एक स्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है ।

(ii) जब प्राप्य पदों की संख्या में कमी की गई हो तो उन राज्य कर्मचारियों की निकाला जावे जो स्थाई सेवा में न हों,

परन्तु शर्त यह है कि किसी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीन केन्द्र में पदों की कमी किए जाने के परिणाम स्वरूप सेवाओं की समाप्ति कनिष्ठता (Juniority) के आधार पर की जावेगी ।

+ टिप्पणी—अभिब्यक्ति “पद के लिए निर्धारित अर्हताएं” में तात्पर्य उन अर्हताओं में है जिनके बिना पूरा करने पर ही, विभागधीन व्यक्ति पद पर भर्ती किया जा सकता था तथा इसमें पद पर स्थाई नियुक्ति के लिए पात्रता को विनियमित करने वाले नियमों तथा संविधान के अनु-309 के परन्तु के अधीन प्रस्तावित नियमों की अनुपामना भी शामिल है ।

निर्णय—यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ कार्यालयों में अस्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों से एक वचन प्राप्त करने की प्रथा चालू है यदि वे एक माह का उचित नोटिस दिये बिना ही त्याग-पत्र दे देते हैं तो वे नोटिस के समय का वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार को जमा करावेंगे ।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 क. द्वारा सरकार एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवाओं की तो नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ता देकर सभी समय समाप्त कर सकती है परन्तु यह

प्रावधान उस नियम में नहीं दिया गया है कि यदि राज्य कर्मचारी उचित समय का नोटिस न देता है तो ऐसी रकम सरकार को जमा करावे। यह प्रावधान स्पष्ट था।
 को अति कर्मचारी एवं सरकार दोनों के प्रत्येक कार्य साबती है। जहाँ तक कर्मचारी का है उसके लिए अवधि का वेतन एवं भत्ता उस नोटिस अवधि की उचित मजदूरी है परन्तु करने वाले प्राधिकारी के लिए उस पद पर नियुक्ति का प्रबन्ध करने व नये कर्मचारी कार्य सम्भालने में बड़ी असुविधा होती है यदि वह उस पद पर नियुक्ति के प्रबन्ध के लिए व्यक्ति को उसका कार्य दिताने के लिए उचित समय का नोटिस प्राप्त नहीं करता है।
 यह तर्क किया गया है कि यदि उचित समय पर नोटिस देने की शर्त पर बल देने का नीय प्रावधान नहीं होगा तो बिना उचित समय के नोटिस देने की प्रवृत्ति का कोई भय नहीं ऐसे मामलों में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी त्यागपत्र स्वीकार करने से मना कर सकता यदि राज्य कर्मचारी बिना इजाजत के कार्यालय से रुक जाता है तो वह उसके विपरीत न तमक कार्यवाही कर सकता है। विशेष रूप से शराब मामलों में ऐसे अधिकारी को निर्भर रहेगा कि वह उसके सम्बन्धित अधिकारियों को कर्मचारी के चरित्र एवं उसके सेवा श्राद्धि के बारे में अपनी राय श्राद्धि दे सकेगा कि वह सरकार के अधीन सेवा करने योग्य नहीं है। उसके लिए यही पर्याप्त दण्ड होगा।

सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि प्रस्थाई अधिकारियों से नोटिस पीरियड का वेतन एवं भत्ता वसूल करने के बचन लेने की श्राद्धि को पहले समाप्त नहीं की गई है, तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। प्रस्थाई राज्य कर्मचारी नोटिस के बदले में कोई वेतन वसूल नहीं करना चाहिए। जहाँ उसकी जगह पर अन्य नियुक्ति का किया जा सकता हो, वहाँ नियुक्तिपूर्व प्राधिकारी आपसी समझौते के नोटिस के समय को कम कर सकता है या (राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट 9) या अनुसूचि के क्रम संख्या 4 स द्वारा राज्य कर्मचारी के लिए नोटिस की शर्तों को समाप्त है। जहाँ यह सम्भव न हो तथा त्यागपत्र स्वीकृत न किया जा सकता हो, तो उसके विपरीत उक्त पैरा 2 के अन्त में कहे गये अनुसार की जा सकती है।

भाग ३

अध्याय ४ वेतन (Pay)

अध्याय 24. किसी समय वेतनमान में किसी पद पर सरकारी सेवा में नियुक्त प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस वेतनमान का न्यूनतम या ऐसी स्टेज पर प्राप्त करेगा जिसके द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया जाय परन्तु सतत यह है कि वह उसके द्वारा प्राप्ति के लिए सतत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वेतन से अधिक नहीं होगा तथा सरकार की स्वीकृति कोई विशेष या वैयक्तिक वेतन सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अपवाद—स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 97 के नीचे निर्णय संख्या 1 के पैरा 1 के अनुसार वेतन

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (50) वित्त वि. (नियम) 66 दिनांक 22-8-1957 प्रतिस्थापित।

प्राप्त करते हैं, उनके लिए नए शिक्षण सत्र में उम्मीद पर पुनर्नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन, विशेष वेतन, शैक्षिक वेतन या वेतन के रूप में स्वीकृत अन्य परिलक्षितियों के प्रतिरिक्त अन्य उस वेतन में कम नहीं होगा जिसे उसने ऐसे गत अवसर पर प्राप्त किया था तथा वह गत ऐसे समय की अवधि की जिसमें उसने वेतन प्राप्त किया था, उस वेतन के सम्बन्ध समय वेतनमान की स्टेज में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा बशर्त कि वह अपना कार्य ग्रहण प्रगति शिक्षण सत्र में खुलने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर कर लेता है।

नियम 25. प्रशिक्षण काल आदि में वेतन—नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी (सेवा) के रूप में सम्भले गये किसी भी समय के बारे में किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा वेतन स्वीकृत किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार प्रायोगिक समझे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह वेतन उस वेतन से अधिक नहीं होगा जिसे कि राज्य कर्मचारी, यदि नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी में प्रतिरिक्त अन्य ड्यूटी पर रहता तो प्राप्त करता।

टिप्पणी—यदि कोई राज्य कर्मचारी नियम 7 (8) (ग) (iii) के नीचे दी गई टिप्पणी के अन्तर्गत अपनी नियुक्ति के आदेश के लिए इन्तजार कर रहा हो तो वह उस पद का वेतन पाने का अधिकारी होगा जिन पद पर वह अन्त में काम कर रहा था उस पद का वेतन प्राप्त करेगा जिस पर कि वह अपना नया चार्ज समालेगा। परन्तु इन दोनों में से जिसका वेतन कम होगा, वही उसे मिलेगा।

जांच निर्देशन—एक राज्य कर्मचारी जो कि निर्देशन के पाठ्यक्रम में या प्रशिक्षण में या कर्तव्य (ड्यूटी) पर माना जाता है तथा जो कि जिस समय वह ऐसी ड्यूटी पर लगाया गया था, अपनी कार्यवाहक नियुक्ति का वेतन प्राप्त कर रहा था, उसे वही कार्यवाहक वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए जिसे कि वह ड्यूटी पर रहता तो समय समय पर नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी के प्रतिरिक्त रूप में प्राप्त करता रहता। उसे वह वेतन स्वीकृत किया जाना पड़ेगा नहीं है जिसे वह प्रशिक्षण पर खाना होने के पूर्व प्राप्त कर रहा हो।

स्पष्टीकरण (Clarification)—एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त एक राज्य कर्मचारी के लिए किन किन परिस्थितियों में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए। मामले की जांच की गई है तथा एतद्वारा यह स्पष्टीकरण किया जाता है कि यदि कोई अधिकारी उन सेवाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए, जिस पर कि स्पेशल वे मिलती हो या जिसकी समान सेवा हो, प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में उस ही पद का मिलेगा जिसे कि वह प्रशिक्षण में जाने के पूर्व पद पर कार्य कर, प्राप्त कर रहा था।

जो मामले उक्त अवतरण 1 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, परन्तु यदि प्रशिक्षण किसी ऐसे एक पद के लिए दिया जा रहा है जिस पर कि विशेष वेतन मिलेगा तो राज्य कर्मचारी को उस पद का विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में स्वीकृत किया जा सकता है। जो मामले उक्त अवतरण सं० 1 व 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें प्रशिक्षण काल में साधारण रूप से विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विविध आदेशों की प्रवृत्ति होगी।

पहिले के मामले जिन पर निर्णय दिया जा चुका है, उन्हें पुनः छेड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी ।

निर्णय संख्या 1—एक प्रश्न उठा है कि प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25 के अन्तर्गत किन परिस्थितियों में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए । मामले की जांच की गई तथा राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग के भीमो दिनांक 6-2-61 (उक्त स्पष्टीकरण) के प्रतिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं—

(1) निम्न दृष्टांतों में प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन दिया जा सकेगा—

(1) यदि अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है जो कि उसके उन कर्तव्यों से सम्बन्धित है, जिन्हें वह विशेष वेतन प्राप्त करते हुये या समान कर्तव्य करते हुए पूरा कर रहा था ।

(2) यदि प्रशिक्षण ऐसे पद के लिए दिया जा रहा हो जिस पर उसे प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पूर्व अपने पद पर पा रहे विशेष वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन मिलने वाला हो ।

(2) उपरोक्त कहे गए मामलों में विशेष वेतन की स्वीकृति, फिर भी, निम्नलिखित बातों के आधार पर दी जाएगी ।

(i) यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो, एवं

(ii) यदि वह अधिकारी प्रशिक्षण पर न जाता तो वह अधिकारी उस पद पर कार्य करता रहता जिससे कि वह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ । या वह एक ऐसे पद को धारण करता रहता जो उसके समान विशेष वेतन वाला होता या उससे अधिक होता जिस पर कि वह प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व काम कर रहा था ।

निर्णय संख्या 2—यह प्रश्न कि, क्या प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को, जो खूटी के रूप में समझा जाता है, क्षतिपूर्क भत्ता (कम्पेन्सेटरी ग्रांट्स) स्वीकृत किया जा सकता है, कुछ समय तक सरकार के विचाराधीन था । मामले की जांच कर ली गई है तथा यह आदेश दिया गया है कि जब तक अन्यथा प्रकार से कुछ नहीं दिया हुआ हो, एक राज्य कर्मचारी को, जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत प्रशिक्षण काल में खूटी के रूप में माना जाता है, ऐसी अवधि में किसी प्रकार का क्षतिपूर्क भत्ता स्वीकार किया जा सकता है जिसे वह प्राप्त करता लेकिन प्रशिक्षण पर रवाना होने के कारण प्राप्त नहीं कर सका । बशर्ते कि उस प्रशिक्षण की अवधि 130 दिनों के ज्यादा न हो ।

यह जारी होने की तारीख अर्थात् 27-2-65 से लागू होगी ।

+ निर्णय सं० 3—वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27-2-65 (उक्त राजस्थान सरकार का निर्णय सं० 2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रशिक्षण के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रामित्वित करने पर विचार किया गया है ।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (22) वित्त वि (व्यय-नियम) 63 दिनांक 17-1-66 द्वारा निबिष्ट ।

सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों में निवेदन है कि कोई अधिकारी, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी सरकार है, प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, वहाँ हम सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र कि प्रशिक्षण पर खाना होने के विषय अधिकारी नगर (अतिरिक्ति) भत्ता प्राप्त करता रहता, दिया जा सकता है तथा इनको एक प्रति मर्तों को प्राधिकृत करने हेतु महा लेखाकार राजस्थान के पास भेजी जा सकती है।

× निर्णय सं० 4—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25 के नीचे दी गयी टिप्पणी में अन्तर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, एक राज्य कर्मचारी, जो प्रस्थापना आदेशों (पोस्टिंग आर्डर) की प्रतीक्षा कर रहा हो, उस पद का वेतन प्राप्त करने का हकदार है तब उतने पद में पारण किया या या वह उस वेतन को प्राप्त करने का हकदार है तब वह अपने नए पद का कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करेगा। परन्तु इनमें से जो कोई भी कम होगा, वह उसे प्राप्त करेगा। उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्थापना आदेशों (पोस्टिंग आर्डर) की प्रतीक्षा करने वाले राज्य कर्मचारी जब तक वे नए पद का कार्यभार नहीं सम्भाल लेते हैं, प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि के वेतन के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। इससे सम्बन्धित अधिकारियों को काफी धार्मिक कठिनाई होती है।

(2) मामले की जांच करली गयी है तथा यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान वेतन निम्नलिखित प्रकार से, प्रस्थापनी तौर पर, उस वेतन के समायोजन की गत के अधीन रहते हुए जो बताया हो तथा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट 'टिप्पणी' के अधीन नए पद का कार्यभार लेने के लिए प्राधिकृत हो, भुगतान किया जा सकता है :—

- | | |
|--|---|
| (1) यदि पूर्व पद प्रस्थापनी रूप में पारण किया गया हो या वह सेवा में कोई ऐसा संवर्ग या पद हो जिससे उसका सम्बन्ध है। | पूर्व पद का विनियम वेतन रहित (यदि कोई हो) स्थाई वेतन। |
| (2) यदि पूर्व पद पर कार्यवाहक या स्थाई रूप में कार्य कर रहा हो। | विनियम वेतन रहित (यदि कोई हो) पारण किए गए पद का वेतन। |
| (3) यदि अवकाश से लौट रहा हो। | अन्तिम अवकाश वेतन (बीज मेमेरी) के बराबर वेतन। |

(3) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख में प्रभावशील होगा। लेकिन एक ऐसे राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में, जो इस आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व अपनी प्रस्थापना के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो, यह आदेश उस तारीख से प्रभावशील होता है जिससे कि राज्य कर्मचारी अपनी प्रस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था।

❖ निर्णय संख्या 5—प्रशिक्षण काल में अतिरिक्ति भत्ता उठाने सम्बन्धी अमल पूर्व आदेशों के अतिरिक्त में यह आदेश दिया जाता है कि जब तक अन्यथा प्रावहित न हो, सरकारों

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (93) एक बी (अध्य-नियम) 66 दिनांक 14-12-66 द्वारा शामिल किया गया।

❖ वित्त विभाग के आदेश सं० एक 1 (22) वित्त वि० (अध्य-नियम) 63 दिनांक 6-2-67. द्वारा निर्दिष्ट।

कर्मचारी जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (1) के अधीन प्रशिक्षण काल में व्यूटो पर माना जाता है, उसे उक्त अवधि के दौरान कोई भी क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है जिसे प्रशिक्षण पर रवाना होने के अलावा प्राप्त करता परन्तु यह है कि प्रशिक्षण की अवधि 120 दिन से अधिक न हो तथा इसके साथ यह धर्त है कि जिस सक्षम प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजने की शक्ति प्रदान की गई है, उसके द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए—

प्रमाणित किया जाता है कि यी / कुमारी / श्रीमती जो विभाग में पद पर हैं एवं जो आदेश सं० दिनांक के अधीन प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं, निम्न भत्ते प्राप्त करते यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना नहीं होते/होती ।

- (1) मकान किराया भत्ता
- (2) परियोजना भत्ता
- (3) राजस्थान नहर परियोजना में डेजर्ट भत्ता
- (4) विलोपित
- (5) ग्राम्य भत्ता
- (6) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता
- (7) सीमा सड़क निर्माण भत्ता

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी का परिवार उसी स्थान पर रहा है जहां उक्त भत्ता स्वीकार्य है ।

(जो आइटम अप्रयोग्य हो, काट दें)

नियम 26—किसी समय चेतनमान वाले (Time Scale) पद पर नियुक्ति होने पर आरम्भिक (इनिशियल) मूल वेतन को नियमित करना—(1) एक राज्य कर्मचारी जो पहले से ही एक सेवा संवर्ग (केडर) या विभाग में सेवा कर रहा हो एवं जो सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्त न किया जाकर सीधी भर्ती या विनिष्ट चयन द्वारा (एक सेवा, संवर्ग या विभाग से दूसरी सेवा संवर्ग या विभाग में, प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त अन्य तरीकों से स्थानान्तरण की शामिल करते हुए) किसी अन्य सेवा, संवर्ग या विभाग में नियुक्त हो गया हो तो उसका आरम्भिक वेतन (इनिशियल पे) इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाएगा ।

यदि धोनी पुराने पद पर अन्तिम वेतन

नए पद पर आरम्भिक वेतन

(इनिशियल पे) :

(क) किसी स्टाई पद पर स्टाई रूप से नियुक्त हो एवं किसी उच्च पद पर कार्यवाहक काम न कर रहा हो ।

(क) धोनी (क) में वर्णित व्यक्ति का आरम्भिक वेतन निम्न तरीके से तय किया जाएगा—

“प्रेक्टिस बंदी भर्ती” पूर्वे प्रमाण से वित्त विभाग की आशा सं० एक 1 (22) वित्त वि० (व्यय-नियम) / 63 दिनांक 12-9-67 द्वारा विनियमित किया गया ।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एक 1 (94) एक डी० (व्यय-नियम) 66 दिनांक 31-12-66 द्वारा परिवर्तित किया गया । ये संशोधन 1-1-67 से प्रभावशील होंगे ।

- (1) यदि नए पद का अधिकतम वेतन पुराने पद के अधिकतम वेतन से ज्यादा हो, तब वेतन नए पद के वेतनमान में, पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से आगे की स्टेज पर निश्चित किया जाएगा।
- (2) यदि नए पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के अधिकतम के बराबर या उससे कम हो तो वेतन नए पद के वेतनमान की उस स्टेज पर निश्चित किया जाएगा जो कि उसके पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन के बराबर है या यदि ऐसी कोई स्टेज नहीं है या यदि उस नए पद के वेतनमान में ऐसी कोई स्टेज नहीं हो तो पुराने पद के अन्तिम मूल वेतन से कम की स्टेज पर निश्चित किया जाएगा तथा अन्तर के बराबर शेष को वैयक्तिक वेतन कर दिया जाएगा।
- (3) यदि नए पद का न्यूनतम उपयुक्त शब्द (1) व (2) में स्वीकार्य वेतन से अधिक है, तो नए पद का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
- (क) (1) निम्न पद पर स्थायी लेकिन जो उसी सेवा, संवर्ग या विभाग में किसी उच्च स्थायी या अस्थायी पद पर कार्य-काहक कार्य कर रहा हो, वहाँ कि ऐसी कार्यवाहक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गए परोक्ष सम्बन्धी नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो।
- (ख) अथवा (क) में वर्णित किसी पदवाक से शासित होने वाले व्यक्तियों का वेतन निम्न तरीके से निश्चित किया जाएगा।
- + (1) यदि नए पद का न्यूनतम वेतन स्थाई रूप से धारित पद के अतिरिक्त अन्य पुराने पद के अन्तिम वेतन के बराबर या उससे अधिक है तो प्रारम्भिक वेतन नए पद के न्यूनतम वेतन पर निश्चित किया जाएगा।
- (2) यदि स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त हो परन्तु उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती, परोक्ष, विजिष्ट घनन, आपाती भर्ती द्वारा या भारत के संविधान के

उपयुक्त पैरा (क) (1), न (2) एवं (3) में वर्णित प्रकार का नहीं था।

(3) स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति, जिस पर कि नियुक्ति-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गए दिवसीय सेवा नियमों में नियमित नहीं की गई हो एवं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं हो।

(4) स्थायी या अस्थायी पद पर अस्थायी नियुक्ति जो उपयुक्त पैरा (1) से (3) में वर्णित प्रकार से भिन्न हो।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन, स्थानापन्न वेतन तथा अस्थायी पद का वेतन है तथा इसमें विविष्ट वेतन शामिल नहीं होगा।

(3) जब नये पद पर नियुक्ति नियम 20 (क) या नियम 215 (ख) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी की प्राप्ति पर की गई हो तथा नए पद का अधिकतम वेतनमान पुराने पद के अधिकतम वेतनमान से कम हो, तो वह नए पद का अधिकतम वेतन प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

• टिप्पणी—सावधि पद पर नियुक्ति होने पर वेतन का स्थिरीकरण इस अधिनियम के अधीन विनियमित किया जाएगा न कि नियम 26 क के अधीन किया जाएगा।

अववाद—अधम प्राकधान के तौपरे अवतरण में दी गई यह बातें, कि अस्थाई पद उभी वेतन शृङ्खला में होने चाहिये जिसमें कि एक अस्थाई पद होता है, प्रभावगीन नहीं होगी यदि एक अस्थाई पद (1) सरकार या विभाग द्वारा उभी प्रवृत्ति के कार्य के लिये मृजित किया जाना है जैसा कि एक साधारण कार्य के लिये विभिन्न सरकार या विभाग के अधीन किसी केटर में स्थाई पद रहते हैं एवं (2) (यह एक स्थाई पद) सरकार या विभाग के अधीन एक केटर में स्थाई पदों पर लागू होने वाली वेतन शृङ्खला की समान वेतन शृङ्खला में स्वीकृत किए गए हों।

• टिप्पणी—(1) इसमें शामिल नहीं किया गये विविध पद से या उस केटर में शामिल एक टेम्पोर पद से साधारण केटर या सेवा में एक पद पर प्रत्यावर्तन या एक अस्थाई पद से स्थाई पद पर प्रत्यावर्तन, इस नियम के प्रयोजन के लिये उस पद पर स्थाई नियुक्ति नहीं होती।

(2) जब एक राज्य कर्मचारी उभी तारीख की किसी ऊँचे पद पर नियुक्त किया जाता है जिसकी कि उसकी वार्षिक वृद्धि निम्न पद में मिलनी होती है तो उच्च पद में उसका प्रारम्भिक वेतन निर्धारण करने के लिये उसके स्थाई मूल वेतन में वह वार्षिक वृद्धि भी मिलाई जावेगी जो कि उस दिन से मृजित होती है।

• जाँच निर्देशन [विनियमित]

(2) एक वेतन शृङ्खला हाल ही की जाय की हुई हो सकती है जब कि मन्त्र (केटर) या श्रेणी, जिससे वह सर्वा हुई है, दर शृङ्खला में (ग्रेड-स्केल) टाइम स्केल के प्रभाव में आने से

• वित्त विभाग (नियम) की अधि. सं० एक 1 (94) वित्त वि (नियम)/66-1 दिनांक 16-8-69 द्वारा निविष्ट एवं जाँच निर्देशन सं० 1, 3, 4 व 6 विनियमित तथा दि० 1-1-67 से प्रभावी।

पूर्व ही चली घा रही है या यह हो सकता है कि एक वेतन-शृंखला में दूसरी वेतन शृंखला का स्थान ले लिया हो। यदि किसी राज्य कर्मचारी ने नई वेतन-शृंखला के लागू होने से पूर्व किसी संवर्ग या श्रेणी में एक पद पर स्थाई या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तथा उस अवधि में किसी स्टेज के बराबर वेतन प्राप्त किया हो या दो स्टेजों के बीच का वेतन प्राप्त किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन नई वेतन शृंखला में अन्तिम रूप में प्राप्त किये गये वेतन के रूप में निश्चित किया जाना चाहिये तथा जिस अवधि में यह प्राप्त किया गया था, उसे उसी स्टेज में वार्षिक वृद्धि के लिए गिना जाना चाहिये तथा यदि वेतन दो स्टेजों के बीच का था तो निम्न स्टेज या उस टाइम स्केल में उसका प्रारम्भिक वेतन निश्चित किया जाना चाहिये।

❧ (3) विलोपित

❧ (4) विलोपित

(5) यदि कोई राज्य कर्मचारी इस नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन (Personal pay) प्राप्त करना हो, जो जब भी राज्य कर्मचारी को नये भ्रमण पुराने पद पर समय शृंखला में दूसरी वार्षिक वृद्धि बकाया होती हो, तो राज्य कर्मचारी को नये पद की दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करनी चाहिये एवं उसी समय वह अपना व्यक्तिगत वेतन एवं अपने पुराने पद की समय शृंखला से सभी सम्बन्ध छोले कर देगा। किसी भी राज्य कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन केवल उसकी ऐसी नई वेतन शृंखला में प्रारम्भिक वेतन तय करने के लिए स्वीकृत किया जाता है जिस पर कि वह अपने पुराने पद पर कार्य करते रहने से कम वेतन प्राप्त करता। व्यक्तिगत वेतन नई स्केल में किसी दूसरे क्रम पर प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता है।

❧ (6) विलोपित

निर्णय—नियम 261 से 286 के अन्तर्गत परिवार वेतन केवल सीमित अवधि के लिए ही स्वीकृत की जाती है। सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के वेतन को नियमित करते समय उनके परिवार वेतन के प्राप्त करने के तथ्य को इन नियमों के अधीन नहीं गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण (विलोपित)

❧ नियम 26 (क) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर स्थाई (सहस्रान्तिव) स्थाई या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो तथा स्थाई, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में, उसके सेवा, संवर्ग या विभाग में पदोन्नति की नियमित शृंखला में पदोन्नत हो गया हो, तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतनमान, उसके द्वारा अपने पुराने वेतन में एक वार्षिक वृद्धि देकर जो वेतन आवेगा, उससे एक स्टेज आगे पर निश्चित किया जावेगा।

परन्तु यह है कि

(1) कि जहाँ एक राज्य कर्मचारी, अपनी उच्च पद पर पदोन्नति होने के ठीक पूर्व, अपना वेतन निम्न पद के वेतनमान में अधिकतम पर पा रहा हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन उच्च पद के वेतनमान में ऐसी स्टेज पर निश्चित किया जावेगा जो उस उच्च वेतनमान में निम्न पद के अधिकतम से ऊपर हो।

❧ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ 1, 94, वित्त वि (नियम) 66-1 दि. 10-8-69 तथा जांच निदेशन सं. 1, 2, 4, व 6 तथा स्पष्टीकरण विलोपित किया गया तथा दि. 1-1-67 से प्रभावी।

(2) कि इस नियम के प्रावधान, इस नियम के नीचे दी गयी धनुषूची में वर्णित मामलों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सरकार वेतन निर्धारण के ऐसे अन्य तरीके बतला सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे; एवं

(3) कि नियम 35 क के उप-नियम (2) के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहाँ पर प्रारम्भिक वेतन इस नियम के अन्तर्गत निश्चित किया जाता है।

+ (2) नियम 31 के प्रावधानों के रहते हुए भी, जहाँ राज्य कर्मचारी का वेतन उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन निश्चित किया जाता है तो उसकी दूसरी वेतन वृद्धि उस तारीख को स्वीकृत की जाएगी जिससे कि वह, यदि निम्न पद पर कार्य करता रहता तो अपनी वेतन वृद्धि प्राप्त करता। परन्तु चर्च यह है कि जहाँ वेतन, वेतनमान के न्यूनतम पर निश्चित किया जाता है तथा इस प्रकार से निश्चित किया गया वेतन निम्न पद में भगनी वेतन वृद्धि एवं उच्च पद में प्रथम वेतन वृद्धि की राशि के बराबर से निम्न पद में उठाया गया वेतन अधिक होता है तो भगनी वेतन वृद्धि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत पूर्ण वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने वाली सेवा के दूरा होने पर ही दिया जा सकेगा।

(ये संशोधन 1-1-67 से लागू होंगे)

स्पष्टीकरण:—एक समझौता उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क के प्रावधान एक ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए जिसके किसी पूर्व अवसर/अवसरों पर उच्चतर पद को धारण किया था तथा उसी उच्चतर पद पर पदोन्नति पर नियम 26 क के अधीन अधिकृत वेतन से उच्चतर वेतन पर प्राप्त कर रहा था या या वरा ऐसे मामले में वेतन, नियम 26 (क) के परन्तुक के अनुसार स्थिर किया जाएगा।

मामले पर विचार किया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाना है कि दि० 1-4-61 में उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क के प्रावधानों के अधीन ही स्थिर किया जाना है तथा उनका वेतन नियम 26 के अधीन स्थिर नहीं किया जा सकता है यदि वह नियम 26 क के अधीन स्थिर किए गए वेतन से अधिक लाभदायक होता हो।

इस आदेश के जारी होने की तारीख से पूर्व जारी किए गए आदेशों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

निर्णय स० 1:—यह आदेश दिया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन को स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में सचिवालय/राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान उच्च न्यायालय/राजस्थान विधान सभा/राज्यपाल का सचिवालय में दिनांक 31-8-61 को निम्न लिपिक या प्रांशुलिपिक के पद को धारण कर रहा था, उपर्युक्त विभागों/कार्यालयों में क्रमशः बरिष्ठ लिपिक या बरिष्ठ प्रांशु लिपिक के पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में पदोन्नति या नियुक्ति होने पर ऐसी स्टेज पर स्थिर किए जाएंगे जो जिस वेतन को वह प्राप्त कर रहा है उस निम्न पद पर दो वेतन वृद्धि देकर जो प्रकल्पित वेतन आया उससे भगनी स्टेज पर स्थिर किया जाएगा।

+ वित्त विभाग की प्राज्ञा संख्या एक 1 (8) गृह से (व्यय नियम) 67 दिनांक 21 मार्च 1967 द्वारा तथा + दि० 22-1-68 द्वारा परिवर्तित किया गया।

निर्णय सं० 2:—नियम 26 के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय सं० 1 के प्रतिक्रमण में यह आदेश दिया जाता है कि ऐसे अधिकारी का वेतन जो स्थाई या स्थानापन्न रूप में पदों को धारण कर रहा है, (मवन एवं पय) शाखा में मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना या लोक निर्माण विभाग में गिर्चाई शाखा के मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के पद पर स्थायी या स्थानापन्न रूप में परीक्षणित या नियुक्ति होने पर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 क या 35, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन स्थिर किया जाएगा।

+ निर्णय सं० 3 (विलोपित)

अनुसूचि (Schedule)

(1) राजस्थान प्रशासन सेवा (R. A. S.) के अधिकारी जो कि राजस्थान प्रशासन सेवा केडर में सलेक्शन ग्रेड पद पर उन्नत हो गये हों।

(2) राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा (राजस्थान हायर ज्युडिसियल सर्विस) के अधिकारी जो सिविल एण्ड एग्रीकल्चरल सेगमन जज (एवं अन्य समान पदों से), डिस्ट्रिक्ट सेगमन जज पद पर (एवं अन्य समान पदों पर) उन्नत किए गए हों।

(3) नायब तहसीलदार जो तहसीलदार उन्नत कर दिए गए हों।

(4) सेवा में दिनांक 1-9-61 को नियुक्त निम्न लिखित जो 1-9-61 को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधानसभा में उच्च लिपिक के पद पर नियुक्त हो गए हों।

(5) सेवा में दिनांक 1-9-61 को नियुक्त स्टेनोग्राफर जो 1-9-61 को या उसके बाद में सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का सचिवालय एवं राजस्थान विधानसभा में वरिष्ठ स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत हो गए हों।

(6) लोक निर्माण विभाग में अपर मुख्य अभियन्ता (एग्रीकल्चरल चीफ इंजिनियर) जो मवन एवं सड़क (B&R) शाखा में मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना (राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट) या लोक निर्माण विभाग की गिर्चाई शाखा मुख्य अभियन्ता (हैडक्वार्टर्स) के पद पर उन्नत हुए हों।

(7) R.S.S. केडर के सहायक सचिव से उपसचिव, राजस्थान सरकार के पद पर उन्नत हुए हों।

(8) सचिवालय में स्थाई रूप से नियुक्त एक्स्ट्रेड या स्टेनोग्राफर जो अनुभाग अधिकारी (सेक्रेटरी आफीसर) के पद पर उन्नत हो गए हों।

टिप्पणी—आइडम संख्या 7 व 8 में वर्णित उभयतियों के सम्बन्ध में नियम 26 क० के प्रावधान दिनांक 1-4-61 से 31-8-61 तक प्रभावशील समझे जायेंगे। दिनांक 1-9-61 से उनके वेतन मुख्य नियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये जायेंगे। आइडम संख्या 3 से 6 तक के सम्बन्ध में उन्नति होने पर दिनांक 1-4-61 से 31-8-61 तक उन्नति होने पर उनका वेतन मुख्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमित किये हुए समझे जायेंगे एवं उसका प्रावधान दिनांक 1-9-61 से प्रभावशील समझा जावेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश सं० एक 1 (8) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दि० 21-3-67 द्वारा विलोपित तथा दि० 1-1-67 से प्रभावी।

नियम 26 ख—फिर भी, इन नियमों में कुछ दिये गए अनुसार जहां एक राज्य कर्मचारी ने नियम 7 (31) (क) के अन्तर्गत उच्चतर दायित्वों या विदेश प्रकार के कठिनाई के कार्यों को पूरा करने के कारण लगातार रूप से कम से कम 2 वर्ष तक विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह अपने द्वारा धारण किये गये पद के दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों या तो एक पद पर उन्नत या नियुक्त हो जाता है तथा उसका वेतन एवं उच्च पद का विशेष वेतन दोनों मिलाकर, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसके द्वारा धारण किए गए पद से कम है, तो यह अन्तर व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकृत कर दिया जायेगा जो बाद में वार्षिक वृद्धि में शामिल कर लिया जायेगा।

यह संशोधन 1-9-61 से लागू किया हुआ समझा जायेगा।

+ संशोधन—राजस्थान अधीनस्थ सेवा सेवा नियम 1963 के नियम 27 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सेवा निवृत्ति के लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने पर उनके द्वारा आहरित 10 रु० के विशेष वेतन को मर्यादित करने सम्बन्धी प्रश्न कुछ समय पूर्व से सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन लेखा निवृत्तियों द्वारा जो लेखाकार अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त नियमों के अधीन सेवाकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं, आहरित 10 रु० के विशेष वेतन को सेवा निवृत्ति के पद के वेतनमान में आहरित वेतन के प्रयोजनार्थ काल्पनिक रूप से वेतन समझा जाए परन्तु यह है कि जहां इस प्रकार से निकाला गया वेतन (अर्थात् वेतन एवं विशेष वेतन) सेवा निवृत्ति के पद के वेतनमान में समकक्ष स्टेज पर नहीं आता हो तो उसे सेवा निवृत्ति के पद के समय वेतनमान से उच्चतर स्टेज पर स्थिर किया जाएगा।

3. लेखाकार के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन का स्थिरीकरण, उपर्युक्त पैरा 2 में निविष्ट तरीके से वेतन में विशेष वेतन को मिलाकर जो वेतन आया उसके आधार पर नियम 26 क के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

4. ये आदेश दिनांक 1-1-67 से प्रभावी होते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 2 व 3 में दिया गया निर्णय उक्त सेवा निवृत्ति पर लागू नहीं होगा जो लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर नियुक्त हुआ है।

11—वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (29) वित्त वि (व्यय-नियम) दिनांक 18-7-68 के पैरा 2 व 3 के अनुसार, जो सेवा निवृत्ति, लेखाकारों की अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, लेखाकार के पद पर पदोन्नत हो गए हैं, उनके द्वारा आहरित वेतन एवं विशेष वेतन 10 रु० को, लेखाकार के पद पर वेतन के स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।

2—एक प्रश्न यह उत्पन्न किया गया है कि उन वाणिज्यिक सेवा निवृत्तियों को जो कि लेखाकारों की अहंकारी परीक्षा पास करने पर लेखाकार के पद पर पदोन्नत हुए हैं, वित्त तरह समझा जाए।

3—मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि वित्त

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (29) वित्त वि (नियम)/68 दिनांक 18-7-68 व 15-5-69 द्वारा निविष्ट।

वाणिज्यिक लेखा लिपिकों को 15 रु० विशेष वेतन मिलता है, फिर भी, उक्त ग्रहणकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लेखाकार के पद पर वेतन के स्थिरीकरण के प्रयोजनार्थ केवल 10 रु० विशेष वेतन को ही वेतन के रूप में गिना जाएगा तथा तदनुसार पूर्वोक्त आदेश के प्रावधान उनके मामलों में भी लागू होंगे। ये आदेश दिनांक 1-1-67 से लागू होंगे।

4—ये आदेश उन वाणिज्यिक लेखा लिपिकों पर लागू नहीं होंगे जो कि वाणिज्यिक लेखाकार के रूप में नियुक्त/पदोन्नत हुए हैं तथा जो लेखाकार प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेखाकार के पद पर नियुक्त हुए हैं।

स्पष्टीकरण 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी, जिसने कि लगातार कम से कम 2 साल तक नियम 7 (31) (क) के अन्तर्गत विशेष वेतन प्राप्त किया है, यदि वह 1-9-61 को या उसके बाद एक उच्च पद पर उन्नत या नियुक्त कर दिया जाता है तो वेतन निर्धारण में उसके विशेष वेतन को भी गिना जायेगा। एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या लगातार 2 साल की अवधि गिनने में सरकारी अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया समय भी शामिल किया जायेगा।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है नियम 26 त में वर्णित दो साल की अवधि में अधिकारी द्वारा उपभोग किया गया सभी समय शामिल किया जायेगा बशर्ते कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जावे कि वह अधिकारी लगातार विशेष भत्ता प्राप्त करता रहा परन्तु वह अवकाश पर रहना होने के कारण नहीं कर सका।

× 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ख की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है जिसके कि अनुसार जहाँ एक राज्य कर्मचारी को, जिसने कि अधिक उत्तरदायित्वो या विशिष्ट प्रकार की लगातार कम से कम दो साल तक की सेवाएं करने के कारण विशिष्ट वेतन प्राप्त कर लिया है, वह पदोन्नति के समय संरक्षित रखा जाता है जो कि भावी वेतन वृद्धियों में समा-योजित कर दिया जाता है।

इस विभाग के पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें कि एक अधिकारी, अपनी पदोन्नति के पूर्व, एक विशिष्ट वेतन उठा रहा था जिसे कि उसने दो साल की अवधि से कम समय से उठाया था। परन्तु उक्त अवधि के भीतर विशिष्ट वेतन की दर में परिवर्तन हो गया था। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि विशिष्ट वेतन को कौनसी दर (संगोपित या पुरानी दर) को नियम 26 ख के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

मामले की जांच करली गयी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति के ठीक पूर्व विशिष्ट वेतन की राशि को ही नियम 26 ख के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

नियम 27—घटाई गई वेतन की समय अंशला में स्थाई नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक (Initial) वेतन को पुनः नियमित करना (रिपेडेशन)—एक राज्य कर्मचारी जो कि किसी वेतन अंशला में किसी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त हो गया है, यदि उसका प्रारम्भिक मूल वेतन, उक्त पद के कार्य एवं जिम्मेदारियों के कम हुए बिना ही किन्हीं अन्य कारणों से कम हो

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (90) एक डी (व्यय नियम)/ 66 दिनांक 23-12-66 द्वारा शामिल किया गया।

गया है एवं जो इस बटोरी के पूर्ण की वेतन अंशला का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, नियम 26 के प्रावधानों द्वारा नियमित किया जाता है, यद्यपि कि उन नियम के लच्छ (क) के अन्तर्गत आये मामलों में तथा लच्छ (ख) के अधीन सेवा से त्यागपत्र देने, हटाने या हटाने करने के अनिश्चित अन्य मामलों में या तो उनमें—

(1) पूर्व में निम्न पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम किया हो—

(i) उन्नी पद पर, उसके वेतन के टाइम स्केल के कम होने के पूर्व ।

(ii) उसी वेतन अंशला के स्थाई या अस्थायी पद पर उस पद की वेतन अंशला कम न होने पर काम किया हो ।

(iii) सार्वजनिक (टेम्पोर, पद या अस्थायी पद के अनिश्चित एक स्थाई पद पर ऐसी वेतन अंशला में काम किया हो जो कि उस पद पर न पड़े हुए के समान हो । यह अस्थायी पद उसी वेतन अंशला में हो जैसा कि स्थाई पद होना है; या

(2) वह एक ऐसे टेम्पोर (सार्वजनिक) पद पर मूल रूप से नियुक्त ही गया हो जिसकी कि वेतन अंशला (टाइम-स्केल) उस पद की सेवाओं (ट्यूटो) एवं उत्तरदायित्वों को कम किये बिना हो घटा हो गई हो एवं उसने पूर्व में टेम्पोर पद की न पड़ाई गई वेतन अंशला के समान अन्य वेतन अंशला वाले किसी टेम्पोर पद पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से कार्य किया हो तो उसका प्रारम्भिक वेतन, उसके विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या अन्य राशि जो वेतन के वर्गीकरण में आती हो, के अनिश्चित उस वेतन से कम नहीं होगा जिसे कि वह पहिले अवसरों पर नियम 26 के अनुसार प्राप्त करता यदि कम की गई वेतन अंशला प्रारम्भ से ही प्रभावशाली हुई हो । एवं वह वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए उस समय को गिनेगा जिसमें कि वह पूर्व अवसरों पर उस वेतन को प्राप्त करता ।

+ **नियम 27 क.** परिधीला काल में वेतन—जहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 309 के पर-तुक के अधीन निमित सेवा नियमों या सरकार के आदेशों एवं अनुदेशों में परिधीला पर या परिधीलाधीन व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि (इन्फ्री-मेंट) निम्न प्रकार से नियमित की जाएगी—

(1) परिधीला काल में कोई वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

(2) यदि सेवा नियमों या नियुक्ति के आदेशों में परिधीला की निश्चित अवधि निर्धारित की गयी हो तथा विभागीय परीक्षाओं आयोजित न किए जाने के कारण या स्थायीकरण (कन्फर्मेशन) के लिए उपयुक्तता का निर्धारण पुरा न होने पर या अन्य किसी कारण से, स्थायीकरण या परिधीलाकाल की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई विनिष्ट आदेश जारी न किया गया हो तो, परिधीला की निर्धारित अवधि के बाद प्रारम्भिक दर पर वेतन उठाये जाने की स्वीकृति दे दी जाएगी जब तक कि स्थायीकरण, परिधीलाकाल की वृद्धि या सेवा समाप्ति का विनिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (94) एक. डी. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 31 दिसम्बर 1966 द्वारा परिवर्तित किया गया । ये संशोधन 1-1-67 में प्रभावशाली होगा ।

(3) परिबीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थायीकरण के आदेशों के जारी किए जाने पर, जो वेतन वृद्धियां सामान्य रूप से बकाया होंगी, वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेंगी ।

(4) परिबीक्षा की निश्चित अवधि की समाप्ति से प्रभावशील स्थायीकरण के आदेशों के जारी किए जाने पर तथा उसके द्वारा परिबीक्षाकाल में वृद्धि की गयी हो तो, वेतन वृद्धियां जो सामान्य रूप से बकाया होंगी वे पूर्व प्रभाव से स्वीकृत की जायेंगी सिवाय इसके कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के उठाये जाने की सामान्य तारीख उत्तम हो दिनों के बराबर हो जायेंगी जितने समय की कि परिबीक्षा काल में वृद्धि की गयी है ।

× (5) उपर्युक्त पैरा (4) के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, जिसका प्रारम्भिक वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के उपनियम (1) के पैरा क (2) एवं ए (2) के अधीन निश्चित किया गया हो, वहां अपनी अन्तिम वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से अपने पूर्व पद पर की गई पूर्ण सेवा की मबोन पद में वेतन वृद्धि दिये जाने के प्रयोजनार्थ गिनी जायेंगी ।

नियम 28. एक पद के वेतन परिवर्तित होने पर वेतन की नियमित करना—यदि किसी पद का वेतन बढ़ा दिया जाय तो उस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को नए वेतन के नए पद पर स्थानान्तरित किया हुआ समझा जावेगा । परन्तु शर्त यह है कि वह अपनी इच्छानुसार अपने पुराने वेतन को उसी शृंखला में अगली वार्षिकोन्नति के समय तक या अन्य किसी और अग्रिम वार्षिकोन्नति के समय तक रख सकता है । या वह अपनी इच्छानुसार उस पद को अपने पद के खाली होने के समय तक या उस वेतन शृंखला की अधिकतम धनराशि तक रख सकता है । एक बार दिये गए आप्त्तन की अन्तिम समझा जायेंगी ।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में जो एक ऐसी तारीख को उच्च वेतन शृंखला में कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो जिसमें कि एक ही बेडर में विभिन्न वेतन शृंखलाओं वाले अनेकों पदों को एक कर दिया हो, तो नियम के प्रावधान में आये हुए 'उसके पुराने वेतन' का तात्पर्य केवल उसमें उस प्रामाणिक तिथि को प्राप्त कर रहे अपने कार्यवाहक वेतन की दर को ही शामिल नहीं किया जावेगा लेकिन उसमें वेतन की उस शृंखला को भी शामिल किया जावेगा जिसमें वह उस वेतन को प्राप्त कर रहा था । इस प्रकार आप्त्तन (विक्स्प) की अवधि के लिए उसकी पुरानी शृंखला को ही, जिसमें कि वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था, सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में धातु रखा हुआ समझा जावेगा और चूंकि वह उस अवधि में अपने पुराने वेतन को रखने का अधिकारी है, तो आप्त्तन के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा वेतन इस पर निर्भर नहीं करता है कि उस प्रामाणिक तिथि के बाद से उस कार्यवाहक नियुक्ति का कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण रहता है या नहीं । फिर भी यह आप्त्तन उस समय समाप्त हो जाता है जब एक बार सम्बन्धित व्यक्ति उस पद पर कार्य करना बन्द कर देता है या जिस शृंखला में वह अपना कार्यवाहक वेतन प्राप्त कर रहा था उसमें अपना वेतन प्राप्त करना बन्द कर देता है ।

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ । (94) वित्त विभाग (नियम) 66 I दिनांक 16-8-66 द्वारा प्रतिस्थापित । दिनांक 1-1-67 से प्रभावी ।

इस नियम का मूल भाग एवं उसका प्रावधान दोनों ही एक साथ एक समय पर प्रभावशील नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिस अवधि में प्राप्तन भरा जाना है वह अवधि प्रावधान के अन्तर्गत प्रभावशील होती है तथा उस समय नियम का मूल भाग प्रभावशील नहीं होता है। किसी भी कारण से प्राप्तन न देने की स्थिति में नियम के लाभ नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं।

जांच निर्देशन:—(1) यह नियम एक पद पर कार्यवाहक रूप में तथा स्थाई रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

(2) यदि किसी पद का अधिकतम वेतन, वार्षिक वृद्धि एवं ग्यूनरम वेतन में बिना परिवर्तन किए ही, बदल दिया जाता है, तो उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन नियम 26 (ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए न कि नियम 26 (क) के अन्तर्गत, चाहे वह उस पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो।

(3) इस नियम के प्रावधान में प्रयुक्त "पुरानी वेतन शृंखला में परवर्ती वार्षिक वृद्धि" में उन मामलों की 'श्रेणी वृद्धि' (Grade Promotion) भी शामिल हैं जिनमें वेतन की समय शृंखला किसी वेतन की 'श्रेणी वृद्धि' शृंखला में परिवर्तित हो गई हो।

(4) नियम 26 के नीचे दी गई जांच निर्देशन संख्या (1) को भी देखें।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या नियमित किये गये राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत नियन्त्रण काल में परिवर्तित वेतन शृंखला को अपनाते की स्वीकृति दी जा सकती है यदि उसको नियमित किए जाने के पूर्व ही उसके पद का वेतन परिवर्तित किया गया हो। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों का निम्न निम्न तरीके से करना चाहिये:—

(1) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला नियन्त्रण की तारीख से पहले से ही विधानित होती हो—

ऐसे मामलों में एक राज्य कर्मचारी को, नियम 28 के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला के लिये प्राप्तन भरने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत, प्राप्तन भरने की स्वीकृति दी जानी चाहिये चाहे जिस समय वह अपना प्राप्तन भर कर देता है, वह उसके नियन्त्रण की अवधि में ही होता हो। तथा इस प्राप्तन के परिणामस्वरूप, नियन्त्रण के पूर्व की तारीख के लिए यदि कोई उसे फायदा पहुंचता हो, तो वह उसे मिलेगा तथा उस वृद्धि का लाभ, उसे नियन्त्रण काल की अवधि में, निर्वाह भत्ता (Subsistence allowance) से भी मिलेगा।

(2) ऐसे मामले जिनमें परिवर्तित वेतन शृंखला नियन्त्रण की अवधि में भी प्रभावशील होती है—

(क) नियन्त्रण काल में एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन अपने स्थाई पद पर रखता है। चूंकि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 में प्रयुक्त "पद को धारण करने वाला" शब्द में वह व्यक्ति भी शामिल है जो एक पद पर अपना लीयन या नियन्त्रित लीयन रखता है चाहे वह वास्तव में उस पद पर कार्य न कर रहा हो, एक ऐसे राज्य कर्मचारी को, उसके नियन्त्रण काल में भी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 के अन्तर्गत या परिवर्तित वेतन शृंखला में प्राप्तन

भरने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये । फिर भी निलम्बन काल की अवधि के लिये प्राप्त करने का लाभ केवल उसके बहाल (Reinstatements) होने पर इस तथ्य पर आधारित होगा कि क्या निलम्बन का समय उसके लिए छूटी के रूप में समझा जायेगा या नहीं ।

(ख) यदि किसी पद का वेतन परिवर्तित हो जाता है तथा उस पर एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन नहीं रखता है तो वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 28 या परिवर्तित वेतन श्रृंखला में प्राप्त करने सम्बन्धित किसी अन्य विशेष नियम के अन्तर्गत अपना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । फिर भी यदि वह उस पद पर बहाल हो जाता है तथा उसके निलम्बन के समय की सेवा (छूटी) के रूप में समझ लिया जाता है, तो बहाल होने के बाद उसे अपना प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है । ऐसे मामले में, जिनमें प्राप्त भर कर देने की कोई समयावधि दी हुई हो तथा यह समय उसका निलम्बन काल में ही व्यतीत हो जाता है तो सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में प्राप्त करने के लिए अवधि को बढ़ा सकती है ।

+ **नियम 29.** जब तक वार्षिक वृद्धि (इन्फ्लैट) रोकनी न जाए वह प्राप्त की जाती रहनी चाहिये—नियम 26क, 27क एवं 30 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जब तक योजाकरण, नियंत्रण एवं अपील (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार वार्षिकोत्पत्ति रोकने के लिए समस्त अधिकारी द्वारा यह न रोकदी जाये, एक राज्य कर्मचारी को उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हमेशा मिलती रहेगी । वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश में उसकी रोक जाने की अवधि का उल्लेख किया जायेगा तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि क्या उस रोक गई वार्षिक वेतन वृद्धि से भावी वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने में भी प्रभाव पड़ेगा ।

(उपयुक्त नियम में प्रथम वंक्ति में सामिल किया गया संशोधन दि० 1-1-67 से प्रभाव-शील होगा ।)

—नियम संख्या 1—प्रस्थापी आधार पर वेतन प्राप्त कर्ता राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि दररा के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को समय समय पर ऐसे पदों पर, जिन्हें कि राजस्थान लोकसेवा आयोग या विभागीय प्रमोशन कमेटी द्वारा भरा जाना चाहिये या लेकिन जो अब तक नहीं भरे गए हैं, नियुक्त किए गए राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रस्थाई आधार पर मासिक वेतन (मेलेरी) के अगस्तन स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है । एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या उक्त अधिकारियों को अपनी वेतन वृद्धि उन पदों के वेतन मान में उठानी चाहिये जिनमें कि बंधन प्रस्थाई तौर पर अपना वेतन उठा रहे हैं । अब तक उक्त वेतन वृद्धि नहीं दी गई है । मामले की पुनर्जांच करती गई है तथा अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 29 के अनुसार अन्य अधिकारियों की भांति वेतन वृद्धि प्राप्त करनी चाहिए । अतः उन समस्त अधिकारियों का मासिक वेतन, जिसे

+ वित्त विभाग के आदेश स. एक 1 (8) वित्त वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21-3-67 द्वारा संशोधित ।

— वित्त विभाग की अधिपति संख्या एक. 1 (39) एक डी./ (व्यय-नियम) 65 दिनांक 11-1-68 द्वारा निविष्ट ।

उन्होंने धन्यवाई और पर प्राप्त किया है, पुनः फिर त किया जाना चाहिये तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के बकायो का भुगतान कर दिया जाए। नियम में वेतन वृद्धि जब भी वे वांछित हों, दी जावे।

[राजस्थान राज्य कर्मचारीयों द्वारा त ॥ (20) धराशास्त्र कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि प्राप्त करने के तरीके के लिए सामान्य वितीय एवं सेवा नियमों के नियम प्रमाण: 162 एवं 168-169 देखिये]

+ नियम 30. एग्जिस्टिंग बार (दस्ता अवरोध) पार करना-जब किसी वेतन शृंखला में दस्ता अवरोध (एग्जिस्टिंग बार) पार करने का प्रावधान हो, तो उस प्रतिव्यय की अगली वार्षिक वृद्धि, उसे रोकने में सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी राज्य कर्मचारी को नहीं दी जायेगी। जब किसी ऐसे राज्य कर्मचारी को दस्ता अवरोध पार करने की स्वीकृति दे दी गई हो जिसे पहिले उसके विपरीत प्रभावशाल किया गया हो, तो वह अपना वेतन उस वेतन शृंखला में उस स्टेज पर प्राप्त करेगा जिस पर कि वार्षिक वृद्धि रोकने वाला सक्षम प्राधिकारी निश्चिन करे। इससे कि इस प्रकार का निश्चिन किया गया वेतन उस वेतन से ज्यादा नहीं होगा जिसे वह अपनी दस्ता अवरोध न रोके आगे पर प्राप्त करता।

टिप्पणियाँ—(1) प्रत्येक अवसर पर जबकि एक राज्य कर्मचारी को ऐसी दस्ता अवरोध (एग्जिस्टिंग बार) पार करने की स्वीकृति दी जाती है जो कि पूर्व में उसके विपरीत लगाया गया था, तो उसका वेतन शृंखला में उस स्टेज पर वेतन, प्रतिव्यय हटाने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चिन किया जादगा जो कि उसे उगने सेवाशान के अनुसार प्राप्त हो सकता है।

(2) दस्ता अवरोध (एग्जिस्टिंग बार) पर रके हुए सभी राज्य कर्मचारियों के मामलों का हर वर्ष अवलोकन किया जाना चाहिये ताकि यह निश्चिन किया जा सके कि क्या उनके कार्य की प्रगति सुदरी है या सामान्यतया यह देखा जाना चाहिए कि क्या उन कर्मियों के कारण उनकी एग्जिस्टिंग बार रोकी गई है, वे कमियां दूर हो गई हैं जिससे कि प्रतिव्यय ममत्र किया जा सके। यदि वे बाद में दस्ता अवरोध की वार्षिक वृद्धि स्वीकर करें तो उसे वह पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये।

× नियम—विन गोप गध पुग हो। ठक क विचारधीन रखते हुए दस्ता अवरोध (एग्जिस्टिंग बार) पर वेतन वृद्धि रोकना।

निर्णय संख्या 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के अनुसार दस्ता अवरोध के धार्मिक धर्मगी दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि की रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी की विनिष्ट स्वीकृति के बिना राज्य कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। दस्ता अवरोध पर वेतन वृद्धि रोका जाना राजस्थान विविध अधिमेत्र (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं धर्मील) नियम, 1558 के अधीन कोई धाम्ति नहीं है। जब किसी राज्य कर्मचारी का समय दस्ता अवरोध को पार करने का हो तथा

+ वित्त विभाग के धादेन सं० एक. 1 (94) एक. डी. (ध्वय नियम) 66 दिनांक 31-12-66 द्वारा मनीषित किया गया।

× वित्त विभाग के धादेन सं० एक. 1 (98) एक. डी. (ध्वय नियम), 66 दि० 6 दारवरी 1967 द्वारा धाम्तिन किया गया।

उस समय उसके विपरीत विभागीय जांच अभी विचाराधीन हो, तो उस दशा में निम्नलिखित वैकल्पिक कदम उठाये जा सकते हैं ।

(क) यदि विभागीय जांच राज्य कर्मचारी की सामान्य दक्षता या सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित किसी विशिष्ट विषय पर हो, अर्थात् जैसे सेवा में उपेक्षा किए जाने के विशिष्ट उदाहरण या राजकीय आदेश की अनुपालना न करने के बारे में हो, तब उसे दक्षता अवरोध पार करने की स्वीकृति दी जा सकती है क्योंकि वह उस पर बाद में उचित छास्ति आरोपित कर सकता है ।

(ख) यदि विभागीय जांच ऐसी सामान्य दक्षता या गवर्न या मिनिमल अवरोध से सम्बन्धित हो कि वेतन वृद्धि रोक सकने में सक्षम प्राधिकारी की राय में, सम्मीर प्रकृति के हैं, तब दक्षता अवरोध को रोकने के लिए, छास्ति आरोपित करने के आदेश के साथ, एक विशिष्ट आदेश होना चाहिये । यदि दक्षता अवरोध पार करने के बकाया होने के समय विभागीय जांच विचाराधीन हो तो उस समय दक्षता अवरोध पर वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिये जाने चाहिये । विभागीय जांच की समाप्ति पर यदि राज्य कर्मचारी दोष मुक्त कर दिया जाता है या उसके विपरीत सम्मीर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो राज्य कर्मचारी को दक्षता अवरोध पार करने में प्रश्न पर जांच की जा सकती है तथा दक्षता अवरोध पार करने तथा वेतन वृद्धि पूर्व प्रभाव से विभागीय जांच में सिद्ध आरोपों के प्रसंग में स्वीकृति की जानी चाहिये ।

× निर्णय संख्या 2—जहां सरकारी कर्मचारियों को अनन्तिम आधार (प्रोबेशनल बेसिस) पर सेलेरी के भुगतान एवं वेतन वृद्धि के लिए प्राधिकृत किया जाता है वहां उन्हें दक्षता अवरोध पार करने की भी अनुमति दी जा सकती है यदि वह उस वेतनमान में लागू होती है परन्तु यह है कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा दक्षतावरोध की स्टेज पर पहुँचने तक की गई सेवा सन्तोषप्रद हो तथा दक्षतावरोध पार करने की शर्तें (यदि कोई हों) पूर्ण की जाती हों

नियम 31 टाइम स्केल (समय वेतनमान) में वेतन वृद्धि (Increments) के लिए सेवा को गिना जाना—निम्नलिखित प्रावधानों में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिन पर समय वेतनमान के वेतन वृद्धि के लिए सेवा को गिना जाता है—

31(क) किसी समय वेतनमान में किसी पद पर चुकी हुई उस समय वेतन मान में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है । परन्तु यह है कि उस समय वेतन मान में अगली वेतन वृद्धि की तारीख निकालने के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त अवधियों का योग जो उस समय वेतन मान में वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है, वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख से जोड़ा जाएगा । नियमों के अधीन वेतन वृद्धि की तारीख गिनने को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण नीचे दिया जाता है—

उदाहरण

गत वेतन वृद्धि की तारीख		
23-4-1964		
जो अपारण अवकाश जो वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता है		
दिन	से	तक
3	29- 5-64	31- 5-64
8	15- 7-64	20- 7-64

× वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एक 1 (39) वित्त वि (नियम) 65 दि० 9-7-68 द्वारा शासित
38 वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (55) वित्त वि नियम/68 दि० 16-11-68 द्वारा प्रतिस्थापित

9	7-10-64	15-10-64
4	18-12-64	21-12-64
3	26- 1-65	28- 1-65
4	16- 3-65	19- 3-65

29

पुराने नियमों तथा संशोधित नियमों के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि की तारीख निम्न प्रकार से निश्चित की जाएगी—

पुराना नियम

इंफ्लूटो की अवधि

	तक	माह	दिन
23- 4-64	28- 5-64	1	6
1- 6-64	14- 7-64	1	14
21- 7-64	6-10-64	2	16
16-10-64	17-12-64	2	2
22-12-64	25- 1-65	1	4
27- 1-65	15- 3-65	1	15
20- 3-65	22- 5-65	2	3

12 (00)

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-5-65

संशोधित नियम

नए वेतन वृद्धि की तारीख 23-4-64

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23-4-65

(असाधारण अवकाश को छोड़कर) 29

असाधारण अवकाश के दिन

अगली वेतन वृद्धि की तारीख 23 4-65 + .9 दिन = अर्थात् 22-5-65

(ल) (i) नियम 20 के उप खण्ड (1) में वर्णन किए गए कम वेतन वाले पद के अनि-
रिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे वह स्थायी या अस्थाई रूप में हो, भारत के बाहर प्रति-
निधुक्ति पर की गई सेवा एव मेडिकल प्रमाण पत्र पर असाधारण अवकाश (Extra ordinary
leave) को छोड़ कर, अन्य अवकाश, उस पद के समय वेतनमान (टारगट स्केल) में वेतन वृद्धि
के लिए गिना जाएगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, तथा, यदि कोई हो
तो, उस पद या उन पदों के समय वेतनमान में भी वेतन-वृद्धि के लिए लागू होगा जिस पर कि
यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया गया होता तो वह अपना लीयन रखता।

(ii) मेडिकल प्रमाण पत्र पर लिए गए अवकाश के अनिरिक्त अन्य असाधारण अवकाश को
छोड़कर, अन्य सम्पूर्ण अवकाश एवं भारत के बाहर प्रतिनिधुक्ति का समय, दोसे एक पद से लिए

लागू होने वाले समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए, शामिल किया जायेगा जिस पर कि राज्य कर्मचारी जिस समय वह अवकाश पर रवाना हुआ या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गया, कार्य-वाहक के रूप में कार्य कर रहा था एवं जिस पक्ष पर वह अपना लोयन रखता परन्तु अपने अवकाश पर चले जाने के कारण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रवाना होने के कारण नहीं रख सका।

+ परन्तु शर्त यह है कि व्यक्तिगत मामलों में सामान्य आदेश या विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि खण्ड (1) या (2) के अन्तर्गत असाधारण अवकाश वेतन-वृद्धि के लिए गिना जाएगा यदि ऐसा अवकाश निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण-वश उपयोग किया गया हो:—

- (1) राज्य कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर का कोई भी कारण
- (2) किसी भी राज्य कर्मचारी द्वारा विज्ञान में या कला में एम. ए. की डिग्री की स्टेज के आगे उच्चतर वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखना।
- (3) इंग्लिनियरिंग, माइन्स, आर्कॉटेक्चर, कृषि, वेटेनरी, साइंस या मेडीसिन में स्नातक की डिग्री से आगे उच्च तकनीकी या वैज्ञानिक अध्ययन चालू रखना।
- (4) शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना।

(क) शिक्षा में एम. ए. की डिग्री

(ख) व्यायाम शिक्षा (फिजिकल एजुकेशन) में स्नातक की डिग्री

(ग) शिक्षा/अध्यापन में स्नातक की डिग्री

(घ) शिक्षा शास्त्री की डिग्री

(ङ) अध्यापन (टीचिंग) में प्रमाण पत्र

(च) व्यायाम शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट

(छ) पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट

(ज) संशुल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश, हैदराबाद द्वारा आयोजित अंग्रेजी के अध्यापन में पोस्ट ग्रेजुएट/डिप्लोमा (9 माह का कोर्स)

(5) शिक्षा विभाग के अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक प्रशिक्षण में जाना—

(क) बेसिक एन. टी. सी. प्रशिक्षण

(ख) मोंटसरी ट्रेनिंग

(ग) बहुरी, गुरूओं एवं अन्यो को पढ़ाने का प्रशिक्षण

(घ) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स, पटियाला द्वारा आयोजित खेलों का प्रशिक्षण (9 माह का पाठ्यक्रम)

(ङ) नेशनल काउन्सिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड इनिशिएटिव, देहली द्वारा आयोजित रिसर्च एवं मॅथेडोलॉजी में प्रशिक्षण।

+ वित्त विभाग के आदेश मर्यादा एक 1 (71) एक डी (व्यव-नियम) 66 दिनांक 28-10-66 द्वारा परिवर्तित किया गया।

(ग) यदि कोई राज्य कर्मचारी जब वह वेतन के समय वेतनमान वाले एक पद पर कार्य-वाहक रूप में कार्य कर रहा हो या एक स्थाई पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसकी नियुक्ति उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में की गई हो या उसे उच्च स्थाई पद पर लगाया गया हो, तथा यदि वह निम्न पद पर पुनः नियुक्त कर दिया जाता है या वेतन के समान समय वेतनमान वाले पद पर पुनः नियुक्त हो जाता है तो उसकी उच्च पद की कार्यवाहक या अस्थाई सेवा, ऐसे निम्न पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाएगी, फिर भी, उच्च पद पर कार्यवाहक के रूप में की गई सेवा, जो कि निम्न पद में वेतन वृद्धि के लिए गिनी जाती है, उस अवधि तक सीमित रहेगी जिसमें कि राज्य कर्मचारी निम्न पद में कार्यवाहक रूप में कार्य करता परन्तु उसकी उन्नति उच्च पद पर होने के कारण वह नहीं कर सका। यह लक्ष्य एक ऐसे राज्य कर्मचारी पर भी लागू होता है जो वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति के समय निम्न पद पर कार्य-वाहक रूप में कार्य नहीं करता हो लेकिन यदि वह उच्च पद पर नियुक्त न किया गया होता तो वह ऐसे निम्न पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करता होता या उसी के समान समय वेतनमान में पद पर कार्य करता रहता।

(घ) निम्नलिखित वर्गों पर लागू होने वाले, समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए विदेशी सेवा गिनी जाएगी—

(1) राज्य सेवा में ऐसा पद जिस पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता है, या ऐसा पद या बहुत से पद, यदि कोई हों जिस पर वह अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं होता।

(2) राज्य सेवा में ऐसा पद, जिस पर विदेशी सेवा में स्थानान्तरण होने में कुछ ही समय पूर्व, वह राज्य कर्मचारी कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था क्योंकि उसने समय तक वह उस पर या उसी समान समय वेतनमान के पद पर कार्यवाहक रूप में लगातार कार्य करता रहना लेकिन वह विदेशी सेवा में प्रस्थान कर गया, एवं

(3) कोई पद जिस पर कि वह ऐसी उन्नति (Promotion) की अवधि के लिए नियम 143 के अन्तर्गत कार्यवाहक उन्नति प्राप्त कर सकता हो।

(ङ) सेवा पर कार्यग्रहण बाल का समय (अवाइनिंग टाइम) वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है—

(1) यदि वह ऐसे पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में नियम 127 के लक्ष्य (1) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि एक राज्य कर्मचारी अपना लीयन रखता हो या यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तो वह उस पर अपना लीयन रखता। इसके अलावा उस पद पर लागू होने वाले समय वेतनमान में भी वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा, जिसका कि वेतन राज्य कर्मचारी समय पर प्राप्त करता है, एवं

(2) यदि वह उस पद या वर्गों पर लागू होने वाले समय वेतनमान में नियम 127 के लक्ष्य (2) के अन्तर्गत आता हो जिस पर कि कार्यग्रहण बाल प्रारम्भ होने (अवाइनिंग टाइम) के पहिले का अवकाश का अन्तिम दिन वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता हो।

+ स्पष्टीकरण—[विलोपित]

जांच निर्देशन—(1) अवकाश से अधिक दिन तक ठहरने का समय किसी समय वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा जब तक कि वह समय सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा भ्रसाधारण अवकाश में रूपान्तरित नहीं कर दिया जाता है एवं जब तक कि नियम 31 के उप-नियम (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत भ्रसाधारण अवकाश विशेष रूप से वेतन वृद्धि में शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत नहीं कर दिया जाता है।

(2) एक राज्य कर्मचारी जबकि वह एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा है तथा दूसरे पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर दिया गया हो तो एक पद से दूसरे पद पर खाना होने के लिए कार्य ग्रहण करते समय (ज्वाइनिंग टाइम) उसी पद पर कर्त्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए जिस पर कि राज्य कर्मचारी उस समय का वेतन प्राप्त करता है एवं वह समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 (क) के अनुसार उसी पद का गिना जावेगा। फिर भी यदि दोनों पदों का वेतन दर एक ही होती है तो एक पद से दूसरे पद के लिए खाना होने का कार्य ग्रहण करने का समय (ज्वाइनिंग टाइम) दोनों में से निम्न पद में कर्त्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए तथा नियम 31 (ग) के अन्तर्गत उसे निम्न पद में वेतन वृद्धि के लिए गिना जावेगा।

(3) यदि कोई राज्य कर्मचारी जो कि किसी पद पर कार्यवाहक रूप में काम करते हुए एक प्रशिक्षण पर खाना होता है या किसी निर्देशन के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए खाना होता है तथा जो, प्रशिक्षण काल में रहते हुए कर्त्तव्य के रूप में माना जाता है, तो इस प्रकार के कर्त्तव्य का समय उस पद में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा जिस पर कि प्रशिक्षण या निर्देशन प्राप्त करने के लिए भेजे जाने के पूर्व वह कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा था, यदि उसे प्रशिक्षण काल में कार्यवाहक पद का वेतन ही स्वीकृत कर दिया जावे।

+ (4) विलोपित—

+ (5) विलोपित—

स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 के नीचे दिये गए जांच निर्देशन सं. 5 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है जिसके कि अनुसार यदि कोई परिबीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) बारह माह से अधिक परिबीक्षा समय के अतीत होने पर स्याई (कम्प्लेंट) कर दिया जाता है, तो वह पूर्व प्रभाव से वेतन-वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है जिसे कि वह साधारण रूप में प्राप्त करता रहता लेकिन प्रोबेशन पर रहने के कारण प्राप्त न कर सका।

इस सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किए गए हैं कि क्या उपरोक्त प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जहाँ पर कि एक परिबीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशन) का परिबीक्षा (प्रोबेशनरी) का समय बका दिया गया हो यहाँ कि इस कार्य के लिए निर्धारित समयावधि में वह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जांच निर्देशन में दिए गए प्रावधान केवल उन्ही मामलों

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एक 1 (94) वित्त विभाग (नियम) 66 I दिनांक 16-8-69 से स्पष्टीकरण जांच निर्देशन संख्या 4 व 5 विलोपित। यह दि० 1-1-67 से प्रभावो होता।

पर लागू होंगे जहाँ पर माधारण परीक्षा (प्रोवेनन) का समय स्वतः ही 12 माह से अधिक है। ये प्रावधान पूर्वोक्त अवसरण से वर्णित दशा पर लागू नहीं होंगे। दूसरे मामलों में, ऐसे मामलों में जहाँ परीक्षा का समय माधारणतः 12 माह से अधिक है, स्थाई होने पर अधिकारियों को वेतन वृद्धि दी जा सकती है जिसे कि वह माधारण रूप में प्राप्त कर लेता परन्तु प्रोवेनन पर रहने के कारण प्राप्त न कर सका। इस सम्बन्ध में अधिकारी को उसके पूर्व प्रभाव के बकाया (एरियर) भी मंजूर किए जायेंगे। दूसरी ओर इसके विपरीत जैसा कि पूर्व अवसरण में कहा गया है, कि विभागीय परीक्षा पास करने में असफल होने के कारण प्रोवेनन का समय बढ़ाए जाने वाले मामलों में बढ़ाई गई परीक्षा की सफलता पर स्थाई करने पर, इस माध्यम पर कि अधिकारी कुछ प्राप्त करता परन्तु वह प्रोवेनन पर रहा, उसके वेतन एवं वेतन-वृद्धि को नियमित करने में कोई सहायता नहीं है। परन्तु उसे स्थाई होने की तिथि से पूर्व का कोई भी बकाया इस सम्बन्ध का नहीं दिया जावेगा। इसका अर्थ यह होगा कि अधिकारी को वेतन-वृद्धि विभागीय परीक्षा में असफल रहने के कारण बिना दूसरी वेतन-वृद्धि पर प्रभाव डाले रोक दी गई है जो कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (बर्गीकरण, नियन्त्रण एवं प्रतीन) नियम, 1958 के नियम 14 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अर्थ में मान्य (पिनेस्टी) के रूप होगी।

नियम 26 के नीचे जाब निर्देशन सं० 5 भी देखिए।

(विशेष—इस नियम में समय समय पर परिवर्तन होने रहे हैं। सभी मसौदों के बाद अन्तिम मसौदों सहित उक्त नियम को रखा गया है)

नियम 32. निर्धारित तिथि से पूर्व वार्षिक वृद्धियाँ (Pre-mature increments):— एक अधिकारी जो किसी निश्चित वेतन श्रेणी में एक संवर्ग (केडर) में पद का सृजन (Creation) करने की शक्ति रखता है, वह उस वेतन की समय श्रेणी में किसी भी राज्य कर्मचारी की निर्धारित तिथि से पूर्व ही वार्षिकोत्पत्ति स्वीकार कर सकता है।

× विषय—सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धीकरण के कारण उत्पन्न विषयताओं का, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के अधीन निराकरण।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के, राजस्थान सिविल सेवा (संगोपित वेतनमान) नियम, 1961, नवीन वेतनमान नियम, 1969 के लागू करने के फलस्वरूप ऐसे अवसर प्राप्त हैं जिनमें उपर्युक्त में से कहीं भी नियमों के लागू करने से सरकारी कर्मचारियों का वेतन उससे अनिष्ट सरकारी कर्मचारियों के वेतन की अपेक्षाकृत एक स्टेज कम पर स्थिर किया गया था। वरिष्ठ/कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विषय-ताओं को दूर करने के लिए यह तय किया गया है कि वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के लिए स्थिर किए गए वेतन के समान राशि तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, यह राशि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा धारित पद पर मंजूरायी नियुक्ति करने में सफल अधिकारी द्वारा उस तारीख से बढ़ाई जानी चाहिए जिसको कि कनिष्ठ कर्मचारी अधिक वेतन प्राप्त करना प्रारम्भ करता है:—

× वित्त विभाग की अधिवृचना संख्या एक। (8) वित्त वि (अर्थ-नियम) 67 द्वारा निविष्ट।

(1) विषमता सीधी उपर्युक्त नियमों के लागू करने के कारण होनी चाहिए तथा वेतन में वृद्धि केवल उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए जिनमें कि कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति/पदोन्नति नियमित तथा भारत के संविधान के अनु. 309 के परन्तुक के अधीन जारी किए गये संबन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार हो या एतदर्थ आधार हो।

(2) वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारियों को पदों के एक ही संवर्ग/श्रेणी से सम्बन्धित होना चाहिए तथा एक ही विभाग/सेवा में सेवा करते रहना चाहिए तथा उसी सम्बन्धित पदोन्नतियों से पूर्व एक ही वेतनमान में वेतन प्राप्त करना चाहिए।

(3) दोनों सरकारी कर्मचारियों को एक ही विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहना चाहिए।

(4) इस निर्णय के अधीन लाभ केवल उसी समय दिया जाएगा जब यह प्रमाणित कर दिया जाए कि वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के बारे में कोई विवाद न हो।

(5) जहाँ कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को एतदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के कारण इन आदेशों के अधीन वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाता है तो वह वृद्धि इस बात के साथ की जा सकती है कि यदि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की एतदर्थ पदोन्नति नियमानुसार नियमित पदोन्नति के रूप में परिवर्तित नहीं की जाती है तथा वह प्रत्यावर्तित हो जाता है तो कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन की तारीख से वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उस स्टेज पर पुनः स्थिर किया जा सकेगा जिस पर कि, यदि उसकी वेतन में वृद्धि नहीं की जाती तो वह अपना वेतन प्राप्त करता रहता।

(2) इस निर्णय में अन्तर्विष्ट प्रावधान निम्नलिखित मामलों में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने में लागू नहीं किए जाएंगे।

(क) जहाँ कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अवकाश रिक्ति या उच्च पद के धारक के प्रसिद्धाण के लिए, जो कि 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, या किसी अन्य परिस्थिति में जहाँ उच्च पद केवल 120 दिन की अवधि तक ही धारण किया जाता हो, रवाना होने के कारण अस्थावधिक रिक्ति के दौरान उच्च पद को धारण कर रहा हो।

(ख) जहाँ कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी, अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किए जाने के कारण या अन्यथा प्राप्त करने के लिए उच्च प्रारम्भिक वेतन देने या निर्धारित परीक्षा पास करने या किसी अन्य कारण से जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 या 26 क, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन मान,) नियम, 1961 या नवीन वेतन मान नियम, 1969 के अधीन वेतन स्थिरीकरण के कारण न हो, वरिष्ठ कर्मचारी की अपेक्षाकृत उच्च दर पर पहिले से ही अधिक वेतन प्राप्त करता है।

(ग) जहाँ कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी मिश्र संवर्ग में पद धारण करता है तथा उस पद के जिस पर कि वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पहिले से ही नियुक्त किया हुआ है, संवर्ग/श्रेणी के प्रति-रिक्त अन्य संवर्ग/पदों की श्रेणी में नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 'क' (वरिष्ठ) कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत हो गया तथा उसके बाद, जिस तारीख को वह (कनिष्ठ) वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था, उस तारीख को या उसके पूर्व वह

सेवापर के पद पर नियुक्त हो गया हो तो वरिष्ठ व्यक्ति की सेवाकार के रूप में तथा वनिष्ठ की वरिष्ठ लिपि के रूप में उनके वेतन में कोई तुलना नहीं होगी ।

(घ) जहाँ वनिष्ठ सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतन मान) नियम 1969 के नियम 12 के अधीन 111 वर्ष के भीतर उनकी भावी सेवा निवृत्ति को ध्यान में रखते हुए एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है ।

(3) इन निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को पुनः स्थिर करने के आदेश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 के अधीन जारी किए जाएंगे । वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि उक्त नियम 31 के अधीन वेतन के पुनः स्थिरीकरण की तारीख में पूर्ण अर्ह-कारी सेवा पूरी करने पर आहरित की जाएगी ।

टिप्पणियाँ—(1) वार्षिक उन्नति अग्रिम रूप में स्वीकार करने के मामलों में प्रायः यह धराशा रहता है कि राज्य कर्मचारी उन्नीस वर्ष में भावी वार्षिक उन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता चाहिए जैसे कि मानों वह शृंखला में उस स्थिति पर अग्रिम वार्षिक वृद्धि स्वीकार करने से साधारण रूप में पहुँच चुका हो एवं इसके विपरीत अन्यथा प्रकार के आदेशों के अभाव में भावी वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में टीक दसी स्थान पर रखा जाना चाहिए जिस रूप में कि राज्य कर्मचारी इस प्रकार पहुँचता है । दूसरे शब्दों में जैसे दूसरी वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने से पहले उसे एक वर्ष तक पूरी सेवा करनी चाहिए (या द्विवर्षीय वृद्धियों के सम्बन्ध में दो वर्ष तक सेवा करनी चाहिए)

(2) नियम 32 नियम 26 में वर्णित तरीके के अतिरिक्त अन्य वेतन की प्रारम्भिक दरों के विचार के लिये प्रावधान करता है ।

(3) इस नियम के अन्तर्गत वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने वाले सदस्य अधिकारी का निश्चय करने के लिए शृंखला की अधिकतम राशि को ध्यान में रखा जाना है ।

(4) समय के पूर्व वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करना वेतन की समय-शृंखला के साधारण सिद्धान्तों के विपरीत है, केवल उन्हीं विनियम परिवर्तनों को छोड़कर, जिनमें कि एक अधिकारी को व्यक्तिगत तनख्वाह की स्वीकृति व्यापकित हो, ऐसी वार्षिक वृद्धि स्वीकार नहीं की जानी चाहिए ।

(5) नियत दिनांक से पूर्व वार्षिक वृद्धि स्वीकृत करने के अस्वाभाव को जब विनियम गौर के साथ की जानी चाहिये चूँकि निश्चित तिथि से पूर्व वार्षिक वृद्धि का स्वीकृत किया जाना वेतन की समय शृंखला के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है ।

(6) राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इन नियमों के किसी भी नियम के अन्तर्गत, जबकि ये नियम स्वयं किसी गलत या अन्वय से मुक्त हैं, वह भी यदि किसी कार्यवाही का, कारण बदलाने के लिए तैयार न होगी ।

निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरण करने पर वेतन—एक अधिकारी को राज्य कर्मचारी की श्रेणी के रूप में उच्च पद या श्रेणी से निम्न पद या श्रेणी में स्थानान्तरित करता है, वह जैसा उचित समझे, जिनो राज्य कर्मचारी को कोई भी वेतन स्वीकृत कर सकता है, पर वह वेतन निम्न पद या श्रेणी के अधिकतम वेतन से ज्यादा नहीं होगा ।

परन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को जो वेतन स्वीकृत किया जायेगा वह उस वेतन से ज्यादा नहीं होगा जो कि वह नियम 26 व नियम 31 के खण्ड (ख) या (ग), जैसी भी स्थिति हो, के लागू होने पर, प्राप्त करता ।

निम्न श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्टेड) करने पर वेतन—(क) यदि किसी राज्य कर्मचारी को दण्ड के रूप में उसकी समय-भृत्यता में एक निम्न स्टेज पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आदेश देने वाला अधिकारी आदेश में उतने समय का वर्णन करेगा जितने के लिए वह आदेश प्रभावशाली रहेगा । वह यह भी वर्णन करेगा कि क्या उसके पूर्व स्टेज पर प्रत्यावर्तित होने पर प्रत्यावर्तन का समय उसकी भावी वृद्धि को बन्द रखेगा एवं यदि हाँ, तो किस सीमा तक बन्द रहेगा ।

(ख) यदि एक राज्य कर्मचारी दण्ड के रूप में निम्न सेवा, श्रेणी अथवा पद पर या एक निम्न समय वेतनमान में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आदेश देने वाला अधिकारी आदेश में उस समय का वर्णन कर भी सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है जिस तक कि वह आदेश प्रभावशाली रहेगा । लेकिन जहाँ पर ऐसे समय का स्पष्ट वर्णन कर दिया जाये वहाँ अधिकारी यह भी उल्लेख करेगा कि क्या उसके पुर्नस्थापन (रेस्टोरेशन) के बाद, प्रत्यावर्तन का समय चाही वार्षिक वृद्धियों को स्वयंसेवक रखेगा, एवं यदि हाँ, तो किस सीमा तक ।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियम का नियम 34 (क) समय श्रेणी में निम्न स्टेज पर प्रत्यावर्तित किए गए समय के बाद पुर्नस्थापन के मामलों में लागू होता है तथा नियम 34 (ख) किसी निम्न श्रेणी या पद पर अवनति की निर्धारित तिथि के बाद पुर्नस्थापन के मामलों में लागू होता है । निम्न श्रेणी में अवनति केवल निदिष्ट समय के लिए की जा सकती है । इसलिए इस प्रकार की अवनति के आदेश देने वाले अधिकारी को अवनति के आदेश में समय को निदिष्ट कर देना चाहिये । निम्न पद या श्रेणी में पदावनति या तो किसी निदिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है जिसमें कि अवनति की अवधि के निदिष्ट समय का उल्लेख करना पड़ता है या वह अवसित या अनिश्चित समय तक होती है । अन्तिम मामले में उच्च पद या श्रेणी में पुर्ननियुक्त होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन साधारण नियमों के अनुसार नियमित होगा न कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 के अनुसार ।

जोष निर्देशन —एक वार्षिक वृद्धि जो कि अवनति के समय में बकाया होती हो, उसे स्वीकृत की जानी चाहिए अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों को स्पष्ट व्याख्या के अनुसार हल किया जाता है । यदि दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों में निहित किसी इरादे में सन्देह मान्य होता हो तो स्पष्टीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखा जाना चाहिये ।

स्पष्टीकरण:—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 के उप नियम (क) की सही व्याख्या के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किए गए हैं । इसलिये निम्नलिखित स्पष्टीकरण निकाले जाते हैं—

(क) किसी भी राज्य कर्मचारी के एक समय वेतनमान में निम्न स्टेज पर दण्ड के रूप में पदावनत करने के आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आदेश में निम्न का उल्लेख करना चाहिये—

(1) दिनांक जिससे वह प्रभावशील होगा एवं समय (वर्ष एवं माह के रूप में) जिससे तब वह दण्ड प्रभावशील रहेगा ।

(2) समय श्रेणी (शायों में) में स्ट्रेज जिस पर राज्य कर्मचारी को पद वनत किया गया हो; एवं

(3) मोमा (वर्ष एवं माह में) यदि कोई हो, जिस तक उपरोक्त (1) में कही गई अवधि, एवं भावी वृद्धियों को स्थगित रखेगी ।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी समय वेतन मान में निम्न स्ट्रेज पर पदावनत करने या दण्ड अनिश्चित समय के लिए या स्थाई रूप में देना नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है । और जो जहाँ एक राज्य कर्मचारी किसी विशिष्ट स्ट्रेज पर पदावनत किया जाता है तो उसका वेतन अवसिति के पूर्ण समय तक उस स्ट्रेज पर समानार स्थाई रहेगा । उपरोक्त (3) के अन्तर्गत जो समय निश्चित किया जाय, वह किसी भी रूप में (1) के अधीन, निर्धारित समय से ज्यादा नहीं होना चाहिये ।

(ख) अवसिति की अवधि समाप्त होने पर एक राज्य कर्मचारी का वेतन क्या होना चाहिये, यह प्रश्न निम्न प्रकार में तय करना चाहिये—

(1) यदि अवसिति के आदेश से यह दिया गया हो कि अवसिति का समय भावी वार्षिक वृद्धि को नहीं रोकेगा, तो राज्य कर्मचारी को वह वेतन दिया जाना चाहिये जिसे वह साधारण रूप में प्राप्त करना परन्तु अवसिति करने के कारण प्राप्त नहीं कर सकेगा । फिर भी, यदि अवसिति के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन दलता अवरोध (कॉन्फिडेंसी बार्) ने कम हो तो उसे उस अवरोध को (बार को) पार करने की स्वीकृति, मिथाय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार, नहीं दी जानी चाहिये ।

(2) यदि आदेश में विनैय रूप से यह दिया गया हो कि अवसिति का समय किसी निश्चित समय तक भावी वृद्धियों को स्थगित करेगा, तो राज्य कर्मचारी का वेतन उपरोक्त (1) के अनुसार निश्चित किया जायेगा लेकिन उसमें वृद्धि के लिए स्थगित की गई अवधि की वार्षिक वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा ।

नियम 34 एड्स—एक राज्य कर्मचारी की वार्षिक वृद्धि रोकने या निम्न सेवा श्रेणी या पद पर उसकी अवसिति करने अथवा निम्न समय वेतन मान या समय वेतन मान में निम्न स्ट्रेज पर पदावनत करने के दण्ड का आदेश जब अपील या निगरानी (Review) पेश करने पर सतत प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है तो राज्य कर्मचारी का वेतन, इन नियमों में कुछ दिए गए अनुसार भी, निम्न तरीके द्वारा नियमित किया जाएगा—

(क) यदि उक्त आदेश निरस्त (Set aside) कर दिया जाता है तो जिसने समय तक वह आदेश प्रभावशील रहा, उसने समय तक का उन वेतनों का अन्तर वह प्राप्त करेगा जिसे वह प्राप्त करता, यदि वह आदेश जारी नहीं किया जाता, एवं वह वेतन जिसे उसने प्राप्त किया ।

[विशेष—कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक वेतन उसने प्राप्त किया है तथा जो वेतन उस प्रकार के आदेश के जारी न होने पर उसे मिलता, उन दोनों वेतनों की राशि का जो अन्तर होगा, वह उसे दिया जाएगा ।]

(क) यदि उक्त आदेश संशोधित कर दिया जाता है तो वेतन इस तरह नियमित किया जाएगा जैसे कि मानों संशोधित आदेश ही प्रथम बार उस पर लागू किया गया हो ।

(विशेष—उक्त स्थिति में संशोधित आदेश को ही प्रारम्भ से प्रभावशाल किया हुआ माना जाएगा ।)

स्पष्टीकरण—यदि इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के जारी करने से पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में एक राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया वेतन यदि पुनः संशोधित (Revised) कर दिया जाता है, तो अवकाश वेतन बंग मस (यात्रा भत्तों के प्रतिरिक्त भोग्य) यदि कोई हों, जो उसे उस समय में मिले हों, संशोधित (Revised) वेतन के अनुसार संशोधित किये जायेंगे ।

नियम 35, (1) अध्याय 6 के प्रावधानों की दृष्टि पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह साव्यिक पद (टेम्पोररी पद) के अतिरिक्त स्थाई पद के मूल वेतन से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि उसकी कार्यवाहक नियुक्ति में साव्यिक पद (टेम्पोररी पद) के अतिरिक्त, उस पद के साथ संलग्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उसके अपने उस पद से भी अधिक हैं जिस पर वह अपना लीयन रखता है या जिस पर वह अपना लीयन रखता, यदि उसका लीयन निम्नलिखित नहीं किया जाता ।

टिप्पणी—सरकार आदेश द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख कर सकती है जिसके अधीन केन्द्र के बाहर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारियों की साधारण रंग से कार्यवाहक उन्नति की जा सकती है ।

(2) इस नियम के लिये कार्यवाहक नियुक्ति में कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा यदि वह पद, जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन की समय श्रृंखला में है जिसमें कि साव्यिक पद की छोड़कर, स्थाई पद है, जिस पर उसका लीयन है या जो अपना लीयन रखता यदि उसका लीयन निम्नलिखित नहीं किया जाता या जो उसी के समान वेतन श्रृंखला में है ।

× टिप्पणी सं० 3—नैक्स्ट बिलो रूल (Next below rule) के रूप में सामान्य रूप से विहित रूढ़ि (Convention) के कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्नलिखित भाग प्रदर्शक सिद्धान्त प्रस्तावित जायेगे:—

(1) सरकारी कर्मचारी की उसकी नियमित लाइन में से उसकी उस स्थानाग्न पदोन्नति की जाये नहीं किया जाना चाहिए जिसे वह यदि अपनी नियमित लाइन में रहता तो प्राप्त करता ।

(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी जो नियमित लाइन से बाहर है, से कनिष्ठ किसी व्यक्ति को प्राथमिक स्थानापन्न पदोन्नति स्वयं में 'नैक्स्ट बिलो रूल' के अधीन क्लेम पैदा नहीं करती ।

(3) ऐसा क्लेम सिद्ध किए जाने से पूर्व, यह अनिवार्य होना चाहिए कि उक्त सरकारी कर्मचारी से जो नियमित लाइन से बाहर है, वरिष्ठ सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानापन्न पदोन्नति दे दी गई है ।

× वित्त विभाग की धारा सं. एक 1(45) वित्त वि./नियम/68 दि० 22-4-70 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) यह भी आवश्यक है कि उससे नीचे के सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि किसी मामले में स्थानापन्न पदोन्नति अनुसूचितता, अनुपयुक्तता, या अवकाश के कारण नहीं दी गई हो ।

(5) इस नियम के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ 120 दिन से अधिक दिन के लिए किसी संवर्ग में रिक्त पद पर ही दिया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, प्रारम्भिक रिक्त पद तथा बाद में हुआ रिक्त पद जिसके आधार पर लाभ दिया जाना है, प्रत्येक 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए होना चाहिए । यह लाभ क्रमशः होने वाले रिक्त पदों जिनकी अवधि मिलाकर 120 दिन से अधिक हो, पर नहीं दिया जाना चाहिए ।

(6) 'नैक्सट विलो रूल' का लाभ एक पद पर एक ही सरकारी कर्मचारी को दिया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि वरिष्ठतम व्यक्ति तथा उससे ठीक नीचे का व्यक्ति नियमित लाइन से बाहर कार्य कर रहे हैं तो कमिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति पर 'नैक्सट विलो रूल' का लाभ केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा अर्थात् वरिष्ठतम को ही मिलेगा न कि अन्य व्यक्तियों को जो चाहे पदोन्नति किए गए कमिष्ठ व्यक्ति से वरिष्ठ हो न हों ।

(7) जहाँ नियमित लाइन से बाहर कोई सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति देय है तथा उसे "नैक्सट विलो रूल" के अधीन उच्च वेतन का लाभ दे दिया गया है, तथा ऐसा वेतन उसके नियमित लाइन से बाहर रहते हुए उसके द्वारा वास्तव में पारित पद के वेतन के अधिकतम 10 अधिक है तो उसे पद के वेतनमान के अधिकतम देने के बजाए जिस दिनांक से उसने उच्चतर वेतन पाना प्रारम्भ किया है, उससे छह माह के भीतर उसकी नियमित लाइन में प्रत्यावर्तित (रिवर्टेड) कर देना चाहिए ।

(8) 'नैक्सट विलो रूल' का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जो या तो सरकार के अधीन या अन्यत्र अपनी नियमित लाइन के बाहर किसी पद पर सीधी भरती के रूप में नियुक्त किया गया है । केवल मात्र जिस पद पर वह सीधे भरती किया गया है उस पर स्थायी होने तक अपना सीजन रखने से ही इस नियम के अधीन उसके क्लेम पर विचार करने के प्रावधान को प्रदान नहीं करेगा ।

ये तुरन्त प्रभावशील होंगे ।

टिप्पणियाँ—(1) इस नियम के लिए कार्यवाहक नियुक्तियों में कायों या उत्तरदायित्वों का कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जावेगा यदि वह पद जिस पर वह नियुक्त किया जाता है, उसी वेतन शृंखला में है जिसमें कि टेन्पोररी पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद है व जिस पर उसका सीजन है या जिस पर वह अपना सीजन रखता यदि उसका सीजन निरन्तर नहीं होता या उसी के समान वेतन शृंखला में है ।

(2) अधिक कार्यवाहक वेतन वर्तमान कर्मचारियों को नहीं दिया जावेगा जहाँ पर कि वेतन शृंखला की दृष्टि से विभिन्न पद नए उम्मीदवारों के लिए एक वेतन शृंखला में मिला दिए गए हैं ।

निर्णय—उच्चतर पदों या अतिरिक्त पदों पर कार्यवाहक उन्नति के लिए अतिरिक्त अनुराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग में बहुत से मामले प्राप्त क्रिये जा रहे हैं ।

(2) (i) उच्चतर पदों के स्थानापन्न काल के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों को राजि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 के द्वारा दायित्व होता है। इस नियम के खण्ड (क) के अनुसार जब कार्यवाहक नियुक्ति में अपने स्थाई पद से, जिस पर कि उसका सीनियर है, सम्बन्धित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हों, तो वह उस पद का प्रारम्भिक वेतन पाने का हकदार है।

(ii) इस नियम के नीचे दी गई टिप्पणी नम्बरा (2) के अनुसार साधारण मामलों में फिर भी, पूर्ण कार्यवाहक उन्नति दो या दो से अधिक माह तक रूकित रहने वाले स्थान पर दी जा सकती है तथा जहां आवश्यक हो, विशेष कारणों से एक माह या उससे अधिक के लिए दी जा सकती है।

(iii) एक माह से कम के समय के लिए औपचारिक रूप से ऐसे प्रबन्ध न किए जाने चाहिए जिसके कारण उच्चतर वेतन या प्रतिरूकित वेतन का नुस्तेम करना पड़े।

एक माह या इससे अधिक समय के लिए लेकिन (2) में कही गई सीमा से कम के लिए प्रबन्ध इस तरह करना चाहिए कि उसके चालू कार्य की वह देर मास करे, न कि उसकी कार्य-वाहक नियुक्ति की जानी चाहिए।

(iv) नियम 36 में दिया हुआ है कि एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी का वेतन उसने कम पर निश्चित किया जा सकता है जिसे वह नियम 35 के अनुसार प्राप्त कर सकता है। यह नियम उस राज्य कर्मचारी को उस पद का पूर्ण वेतन देने से रोकने के लिए बनाया गया है जिस पर कि वह साधारणतया उन्नत नहीं किया जाता, परन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी उस उच्च पद पर कार्यवाहक उन्नति की गई है। यह ध्यानी की जाती है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, जब वह कार्यवाहक नियुक्ति करता हो, यह विचारना चाहिए कि क्या किसी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को पद का प्रारम्भिक वेतन दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। यदि किसी राज्य कर्मचारी को केवल उस पद का चालू कार्य देखने के लिए ही नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन नियम 26 के नीचे दी गई 'टिप्पणी' के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

(3) प्रबन्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व उसके नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार स्पष्ट आदेश निकासने चाहिए कि क्या नियुक्ति कार्यवाहक नियुक्ति है या केवल चालू कार्य को देखने के लिए की गई नियुक्ति है। यदि कार्यवाहक नियुक्ति दो माह से कम समय के लिए की गई हो तो उसके कारणों का उल्लेख नियुक्ति आदेश में दिया जाना चाहिए तथा यदि वेतन नियम 35 के अनुसार मिलने वाले वेतन से कम पर निश्चित किया जाना हो तो शक्तियों की अनुसूची की मद संख्या 7 के अन्तर्गत एक विशिष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए।

+ स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के 35 से 50 के क्षेत्र के एवं उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में सदेह प्रकट किए गए हैं जिनके अधीन एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोहरा प्रबन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए सरकार निम्न प्रकार नि स्पष्टीकरण एवं निर्देशन प्राप्त करती है :—

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 8 (28) एफ II / 55 दिनांक 9-8-62 द्वारा शामिल किया गया तथा वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (71) एफ ड 1 (व्यय-नियम) 65 दिनांक 14-12-65 द्वारा संशोधित किया गया (संशोधन में तीन माह के स्थान पर 6 माह किए गए)

जब कोई पद रिक्त हो तो सशम प्राधिकारी के लिए निम्न तरीके मुझे हुए हैं :—

(1) स्टाफ के अन्य सदस्यों में कार्य को बांट देना तथा पद को गानी करना ।

(2) नई नियुक्ति या उन्नति प्रदान कर स्थान को पूर्ण करना ।

(3) किसी राज्य कर्मचारी को अपने पद के कार्यभार के प्रतिरिक्त उस पद का कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त करना ।

जगह के रिक्त होने पर सशम प्राधिकारी को निर्णय करना चाहिये कि उपरोक्त बताया गए तरीकों में किस मामले में कौनसा तरीका ठीक है । यदि एक माह में अधिक के लिए रिक्त रहने वाला नहीं हो तो जहाँ तक सम्भव हो, उस पद का कार्यभार स्टाफ के अन्य सदस्यों के बीच में बांट दिया जाना चाहिए । जब किसी पद पर वैधानिक कार्य या बर्तव्य संलग्न हो या जहाँ अन्य कारण से पदों को रिक्त रखा जाना सुविधाजनक न हो, चाहे वह स्थान एक माह से अधिक के लिए रिक्त रहने वाला नहीं हो, या जहाँ पर एक पद एक माह से अधिक समय के लिए रिक्त रखा जाना सम्भव हो, तो एक व्यक्ति को एक पद पर उन्नत या नियुक्त किया जा सकता है ।

यदि पद पर बाह्य (Market) से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसका वेतन या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 (क) व 26 को विनाशर निर्दिष्ट किया जावेगा ।

जब एक राज्य कर्मचारी एक रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 (क) या 35 (क) के अनुसार हम बात की ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा कि उस नियुक्ति में कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का धारण अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं ।

(1) जहाँ एक राज्य कर्मचारी किसी पद पर अपने कार्य के प्रतिरिक्त उसके कार्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस सम्बन्ध में तीन सम्भावनाएं हो सकती हैं—

(i) वह पद उस पद के अधीनस्थ हो सकता है जिसे वह धारण कर रहा हो ।

(ii) वह पद उसके द्वारा धारण किए गए पद के समान या नीचा (लेकिन अधीनस्थ) हो सकता है ।

स्तरदीकरण—“बराबर पदों” का तात्पर्य उनी केटर में वेतन की अनुरूप समय प्रेसी में होने वाले पदों में है ।

(iii) वह पद अपने द्वारा धारण किए गये पद से उच्च हो सकता है ।

इन सभी मामलों में नियुक्ति एवं प्रतिरिक्त वेतन की स्वीकृति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत नियमित होगी ।

(2) प्रथम मामले में राज्य कर्मचारी को जो कुछ वह प्राप्त कर रहा है, उसके प्रतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलेगा ।

(3) दूसरे प्रकार के मामले में राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (क) के अन्तर्गत अपना वेतन तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अन्तर्गत दूसरे पद के प्रारम्भिक वेतन का 10 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है यदि दोहरे कार्यभार का समय 60 दिन तक है या 30 दिन या इससे अधिक है । परन्तु यदि दोहरे कार्यभार को

सम्भालने का समय 60 दिन से ज्यादा है तो दूसरे पद के प्रारम्भिक वेतन के 20 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) तीसरे मामले में यदि उच्च पद का चार्ज 60 दिन से कम के लिए सम्भावना हो परन्तु 30 दिन या इससे अधिक समय के लिए हो तथा राज्य कर्मचारी उच्च पद पर कार्य करने के लिए योग्यता रखता हो या जो नियमित या प्राशासनिक उन्नति के लिए पर्याप्त सीनियर हो तो उसे उच्च पद पर विशेष (स्पेशल) वेतन के मिलने पर भी एक पद को उच्च पद समझा जाना चाहिए तथा उसे उस पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (क) के अन्तर्गत उच्च पद पर वेतन प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है । फिर भी यदि निम्न पद अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) पद न हो तो राज्य कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अन्तर्गत उस पद के प्रारम्भिक वेतन के 10 प्रतिशत के रूप में विशेष वेतन तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

फिर भी ऐसे उक्त मामलों में जिनमें उच्च पद का कार्यभार 60 दिन से अधिक समय के लिए सम्भालना हो तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (ख) के अनुसार निम्न पद के प्रारम्भिक वेतन के 20 प्रतिशत तक विशेष वेतन स्वीकृत किया जा सकता है ।

× स्पष्टीकरण—उक्त स्पष्टीकरण नियम 50 के अन्तर्गत, ऐसे मामलों में जहाँ पर 30 दिनों या इससे अधिक समय के लिए दोहरा प्रबन्ध के लिए, अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाता है ।

एक प्रश्न इस सम्बन्ध में उत्पन्न किया गया है कि अवकाश के पूर्व में एवं बाद में जाने वाले अवकाशों को दोहरा प्रबन्ध के समय में तथा उसका अतिरिक्त वेतन देने के लिए गिना जाना चाहिए या नहीं । वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अवकाशों की उस अवधि को दोहरा प्रबन्ध के समय में संगणित नहीं की जाती है तथा उसके लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है ।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 63 को ध्यान में रखते हुए विषय पर जांच कर ली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ अवकाश के पूर्व एवं बाद के सार्वजनिक अवकाशों को दोहरा प्रबन्ध की अवधि में गिना जाना चाहिए एवं तदनुसार अतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी—यदि राज्य कर्मचारी उच्च पद का कार्यभार सम्भालने की योग्यता न रखता हो तथा जो नियमित या प्राशासनिक उन्नति के लिए पर्याप्त सीनियर न हो, तो उसे उस पद के शर्तियों का बालू कार्य सम्भालने के लिए नियुक्त किया जा सकता है तथा यदि उच्च पद का चार्ज 30 दिन या उससे अधिक के लिए देता है तो उसे अपने वेतन का 10 प्रतिशत तक विशेष वेतन स्वीकृत किया जा सकता है ।

किसी भी मामले में इस प्रकार का दोहरा प्रबन्ध छह (6) माह से अधिक के लिए चालू नहीं रखा जाना चाहिये । छह माह से अधिक समय के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं

× राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 23 सितम्बर 1966 में प्रकाशित वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 2 (25) एफ डी (व्यय-नियम) 66 दिनांक 1 जुलाई 1966 द्वारा शामिल किया गया ।

मिलेगा। छह माह के बाद नियमित नियुक्ति या उन्नति रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए की जानी चाहिए। उक्त पद के छह माह तक न भरने पर उसे एवेडेन्स में रखा हुआ सम्माना जावेगा।

(यह संशोधन (छह माह का) दिनांक 1-1-65 से लागू होगा जो राज्य कर्मचारी 1-11-65 से पूर्व दोहरा कार्यभार सम्मानित हुए थे उनके लिए यह संशोधन उस तारीख से लागू होगा जिसमें अपने कार्यभार सम्भालना शुरू किया है)।

टिप्पणी—दूसरे पद अधीन एक पद उस समय सम्माना जावेगा जब कि एक पद के कर्मचारी का कार्य अन्य पद पर काम करने वाले द्वारा देखा जाता है या निगरानी किया जाता है तथा दोनों पद एक ही कार्यालय में हों। यदि एक राजपत्रित राज्य कर्मचारी किसी अराजपत्रित पद का कार्यभार सम्मानित तो उसे उस पद के अधीनस्थ पद का कार्यभार सम्माना हुआ सम्माना चाहिए बशर्ते कि अराजपत्रित पद राजपत्रित पद के नीचे नियन्त्रण में हो।

नियम 35. क(1) नियम 35 व 36 के प्रावधानों की शर्तों पर एक राज्य कर्मचारी जो एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह उस कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा।

(2) वेतन वृद्धि अग्रेषण प्रकार से मूल वेतन में वृद्धि होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन ऐसी वृद्धि की तारीख से उपनियम के अन्तर्गत इस रूप में पुनः निर्दिष्ट किया जावेगा कि भागों यह पद पर उस तारीख की ही कार्यवाहक रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहाँ पर ऐसा पुनः निर्धारण (Refixation) उसके हित में हो।

परन्तु शर्त यह है कि नियम 26 के प्रावधान इस नियम के उपनियम (2) के अधीन वेतन के पुनर्निर्धारण (रीफिक्सेशन) के मामलों में लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—उपनियम (2) 1-5-58 से प्रभावशील है।

× (3) उपनियम (2) में किसी भी शर्त के अन्तर्निहित होते हुए भी, उस तारीख से जिसकी हि सरकारी कर्मचारी का स्थानापन्न वेतन, संस्थापी वेतन के समकक्ष या उससे कम होना है, तो स्थानापन्न वेतन संस्थापी वेतन के ऊपर की स्टेज पर पुनः स्थिर किया जाएगा। सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि वेतन के उक्त रूप से पुनः स्थिरीकरण किए जाने की तारीख से नियम 31 के अधीन आवश्यक अहंकारी सेवा पूरी करने पर ही आहरित की जाएगी।

ये आदेश दिनांक 1-4-66 से प्रभावशील हुए सम्भले जाएंगे।

नियम 36. निम्न दर पर कार्यवाहक वेतन निर्दिष्ट करने की शक्ति—राज्य सरकार एक कार्यवाहक राज्य कर्मचारी का वेतन, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत वेतन में कम राशि पर निर्दिष्ट कर सकती है।

टिप्पणी—इसका एक उदाहरण, जहाँ पर यह नियम लागू होना चाहिए, यह है कि जब एक राज्य कर्मचारी एक पद के पूर्ण कर्तव्यों की नहीं निभा रहा हो, लेकिन केवल कुछ कर्तव्यों का ही चार्ज सम्भाल रहा हो।

× वित्त विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 1 (21) वित्त वि० (नियम/69 दिनांक 9-5-69 द्वारा निविष्ट किया गया।

नियम 37. कार्यवाहक वेतन का नियमन, जब पद पर वेतन ऐसी दर पर मुकर्रर हो जो दूसरे उच्च कर्मचारी की निज़ि हो—जब कोई राज्य कर्मचारी एक पद पर कार्यवाहक रूप से कार्य करता है जिसका कि वेतन अन्य राज्य कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन पर निर्दिष्ट हो चुका है तो सरकार उसे इस प्रकार निर्दिष्ट की गई किसी दर पर उसे वेतन प्राप्त करने की इजाजत दे सकती है यद्यपि इस प्रकार निर्दिष्ट की गई दर, समय यैणी की हो तो सरकार उसे प्राथमिक वेतन प्रदान करने की स्वीकृति दे सकती है जो कि उस समय यैणी की निम्नतम स्टेज के वेतन से ज्यादा न होगा तथा भावो वॉयकोन्ति स्वीकृत दर से अधिक नहीं होगी ।

नियम 38. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए नए राज्य कर्मचारियों के स्थान पर कार्यवाहक उपस्थिति—राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन राज्य कर्मचारियों के बचले में कार्यवाहक उपस्थिति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर सकती है जो कि नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत छूटी पर समझे जाते हैं ।

नियम 38 के अन्तर्गत मूल्य प्राधिकारी किसी भी राज्य कर्मचारी को उस कर्मचारी के स्थान पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर सकता है जो कि नियम 7 (8) (ख) के अधीन छूटी पर माना जाता है । इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे मामलों में, जिनमें कि कार्यवाहक उपस्थिति दी जाती है, उन राज्य कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए नए पद का सृजन करना जरूरी है, जो कि भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं एवं जो नियम 7 (8) (ख) (1) के अन्तर्गत छूटी पर समझा जाता है ।

राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि, यदि कोई उम्मीदवार भारत में निर्देशन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए भेजा जाता है तो उसे ऐसे निर्देशन या प्रशिक्षण में स्थापित करने के लिए नये पद का सृजन किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसे नियुक्ति देने के आदेश को ही इस सम्बन्ध में स्वीकृति समझा जावेगा ।

सभी विचारधेन मामले इस आधार पर हल किये जा सकते हैं ।

नियम 39. निज़ि वेतन का घटना—जब तक स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी यद्यपि प्रकार से आदेश न दे दे, कर्मचारी का वेतन उतना घटाया जा सकता है जितना कि कर्मचारी का वेतन बढ़ता जाय तथा जैसे ही उस कर्मचारी का वेतन उस व्यक्तिगत वेतन के बराबर बढ़ जायेगा वैसे ही उसकी व्यक्तिगत वेतन निलम्बा बन्द हो जायेगा ।

नियम 40. अस्थाई पद का वेतन—जब कोई ऐसे अस्थाई पद का सृजन किया जाता है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना हो जो कि पहिले से ही राज्यकीय सेवा में न हो तो उस पद का वेतन उस आवश्यक न्यूनतम (Minimum) रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा जो कि उस पद पर योग्य व्यक्तियों को कार्य पर लाने में पर्याप्त हो सके ।

नियम 41. जब एक ऐसा अस्थाई पद सृजित होता है जो कि सम्भवतः राज्य सेवा में लगे राज्य कर्मचारी द्वारा भरा जा सके, तो उसका वेतन निम्न की ध्यान में रखकर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए—

(क) सम्पादन किये जाने वाले काम की प्रकृति एवं उसकी जिम्मेदारी की ध्यान में रखते हुए ।

(स) एक स्तर के कर्मचारी का वर्तमान वेतन उस पद पर निर्धारित के लिए पर्याप्त हो।

टिप्पणियाँ—(1) एक राज्य कर्मचारी जा कि “विशेष कर्तव्य” (Special duty) या प्रतिनिधित्व पर (on deputation) पर जाता है उसे अपने अस्थाई पद का वेतन प्राप्त करना चाहिए जो कि उसे समय-समय पर मिलता रहता यदि वह दृग प्रकार प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता यदि स्वोच्छ्रित प्रदान करने वाला प्राधिकारी इसके मनुष्य हो जाना है कि इस प्रकार में प्रतिनिधित्व किया गया कर्मचारी सीधे ही उस अपने पद में जिन पर वह ‘विशेष कर्तव्य’ पर या प्रतिनिधित्व पर भेजा गया है, उच्च वेतन की दर वाले पद पर उन्नत हो जाता तथा ऐसे पद पर अनुमानतः उसी समय तक कम से कम कार्य करता रहता जितने समय तक अपने अस्थाई पद के चलने की धारा है, तो वह दृग तथ्य को ध्यान में रख सकता है तथा मनुष्य समय तक के लिए एक समान वेतन निर्धारण पर करता है।

(2) ऐसे मामलों में जो कि वेतन स्वीकृत करने का कुछ। प्रायः काम को निर्दिष्ट रूप से वृद्धि या उत्तरदायित्व का अथवा उस पद के कार्यों की तुलना में मिला करना है जिसे वह अपनी नियत श्रेणी में रहकर अस्थायी रूप से प्राप्त करता है। जहां पर उत्तरदायित्व की जांच व्यावहारिक नहीं हो, वहां नियम 40 का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(3) काम की या उत्तरदायित्व का अधिकता के कारण, किन्हीं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, प्रतिनिधित्व स्वीकृत किया गया वेतन उसके मूल वेतन के 1/5 भाग या 300 रु, इनमें से जो कम हो, से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(4) उन राज्य कर्मचारियों को जो उन पदों पर प्रतिनिधित्व किये गए हैं जिनका कार्य या उत्तरदायित्व उन्हीं पदों से समान है जिनको कि वे अस्थायी प्रकार से ग्रहण करते, उन्हें वेतन में कोई वृद्धि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए चाहे उन्हें किसी विशेष परिस्थितियों में काम करने के कारण अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिए। इस तरह का एक सुन्दर उदाहरण उन लोगों को मिलेगा जो समितियों (बोर्डों) या आयोगों (कमीशन) में प्रतिनिधित्व (रेप्रेजेंटेशन) पर भेजे जाते हैं। समितियों एवं आयोगों के सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व पर भेड़े गये राज्य कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व उनसे अधिक नहीं हैं जिन्हें वे अपनी नियत श्रेणी में रहकर पूरा करते। एवं केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही अनिश्चित परिस्थितियों में उन्नत हो जा सकता है। फिर भी अपवाद स्वरूप मामलों में उन मिथ्याओं में गिरावट बरतनी पड़ेगी जहां पर कि कर्तव्यों को ध्यान में रखकर, यह आवश्यक होता है कि विशेष योग्यताओं के अधिकारी विशेष गतों पर लाय जावें।

(5) अस्थाई पदों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया जावेगा—साधारण कार्य को करने के लिए सृजित किये गए पद जिनके लिए एक केडर में पहिले से ही स्थाई पद मौजूद हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि नये पद अस्थाई हैं और स्थाई नहीं हैं, एवं दूसरे पद जो साधारण कार्य से असम्बद्ध विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए धन में पद सृजित किये जाने चाहिए जिन्हें एक सेवा को करना पड़ता है। आगिरी निम्न के पदों का एक उदाहरण जॉब कमीशन में एक स्थान का है। मौलिक परिभाषा द्वारा इनको पहचाना जाना कठिन है परन्तु व्यवहार में दृष्टिगत मामलों में पहचान करने में बहुत ही कम कठिनाई आती है। पद की प्रथम श्रेणी को सेवा के केडर में एक अस्थाई वृद्धि के रूप में समझा जाना चाहिये चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं हो। अस्थाई पदों की बाद की श्रेणी को अवर्गीकृत एवं प्रथम-एक्स-केडर पद के रूप में समझा जाना चाहिये।

अस्माई पद जिन्हें इस सिद्धान्त से सेवा के किसी केडर में अस्माई वृद्धि सम्पन्नी जानी चाहिये, उन्हें बिना पारिश्रमिक के साधारण सेवा की समय श्रेणी में सूजित किया जाना चाहिये। इस पदों की कर्मचारी, इसलिये, अपनी साधारण समय श्रेणी का वेतन प्राप्त करेंगे। यदि किन्हीं पदों पर कार्य या उत्तरदायित्व का भार सामान्यतः अपने मूल केडर के कर्तव्यों की तुलना में अधिक हो तो उसके अतिरिक्त विशेष वेतन उनके लिए स्वीकृत किया जाना आवश्यक होगा।

पृथक् एम्स-केडर पदों के लिए सामूहिक तौर पर कभी वेतन की कुल एकत्रित राशि निर्धारित करना वांछनीय होगा। फिर भी जहाँ पद पर नियुक्ति सेवा में लगे कर्मचारियों से ले की जाती हो तो पद को धारण करने वाले की समय श्रेणी में सूजित करना उचित होगा।

जांच निवेदन;—इन नियमों के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यों को मान्यता नहीं दी जावेगी। विशेष कार्य करने के लिये एक अस्माई पद का सूजन कराना पड़ेगा। यदि विशेष कर्तव्य एक राज्य कर्मचारी के कर्तव्यों के साथ में कराये जाने हो तो नियम 41 व 50 लागू होंगे।

अध्याय ५ वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते

नियम 42—सामान्य नियमों के अनुसार कि भत्ते, प्राप्त कर्ता को लाभ का पूर्ण साधन नहीं होता है, सरकार अपने नियमों के अधीन राज्य कर्मचारियों को ऐसे भत्ते स्वीकृत कर सकती है तथा उसकी राशि निर्धारित करने के लिए एवं उसकी प्राप्त करने की शर्तों के बारे में नियम बना सकती है।

(इस नियम के अधीन बनये गए नियमों के लिए परिशिष्ट 16, 17 व 18 देखें)

नियम 43 (क) काम करने एवं उसका शुल्क स्वीकार करने की स्वीकृति—नियम 44 से 46 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन एक राज्य कर्मचारी को, गैर सरकारी व्यक्ति या निकाय या सार्वजनिक निकाय जिसमें स्थानीय निधि द्वारा प्रशासन किया जाता हो, का कार्य करने एवं उसका आवर्तक या अनावर्तक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक लेने की स्वीकृति दी जा सकती है, यदि उसकी सेवा लेना जरूरी हो तथा यदि वह उस कार्य को अपने राजकीय कर्तव्यों एवं बाधियों में बिना बाधा पहुँचाये हुए कर सकता हो।

टिप्पणी (विनोदित)

(ख) शुल्क (फीस) स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक—सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी किसी निजी (प्राइवेट) या सार्वजनिक संस्था या प्राइवेट व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता है तथा उसका शुल्क (फीस) नहीं ले सकता है। यह सक्षम प्राधिकारी, केवल कर्मचारी के अवकाश पर रहने के अतिरिक्त, यह प्रमाणित करेगा कि उसके उरोक्त कार्य करने में सरकारी कार्यों एवं जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है।

(ग) ये परिस्थितियाँ जिनमें पारिश्रमिक (Honorarium) स्वीकृत किया जा सकता है—राज्य सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी कार्य के लिए संचित निधि से पारिश्रमिक प्राप्त

करने के लिए स्वीकृति दे सकती है या उससे स्वीकृत कर सकती है यदि वह कार्य आकस्मिक या त्रमानुगत ढंग का हो या इतना परिश्रम का हो या ऐसी विशेष योग्यता का हो, जिसके लिए ऐसा पारिश्रमिक देना उचित है। सिवाय इसके कि जब कोई विशेष कारण, जिनको कि लिखा जाना चाहिए, इस प्रावधान का उल्लंघन कराते हों, किसी पारिश्रमिक को स्वीकार करने या उसको लेने की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कार्य सरकार को पूर्व स्वीकृति से न लिया जाए तथा इसकी राशि पहले से ही तय नहीं की गई हो।

निर्देशन सं० १—कभी कभी ये प्रश्न उठाये जाते हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत किसी राजपत्रित अधिकारी के लिए अधिक समय तक काम करने का पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है जब कि उसने ही अधिक समय तक काम करने पर एक राजपत्रित कर्मचारी को पारिश्रमिक स्वीकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (13) की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जिसके कि अनुसार पारिश्रमिक केवल आकस्मिक या त्रमानुगत ढंग के विशेष कार्य के लिए ही स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जब एक राज्य कर्मचारी अपनी साधारण सेवा करता है तो उसे पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जाता है चाहे वह सामान्य समय से अधिक समय तक काम क्यों न करे। इसी प्रकार जब सेवाएँ साधारण सेवाओं के समान हों तो भी उनके लिए पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

फिर भी, लिपिक वर्ग से सम्बन्धित सदस्यों के मामले में जब एक कर्मचारी को अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में एक उचित समय तक अग्राधारण सम्बन्ध समय तक कार्य करना पड़ता हो तो उसे सरकार प्रचलित पद्धति के अनुसार पारिश्रमिक स्वीकृत कर सकती है। किसी भी राजपत्रित अधिकारी के लिए किसी भी कार्य का पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जो कि उसकी सामान्य सेवाओं का हिस्सा हो या उसके समान हो यद्यपि चाहे वह कार्यालय समय के बाद भी कार्य करता हो। इसलिये इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार को कभी भी राजपत्रित अधिकारियों के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए।

(विशेष—उक्त हिदायत से स्पष्ट है कि राजपत्रित अधिकारी पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं है, अतः उन्हें इसके लिए आवेदन आदि नहीं करना चाहिए)

निर्देशन सं० २—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या नियम 43 (ग) के अधीन किसी राज्य कर्मचारी को, जो अपने पद की सामान्य सेवा (क्यूटी) के साथ में अन्य स्वीकृत पद की सेवाओं को भी पूरा कर रहा हो, पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है।

पारिश्रमिक की परिभाषा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (13) में आकस्मिक या त्रमानुगत ढंग के विशेष कार्य के लिए राज्य की संचित निधि या भारत की संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप में किसी राज्य कर्मचारी को आवर्तक या अनवर्तक भुगतान के रूप में की गई है। जब एक पद स्वीकृत किया जाता है तो उसकी सेवाएँ मुदिकल से ही आकस्मिक या त्रमानुगत ढंग की मानी जा सकती है। अतः जब अपने कार्य के प्रतिरिक्त, एक राज्य कर्मचारी दूसरे स्वीकृत पद की सेवाओं को पूरा करने के लिए कहा जाय तो उसे प्रतिरिक्त कार्य करता हुआ समझना चाहिए जो कि आकस्मिक या त्रमानुगत ढंग की नहीं है, चाहे उसे ऐसी प्रतिरिक्त सेवाओं को छोड़े समय के लिए करने के लिए ही कहा जाय। इसलिये एक कर्मचारी को जब भी अपने पद

के अतिरिक्त एक स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये कहा जाय तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत पारिश्रमिक नहीं मिल सकेगा ।

पूर्व के मामले जो पहिले धन्यथा प्रकार से तय किये जा चुके हैं, उन्हें पुनः खोलने की जरूरत नहीं है ।

निर्देशन सं० 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (ग) के अन्तर्गत कोई भी राज्य कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी कार्य को नहीं ले सकता है तथा उसका पारिश्रमिक स्वीकार नहीं कर सकता है । सामुदायिक विकास में लगा हुआ क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) एवं ग्राम सेवक, विकास अधिकारी जैसे व्यक्ति 'पंचायती राज' पत्रिका में पत्रों एवं लेखों के रूप में प्रकाशन सामग्री दे सकते हैं जो कि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रचार मन्त्रालय के माध्यम से निकाला जाता है । तथा वे उनका पारिश्रमिक सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में प्राप्त करते हैं, जैसा कि उक्त नियम में वाहा गया है ।

राज्य सरकार ने मामले पर विचार कर अपनी यह राय बनाई है कि उक्त कार्य को लेने एवं उसके पारिश्रमिक को स्वीकार करने की भांजा सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में प्राप्त करने में बहुत देर व असुविधा होती है इसलिए सरकार आदेश देती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में नियोजित क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग (फील्ड स्टाफ) जो उपरोक्त पत्रिका में पत्रों एवं लेखों के रूप में योगदान करते हैं, उन्हें ऐसा करने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने की भांजा दी जाती है ।

नियम सं० 1—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में पूर्ण समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग या आंशिक समय के लिए नियुक्त अध्यापन वर्ग को, जिसे कि अध्यापन सेवाओं के लिए विशेष वेतन मिलता हो, उक्त संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में लिए जाने वाले टैस्टों व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाएँ जाचने या व्यावहारिक परीक्षा लेने आदि का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के रूप में, नियम 43 (ग) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है ।

मामले की जाच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पूर्ण समय या आंशिक समय के लिए नियुक्त किये गये अध्यापन वर्ग के कर्मचारियों को प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिकाएँ जाचने या व्यावहारिक परीक्षा लेने आदि का कोई भी पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जायगा क्योंकि ऐसी संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में नियुक्त अध्यापन वर्ग की यह अध्यापन सेवाओं में शामिल है । फिर भी उन लोगों के लिए पारिश्रमिक दिया जाता रहेगा जो इन संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं ।

निर्णय सं० 2—विषय राजकीय विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुनायरो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारियों द्वारा भाग लेना तथा उनका उन्हें पारिश्रमिक देना—

राज्य कर्मचारी जो कि कवि या कलाकार हैं, उन्हें समय पर सार्वजनिक संपर्कालय तथा अन्य कुछ विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुनायरो तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा उनकी सेवा के लिए उन्हें संबंधित निधि से पारिश्रमिक दिया जाता है ।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 के अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी मध्यम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना एक कार्यालय में कार्य करते हुए दूसरे कार्यालय का कार्य नहीं ले सकता है तथा न उसका पारिश्रमिक ही स्वीकार कर सकता है।

मामले की जाच की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उन राज्य कर्मचारियों को, जिन्हें मासिक मन्थनलय या ऐसे उत्सव मनाने वाले अन्य विभागों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों, मुद्यायों तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बुलाया जाता है, निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए उनमें भाग लेने की स्वीकृति दी हुई समझी जाती है—

(1) किसी एक अवसर पर राज्य कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक 25 रु० से ज्यादा न हो तथा एक मास में 50 रु० से ज्यादा न हो।

(2) सांस्कृतिक मन्थन निदेशालय या ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्य विभागों के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने पर इन आदेशों के अन्तर्गत पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

शुल्क एवं पारिश्रमिक (Fees and Honoraria)

(घ) स्वीकृति के कारणों की लिखा जावे—शुल्क एवं पारिश्रमिक दोनों ही मामलों में स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी लिखित में यह उल्लेख करेगा कि नियम 13 में वर्णित सामान्य सिद्धान्तों का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा वह उसमें उन कारणों का भी उल्लेख करेगा कि जो उसकी राय में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिलाने के लिए पर्याप्त हों।

पारिश्रमिक की स्वीकृति राज्य कर्मचारी को केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है कि उसके कार्य में सत्प्राप्ति हुई हो गई है अर्थात् अंसे कि उसके विभाग के उत्पादन में विशेष सम्मेलन हो रहा हो। ऐसी सत्प्राप्ति कार्य हुई राजकीय सेवा की साधारण घटना है तथा उन्हें पूरा करने में राज्य कर्मचारी का बर्तव्य बंध होता है। अतः परिणामस्वरूप उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 9 के तम मन्थन ९ पर दिखाई गई सीमा तक ऐसे कार्य लेने तथा पारिश्रमिक स्वीकृति करने या लेने की शक्ति प्रदान कर दी गई है किन्तु कि लिए पारिश्रमिक दिया जाता है। इस मन्थन में निम्नलिखित प्रदान उठाये गये हैं—

(1) क्या ऐसे मामलों में जिनमें कार्य लेने की स्वीकृति तथा पारिश्रमिक के स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी पारिश्रमिक स्वीकृति करने में मध्यम प्राधिकारी से निम्न हो, (ऐसे मामले उदाहरण के रूप में जहाँ एक राज्य कर्मचारी एक विभाग में कार्य करता है तथा दूसरे विभाग का कार्य स्वीकार करता है) जिन विभाग की स्वीकृति, ऐसे कार्य को लेने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करनी आवश्यक होगी जिनमें कि निर्धारित सीमा राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 9 की तम मन्थन 9 में दी हुई से अधिक है, तथा

क्या ऐसे मामलों में दो या दो से अधिक जिनमें एक कार्य को लेने तथा उनका पारिश्रमिक स्वीकार करने की स्वीकृति उधार देने वाले प्राधिकारी द्वारा निकाली जायेगी तथा दूसरी पारिश्रमिक के रूप में निर्धारित राशि स्वीकृति करने की उधार देने वाले प्राधिकारी द्वारा निकाली जायेगी।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में उधार देने वाला प्राधिकारी, यह निर्णय लेने के बाद कि अपनी साधारण कार्यालय की सेवाओं एवं उत्तरदायित्वों में बिना बाधा पहुँचे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को कार्य लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा सकती है, वह उधार लेने वाले विभाग को अपनी अनुमति भेज देगा जिसमें वह प्रतिरिक्त कार्य लेने एवं पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति होगी। वह इसके साथ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (घ) के अन्तर्गत चाहा गया प्रमाण पत्र भी भेजेगा। एवं इसके बाद उधार लेने वाले प्राधिकारी को पारिश्रमिक की एक स्वीकृति जारी करेगा उसमें वह (1) उपरोक्त 43 (घ) में चाहा गया प्रमाण पत्र तथा (2) इस सम्बन्ध के प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा कि स्वीकृति उधार देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की गई है।

जहाँ एक सक्षम प्राधिकारी को अपने कर्मचारियों में से किसी एक के लिए पारिश्रमिक स्वीकृत करता हो तो उसकी स्वीकृति में 43 (घ) में निर्धारित प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा जो कि स्वतः ही उस कार्य को लेने तथा पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

अवतरण 2 एवं 3 में कहे गये प्रकार के मामलों में उधार लेने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी करनी चाहिए यदि पारिश्रमिक की मात्रा परिसिद्ध 9 के क्रम सं० 9 से अधिक हो।

स्पष्टीकरण—नियम 43 (घ) के नीचे एक निर्णय द्वारा चाहा गया है कि किसी दूसरे विभाग के कार्य को लेने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने में राज्याधिकारियों द्वारा उधार देने वाले विभाग (Lending Deptt.) की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 (घ) में दिया हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य कर्मचारी प्राईवेट या सार्वजनिक संस्था या प्राईवेट व्यक्ति के कार्य को नहीं ले सकता है और न उसके बदले में कोई फीस ही स्वीकृत कर सकता है। इन प्रावधानों से कुछ मामलों में अनावश्यक देर हो गई है। सरकार ने सामान्य रूप से विचार किया है तथा उसी राय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, विद्वद्विद्यालयों एवं सरकारी विभिन्न विभागों प्रादि द्वारा जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उनके सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में कार्य करने तथा उसका पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप में स्वीकृति प्रदान करना जरूरी नहीं है। इसलिए सरकार प्रादेश देती है कि सरकार का एक अधिकारी जो निम्नलिखित परीक्षा लेने वाले निकार्थों द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने के लिए बुलाया जाता है वे इस शर्त के साथ कार्यभार व उसका पारिश्रमिक स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसा कार्य उनके साधारण कर्तव्यों में कोई बाधा नहीं आता :—

- (1) राजस्थान के विद्वद्विद्यालय।
- (2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय लोक सेवा आयोग।
- (3) प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षणालय, जयपुर।
- (4) राज्य सरकार के अन्य विभाग।

बोच निर्देशन—जहाँ अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में उन्हें पारि-

श्रमिय या शुल्क स्वीकृत करने के कारण भेजे जायें तार्किक वे स्वीकृति की प्रोत्तिव्यता की जाँच कर सकें ।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या परमनल एसिस्टेंट (निजि महायक), निजि सचिव/स्टेनोग्राफर (शीघ्र लिपिक) आदि जो कि कुछ नियमों/कम्पनियों के संचालक मण्डलों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मनोनीत अधिकारियों के साथ लगे होते हैं, उन्हें इन मण्डलों से शुल्क के रूप में अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है चूंकि वे उन अधिकारियों का कार्य करते हैं जिनके कि साथ वे सलग हैं और जो इन मण्डलों के कार्यों को पूरा करने के लिए मनोनीत हुए हैं । मामले की जांच कर ली गई है तथा यह निर्णय किया जाता है कि वे उन राज्याधिकारियों के साथ इन मण्डलों के कार्य को पूरा करने का कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

नियम 44. चिकित्सा अधिकारियों द्वारा फीस स्वीकार करने के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति—उन शर्तों एवं सीमाओं के लिए अलग से नियम हैं जिनके कि अनुसार व्यवसायिक चिकित्सा के लिए एवं व्यावसायिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं के लिए फीस राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वीकार की जा सकती है ।

× टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल आफिसर) शब्द के अन्तर्गत चीफ/पब्लिक एनालिस्ट (मुख्य, सरकारी विश्लेषक) भी शामिल हैं ।

नियम 45 व 46 विलोपित किये गये ।

नियम 47. सरकार के पास शुल्क कब जमा कराना चाहिये—जब तक सरकार विशेष आदेश द्वारा अथवा प्रकार से आदेशित न करे, 500) रु० अथवा वह शुल्क यदि आवश्यक हो, तो 250) रु० की वार्षिक राशि जो कि राज्य कर्मचारी को दी जाती है, से अधिक राशि के 1/3 भाग से अधिक राशि के शुल्क का 1/3 भाग सामान्य राजस्वों में जमा कराया जाएगा ।

टिप्पणियाँ (1) यह नियम विद्वत्विद्यालय या अन्य परोक्ष संस्था से, उसकी परीक्षक के रूप में की गई सेवाओं के परिणाम स्वरूप राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए शुल्कों पर लागू नहीं होगा ।

(2) राज्य कर्मचारी किसी अदानत के मध्यम तकनीकी मामलों में दस सप्ताह देने के कारण जो शुल्क प्राप्त करता है, वह उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है ।

+ (3) आवश्यक तथा अनावश्यक शुल्क अलग अलग समझे जाएंगे तथा उन्हें इस नियम के अन्तर्गत सामान्य राजस्व में 1 3 हिस्सा जमा कराने के लिए शामिल नहीं किया जावेगा । इस नियम में निर्धारित 400 रु० की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू समझी जानी चाहिए तथा अनावश्यक शुल्क के मामले में वित्तीय वर्ष में कुल आवश्यक शुल्क के योग के अनुसार सीमा लागू की जानी चाहिए ।

× वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एक 1 (77) एक डी (व्यय-नियम) 65-1 दिनांक 6-1-66 द्वारा शामिल किया गया तथा दिनांक 21-11-62 में प्रभावो किया गया ।

+ (वित्त विभाग की आज्ञा सख्या एक 1 (10) एक. डी. (व्यय नियम) 64-II दिनांक 29-9-64 द्वारा शामिल किया गया)

× निर्णय—एक सन्देश उत्पन्न किया गया है कि क्या भारतीय प्रशासनिक-सेवा (आई. ए. एस.) केडर के राज्याधिकारियों पर भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 तथा वित्त विभाग के भीमो संख्या एफ. (26) (30) एफ 1/54 दिनांक 1-10-54 के प्रावधान लागू होंगे ।

मामले की जांच करती गई है तथा यह निरुपेक्ष किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के केडर के अधिकारियों के मामले निम्न दोहराये गए एस. भार. एवं एम. भार. प्रावधानों द्वारा निपटाए जायेंगे जो कि नियम 47 व वित्त विभाग के उक्त भीमो के समान हैं ।

• एस. भार. (अनुपूरक नियम) 12—जब तक कि राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश द्वारा अन्यथा प्रकार से आदेश न दे दें, 400 रु० या यदि वह आवश्यक शुल्क है तो 250) रु० वार्षिक जो कि सरकारी कर्मचारी को दी जाती हो, से अधिक राशि के शुल्क का 1/3 भाग सामान्य राजस्व में जमा कराया जायेगा ।

नियम संख्या 2—राज्य कर्मचारी जो राजकीय प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी के आई-रेक्टरों के मण्डलों, सहकारी समितियों, स्वतन्त्र निकायों, (Autonomous Bodies) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नियमों या नियमित निकाय या सांविधिक (Statutory) मंडलों या अन्य संस्थाओं में भाग लेते हैं, फीस एवं अन्य पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता व्यय एवं दैनिक भत्ता) जो ऐसे निकायों द्वारा उनको दिया जाय, स्वीकार कर सकते हैं तथा सम्पूर्ण राशि को सम्पत्ति विभाग की प्राप्ति मद में जमा करा सकते हैं ।

किर भी ऐसे अधिकारी राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं । यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत करने वाले-विवरण में अधिकारी एक प्रमाण पत्र इस सम्बन्ध का देगा कि उसके द्वारा नियम से प्राप्त सम्पूर्ण फीस या पारिश्रमिक (यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सहित) राज्य सरकार को जमा करा दिया गया है ।

स्वामीय मीटिंगों के मामले में ऐसी प्रत्येक मीटिंग में उपस्थित होने के लिए वांछित भत्ता केवल 5) रु० प्राप्त करेंगे ।

• निर्णय संख्या 3—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या एक राज्य कर्मचारी को, जिसे सम्पन्न पाठ्यक्रम चालू रखने के लिए या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषयों में सम्पन्न करने के लिए सम्पन्न प्रवक्ता स्वीकृत किया गया है तथा जिसे अपने प्रवक्ता वेतन के प्रतिरिक्त छात्र-वृत्ति या स्टैण्डर्ड राजकीय या अराजकीय स्त्रोत से मिलता है, नियम 47 के अन्तर्गत स्टैण्डर्ड का 1/3 भाग सरकार को जमा कराना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि भारत की संविधान विधि या राज्य की संविधान विधि से छात्रवृत्ति या स्टैण्डर्ड (वर्गीकृत) के रूप का कोई भी भुगतान नियम 7 (13) के अन्तर्गत 'पारिश्रमिक' माना जाता है । केवल उन्हीं समय जब राज्य कर्मचारी उक्त दोनों साधनों के प्रतिरिक्त अन्य साधन द्वारा छात्रवृत्ति या स्टैण्डर्ड प्राप्त करता है, उसे फीस के रूप में समझा जायेगा ।

× वित्त विभाग की भाज्ञा संख्या एफ. 16 (50)-एफ. डी. (व्यय नियम) 65 दिनांक 27-8-65 द्वारा 250 के स्थान पर 400 रु० किए गए ।

क (वित्त विभाग की भाज्ञा संख्या एफ. 1 (50) (व्यय-नियम) 75 दिनांक 27-8-65 द्वारा पारित किया गया)

यह यह निर्णय किया गया है कि अध्ययन अवकाश या अन्य अवकाश काल में अध्ययन पाठ्यक्रम खालू रखने या किसी व्यवसायात्मक या तकनीकी विषय में अध्ययन के लिए यदि कोई भी राज्य कर्मचारी भारत की संविधान विधि या राज्य की संविधान विधि के अनुरिक्त अन्य मायन से छात्रवृत्ति या स्टेंडपन्ड (बन्नीफर) प्राप्त करेगा, उसमें से नियम 47 के अधीन कोई कटौती नहीं की जावेगी ।

निर्णय संख्या 4—मीमो दिनांक 24-9-59 के द्वारा विस्तृत किए गए नियम 7 (9) के अन्तर्गत आह्वितिक, मौखिक एवं कलामक से प्राप्त ज्ञान, यदि ऐसे प्रयत्न राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान से सम्बन्धित है, 'फीस' होनी है, जब ऐसी ज्ञान भारत की संविधान विधि एवं राज्य की संविधान विधि के अनुरिक्त अन्य मायन से होती है तथा वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 के प्रावधानों के अन्तर्गत जानी है । अब यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने सेवाकाल में प्राप्त ज्ञान की सहायता से कोई पुस्तक लिखे तथा वह पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमनों या पद्धतियों का सूचन मात्र न हो बल्कि लेखक की बुद्धिमत्ता को प्रकट करे तो ऐसी पुस्तकों के लेखने तथा उनकी रायल्टी में होने वाली आमदनी पर नियम 47 लागू नहीं किया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे मामलों में नियम 47 में छूट देने की दिशारिक्त करते समय ज्ञान सम्बन्ध का एक प्रमाणपत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए । यह भी निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 49 के अन्तर्गत सहाय प्राधिकारी की स्वीकृति से उसके द्वारा निकाले गए आविष्कार से प्राप्त होने वाली आमदनी को के अन्तर्गत नहीं लाया जावेगा ।

निर्णय सं० 5—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 47 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को (1) उनके द्वारा परीक्षक, पेपर सेटर, म्युनिसिपैलिटी, निरीक्षक (इन्विजिनेटर) या जॉब कर्ता के रूप में दी गई सेवाओं के बढते बिन्दु विद्यालय, विद्या बोर्ड या अन्य परीक्षा देने वाली संस्था से प्राप्त की गई फीसों के सम्बन्ध में व (2) अपने कार्य में बिना रुकावट डाले नगरपालिकाओं, ग्राम्य स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, पंचायत समितियों व उनकी सेवाओं की फीस प्राप्त करने के बारे में छूट दे दी है ।

फिर भी, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 43 के प्रावधान खालू रहेंगे तथा नियम 43 के प्रावधान के अन्तर्गत मन्त्र प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उपरोक्त व्यवस्था के अधीन कोई कार्य नहीं लिया जावेगा तथा न कोई मुन्त्र ही स्वीकार किया जावेगा ।

टिप्पणी :—विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा संस्था में परीक्षक के रूप में काम करने पर जो राज्य कर्मचारी अपनी सेवाओं के बढते मुन्त्र प्राप्त करता है, उन पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है ।

नियम 48. बिना विशेष आज्ञा के स्वीकार किया जाने वाला भुगतान—राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुरिक्त, कोई भी राज्य कर्मचारी बिना विशेष स्वीकृति के, निम्न राशि प्राप्त करने एवं उसे अपने पाम रखने का हक्कदार है :—

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में किसी नियन्त्र या योजना के लिए दिया गया भुगतान ।

(ए) न्याय के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अपराधी को गिरफ्तार कराने या कोई सूचना देने या विशेष सेवा करने के लिए कोई इनाम प्राप्त किया हो ।

(ग) किसी अधिनियम या विनियमनों या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई इनाम जो वो जाने वाली हो ।

(घ) कस्टम एवं आबकारी (एक्साइज) नियमों के प्रशासन के सम्बन्ध में जो गई सेवाओं के लिए स्वीकृत इनाम ।

(ङ) किसी विशेष या स्थानीय नियम अथवा सरकार की आदेश द्वारा सरकारी हस्तियत से पूरी की जाने वाली सेवाओं के लिये किसी राज्य कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला शुल्क ।

(च) 'राजस्थान एवार्ड ऑफ कंस प्राइजेज टू गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स' 1960 के अधीन सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा इनाम में दी गई मुद्रा इनाम ।

नियम संख्या 1. राज्य कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय आकाशवाणी (All India Radio) कार्यक्रमों में भाग लेने तथा उनको उसका पारिश्रमिक स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रश्न की जाँच सरकार द्वारा गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के अपने पत्र संख्या 25/32/56 स्वा/ए दिनांक 15-1-57 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार की गई । यह निर्णय किया गया है कि यदि प्रसारण शुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रकृति के हों तो उन्हें अखिल भारतीय आकाशवाणी से प्रसारण के लिये कोई आज्ञा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है । ऐसे मामलों में यह निश्चय करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर होगी कि प्रसूत प्रसारण ऐसी प्रकृति के हैं या नहीं ।

यह सरकार भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथा से सहमत हो गई है जिसके अनुसार एक सरकार द्वारा अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों को किये सभी भुगतान 'पारिश्रमिक' व शुल्क के रूप में माने जाने हैं एवं उसके किसी भी भाग की वसूली उसे कीस मान कर नहीं की जा सकेगी ।

यह और भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामले जिनमें प्रसारण की कोई स्वीकृति की जरूरत न हो, उनमें राज्य कर्मचारी को पारिश्रमिक प्राप्त करने में भी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है । जिन मामलों में प्रसारण की स्वीकृति लेना आवश्यक हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति में, यदि दी जा चुकी हो, उसके पारिश्रमिक की स्वीकृति भी शामिल की हुई समझी जानी चाहिये ।

नियम सं० 2. यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन के प्रसार हेतु अखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

स्पष्टीकरण— इस विभाग की आज्ञा दिनांक 18-11-67 (नियम 113 के नीचे निर्णय सं० 2 के रूप में प्रदर्शित है) में राज्य कर्मचारियों को यह अनुमति प्रदान की गई थी कि वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (74) वित्त वि (व्यय नियम) दिनांक 16-11-67 द्वारा निविष्ट ।

+ परिपत्र सं० एफ 1 (74) वित्त वि (व्यय नियम) दि० 4-4-68 द्वारा निविष्ट ।

कि वे बिना तक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आकाशवाणी पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कहा भी गई है कि क्या राज्य कर्मचारी इस प्रसारण का पारिश्रमिक (रेगुलरेशन) भी बिना तक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु तक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।

आदेश— X यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को हृदि, पशुपालन सहकारिता एवं पंचायत एवं विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियों के प्रसार हेतु मखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

नियम 49. अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकारी (पेटेन्टराइट) प्राप्त करने पर प्रतियोग-एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवाएँ संज्ञाना एवं तकनीकी अनुसंधान करने की हों, सरकार की स्वीकृति के तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किए गए नए आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा। न वह किसी अन्य व्यक्ति को निवेदन करने के लिये या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

+ **नियम 50.** नियुक्तियों का समन्वय—सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी भी एक समय में दो स्वतंत्र पदों पर स्थाई, अस्थायी या स्थानापन्न रूप से एक साथ काम करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियमित होगा।

(क) एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन—वह उन पदों में से अधिकतम वेतन वाले पद का अधिकतम वेतन प्राप्त कर सकता है क्योंकि यदि वह उस अकेले पद पर कार्य करता तो उसे प्राप्त करता। यह उस वेतन की पद की अवधि तक प्राप्त कर सकता है।

+ (ख) अन्य पद के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो कि जैसा सरकार निर्धारित करे, परन्तु वह उस पद के प्रारम्भिक (प्रिन्सिपल) वेतन के 1/5 भाग से ज्यादा नहीं होगा।

(ग) यदि किसी पद या अधिक पदों के साथ क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते जुड़े हुए हों तो वह ऐसे क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते प्राप्त कर सकता है जिसे सरकार निर्दिष्ट करे परन्तु यह है कि ऐसे भत्ते समस्त पदों के साथ संलग्न क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्तों के योग से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणियाँ—(1) से (5) विसीपत्र

X वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (70) वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 3-11-69 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (24) वित्त वि (नियम) 69 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

नियम 50 क व 50 ख (विलोपित)

जांच निर्देश—नियम 50 (ख) के प्रयोजन हेतु प्रारम्भिक वेतन यह समझा जाना चाहिए । जिसे सरकारी कर्मचारी जिसे अतिरिक्त चार्ज दिया गया है नियम 26 के अधीन अतिरिक्त पद के समय वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा जैसे मानो वह उस पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित होता । फिर भी, ऐसे मामलों में जहाँ निम्न पद का अधिकतम वेतन सरकारी कर्मचारी के उसके स्थाई पद के वेतन से कम है तो निम्न पद का अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक वेतन समझा जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 1 व 2 विलोपित किये गये

स्पष्टीकरण—विलोपित किया गया ।

निर्णय संख्या 3—सरकार ने उस तारीख से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया है कि उन मामलों में किस तारीख से पदों के सृजन की स्वीकृति की प्रभावी समझा जाना चाहिए जहाँ स्वयं स्वीकृति में उसके प्रभावी होने की तारीख को विशेष उल्लेख नहीं हो । यह निश्चय किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्रभावी की तारीख उस तारीख से समझी जायगी जिसको कि यह सूचित पद पूर्णकालिक आधार पर प्रथम बार भरा गया है । चूंकि उस समय से पूर्व उस पद को अस्तित्व में ही नहीं समझा जाएगा अतः उक्त तारीख से पूर्व किसी भी प्रवधि के लिए उक्त पद के कार्य के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए स्थानान्तरण वेतन या अतिरिक्त वेतन दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा ।

(इस सम्बन्ध में नियम 35 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण भी देखें)

अध्याय ७

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति (Deputation out of India)

नियम 51. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता के शीर्षक सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित होगा—अब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा अस्थाई रूप से भारत के बाहर, भारत में पारण किये गये अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिए अस्थाई रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन एवं भत्ता निम्नलिखित भारत सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित होगा—

+ विषय—बाहर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन देने के लिए पद का औपचारिक रूप से सृजन—राजस्थान सेवा नियमों का नियम 51 ।

अब कोई सरकारी कर्मचारी बाहर सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो एक भलग पद के सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में तथा वेतन व भत्तों को विनियमित करने की प्रक्रिया के बारे में बार बार संदेह व्यक्त किए जाते हैं ।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एच 1 (37) वित्त वि० (अग्र नियम) 64 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट ।

कि वे बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आकाशवाणी पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में संका की गई है कि नया राज्य कर्मचारी इस प्रसारण का पारिश्रमिक (रेड्युनरेशन) भी बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त कार्य के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है।

आदेश— X यह आदेश दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को दृष्टि, पशुपालन सहकारिता एवं पंचायत एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियों के प्रसार हेतु प्रखिल भारतीय आकाशवाणी पर प्रसारित करने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

नियम 49. अनुसंधान कार्य में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा किये गये किसी आविष्कार के स्वाधिकारी (पेटेन्ट राइट) प्राप्त करने पर प्रतिपेय—एक राज्य कर्मचारी जिसकी सेवामें वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने की हो, सरकार की स्वीकृति के तथा उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के बिना वह अपने द्वारा किए गए नए आविष्कार के स्वाधिकार प्राप्त करने के लिए निवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा। न वह किसी अन्य व्यक्ति को निवेदन करने के लिये या प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय ६

नियुक्तियों का समन्वय (Combination of appointments)

+ **नियम 50.** नियुक्तियों का समन्वय—सरकार किसी भी राज्य कर्मचारी को किसी भी एक समय में दो स्वतंत्र पदों पर स्टाई, अस्थाई या स्वतन्त्र रूप से एक साथ काम करने के लिये नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में उसका वेतन निम्न प्रकार से नियमित होगा।

(क) एक से अधिक पद ग्रहण करने पर वेतन का नियमन—वह उन पदों में से अधिकतम वेतन वाले पद का अधिकतम वेतन प्राप्त कर सकता है क्योंकि यदि वह उस अकेले पद पर कार्य करता तो उसे प्राप्त करता। वह उस वेतन को पद की अवधि तक प्राप्त कर सकता है।

+ (ख) अन्य पद के लिये वह ऐसा उचित वेतन प्राप्त करेगा जो कि सैदा सरकार निर्धारित करे, परन्तु वह उस पद के प्रारम्भिक (प्रिन्सिपल) वेतन के 1.5 भाग से ज्यादा नहीं होगा।

(ग) यदि किसी पद या अधिक पदों के साथ क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते जुड़े हुए हों तो वह ऐसे क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्ते प्राप्त कर सकता है जिसे सरकार निर्दिष्ट करे परन्तु यह है कि ऐसे भत्ते समस्त पदों के साथ संलग्न क्षतिपूर्ति या सिम्पचुरी भत्तों के योग से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणियाँ—(1) से (5) विलोपित

X वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (70) वित्त वि (नियम) 65 दिनांक 5-11-69 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (24) वित्त वि (नियम) 69 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

नियम 50 क व 50 स (बिलोपित)

जांच निवेद—नियम 50 (स) के प्रयोजन हेतु प्रारम्भिक वेतन वह समझा जाना चाहिए। जिसे सरकारी कर्मचारी जिसे अतिरिक्त धाज दिया गया है नियम 26 के अधीन अतिरिक्त पद के समय वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा जैसे मानो वह उस पर औपचारिक रूप से स्थानान्तरित होता। फिर भी, ऐसे मामलों में जहाँ निम्न पद का अधिकतम वेतन सरकारी कर्मचारी के उसके स्थाई पद के वेतन से कम है तो निम्न पद का अधिकतम वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक वेतन समझा जाना चाहिए।

निर्णय संख्या 1 व 2 बिलोपित किये गये

स्पष्टीकरण—बिलोपित किया गया।

निर्णय संख्या 3—सरकार ने उस तारीख से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया है कि उन मामलों में किस तारीख से पदों के सृजन की स्वीकृति को प्रभावी समझा जाना चाहिए जहाँ स्थायी स्वीकृति के उसके प्रभावी होने की तारीख का विशेष उल्लेख नहीं हो। यह निश्चय किया जाता है कि ऐसे मामलों में प्रभावी की तारीख उस तारीख से समझी जायेगी जिसको कि यह सृजित पद पूर्णकालिक आधार पर प्रथम बार मरा गया है। चूंकि उस समय से पूर्व उस पद की अस्तित्व में ही नहीं समझा जाया अतः उक्त तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए उक्त पद के कार्य के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए स्थानान्तरण वेतन या अतिरिक्त वेतन दिया जाता स्वीकार्य नहीं होगा।

(इस सम्बन्ध में नियम 35 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण भी देखें)

अध्याय ७**भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति (Deputation out of India)**

नियम 51. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता के औपचारिक रूप से सृजन—राजस्थान सेवा नियमों का नियम 51। जब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा स्थायी रूप से भारत के बाहर, भारत में धारण किये गये अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिए अस्थाई रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन एवं भत्ता निम्नलिखित भारत सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित होगा—

1. विषय—बाहर सेवा पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन देने के लिए पद का औपचारिक रूप से सृजन—राजस्थान सेवा नियमों का नियम 51।

जब कोई सरकारी कर्मचारी बाहर सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो एक प्रत्येक पद के सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में तथा वेतन व भत्तों को नियमित करने की प्रक्रिया के बारे में बार बार सम्बन्ध व्यक्त किए जाते हैं।

1. वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (37) वित्त वि० (अप. नियम) 64 दिनांक 15-12-69 द्वारा निविष्ट।

यह स्पष्ट किया जाना है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के अधीन, किसी भी सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए बाहर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य की भांति, मोटिंग या सेमीनार में उपस्थित होने के लिए सेवा के सदस्य के रूप में समझा जाता है। इसी प्रकार कभी कभी किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में समझे जाते हुए बाहर किसी प्रसिद्धि में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। दोनों मामलों में वह बाहर प्रतिनियुक्ति को छोड़कर जो वेतन प्राप्त करता, वही वेतन प्राप्त करता है। ऐसे मामले में, बाहर प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त पद को भरने के लिए स्थानापन्न प्रबन्ध किया जा सकता है तथा बाहर प्रतिनियुक्ति किए गए सरकारी कर्मचारी को खपाने के लिए नए पद का सृजन करना आवश्यक नहीं है। बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सरकारी कर्मचारी को विशेष सेवा पर समझा जाता है यद्यपि किसी भी पद पर यह अपना वेतन प्राप्त नहीं करता है तो भी उसका वेतन वही समझा जाता है जो यदि वह भारत में ज्यूटी पर रहता तो प्राप्त करता।

भारत सरकार के नियम जिनके अनुसार भारत के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किए गए राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते विनियमित किए जाते हैं।

भौतिक नियम (F.R.) 51 जब कोई राज्य कर्मचारी उचित स्वीकृति द्वारा अस्थायी समय के लिए भारत के बाहर, भारत में धारण किये गये अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्त किया जाता है या किसी विशेष कार्य के लिये अस्थायी रूप से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे अपने प्रतिनियुक्ति काल में वही वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जिसे वह भारत में, सेवा में उपस्थित रहने पर प्राप्त करता रहता।

परन्तु यदि यह है कि एक राज्य कर्मचारी जो 'प्रोमोशन वेतन' (एवरेज पे) पर भारत के बाहर पहिले से ही प्रवक्तान पर हो, तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रवक्तान में और रहने के लिये कहा जाय तो ऐसे मामले में उसे उस समय में अपने प्रवक्तान वेतन के अतिरिक्त, स्वयं के वेतन का 1/6 भाग पारिधमिक के रूप में मिलेगा जिसे कि यदि वह भारत में सेवा में रहता तो प्राप्त करता। भारत से आने जाने का यात्रा व्यय स्वयं उसके द्वारा ही सहन किया जावेगा।

टिप्पणी—वेतन का वह भाग जिसे राज्य कर्मचारी को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति के समय विदेशी मुद्रा (करेंसी) में प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, वह इस सम्बन्ध में समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट किया जावेगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य कर्मचारी को विदेशी देश में क्षतिपूर्क भत्ता उस धनराशि तक स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति उचित समझे।

उपनियम (1) और उपनियम (2) के अन्तर्गत, वेतन, पारिधमिक या क्षतिपूर्क भत्ते के बराबर की विदेशी मुद्रा विनियम की इस दर से गिनी जायेगी जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

भौतिक नियम 51 क—जब किसी सरकारी कर्मचारी को उचित स्वीकृति के साथ जिस सेवा के संवर्ग से उसका सम्बन्ध है उसमें नियुक्त पद के अतिरिक्त अन्य नियमित रूप से गठित स्थायी या अर्द्ध-स्थायी पद को धारण करने हेतु भारत के बाहर ज्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है तो उसका वेतन भारत सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

भारत सरकार के अधीन सेवा करने वाले सिविल अधिकारियों को, 4 वे योरोप जिसमें

नियर ईस्ट व समरोका भी शामिल हैं, दो गई रियायतें मौलिक नियमों के भाग 11 के परिशिष्ट संख्या 7 में दोहराई गई हैं ।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन भारत के बाहर प्रशिक्षण पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले वेतन, विदेश अथवा आदि के सम्बन्ध में शर्तें—

निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि जब राज्य कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्र सभ, कोन्सो प्लान, चार सूत्रीय कार्यक्रम आदि की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाते हैं तथा योजनाएं गैर सरकारी एजेंसियों (रोक फेलर फाउन्डेशन, फोडे फाउन्डेशन आदि) द्वारा चालू की जाती हों तो उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार से विनियमित की जायेगी ।

(1) वेतन—भारत में अपने पद से राज्य कर्मचारी के अनुपस्थित रहने का पूर्ण समय उस पूर्ण वेतन पर 'प्रतिनियुक्ति काल' के रूप में माना जावेगा जिसे कि यदि वह भारत में सेवा में रहता तो प्राप्त करता ।

+ (ii) अपने प्रशिक्षण के प्रथम 6 माह के दौरान सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत किया जा सकता है जिस पर कि वह उसे प्राप्त करता यदि वह भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रवाना नहीं होता । 6 माह के बाद के प्रशिक्षण के लिए कोई महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा फिर भी, यदि सरकारी कर्मचारी ने राजस्थान सैन्य सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 19.1 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वेतनमान को रखा है या वह वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (7) वित्त वि. (नियम) 69 दिनांक 7-4-59 के अधीन महंगाई वेतन के लिए अन्य प्रकार से हकदार है तो उसे छह माह के बाद की प्रशिक्षण अवधि में महंगाई भत्ता, बाहर प्रतिनियुक्ति के दौरान वेतन के अनुकूल महंगाई वेतन के बराबर की दर पर स्वीकृत किया जा सकता है ।

(iii) भ्रमण किराया भत्ता/किराये की वसूली—उसी समान दर से, जिसे वह भारत में प्राप्त करता परन्तु विदेश में प्रतिनियुक्त हो गया, प्रशिक्षण के पूरे समय का भ्रमण किराया भत्ता भ्रमण किराया भत्ता नियम (राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 17) के नियम 9 में दी गई शर्तों को पूरा करने के आधार पर मिलेगा । यदि राज्य कर्मचारी को अपने विदेश में प्रतिनियुक्ति के काल में राजकीय निवास सुविधा प्राप्त करने की इजाजत दे दी जाती है तो उसका किराया साधारण रूप में उसी दर से वसूल करते रहना चाहिए जो कि उससे साधारण तौर पर वसूल किया जाता रहता यदि वह प्रतिनियुक्ति पर रवाना नहीं होता ।

चूंकि इन आदेशों के अन्तर्गत शर्तें वर्तमान शर्तों के अनिश्चित उचित रूप से अधिक उदार होंगी, इसलिए यह निश्चित करना जरूरी है कि प्रशिक्षण के लिये विदेश में भेजे गये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का समय अत्यावश्यक समय से ज्यादा लम्बा नहीं होना चाहिये ।

और भी वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत विदेश में राज्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से सम्बन्धित प्रशासनात्मक विभागों की ओर से होना चाहिए । किसी भी

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (87) वित्त वि. (नियम) 62 दिनांक 13-8-70 द्वारा प्रतिस्थापित

हासत में राज्य कर्मचारियों को स्वयं विदेशी सरकारों या संस्थाओं में छान्दवृत्तियां प्राप्त करने के लिये सोपा प्रयास या बानबोन नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त अवतरण 1 में वर्णित शर्तों के अनुसार बाहर विदेश में प्रतिभण के मामले को चलाने में पूर्व यह निश्चय कर लेना जरूरी है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को सेवाएं एक उचित समय के लिये राज्य सरकार को उपलब्ध हो सकेंगी जैसे क्षयना प्रतिभण पूर्ण करने के बाद कम से कम + चार साल तक उसे नौकरी करनी होगी एवं इस बात का भी ध्यान रचना होगा कि प्राधिकारों को उस विषय का पूरा पूर्व ज्ञान होना चाहिये जिसमें कि वह प्रतिभण प्राप्त करेगा। इसलिये प्रतिभण योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभण के लिये सरकार द्वारा भेजे जाने वाले राज्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों को स्वीकृत कराने में साधारणतया निम्न बातों में सन्तुष्ट हो जाना चाहिए—

(क) प्रतिभण पूर्ण करने के बाद कम से कम उसे चार साल तक सेवा करनी चाहिए एवं उस अवधि तक उसे सेवा में मुक्त (रिटायर) करने को माना नहीं करनी चाहिये।

(ख) यदि कोई राज्य कर्मचारी सरकार को प्रस्ताई सेवा में नियुक्त हो तो प्रतिभण की समाप्ति के बाद कम से कम चार साल तक उसके राजकोष सेवा में रहने की सम्भावना होनी चाहिये तथा उसे लिखित में इस बात का एक प्रतिज्ञा पत्र देना चाहिये कि वह उसने समय के लिए राज्य सरकार की सेवा करने में सहमत है।

(ग) उसे कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर लेनी चाहिए। इस अवधि में ऐसी दशा में फिर भी रिटायर को ना मरनी है बल्कि प्रतिभण को प्रकृति इस प्रकार के प्रतिबन्ध पर चल न देती हो दूसरे शब्दों में बल्कि यदि इस पत्र के माध्यम नियुक्त किया गया हो कि उनकी नियमित कर्तव्यों (ज्युटो) पर लगाने में पूर्व प्रतिभण के लिए जाना चाहिये।

(घ) ऐसे मामलों में 18 माह की प्रतिनियुक्ति का समय साधारणतया उचित रूप से अधिकतम समय समझा जाना चाहिए।

यदि विदेश में प्रतिभण का सम्बन्ध डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने से हो प्रतिभण के प्रथम 6 माह उपरोक्त अवतरण 1 में दी गई शर्तों के साधारण पर प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जावेगा। गैर समय निम्न शर्तों पर 'विशेष अवकाश' (Special leave) की स्वीकृति द्वारा नियमित किया जावेगा—

(i) विशेष अवकाश का समय उपरि के लिए सेवा के रूप में गिना जावेगा, तथा यदि कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने वाली सेवा में है तो वह समय पेन्शन के लिए भी गिना जावेगा।

(ii) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखे (Account) में से नहीं काटा जावेगा।

(iii) विशेष अवकाश का 'अवकाश वेतन' राज्य कर्मचारी के अर्द्ध वेतन अवकाश (Half pay leave) के लिए स्वीकृत अवकाश वेतन के बराबर होगा।

(iv) विशेष अवकाश के समय में कोई मंहगाई भत्ता मिल सकेगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (87) वित्त वि० (ए) नियम/62 दिनांक 27-5-68 द्वारा तीन साल के स्थान पर प्रतिस्थापित)

(v) मकान किराया भत्ता उपरोक्त अवतरण । (3) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जावेगा ।

एक राज्य कर्मचारी जो भारत के बाहर प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त हो जाता है तो वह प्रशिक्षण के समय का ध्यान न रखते हुए इस अध्याय के अन्त में संलग्न एक फार्म में प्रतिज्ञा पत्र (Bond) भरेगा । बोर्ड में जिस कुल राशि को सोटाने का विशिष्ट उल्लेख किया जावेगा उसमें सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को दो गई कुल राशि जैसे वेतन एवं भत्ते, भवकाश वेतन, फीस की राशि, यात्रा एवं अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एवं सम्बन्धित विदेशी सरकारी एजेंसियों द्वारा सहन किये गए प्रशिक्षण के व्यय आदि शामिल होंगे । विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा चरा गया बॉन्ड नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की अभिरक्षा (कस्टोडी) में रखा जावेगा ।

जिस किसी भी राज्य कर्मचारी को विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत देश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, उसकी जांच एक समिति द्वारा होगी जो कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव (व्यय) × (विकास प्रायुक्त) एवं सम्बन्धित विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी । यदि आवश्यक हो तो समिति सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को भी सहचरित (Co-opt) कर सकती है ।

व्यक्तिगत मामलों में उपरोक्त प्रतिनियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में वास्तविक स्वीकृतियों केवल वित्त विभाग (व्यय) की सहायता में ही जारी की जानी चाहिये ।

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होंगे । इन आदेशों के जारी होने की तारीख से या उसके बाद से प्रशिक्षण पर रवाना होने वाले राज्य कर्मचारियों के मामले इसमें दिये गए प्रावधानों के अनुसार ही विनियमित होंगे । इन आदेशों के विपरीत अन्यथा प्रकार से जो मामले पूर्व में तय हो गए हों उन्हें पुनः चलाने की आवश्यकता नहीं ।

नियम संख्या 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या उन मामलों में भी बॉन्ड भराने की आवश्यकता समझी जायेगी जिनमें कि प्रशिक्षण का समय (दिन से प्रशिक्षण स्थान तक आने जाने के समय को निकाल कर) 6 माह से ज्यादा का न हो तथा पूर्ण समय पूर्ण वेतन पर प्रतिनियुक्ति का समय समझा जावे । यह निर्णय किया गया है कि विदेश में प्रशिक्षण के सभी मामलों में जो कि, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि प्रतिनियुक्ति के समय को प्रतिनियुक्ति या विशेष भवकाश के रूप में माना जाय, नियम 51 के नीचे दिये गए राजस्थान सरकार के निर्णय से नियमित किये जाते हैं उसके अनुसार प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को बॉन्ड भरने के लिए कहा जाना चाहिये । ऐसे सभी मामलों में बॉन्ड परिशिष्ट 18 पर दिए गए संबंधित प्रश्न में निम्नांकित किया जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 3—(1) सेंट्रल भोवरसीज स्कालरशिप योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है तथा वह विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं उच्चतर शिक्षा की समान संस्थाओं के लिए है

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (87) एफ डी/(ए) /62 दिनांक 19-7-65 द्वारा शामिल किया गया ।

ताकि वे अपने अध्यापकों को भारत के बाहर उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें तथा इस प्रकार देश में पाठ्यक्रम व अनुसंधान का स्तर ऊँचा उठा सकें। इस योजना के अन्तर्गत मेन्टेनेंस एनालन्स, रेल एवं समुद्र विरामा, व्यूशन एवं परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की कीमत आदि के व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार अनुदान देती है तथा शेष 50 प्रतिशत तक रक्षा जिम्मेदार एजेंसी को देना पड़ता है। मेन्टेनेंस एनालन्स व अन्य सुविधाओं का पूर्ण व्यय पहिले पहिल भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित निधि से महन किया जाता है। भेजे गये उम्मीदवार के द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उपरोक्त आधार पर बांट दिया जायेगा।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति के सम्बन्ध का मामला कुछ समय पूर्व से ही राज्य सरकार के विचाराधीन था तथा यह आदेश दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत भारत के बाहर उच्चतर शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए चयन किए गए राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें माननी होंगी—

(क) विशेष अवकाश का समय उन्नति के लिए सेवा में गिना जायेगा तथा यदि राज्य कर्मचारी पेंशन योग्य सेवा में हो तो वह समय पेंशन के लिए भी गिना जावेगा।

(ख) 'विशेष अवकाश' राज्य कर्मचारी के अवकाश लेख में नाम नहीं लिखा जावेगा। 'विशेष अवकाश' में अवकाश वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 97 के लच्छ (2) के प्रावधान के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(ग) उपरोक्त लच्छ (ख) के अन्तर्गत अवकाश वेतन के साथ में मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 10 (10) एक. II/53 दिनांक 27-2-56 में दी गई दरों के अनुसार नियमित किया जावेगा।

(3) उम्मीदवारों के चयन एवं छोट भरने की पद्धति, जैसा कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 51 के निर्णय में दिया हुआ है, इन मामलों में भी लागू होगा।

निर्णय संख्या 4—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या अस्थाई राज्य कर्मचारी को भी विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। यदि हा, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ?

मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया है कि आचारण नीर पर अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए जबकि आवश्यक योग्यता रखने वाले अस्थाई राज्य कर्मचारी उपलब्ध न हों। जब एक अस्थाई राज्य कर्मचारी उपयुक्त योग्यता के साथ उच्च विभाग में उपलब्ध न हो तो अस्थाई राज्य कर्मचारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। परन्तु शर्त यह है कि—

(i) अस्थाई राज्य कर्मचारी ने अपनी तीन साल की सेवाएं पूरी करली हों,

(ii) एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की नियुक्ति नियमित हो अर्थात् वह नियुक्ति के लिये आवश्यक शिक्षा, आयु व योग्यता आदि रखता हो तथा जहां सेवा नियमों में आवश्यक हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करली हो।

+ निर्णय संख्या (5) एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी,

+ (वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (87) एक. टी. ए. (नियम) 62 दिनांक 3-5-64 द्वारा शामिल किया गया)

जिसकी कि विदेश (abroad) में समयावधि बढ़ा दी गई है, के मामले में एक पूरा बन्धन पत्र (बॉन्ड) प्रशिक्षण की ऐसी अवधि अवधि में प्रशिक्षण की लागत को अन्तर्विष्ट किए जाने के लिए भरना आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि, ऐसे समस्त मामलों में, अनुपूरक बॉन्ड आवश्यक होगा एवं जिन राज्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है, उनसे यह बोध भरवा लिया जाना चाहिए। स्थायी एवं अस्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए अनुपूरक बन्धन पत्रों के प्रसंग प्रपत्र इसके साथ संलग्न हैं।

अनुपूरक बॉन्ड में निदिष्ट की जाने वाली प्रत्यावर्तन (refund) की एक मुदत राशि में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को चुकाई गयी समस्त राशियों को या उसके प्रशिक्षण की, अवधि अवधि में उस पर किए गए समस्त व्ययों की राशि को सर्वात् वेतन एवं भत्ते, अवकाश वेतन, शुल्कों की लागत, यात्रा एवं अन्य व्यय, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का व्यय एवं विदेशी सम्बन्धित सरकार/एजेंसी द्वारा सहन किए विदेश के प्रशिक्षण की लागत, शामिल किया जाना चाहिए।

अनुरूपक बन्धन पत्र का बराया जाना ऐसे मामलों में भी प्रवृत्त कराया जा सकता है जो एवदपश्चात् होते हों एवं इसे ऐसे मामलों में भराये जाने पर जोर देने की जरूरत नहीं है जिनमें कि प्रशिक्षण के लिए प्रतिनिष्ठिक की अवधि की वृद्धि के आदेश पहिले ही जारी किए जा चुके हैं।

× निर्णय सं० 6—यह तय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को जो विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अधीन भारत के बाहर प्रशिक्षण पर भेजे जाते हैं, उन्हें उनकी वांछी यात्रा पर नीचे पैरा 3 में बलित अधिकतम सीमा तक की स्टोप ओवर/स्टे ओवर सम्बन्धी रियायतें उपभोग करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रयोजनाय प्रशिक्षणाधिकियों को अवकाश उनके प्रशासनिक विभागों से तथा प्रयुक्त भेजने वाले अधिकारी, यदि कोई हो, से प्राप्त करनी होगी तथा इसके बाद यात्रा का प्रबन्ध करने वाली सम्बन्धी एजेंसी के पास स्वीकृति के आदेश के साथ जाना होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना है कि यात्रा के रूप में किया गया व्यय जो ऐसे स्टोप ओवर/स्टे ओवर पर किया जाय वह स्वयं प्रशिक्षणाधिकियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रयोजनाय प्रशिक्षणाधिकियों द्वारा सहायता एजेंसियों को किसी प्रकार का निवेदन नहीं करना चाहिए।

स्टोप ओवर/स्टे ओवर की लागत को पूरा करने हेतु प्रशिक्षणाधिकियों को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके पास हक की उपलब्ध विदेशी मुद्रा की उचित राशि होने पर ही ऐसा ध्यान करना चाहिए।

वापसी यात्रा पर स्टोप ओवर/स्टे ओवर की व्यवस्था निम्न सीमाओं के भीतर की जा सकती है।

(क) जब बाहर का प्रशिक्षण 3 माह या इससे कम का हो तो प्रशिक्षणाधिकी एक सप्ताह तक की अवधि तक का स्टोप ओवर/स्टे ओवर कर सकता है।

(ब) लेकिन जब प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से अधिक किन्तु 6 माह से कम हो तो स्टोप ओवर/स्टे ओवर 2 सप्ताह तक हो सकता है।

× वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक I (10) वित्त वि (व्यय-नियम) 66 दि० 5-5-66 द्वारा निविष्ट

(ग) जब प्रशिक्षण अवधि ६ माह की हो तो स्टाप ओवर/स्टे ओवर तीन सप्ताह तक हो सकता है ।

प्रशासनिक विभाग पैराग्राफ ३ में निर्धारित सीमाओं के भीतर स्टाप ओवर/स्टे ओवर स्वीकृत करने हेतु मजमूदा प्राधिकारी होगा । पैरा ३ में निर्धारित सीमा में अधिक के स्टाप ओवर/स्टे ओवर की कोई धागा नहीं दी जाएगी तथा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि वे ऐसी निकाशियों विशेष विचार हेतु वित्त विभाग को न भेजें ।

यद्यपि पैरा ३ के अनुसार स्टाप ओवर सामान्यतया वापसी यात्रा के लिए ही स्वीकृत किया जाता है लेकिन निर्धारित सम्पूर्ण सीमाओं एवं उन्हीं शर्तों के भीतर अधिकतम एक सप्ताह तक की घाट्टा बाहे यात्रा में भी स्वीकृत करने में कोई हानि नहीं है बशर्ते कि प्रशासनिक विभाग हमारे समुष्ट हो जाए कि प्रशिक्षणार्थी के पास तत्प्रयोजनार्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा है ।

§ निर्णय संख्या ७ विषय—छह माह से अधिक समय के लिए प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे गए अधिकारियों के लिए शर्तें स्वीकृत किया जाना—राजस्थान सेवा नियमों के नियम ५१ के मोचे राजस्थान सरकार का निर्णय ।

उपयुक्त राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या १ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा यह कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि उक्त निर्णय संख्या १ में अन्तर्निहित प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बाहर जाने वाले अधिकारियों के मामले में कब स्वीकृत की जानी चाहिए एवं कब इन शर्तों को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । मार्ग दर्शन के लिए तदनुसार निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए जाते हैं:—

(१) उपयुक्त कार्यालय ज्ञापन (प्रस्ताव निर्णय संख्या १) में वर्णित उदाहरण की गयी प्रतिनियुक्ति की शर्तें, नियम के रूप में, केवल उन्हीं मामलों में स्वीकृत की जानी चाहिए जहाँ पर किसी राज्य कर्मचारी को प्रस्तावित प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा भेजा गया हो । भेजे जाने की जांच कठोरता पूर्वक की जानी चाहिए एवं सामान्यतया केवल उन्हीं मामलों को भेजा गया (प्रोन्सर्ड) समझा जाना चाहिए जिनमें प्रयास (इनिमिगटिव) सरकार द्वारा किया गया हो न कि सम्मनित व्यक्ति द्वारा किया गया हो । दूसरे शब्दों में, जहाँ योजना की शर्तों के अधीन प्रशिक्षण के लिए मनोनयन सरकार द्वारा किया जाना होता है, वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा निकाशित किए गए तथा चयन समिति (स्त्रीनिंग कमेटी) द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को ही सरकार द्वारा भेजा गया समझा जाएगा । इसके विपरीत जहाँ जहाँ प्रारम्भिक प्रयास स्वयं सरकारी कर्मचारी की ओर से हो, जो प्रशिक्षण या शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है, वहाँ ऐसे मामले में व्यक्ति को सरकार द्वारा भेजा गया नहीं समझा जाएगा चाहे चयन के लिए आवेदन सरकार द्वारा ही क्यों न भेजा गया हो । ऐसे मामलों में केवल अध्ययन अवकाश ही स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(ii) उपयुक्त दि० १४-१२-६३ के आदेश की प्रतिनियुक्ति की शर्तें समान रूप में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में तथा आर्थिक विकास एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्तियों पर भी लागू है । प्रशिक्षण विनियोजित क्षेत्रों में होना चाहिए तथा इसमें यह

§ वित्त विभाग के ज्ञापन सं० एफ १ (८७) वित्त वि (व्यय-नियम) ६२ दि० ६-५-६७ द्वारा निविष्ट ।

ज्यान् नहीं रखा जाना चाहिए कि प्राया उससे थैलसिक डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा या नहीं या प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो नियोजन कर्ता विभाग के लिए लाभप्रद हो तथा न कि केवल व्यक्ति के लिए ही लाभप्रद हो। शोर भी प्रतिनियुक्ति अधिकतम 18 माह तक की होनी चाहिए।

उपयुक्त निर्दिष्ट सिद्धान्तों का भविष्य में कठोरता से पालन किया जाना चाहिए लेकिन जिन मामलों में अन्यथा प्रकार से निर्णय लिया जा चुका है उन पर पुनः विचार नहीं किया जाना है।

अध्याय ८

वर्खास्तगी, निष्कासन एवं निलम्बन

(Dismissal, Removal and Suspension)

नियम 52. वर्खास्तगी (Dismissal) की तारीख, वेतन एवं भत्तों का बन्द करना—
जिस दिन राज्य कर्मचारी सेवा से वर्खास्त (डिसमिस्) कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है तो उसका वेतन एवं भत्ता उसी दिन से बन्द कर दिया जाता है।

(वेतन एवं भत्तों के अन्तिम भुगतान की प्रवृत्ति के लिये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 164 को भी देखें)।

नियम 53—निर्वाह अनुदान (Subsistence grant):—(1) निलम्बन काल में एक राज्य कर्मचारी निम्नलिखित धन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, मुरदा रूप से—

[क] निर्वाह भत्ता, उस अवकाश वेतन की धन राशि के बराबर जिसे कि राज्य कर्मचारी प्राप्त करता यदि वह अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहता तथा संहर्गाई भत्ता जो ऐसे अवकाश वेतन पर मिलता हो।

परन्तु शर्त यह है कि जहाँ निलम्बन का समय 12 माह से अधिक का हो, तो वह अधिकारी जिसने उसके निलम्बन के आदेश दिए हों या उसके द्वारा दिए गए समझे गए हों, तो वह 12 माह से कितने भी अधिक समय के लिए निर्वाह भत्ता की राशि को निम्न प्रकार से परिवर्तित कर सकता है—

(1) निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह धनराशि प्रथम 12 माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई है, जिनको कि लिखित में लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी के हित के लिए नहीं है।

(2) निर्वाह भत्ते की धनराशि उचित धनराशि तक घटाई जा सकती है। लेकिन यह धनराशि प्रथम बारह माह की अवधि में प्राप्य निर्वाह भत्ते की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं घटाई जा सकती है यदि उक्त अधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि किन्हीं ऐसे कारणों से बढ़ाई गई है, जिनको कि लिखित में लिखा जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कर्मचारी को हित पहुंचाने वाले हों।

(3) मंहगाई भत्ते की दरें उपरोक्त उप खण्ड (1) व (2) के अन्तर्गत प्राप्य निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई या घटी हुई राशि पर, जैसी भी स्थिति हो, आधारित होगा।

+ 53 (ख) कोई अन्य सतिपूरक भत्ता जो ऐसे वेतन के आधार पर समय समय पर प्राप्य हो, जिसको कि राज्य कर्मचारी अपने निलम्बन के दिनांक की उचित भत्तों के व्यूहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त कर रहा था।

स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 (1) (क) के प्रावधानों में कही गई 12 माह की अवधि वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या दिनांक 22-1-64 से गिनी जानी है अथवा उस तारीख से जिसको कि सक्षम प्राधिकारी ने राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया है।

मामले की जांच की जा चुकी है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त नियम में कही गई 12 माह की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिसको कि राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया था।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी यह प्रमाण पत्र न दे दे कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यवसाय, व्यापार या धोकेदान में नहीं लगा है।

परन्तु यह है कि "सरकारी सेवा से बर्खास्त, निष्कासित या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गोकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (3) या (4) के अधीन ऐसी बर्खास्तगी, सेवा निष्कासन या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से निलम्बित किया गया है या समझा गया है, या हटा हुआ समझा गया तथा जो किसी ऐसी अवधि या अवधियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसमें कि वह निलम्बित रखा गया है या निलम्बित किया हुआ समझा गया है, तो वह उस राशि तक निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता प्राप्त करने का हक्दार होगा जिसमें कि उसकी उक्त अवधि या अवधियों की आय उस निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्ते की राशि से कम पड़े जिसे वह अन्य प्रकार से प्राप्त करता। जहाँ स्वीकार्य निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता उसके द्वारा प्राप्त अन्य आय के बराबर या इससे कम है तो इस प्रावधान की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी।

जांच निर्देशन—(विनियमित की गई)

नियम 54. पुनर्नियुक्ति (Reinstatement)—(1) एक राज्य कर्मचारी जो कि बर्खास्त (द्विगमित) हो गया हो, निष्कासित कर दिया गया हो (Removed), आवश्यक रूप से सेवा में निवृत्त (रिटायर) कर दिया गया हो, या निलम्बित कर दिया गया हो, पर पुनर्नियुक्त हो गया हो या जो पुनर्नियुक्त हो गया होता लेकिन निलम्बन काल में अधिवार्षिकी आयु (Superannuation) पर उसकी सेवा निवृत्त किया गया, पुनर्नियुक्ति के आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी इन पर विचार करेगा तथा निम्न के बारे में एक विशेष आदेश निश्चितगा—

+ वित्त विभाग की धाजा संख्या एक 1 (30) एक. सी. (धय-नि.) 65 दिनांक 17-7-67 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(क) सेवा (इयूटी) से उसके अनुपस्थित रहने के समय का या अधिवापिकी आर्गु पर सेवा निवृत्त होने की तारीख तक समाप्त होने वाले निलम्बन के समय का, जैसी भी स्थिति हो, राज्य कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में।

(ख) क्या उक्त अवधि 'सेवा में बिताई गई अवधि' समझी जायेगी अथवा नहीं।

(ग) जहाँ ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह विचार करे कि राज्य कर्मचारी को पूर्णतया दोष-मुक्त (Exonerated) कर दिया गया है अथवा निलम्बन के मामले में उसे निलम्बित किया जाना पूर्णतः अनुचित था, तो राज्य कर्मचारी उस समय का अपना पूर्ण वेतन भय मंहगाई भत्ते के उसी दर से प्राप्त करेगा जिसकी कि वह पाने का हकदार होता यदि वह, जैसी भी स्थिति हो, बर्खास्त नहीं किया गया होता; हटाया नहीं जाता, या आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त नहीं किया जाता या निलम्बित नहीं किया जाता।

(3) अन्य मामलों में राज्य कर्मचारी को वेतन एवं मंहगाई भत्ते का ऐसा हिस्सा दिया जावेगा जिसे कि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे।

(4) खण्ड (2) के अन्तर्गत जाने वाले मामले में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सभी कार्यों के लिए सेवा में बिताए गए समय के रूप में समझा जावेगा।

(5) खण्ड (3) के अन्तर्गत जाने वाले मामलों में सेवा से अनुपस्थिति के समय को सेवा में बिताए गए समय के रूप में तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक ऐसा सक्षम प्राधिकारी विशेष रूप से निर्देश न दे कि वह किसी विशेष कार्य के लिए इस प्रकार से समझा जावेगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी ऐसा चाहे तो सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि सेवा से अनुपस्थिति का समय राज्य कर्मचारी के अकाया एवं उसे स्वीकृत किए जाने योग्य किसी भी प्रकार के अवकाश में बदल दिया जावेगा।

टिप्पणी—इस परन्तुक के अन्तर्गत विस्तारित गये सेवा से अनुपस्थिति के समय को किस रूप में समझा जावे, इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अन्तिम रूप से मान्य हैं तथा जहाँ तक पर्याप्त राज्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है, तीन माह से अधिक के अवकाश अवकाश की स्वीकृति के लिए और अन्य उच्चतर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

कौनवारी कार्यवाहियों के समय में गिरफ्तारी के लिए, जूनों के लिए या किसी कानून के अन्तर्गत नजरबंदी के समय में निरोधारमक नजरबन्दी के प्रावधानों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई प्रशासनात्मक हिदायतों के लिए परिशिष्ट 1 खण्ड (2) देखें :

टिप्पणी—(1) पुनर्विचिन्तन (Revising) या अपील सम्बन्धी (Appellate) प्राधिकारी निलम्बन काल में बिताए गए समय को अवकाश में परिवर्तित करने एवं उसके उचित अवकाश वेतन के भुगतान कराने के आदेश देने में सक्षम है।

(2) यदि एक राज्य कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त (डिमिस्स) कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, परन्तु अपील करने पर किसी पंरवर्ती (Subsequent date) तारीख से पुनर्नियुक्त कर दिया जाता हो तथा बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने व पुनर्नियुक्ति के बीच के समय को सेवा के रूप में बिताया गया समय मानने के लिए आदेश दे दिया जाता है तथा वह समय अवकाश एवं वेतन वृद्धि के लिए शामिल किये जाने के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस प्रकार के

घाटेनों का परिपालन किया जाना चाहिए, चाहे राज्य कर्मचारी अपनी बीमारी के समय के भीतर किसी स्टाई पद पर अपनी सीजन न रहता हो। जो राज्य कर्मचारी सेवा में बर्खास्त या हटाये गये हैं, उनके द्वारा जो स्वामि रिक्त किए गए हैं, उन्हें स्टाई रूप में इस बात के साथ भरा जा सकता है कि इस प्रकार का किया गया प्रबंध उपलब्ध हो जाएगा यदि सेवा से बर्खास्त किया गया कर्मचारी अपनी जरूरतों पर पुनर्नियुक्त हो जाता है।

(3) एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामलों में जिनमें कि निलम्बन काल के समय को अवकाश पर बिताए गए समय के रूप में मानने का आदेश दे दिया जाता है तथा परिवर्तन करने पर जब यह बिंदु होवे कि समय के बहुत से भाग को समाधारण अवकाश के रूप में समझा जाता है जिसका कि कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता है, तो पहिले से ही दिए गए निर्वाह भत्ते की राशि की वसूली यथोचित मानी जाएगी। यह निर्णय किया गया है कि निलम्बन काल के समय के किसी भी घंटे को समाधारण अवकाश में परिवर्तन करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उन व्यक्तियों के मामले में जो पुरातया दोष मुक्त नहीं किए गए हैं, निलम्बन के समय को भत्ते की राशि या बिना भत्ते के अवकाश में बदलने से, उनके निलम्बन के कारण तथा उनसे निवृत्ति के बाद के सभी विपरीत परिणामों को हटाया जाता है। जिस क्षण से निलम्बन का समय अवकाश में बदल दिया जाता है, उसी समय से वह निलम्बन के आदेश को प्रभावहीन करता है तथा वह समय निलम्बन काल में शिथिल बिताया गया नहीं समझा जाएगा। इसलिए यह पाया गया है कि एक राज्य अधिकारी निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ते एवं शक्तिपूर्वक भत्ते की जो कुल धनराशि प्राप्त करता है, यदि वह अवकाश वेतन एवं भत्तों से अधिक होता है तो वह अधिक राशि वापिस जमा करानी पड़ेगी तथा इन परिणामों से बचने का कोई उपाय नहीं।

(4) समाधारण अवकाश की स्वीकृति एवं राज्य सेवा से बर्खास्तगी दोनों पूर्णतया विभिन्न मामले हैं तथा निलम्बित अवधि को अवकाश में बदलने का अवकाश का उदाहरण इसका ही बर्खास्तगी के मामलों पर पूर्व प्रभाव में (Retrospective effect) में लागू नहीं होता है क्योंकि बर्खास्तगी में राज्य कर्मचारी को अपने पद से हटाया जाता है। इसलिए इस सम्भावधि में राज्य कर्मचारी को जो निर्वाह भत्ता (Maintenance) स्वीकार किया जाए, वह उससे वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

[बिन्दु—बहने का तात्पर्य यह है कि यदि निलम्बित राज्य कर्मचारी का निलम्बन काल का समय किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जाना हो तो वह पूर्व प्रभाव से लागू होता है तथा यदि अवकाश वेतन व भत्ते निलम्बन काल के निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों से कम हो तो उसे अधिक रकम को वापिस जमा कराना पड़ेगा। परन्तु बर्खास्तगी का आदेश पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होता है, इसलिए यदि किसी राज्य कर्मचारी को इस सम्भावधि में जो भी निर्वाह भत्ता दरवादा मिलता है, वह पूर्व प्रभाव न रखने के कारण वापिस जमा नहीं कराया जा सकता है।]

(5) एक राज्य कर्मचारी को सेवा में बर्खास्त किये जाने या हटाये जाने या आवश्यक रूप में सेवा मुक्त किए जाने के कारण रिक्त किया गया एक स्टाई पद, उस समय तक स्टाई रूप से नहीं भरा जाना चाहिए, जब तक कि, जैसी भी स्थिति हो, इस प्रकार की बर्खास्तगी, हटाये जाने या आवश्यक रूप से सेवा मुक्त किए जाने से 12 माह का समय व्यतीत न हो गया हो। जब एक साल की अवधि के समाप्त होने पर, स्टाई पद भर लिया जाता है तथा उसके बाद वह

पद का मूल कर्मचारी सेवा में पुनर्नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे किसी भी पद के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उसी श्रेणी में स्थाई रूप से रिक्त हो जिसमें कि उसका पूर्व का स्थाई पद था । यदि इस प्रकार का कोई पद रिक्त न हो, उसे एक अधिसंख्यक पद (Supernumerary Post) के विपरीत लगाया जाना चाहिए जो कि उचित स्वीकृति द्वारा इन श्रेणी (Grade) में सृजित (Create) किया जाना चाहिए तथा इस शर्त (Stipulation) के साथ सृजित किया जाना चाहिए कि उक्त वेतन श्रृंखला में प्रथम स्थान रिक्त होने पर उसे समाप्त कर दिया जावेगा ।

निर्णय—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि एक ऐसे मामले में जिसमें कि राज्य कर्मचारी की सेवाएं 6-3-57 को समाप्त कर दी गई थी तथा अपील पर वह पुनर्नियुक्त कर दिया गया था तथा अपील प्राधिकारी (Appellate Authority) ने घोषित कर दिया कि उसे 6-3-57 से 30-6-57 तक का उसका बकाया अवकाश स्वीकृत किया जावेगा तथा 1-7-57 के बाद का उसे अपने पद का पूर्ण वेतन मिलेगा । कर्मचारी ने अपने पद का कार्यभार 16-12-57 को सम्भाला ।

बुकि कोई ऐसा पद नहीं था जिसके विपरीत बर्तमान के समय में राज्य कर्मचारी का सीजन दिलाया जा सके क्योंकि कार्य को चलाने के लिए कार्यवाहक प्रबन्ध उस पद पर पहिले ही किया जा चुका था, उसे सीजन प्रदान करने तथा उसे उस समय का वेतन एवं भत्ता प्राप्त करने के लिए एवं पद सृजन करने का प्रस्ताव पेश किया गया ।

मामले की जांच करली गई है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियमों का नियम 54 पूर्ण है तथा यदि 'लीमन' की शर्त पहिले पूरी की जाती है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता है । इन परिस्थितियों में राज्य कर्मचारी का वेतन एवं भत्ता राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के अन्तर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इसके लिए एक अधिकांश पद के सृजन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार की अधिकांशता स्वीकार्य होती है ।

नियम 55 — निलम्बन काल में अवकाश की स्वीकृति—निलम्बन काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 55 के अन्तर्गत निलम्बन काल में राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने पर प्रभावशाली डाला गया है । फिर भी इस नियम के पालन में उसके परिवार आदि में अधिक बोझ होने की दशा में उसे कठिनाई होती है, इसलिए राजप्रमुख ने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में पद को भरने वाले सहाय प्राधिकारी द्वारा उसे मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है । यह मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति अवश्यवश्यक परिस्थितियों में जोब की स्थिति को एवं उसकी प्रगति में राज्य कर्मचारी की अनुपस्थिति सम्भावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए उचित समय के लिए दी जाएगी ।

नियम 55. (क)—अवकाश ऐसे राज्य कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसको कि दण्ड देने वाले सहाय प्राधिकारी ने, राज्य सेवा से बर्खास्त करने, निष्कासित करने या आवश्यक रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय कर लिया हो ।

अध्याय 9

अनिवार्य सेवा निवृत्ति (Compulsory Retirement)

नियम 56. (क) अधिवायिकी आयु (Superannuation) प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति (i) जब तक इन नियमों में कुछ अन्यथा प्रकार से न दिया गया हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों × [एक विशिष्ट अधिकारी (मेडिकल काउंसिलों के अध्यापन वर्ग के सदस्यों सहित)] के अतिरिक्त अन्य राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख यह होगी जिसकी वह + (55, वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है। उसे सांख्यिक हित की दृष्टि से, जिसकी जिम्मा जाएगा, सरकार की स्वीकृति द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है। परन्तु जिन्होंने बहुत विशेष परिचित की छोड़कर उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता है।

+ परन्तु शर्त यह है कि विपरीत रूप में किसी प्रकार के प्रावधान के होते हुए भी एक राज्य कर्मचारी जो रिसावर 1962 को सेवा निवृत्त नहीं हुआ हो, लेकिन जिसकी बाद में 55 वर्ष की आयु हो गयी हो, तो जिसकी अवधि के लिए उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा की है, उसे उक्त नियम के अर्थ में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बाद सेवा में वृद्धि स्वीकृत कर, रखा हुआ समझा जाएगा।

+ अनुदेश-1 जुलाई, 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के राज्य कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति।

राज्यपाल ने वित्त विभाग की अधिसूचना न. एक 1 (42) एक. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 13-6-67 के अनुसार 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को उन्हें प्रवक्ताग वेतन एवं पेंशन स्वीकृत करने आदि के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:—

प्रशासनिक विभागों एवं विभागाध्यक्षों के लिए इन अनुदेशों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना चाहिए तथा उन राज्य कर्मचारियों को मुनिद्वित रूप से सेवा-निवृत्त किया जाना चाहिए जिन्होंने 1 जुलाई 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त करली है। उन्हें प्रवक्ताग वेतन, जो भी बचाया हो, तथा पेंशन आदि स्वीकृत किए जाने चाहिये।

(1) सभी राज्य कर्मचारी, जो 1 जुलाई 1967 को सेवा-निवृत्त होने हैं, 1 जुलाई 1967 को (सम्यान्तपूर्व) अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। जहाँ चार्ज में स्टोर आदि का कार्यभार भी संभालना हो, वहाँ यह कार्य 1 जुलाई, 1967 (पूर्वाह्न) से पूर्व ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(2) कार्य का प्रभार ऐसे राज्य कर्मचारी को सभाला जाएगा जिसे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश के अधीन, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी से कार्यभार संभालने के लिए कहा जाता है।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (35) एक. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 11 मई 1967 द्वारा शामिल किया गया। यह संशोधन 2-2-65 से प्रभाव में आया।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (42) एक. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 13 जून 1967 द्वारा शामिल किया गया। यह दि. 1-1-67 से प्रभावी होगा।

यदि कार्यभार संभालने का कोई प्रबन्ध न हो सके तो कार्यभार, चतुर्थ श्रेणी के प्रतिरिक्त विभाग के किसी भी अन्य राज्य कर्मचारी को, जो सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी के मुख्यालय पर उपलब्ध हो, संभाला दिया जाएगा ।

(1) राज्य कर्मचारी जो राजकीय उपक्रम (पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजिज)/स्वतन्त्र निकायों/निगमों/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकायों या अन्य विदेशी (फोरेन) सेवा या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जो भारत के भीतर या बाहर, राजस्थान सरकार की ओर से विनिश्चित कर्तव्य पर हैं, उन्हें सरकार को 30 जून 1967 को प्रत्यावर्तित किया तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्ल) से सेवा-निवृत्त किया हुआ समझा जाएगा ।

(4) राज्य कर्मचारी जो 30-6-67 को निलम्बित हैं, दिनांक 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्ल) को राजकीय सेवा से निवृत्त होंगे लेकिन उनके विपरीत चल रही समस्त कार्यवाहियां चालू रहेंगी ।

(5) राज्य कर्मचारी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई किसी भी किस्म के भवकाश पर हैं, वे भी दिनांक 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्ल) से राजकीय सेवा से निवृत्त हो जाएंगे तथा सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप जो उपाजित भवकाश उपभोग न किया हुआ बच रहता है, उसे प्रस्वीकृत किया गया भवकाश समझा जाएगा तथा उपाजित भवकाश के इस प्रकार से उपभोग न किए गए भाग का भवकाश वेतन का 1 जुलाई 1967 के बाद भुगतान किया जाएगा ।

(6) एक राज्य कर्मचारी जो सरप्लस है या प्रादेशों की प्रतीक्षा कर रहा है, वह एक 1 जुलाई, 1967 (पूर्वाह्ल) को सेवा से निवृत्त होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसके कि अधीन वह प्रादेशों की प्रतीक्षा कर रहा है या वह सरप्लस है ।

(7) एक राज्य कर्मचारी जो 1 जुलाई, 1967 के पूर्व कार्य-ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) का उपयोग कर रहा है वह नए मुख्यालय पर सेवा पर उपस्थित होगा तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्ल) का अपने कार्यभार से मुक्त होगा, बशर्ते कि यदि नए मुख्यालयों पर सेवा से 1 जुलाई 1967 से पूर्व उपस्थित नहीं हो सकना हो तो राज्य कर्मचारी अपने पुराने मुख्यालय पर ही ठहरा रहेगा तथा 1 जुलाई 1967 (पूर्वाह्ल) को अपने सेवा-निवृत्त होने की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा जिसके कि अधीन वह कार्य-ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग करने से पूर्व सेवा कर रहा था ।

× (8) एक राज्य कर्मचारी जिसके कि अपने धाते में 1 जुलाई 1967 के पूर्व उपाजित भवकाश हो, ऐसे भवकाश के लिए निवेशन करेगा तथा उसे भवकाश भवकाश का, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, भुगतान किया जाएगा । फिर भी, यदि उपाजित भवकाश की राशि तीस दिन से कम हो, तो उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91, 92, 94 एवं 97 में छूट देते हुए तीस दिन का भवकाश वेतन स्वीकृत किया जाएगा ।

+ स्परटीकरण-सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी जो बेकेशन

× वित्त विभाग के जुद्धि पत्र संख्या एफ 1 (42) वित्त वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 28-6-67 द्वारा संशोधित ।

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एफ 1 (42) वित्त वि. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 21/30-11-67 द्वारा निविष्ट ।

विभाग का है तथा जो दि० 30-6-67 को अपने स्थानों में कोई उपाजित अवकाश नहीं रखता है, तथा उसे वित्त विभाग के आदेश दि. 13 6-67 (उपपुंक्त अनुदेश सं. 1) के पैरा 3 (8) के अनुसार 30 दिनों का अवकाश वेतन का भुगतान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रश्न कि आया कोई सरकारी कर्मचारी बेरोजगार विभाग का है या नहीं, यह एक सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। 30 दिन का अवकाश का भुगतान केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिनको 30-6-67 को अपने स्थानों में 30 दिन से कम का उपाजित अवकाश या यह एक अवस्था है कि चाहे वे बेरोजगार विभाग के हों या नहीं। ऐसे मामलों में जहाँ जहाँ सरकारी कर्मचारी का 30-6-67 को कोई उपाजित अवकाश न हो वहाँ पर 30 दिन के अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त करने का हक्कार नहीं है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 32 (ग) की धोर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अवकाश की कुल अवधि जो वेतन के साथ लेने पर कुल मिलाकर एक साथ 120 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अतः ऐसे मामलों में जहाँ अवकाश बेरोजगार के साथ में उपपुंक्त आदेश के अधीन मना किया गया है वहाँ उपाजित अवकाश एवं बेरोजगार की अवधि मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके साथ यह धोर धोर होगी कि अस्वीकृत अवकाश उस तारीख के बाद का नहीं होगा जिसको कि सरकारी कर्मचारी वित्त विभाग की जाय ग एक। (42) वित्त विभाग (व्यय-नियम) 67 दिनांक 18-6-67 में प्रावहित किये गए अनुसार 58 वर्ष का होता है।

+ (9) "इस प्रकार से आवेदन किये गये अवकाश को, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देने हूँ। जुलाई 1967 में पूर्व अस्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा। अस्वीकृत किए गये अवकाश (रिपूग्ड लीव) की अवधि में ऐसे मामलों में स्वीकार्य अवकाश वेतन वही होगा जो कि वित्त विभाग की आज्ञा सं. एक। (48) एक ही (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 के अनुसार स्वीकार्य है एवं वह प्रत्येक माह के अन्त में भुगतान किया जायेगा।

वर्तमान प्रावधानों के अधीन, भुगतान योग्य अवकाश-वेतन केवल तभी निकाला जा सकता है जबकि पेंशन एवं पेंशन के समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की राशि प्राप्त हो। चूंकि पेंशन के लाभों की अन्तिम रूप में निपटारने में कुछ समय लगेगा अतः पेंशन एवं पेंशन के समान अन्य सेवा निवृत्ति लाभों की राशि प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा एवं इससे अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) के भुगतान करने में देरी होगी। अतः यह निर्णय किया गया है कि जहाँ पेंशन एवं पेंशन के बराबर अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं हो, अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) का भुगतान उभी रूप में किया जाये जैसा कि सामान्य रूप में किया जाता है तथा अधिक भुगतान जो भी किया गया होगा उसकी जब भी स्वीकृत हो जाएँगे पेंशन X उपदान या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में से समायोजित कर लिया जायेगा। यह देखने की दृष्टि में कि अवकाश वेतन के अधिक भुगतान की राशि बिना वसूल की हुई न रह जाये, इसके लिए निम्नलिखित नियायति का पालन किया जाना चाहिये:—

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एक। (42) एक ही (व्यय-नियम)/67 दिनांक 15 जुलाई 1967 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा X दिनांक 26-7-67 द्वारा संशोधित किया गया।

(1) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार, राजस्थान, इस प्रकार से किए गए अधिक भुगतान को दर्ज कर सकता है जिसे कि ओ पेंशन/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (डेप कम रिटायरमेंट प्रोच्युटी) में से समायोजित किया जाना है।

(2) राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में आहरण एवं वितरण प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को भुगतान किए गए अवकाश वेतन की राशि को पेंशन के कागजातों के साथ महालेखाकार को सूचित करेगा तथा महालेखाकार उक्त सूचना के आधार पर अधिक भुगतान को पेंशन/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की राशि में से वसूल करने के लिए प्रकृति करेगा।

ये आदेश दिनांक 1-7-67 से प्रभावशील होंगे।

(10) जून माह के बकाया वेतन एवं भत्तों का भुगतान, सामान्य रूप से किया जाएगा तथा अक्षेयता प्रमाण पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की शर्त एतद्द्वारा समाप्त की जाती है। फिर भी, अक्षेयता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा उसे अंतिम पेंशन कागजातों के साथ सलग्न किया जा सकता है तथा बकाया राशि को मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान एवं, या पेंशन में से या अंशदायी भविष्य निधि में योगदान कर्ता के मामले में राजकीय अंशदान की राशि में या ब्याज के या विशिष्ट अंशदान में से या सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारी को 1 जुलाई 1967 को देय एरियर बलेन्स की राशि में से, समायोजित कर लिया जाएगा।

(11) एक राज्य कर्मचारी को 1 जुलाई 1967 को सेवा-निवृत्त हो रहा हो उसके 10 (दस) साल की ग्रहकारी सेवा (बवालीफाइन सविस) की सारी के आधार पर, जब तक उसका पेंशन का मामला अंतिम रूप से तय न हो जाये, उसे प्रत्याशित पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। राजपत्रित अधिकारी, शीघ्र ही महालेखाकार के पास, राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 7 में निर्धारित प्रपत्र सं. (अ) में ग्रहकारी सेवा का विवरण, सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी की मार्फत प्रत्याशित पेंशन प्राधिकृत करने के लिए, महालेखाकार द्वारा सेवा-वृत्त के आधार पर, उस पर लाल स्याही से 'प्रत्याशित पेंशन' लिखकर भेजेगा। महालेखाकार राजपत्रित अधिकारियों के लिये अगस्त 1967 के अन्त तक प्रत्याशित पेंशन हेतु प्राधिकृत करेगा जिससे कि सितम्बर 1967 से वे उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में, कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा, राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 7 में निर्धारित प्रपत्र सख्या 'अ' में प्रत्याशित पेंशन के लिये मामले को तैयार करने की कार्यवाही करेगा जिस पर वह सम्बन्धित पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिये 10 वर्षों की ग्रहकारी सेवा, सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी द्वारा किए जाने के सरकारी प्रमाण के आधार पर लाल स्याही से 'प्रत्याशित पेंशन' लिखेगा। सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी, प्रत्याशित पेंशन स्वीकृत कर सकता है तथा उसे राज्य कर्मचारियों को वितरित करने के लिये वित्त विभाग की आज्ञा संख्या दिनांक 29-4-67 के साथ पठित वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1 (52) एफ डी (व्यय-नियम) 65 दिनांक 14-9-66 के अनुसार उठा सकता है।

(12) स्वयं सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी तथा पेंशन स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी पेंशन सम्बन्धी मामलों को तैयार करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी के लिये 31 दिसम्बर 1967 से पूर्व पूर्ण पेंशन एवं उपदान या अंशदायी भविष्य निधि की राशि का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन के मामले

सभी दृष्टि से प्रबतूबर 1967 की समाप्ति में पूर्ण कर महालेखाकार के पास प्रपत्रित कर दिए जाएंगे।

(13) वित्त विभाग की प्रज्ञा संख्या-(1) 18 एक डी/ए/नियम/61 दि० 22 प्रपत्र 1961 द्वारा सम्मिलित राजस्थान सेवा नियमों के नियम 241 के नीचे राजस्थान सरकार के प्रनुदेन संख्या 2 के प्रनुसार वेतन निर्धारण, व्यवधानों को भाफ करने (कन्डोनेशन प्राफ ब्रैक), परिलिपियों (प्रोस्पेक्ट्स) में परिवर्तन, जन्मतिथि की सुद्धि, सेवा-युक्त (सर्विस रिट्टी) प्रादि परिवर्तन, जिनसे राज्य कर्मचारी को पैशन में प्रभाव पड़ता है, वही किए जाने चाहिए जहां उनकी मांग सेवा से निवृत्त होने से तीन वर्ष के भीतर की गई हो। तदनुसार 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों की कोई मांग एवं प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी, इन प्रादेशों के जारी होने की तारीख की जो दावे (क्लेम) एवं प्रत्यवेदन (रिप्रिजेंटेशन) विवाराधीन हो, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तीन माह के भीतर निदवधारक रूप से निपटा दिये जाएंगे।

(14) 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी, जो जोधपुर प्रदायी भविष्य निधि के सदस्य हैं, उन्हें सेवा निवृत्त होने के बाद सीधे ही उनके चन्दे की राशि सम्मिलित सेवाधिकारी, (महालेखाकार, राजस्थान) द्वारा भुगतान की जाएगी। राजकीय प्रदायन तथा उसके ब्याज एवं विशिष्ट प्रदायन का भुगतान सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी के लिए 31 दिसम्बर 1967 से पूर्व कर दिया जाएगा।

(15) राज्य कर्मचारी जो 1 जुलाई 1967 को सेवा निवृत्त होते हों, एवं जिनकी बीमा पालिसी 58 वर्ष की आयु पर परिपक्व (मैथोर) होती है, वे राजस्थान राज्य सरकार बीमा नियम, 1953 के नियम 45 व 48 के अधीन प्रदत्त लाभों का उपयोग कर सकते हैं।

(16) किसी भी बिस्म के ऋण या भ्रमि की राशि एवं उस पर ब्याज जो सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारियों के विच्छ बकाया हो तथा बिस्मों या एक मुदत में चुकाया जाने योग्य हो, वह उनके द्वारा तद मे एक मुदत जमा कराया जा सकता है या मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की राशि मे से भ्रमवा प्रदायी भविष्य निधि मे योगदाता होने की दशा मे राजकीय प्रदायन तथा उस पर ब्याज एवं विशिष्ट प्रदायन की राशि मे से समायोजित की जा सकती है या महाम प्राधिकारी की लिखित मे निवेदन करने पर, उस माह से पूर्व माह तक बिस्म कि राज्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, उपयुक्त मासिक बिस्मों मे भुगतान करने योग्य पैशन मे काटी जा सकती है।

(17) सेवा-निवृत्त राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रादि के सहित बकाया दावे (एरियर क्लेम), इस अधिसूचना के जारी होने से दो माह के भीतर तय कर दिए जाएंगे।

÷ निर्णय सं० 1—वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) / 67 दिनांक 13-6-67 द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 से 55 वर्ष दिनांक 1-7-67 से कर दी गई है। विभिन्न सरकारी मस्याधों / सरकारी यकीलों /

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) / 67—VI दिनांक 16-6-67 द्वारा निविष्ट तथा।

अध्यापकों जो विधि महाविद्यालयों आदि में अंशकालिक / पूर्णकालिक आधार पर अध्यापन कार्य में लगे हैं, उन पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में जो कर्मचारी 55 वर्ष की या इससे अधिक आयु प्राप्त करते हैं उनके मामलों पर और विचार किया गया है तथा X [यह निश्चय किया गया है कि उपरोक्त नियम (I) सरकारी वकीलों (II) विधि महाविद्यालयों में अंशकालिक अध्यापकों के सिवाय विभिन्न राजकीय प्रशिक्षण संस्थायों में सेवा कर रहे समस्त पूर्णकालिक/अंशकालिक अध्यापक वर्ग पर लागू होगा ।]

विषय :—1 जुलाई 1967 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति ।

+ निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 II दिनांक 13-6-67 के पैरा 3 के उप पैरा 8 एवं 9 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जो 1-7-67 की सेवा निवृत्त हो गया था एवं उस तारीख को जिसके लेख में उपाधित अवकाश बकाया था वह अधिकतम 120 दिन तक के अवकाश के लिए आवेदन कर सकता था जो उस समय अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा । वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अनुसार सभी मामलों में अवकाश वेतन केवल सभी उठाया जा सकता है जब कि पहले उनके अवकाश की प्राप्ति का सत्यापन हो चुके एवं उनके लिए अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा चुके । उक्त आदेश के अधीन सेवा निवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों के अवकाश वेतन के मामलों की सीध निपटाने के लिए राज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि सभी मामलों में जिनमें अवकाश के स्वत्व (टाइटिल) का महालेखाकार, राजस्थान ने सत्यापन कर दिया है, तथा जिन आवेदन पर उनका जितना अवकाश बकाया पाया गया है, एवं जिन्हे अस्वीकृत अवकाश माना जाएगा, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया हुआ समझा जाना चाहिए एवं उनके लिए औपचारिक आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं होगी । अतः एतदनुसार महालेखाकार, राजस्थान, अवकाश स्वत्व (टाइटिल) के सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के प्राप्त करने पर, अधिकारी के अवकाश के लिए आवेदन किए गए अवकाश का सत्यापन करने के बाद, उस अधिकारी को अवकाश वेतन के भुगतान के लिए उक्त सत्यापन के आधार पर एक प्रमाण पत्र (Authority) जारी करेगा तथा अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास भी उस अवधि की सूचना भेजेगा जिसके कि अवकाश वेतन ■ लिए उसे प्राधिकृत किया गया है ।

विषय :—दिनांक 1-7-67 को 55 वर्ष की या उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

■ निर्णय संख्या 3—वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) एफ. डी. (व्यय-

X वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम)/67 VI दि. 30-6-67 द्वारा प्रतिस्थापित ।

+ वित्त विभाग की जापन संख्या 1 (42) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 10 अगस्त 1967

⊗ वित्त विभाग के जापन संख्या एफ 1 (42) एफ. डी. (व्यय-नियम) 67 दिनांक 18-8-67 द्वारा शामिल किया गया ।

नियम) 67 II दिनांक 13-6-57 के पैरा 3 के उप-पैरा 8 एवं 9 की ओर ध्यान आकषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक प्रदन उत्पन्न हुआ है कि अधिकतम 120 दिन का उपाजित अवकाश जो कि 1-7-67 से पूर्व राज्य कर्मचारी के लेखे में जमा हो, अस्वीकृत किया हुआ समझा जा सकता है एवं स्वीकृत किया जा सकता है चाहे उसके लेखे में जमा अवकाश का समय उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से आगे तक भी क्यों न जाता हो।

2—यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश का उतना समय ही अस्वीकृत किया हुआ समझा जाना चाहिए एवं स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि राज्य कर्मचारी के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से अधिक न पहुँचे।

जो मामले उक्त पैरा 2 से भिन्न अन्य तरीके में तय किए जा चुके हैं, उन्हें पुनः शुरू किया जाना चाहिए तथा पहिले जारी किए गए आदेशों को उचित रूप से परिशीलित माना जाना चाहिए।

+ निर्णय संख्या 4—वित्त विभाग के आदेश दि० 13-6-67 के पैरा 3 (16) (नियम 56 (क) (1) के नीचे अनुदेश के रूप में प्रदर्शित) के अनुसार दिनांक 1-7-67 को सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बकाया ऋण / अग्रिम एवं उसके व्याज की बसूली सरकारी कर्मचारी के उस माह से जिसमें सरकारी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता, पूर्व माह तक के माहों की उचित मासिक किरतों में बसूल की जाएगी। यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 1 जुलाई 1967 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऋण / अग्रिम एवं उसके व्याज की बसूली निम्नलिखित तरीके के अनुसार की जानी चाहिए—

(क) दिनांक 30-6-68 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऋण / अग्रिम एवं उस पर व्याज की बसूली उसकी पेंशन में से की जानी चाहिए तथा सम्पूर्ण राशि उस माह से पूर्व माह तक बसूल की जानी चाहिए जिसमें कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

(ख) दिनांक 30-6-68 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में किरतों की पुनर्गणना इस प्रकार की जानी चाहिए कि पूर्ण राशि सेवा निवृत्ति की तारीख में पूर्व ही जाए।

(ग) अन्य प्रकार से निश्चित किए गए मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

÷ निर्णय संख्या 5—प्रापका ध्यान वित्त विभाग की अधिमूचना सं० एक 1 (71) वित्त (नियम) 69-11 दिनांक 19-11-69 की ओर दिलाया जाता है जिसके अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 से घटाने पर 58 वर्ष की गई है। उपरोक्त

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं० एक 1 (42) वित्त वि (अपय-नियम) 67 दिनांक 25-3-68 द्वारा निविष्टः।

÷ वित्त विभाग की अधिमूचना सं० एक 1 (71) वित्त नियम 69-11 दिनांक 19-11-69 द्वारा निविष्टः।

प्राज्ञा के फलस्वरूप समस्त चतुर्थ श्रेणी के सभी ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के हों, 1-12-69 से सेवा निवृत्त किये जाते हैं।

समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयध्यक्षों से निवेदन है कि वे इस बात का पूर्ण सुनिश्चयन करें कि उनके अधीन ऐसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के हों 1-12-69 को सेवा निवृत्त कर दिये जावें।

ऐसे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के सम्बन्ध में भ्रम से आदेश जारी किए जाएंगे।

X निर्णय सं० 6—सरकार ने निर्णय किया है कि निम्नलिखित श्रेणी के कार्य प्रभुत कर्मचारियों के मामले में अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख दि० 1-12-69 से वह तारीख होगी जिसको कर्मचारी 55 वर्ष का होता है। एतदनुसार सभी कार्य प्रभुत कर्मचारी जिनकी दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु हो गई है, सेवा में नहीं रखा जाएगा।

1. बागवान/मांसी 2. खलीखो 3. बेलदोर/मैंगमैन 4. सैफई करने वाला 5. कुली
6. स्टोन कटर/ड्रेसर 7. राज 8. ननसाज 9. मददगार 10. माली

2. जहाँ पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन निर्मित एवं प्रमाणित स्थायी आदेश हैं, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रमाणित अधिकारी के लिए आदेश में संशोधन करने तथा दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को सेवा निवृत्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निश्चय चाहिए। इसी प्रकार "अवार्ड" द्वारा प्राप्त होने वाले व्यक्तियों के मामले में विधि/यम विभाग के परामर्श से तत्समान कार्यवाही करनी चाहिए।

3. ऐसे मामलों में जहाँ स्थायी आदेश न हों तथा सेवा की शर्तें कार्यकारी आदेशों या आदेशों या प्रश्न द्वारा विनियमित होती हों, वहाँ दिनांक 1-12-69 को 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले कार्य प्रभुत कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसे कर्मचारों, जिनकी सेवायें इस आदेश के अनुसार समाप्त होंगी, सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर प्रयोग नियमों के अनुसार स्वीकृत मविष्य विधि लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। फिर भी, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम (अधिनियम सं० 14 सन् 1947) की धारा 25 ब के अधीन कटौती लाभ के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित श्रेणी के कार्य प्रभुत कर्मचारियों की, जो राजस्थान लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) व उद्यान, सिंचाई, जलकल एवं आयुर्वेदिक विभाग के कार्य प्रभुत कर्मचारी सेवा नियम, 1969 द्वारा शासित होते हैं, सेवायें उक्त तिथि को 55 वर्ष या इससे अधिक की होने पर दिनांक 1-12-69 से समाप्त की जाएंगी। नियमों में औपचारिक संशोधन उचित समय पर जारी किए जाएंगे।

÷ (ii) चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख वह होगी, जिसकी कि वह 58 वर्ष की अवस्था प्राप्त करता है।

X वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (71) वित्त वि (स्थायी नियम) 68 दिनांक 29-11-69 द्वारा निविष्ट।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (7) वित्त वि (नियम) 69-1 दिनांक 19-11-69 द्वारा '60 वर्ष' के स्थान पर प्रतिस्थापित। दिनांक 1-12-69 से प्रभावी।

*निर्णय:- (वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (71) वित्त वि/नियम/69 दि० 19-11-69 द्वारा) चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दिने जाने के परिणाम स्वरूप जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 1-12-69 को 58 वर्ष या इससे अधिक की आयु के हो गए हैं, उक्त दिनांक से उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया है। चूंकि इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया अतः उन्हें अवकाश का उपयोग करने में बाधित कर दिया गया था। अतः राजस्थान ने आदेश दिया है कि उन्हें निम्नलिखित अवकाश सम्बन्धी रियायतें प्रदान की जाएं—

(1) सरकारी कर्मचारी जिनके सेवा में दिनांक 1-12-69 से ठीक पूर्व जितना उपाजित अवकाश बचाया है, वह उस अवकाश के लिए आवेदन करेगा। आवेदन अवकाश को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 में छूट देते हुए, अधिकतम 120 दिन की सीमा के अधीन रहते हुए, अस्वीकृत अवकाश के रूप में समझा जाएगा। अस्वीकृत अवकाश की स्वीकृति प्राप्ति की इस शर्त पर दी दी जाएगी कि वह उस तारीख के बाद तक का नहीं होगा जिसकी कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता।

(2) उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो 1-12-69 के बाद किन्तु 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होते हैं/हूए हैं, उन्हें बचाया एवं आवेदित उपाजित अवकाश निम्नलिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है—

(क) 1-12-69 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में समस्त बचाया उपाजित अवकाश जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, जिसे वह सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप से उपाजित कर सकता था, उसमें से उसके द्वारा वास्तविक रूप में उपयोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को काट कर, अस्वीकृत अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

(ख) दिनांक 1-1-70 को या उसके बाद परन्तु दिनांक 30-4-70 तक सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा निवृत्ति के पूर्व बचाया उपाजित अवकाश, जो 120 दिन से अधिक का नहीं होगा, अस्वीकृत अवकाश समझा जाएगा परन्तु उसमें से (1) दिनांक 31-12-69 तक वास्तव में उपयोग किये गये सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को (2) तथा दिनांक 1-1-70 से उसके सेवा निवृत्त होने के ठीक पूर्व की तारीख तक की अवधि को, घटा दिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त (1) व (2) के अधीन स्वीकार्य अवकाश वेतन नियम 89 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एक 1 (48) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा निविष्ट किया गया था) के अनुसार निकाला जाएगा तथा हर माह के अन्त में भुगतान योग्य होगा। जहां पेंशन या उपदान के समस्त पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त नहीं हों वहां अवकाश वेतन का भुगतान सामान्य रूप में किया जाना चाहिए तथा अधिक भुगतानों की पेंशन या प्रच्युती या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में से, जब वे स्वीकृत हों, काट लिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अवकाश वेतन का अधिक भुगतान दमूल किया जा सके, ग्राहण एवं वितरण अधिकारी पेंशन कागजातों के साथ साथ सम्बन्धित सरकारी कर्म-

* वित्त विभाग की आज्ञा सं. एक 1 (80) वित्त वि/नियम/69 दिनांक 27-12-69 द्वारा निविष्ट।

चारों को भुगतान की गई अवकाश वेतन की राशि की सूचना देगा तथा उक्त सूचना के आधार पर महाविद्यालय अधिक राशि को पेंशन से वसूल करने के लिए एक टिप्पणी लिखेगा—

टिप्पणी सं. 1—संस्थाओं के अध्यापक एवं अध्यापक चाहे राजपत्रित हों या सराजपत्रित तथा जो शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के तीन माह में अवधि सितम्बर तक पूर्ण अधिवाषिकी आयु को प्राप्त करते हों, उनको सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिये एवं वे जो अधिवाषिकी आयु प्राप्त करते हो तथा सितम्बर के बाद सेवा निवृत्त किये जाने हों तथा अध्ययन के हित की दृष्टि से उन्हें रोका जाना आवश्यक हो तो उनकी सेवाएं सत्र के अन्त तक मध्य गर्मियों के अवकाश के रोकी जा सकती है। यह प्रादेश चिकित्सा, कृषि, पशुपालन एवं प्रायुर्वेदिक कालेजों के अध्यापन वर्ग पर भी लागू होगा।

× “टिप्पणी संख्या 2—सरकारी कर्मचारी जो जिसको अधिवाषिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा में वृद्धि की गई है, सेवा वृद्धि काल में दूसरे पद पर परोक्ष नही किया जाएगा।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (क) के नीचे दी गई टिप्पणी के अन्तर्गत उन अध्यापकों की सेवाएं, जो कि शिक्षण सत्र में सितम्बर के बाद सेवा निवृत्त होने हैं, उन्हें प्रीम्पावकाश सहित सत्र के अन्त तक सेवा में रखा जा सकता है।

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत 2-10-59 से पंचायत समितियों के निर्माण के फलस्वरूप कुछ प्राथमिक पाठशालाएं पंचायत समितियों के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर दी गई हैं।

यह प्रादेश दिया गया है कि उपरोक्त टिप्पणी वर्णित वर्गों के अनुसार पंचायत समितियों द्वारा ऐसे अध्यापकों को रोका जाना सक्षम प्राधिकारों के प्रादेशों से रोका हुआ समझा जावेगा।

यह प्रादेश दिनांक 2-10-59 से प्रभाव में आया हुआ समझा जाना चाहिये।

÷ (iii) चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापन वर्ग में) सदस्य आदि जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भारी सेवा के लिए फिट घोषित किया जाता है, की अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख वह होगी जिसकी वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। अन्य मामलों में ऐसे सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति वह तारीख होगी जिसकी वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

+ टिप्पणी—विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य अध्यापन संस्थाओं या उक्त संस्थाओं के अध्यक्षों, (राजपत्रित या सराजपत्रित) जो संवत्सरिक वर्ष में सितम्बर माह के पूर्व ही अधिवाषिकी आयु (सुपरएग्युएशन) प्राप्त करने को हैं, उन्हें निवृत्ति पूर्व अवकाश, (नोव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट) अवश्य हो, यदि स्वीकार्य हो तथा आवेदन किया गया हो, स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा नियत तारीख को उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार वे व्यक्ति जो 1 सितम्बर को या उनके बाद अधिवाषिकी आयु प्राप्त करने को हैं लेकिन जो निवृत्ति-पूर्व अवकाश उम सीमा तक लेने के हकदार हैं कि वे 1 सितम्बर से पूर्व अवकाश पर रवाना होने के लिए बिदा किए जा सकते हैं, उन्हें भी यदि उन्होंने आवेदन किया हो तो यवराश अवश्य ही स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा नियत तिथि को सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो 1 सितम्बर को

वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एफ 1 (64) वित्त वि (नियम), 69 दिनांक 15-10-69 द्वारा निवृत्त।

÷ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (15) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 11-5-67 द्वारा निवृत्त तथा दिनांक 2-2-65 से प्रभावी।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) 66 दि० 21-3-69 द्वारा निवृत्त तथा दिनांक 1-12-62 से प्रभावी।

या उसके बाद अधिकाधिक प्राप्ति करते हैं एवं जो न तो अपना ऐसा अवकाश बनाया रखते हैं जिसका कि वे । निम्नलिखित के पूर्व उपभोग कर सकते वे इस न निवृत्ति पूर्व अवकाश का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें नियत तिथि को सेवा निवृत्त कर दिया जाना चाहिए । फिर भी, नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी यह विचारता हो कि कर्मों के अवकाश (समर वेकेशन) महित औद्योगिक वर्ष के अवशिष्ट समय के भीतर उनकी सेवाओं की अध्ययन के दिन की दृष्टि से धाम्य रखा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर पुनः नियुक्त कर सकता है—

(1) पुनर्नियुक्ति पर वेतन, सेवा निवृत्ति के पूर्व अन्त में उठाए गए वेतन में से पेंशन (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (इस कम रिटायरमेंट प्रेन्स्यूटी) के बराबर की पेंशन) काटकर जो भी राशि बाएंगी, उसके बराबर निदिष्ट किया जाएगा ।

(2) पेंशन बन्धनों के अन्तिम निर्णय को विचाराधीन रखते हुए, उक्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति पर वेतन अस्थायी तौर पर उनके द्वारा अन्तिम उठाए गए वेतन की दर में उठाने की स्वीकृति दी जाएगी लेकिन इस शर्त के अधीन रहते हुए ही जाएगी कि अधि-भुगतान (एक्सेस पेमेन्ट) का पेंशन बन्धनों का अन्तिम निर्णय होने पर पेंशन एवं मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान (इस कम रिटायरमेंट प्रेन्स्यूटी) में से समायोजन कर दिया जाएगा ।

(3) ऐसे मामलों में जहां पुनर्नियुक्ति पर वेतन उपर्युक्त प्रादुर्भूत (1) के अधीन निदिष्ट या जाए, ही नियम 337 के प्रावधान एवं तदधीन निर्णय, पुनर्नियुक्ति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे ।

56 (ख)-विलोपित किया गया ।

स्पष्टीकरण—कृपया जगह पर सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 210 के खण्ड (ग) के प्रावधान राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (ख) के प्रावधानों में संगत हैं । यह निदिष्ट किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 (ख) निर्धारित करता है कि कदाचरण के आरोप पर निम्नलिखित सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की प्राप्ति करने पर सेवा निवृत्त होने के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही उसे सेवा निवृत्त होने की आज्ञा दी जाएगी लेकिन उसे सेवा में उस समय तक रखा जाएगा जब तक कि उसके विच्छेद आरोपों की जांच पूर्ण न हो जाए तथा सशम प्राधिकारी द्वारा उस पर अन्तिम आदेश न दे दिया जाए । राजस्थान सेवा नियमों का मंगोचित खण्ड (ग) उक्त अधिकारियों का वर्णन करता है जो निम्नलिखित रहते हुए सेवा निवृत्त होने हैं या जिन्हें सेवा निवृत्त होने की स्वीकृति दी जानी है । सन्देहों के निराकरण हेतु इस सम्बन्ध में स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाना है—

वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं परीक्षा नियमों के नियम 14 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है यदि सरकार कर्मचारी निम्नलिखित हो । ऐसे मामलों को पूरा करने के लिए ही राजस्थान सेवा नियमों के नियम 210 के खण्ड (ग) को मंगोचित किया गया । प्रत्यः यह स्पष्ट जांच कार्यवाही के पूर्ण होने पर जारी किए गए सशम प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व या बाद में निम्नलिखित काल में सेवा निवृत्ति के मामलों की संयोजकता करता है । इसके विपरीत राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 (ख) को अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व, निम्नलिखित काल में सरकारी कर्मचारी द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की प्राप्ति प्राप्त करने पर स्वतः ही उसकी सेवा निवृत्ति पर प्रतिषेध लगाने हेतु मंगोचित किया जाना है । निम्नलिखित काल में सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने या उसकी स्वीकृति देने का प्रश्न केवल तब ही उत्पन्न हो सकता है जब जांच कार्यवाही पूरी हो गई हो इसके पूर्व

के रूप में नहीं माना जायेगा । X पेन्शन सम्बन्धी लाभों के लिए राज्य कर्मचारी को अपनी प्रतिवार्षिक सेवा निवृत्ति की तारीख से सेवा निवृत्त किया हुआ समझा जायेगा या उसे यदि सेवा में वृद्धि की गई है, तो उस वर्धित अवधि की समाप्ति पर, स्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा एवं पेन्शन सम्बन्धी लाभों के लिए उस तिथि में जिसको कि वह सेवा निवृत्त होता है या उसकी वर्धित अवधि समाप्त होती है, पात्र समझा जायेगा ।]

(2) यह नियम उन सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होता है जिन पर ये नियम लागू होते हैं चाहे वे अस्थाई या स्थाई पदों पर स्थाई रूप से या कार्यवाहक रूप से काम कर रहे हों ।

(3) विलोपित की गई—

निर्णय—विभिन्न विभागों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहिले ही सेवा निवृत्त कर दिए गए । यद्यपि उन्हें नियम 246 के अन्तर्गत सेवा निवृत्त किया जाना था । इन सब पुराने मामलों को विनियमित करने के उद्देश्य से सरकार आदेश देती है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 9-10-53 तक 55 वर्ष व 60 वर्ष की बीच की अवस्था में सेवा में निवृत्त हो गये हैं, उन्हें प्रतिवार्षिकी मायु प्राप्त पेन्शन/प्रेच्युटी (उपदान) पर सेवा निवृत्त किया हुआ समझा जाना चाहिए ।

(2) चूंकि नियम 246 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 35 (48) मार/52 दिनांक 9-10-53 द्वारा हटा दिया गया है तथा उसमें सम्बन्धित प्रावधान नियम 56 की टिप्पणी संख्या 3 में दे दिया गया है, ऐसे सभी मामलों में इस नियम द्वारा वासित किए जाएंगे ।

जांच निर्देशन—(1) जब तक राज्य कर्मचारी का विवेकित अवस्था प्राप्त करने पर, सेवा निवृत्त होता या रिटायर्ड होता या अवकाश पर बन्द रहना चाहा गया हो, तो जिस तारीख को वह उस अवस्था को प्राप्त करता है वो वह दिन, जैसा भी कमिनि हो, अवकाश का दिन मिला जाता है तथा राज्य कर्मचारी को उस दिन से, उसको मिलाकर, सेवा से निवृत्त या रिटायर्ड हो जाना चाहिए यथा अवकाश से बन्द हो जाना चाहिए ।

(2) नियम 346 इसकी रियायती एवं शर्तों के अन्तर्गत एक व्यक्ति को, जो प्रतिवार्षिकी मायु प्राप्त हो या पेन्शन पर सेवा से निवृत्त हो रहा हो, उसे इस नियम के बाहर एवं नियम 346 में वर्णित उन शर्तों के आधार पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करता है, जिसका कि पालन प्रत्येक स्वीकृति के नवीनीकरण (Renewal) में किया जाना है ।

भाग ४

अध्याय १० अवकाश (Leave)

खण्ड 1 -अवकाश की सामान्य शर्तें

नियम 57. सेवा (Duty) द्वारा अर्जित अवकाश—अवकाश केवल सेवा द्वारा ही अर्जित

X वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (9) एफ. डी. (व्यय-नियम) 65 दिनांक 26-2-65 द्वारा शामिल किया गया)

किया जाता है। इस नियम के लिए विदेशी सेवा में विताया गया समय भी सेवा में गिना जाता है, यदि ऐसे समय के अवकाश वेतन के लिए अंशदान दिया जाता है।

नियम संख्या 1—सेवाओं के एकीकरण के समय में भिन्न भिन्न समय तक बहुत से राज्य कर्मचारियों को बिना नियुक्ति (Posting) के रहना पड़ा। एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि क्या ऐसे समय को अवकाश उपाजित करने के लिए गिना जावेगा।

चूंकि अवकाश केवल वास्तविक सेवा करने पर ही उपाजित किया जाता है, तथा ऐसी अवधियों में राज्य कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक सेवा नहीं की गई, अतः यह निर्णय किया जाता है कि उक्त विचाराधीन समय अवकाश उपाजित करने में नहीं गिना जाएगा चाहे उसे पेशान कार्यों के लिए वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 23 (2)-घार/52 दिनांक 31-5-52 (वैलिये राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के नीचे राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 1) के अनुसार गिना जा सकता है।

नियम संख्या 2—कुछ संदेह उत्पन्न किए गये हैं कि क्या वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7-1-53 (नियम संख्या 1 जो ऊपर लिखा गया है) में वर्णित 'अवकाश' शब्द का अर्थ क्या केवल उपाजित अवकाश (Privilege leave) है या उसमें अन्य किस्म के अवकाश भी शामिल हैं जैसे आधे वेतन अवकाश (Half pay leave) तथा क्या यह आदेश पूर्ण समय से प्रभावशील होगा। मामले की जांच करली गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त आदेश में आये हुए 'अवकाश' का तात्पर्य उपाजित अवकाश एवं उसके समान अवकाश से ही है न कि अन्य किस्म के अवकाश से है। यह आदेश पूर्ण काल से लागू होगा है लेकिन जो राज्य कर्मचारी 7-1-53 के पूर्व सेवा निवृत्त किए जा चुके हैं, उनसे कोई बसूली नहीं की जानी है।

(2) जो राज्य कर्मचारी अनियुक्त (Unposted) या 'सरप्लस' रहे, उनका अवकाश का लेना, जैसा कि उक्त अवतरण में स्पष्ट किया गया है, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7-1-53 (उक्त निर्णय संख्या 1) के अनुसार संशोधित (Revised) किया जाना चाहिए। सराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के मामले में यह विभागों के अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

यदि राज्य कर्मचारियों के अवकाश के लेख के संशोधित करने पर अधिक अवकाश लिया हुआ प्रतीत होता है तो इस प्रकार के अधिक अवकाश का समायोजन (Adjustment) अवश्य में उपाजित किए गये अवकाश से किया जाना चाहिए।

नियम 57 (क)—दूसरे नियमों के समूह से नियंत्रित एक राज्य कर्मचारी द्वारा इन नियमों से शासित पद पर काम करने पर उसके अवकाश का नियमन का प्रकार—जब तक किसी मामले में इन नियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत अन्यथा प्रकार से न दिया गया हो, एक राज्य कर्मचारी ऐसी सेवा या पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिस पर यह नियम लागू होते हैं, तथा ऐसी सेवा या पद से जाता है जिस पर यह नियम लागू नहीं होते हैं, वह ऐसे स्थानान्तरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश, साधारणतया इन नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं कर सकता है।

नियम 58—पुनर्नियोजन (Re-employment) या पुनर्नियुक्ति होने पर दक्षिण होने से पूर्व की गई सेवाओं का अवकाश—यदि एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा को क्षतिपूर्ति पर (Compensation) या अशक्त पेंशन (Invalid Pension) या उपदान (ग्रैजुटी) पर छोड़

देता है तथा पुनः, सेवा में ले लिया जाता है एवं इसके परिणामस्वरूप उसका उपदान वापिस लौटा दिया जाता है या उसकी पेंशन पुनः कर से रक्षित (Abeyance) रखी जाती है तथा इसके द्वारा उसकी पूर्ण की सेवाएं अन्तिम सेवा मधुनि पर पेंशन योग्य हो जाती है तो पुनः नियुक्ति करने वाले सशम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जिनकी सीमा तक वह निर्धारित करे, उसकी गन सेवाएं अवकाश के लिए गिनी जा सकती हैं।

(ग) एक राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा में बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है, पर जो अपील या निगरानी (Revision) पर पुनः नियुक्त हो जाता है, तो वह अपनी पूर्ण की सेवाओं को अवकाश के लिए गिनाने का हकदार होगा।

जीव निर्देशन—(1) एक व्यक्ति जो अधिकाधिक घाबु प्राप्त होने पर या सेवा निवृत्ति पेंशन पर सेवा निवृत्त हो गया है, उसकी पुनर्नियुक्ति (Re-employment) साधारणतया एक अवकाश स्वभाव एवं अस्थायी उपाय है। ऐसे मामलों में पुनर्नियुक्ति व्यक्ति की सेवा की धारणा गममा जाना चाहिए तथा पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसका अवकाश, अस्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले नियमों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

(2) विनियम

निर्णय—ऐसे मामलों में जिनमें कि सर्वजनिक सेवा से त्याग पत्र को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 208 (ग) के अर्थ के अनुसार त्याग पत्र के रूप में नहीं गममा जाता है, तो अवकाश के मामले में भी उसे सेवा को निरन्तर गिने जाने का लाभ दिया जाना चाहिए।

+ **क्लिअर 59**—अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है (Leave can not be claimed as right)—अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। अवकाश स्वीकृत कर्ता सशम प्राधिकारी राजकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है या उसे रद्द (Revoke) कर सकता है। परन्तु कोई भी अवकाश जिसके लिए आवेदन किया हो एवं जो सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बनाया हो, उसे उक्त प्राधिकारी स्वीकृत करने से मना नहीं कर सकता है, वह या तो सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी कि हम मध्यम में सरकार ने शक्ति प्रदान कर रखी है, निश्चित से मना की जाएगी। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध पर राज्य कर्मचारी द्वारा आवेदन किए गए बनाया अवकाश की किस्म को नहीं बदला जा सकता है एवं चूंकि सशम प्राधिकारी के लिए यह छूट है कि वह इस नियम के अन्तर्गत आवेदन किए गए अवकाश को स्वीकृत करने से मना कर सकता है या 'रद्द (Revoke) कर सकता है, अतः उसके लिए यह छूट नहीं है कि वह उक्त अवकाश के किस्म में परिवर्तन कर सके।

निर्णय—सभी धर्मा कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जहां राज्य कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए गए दो अवकाशों के बीच की सेवा का समय केवल नाम मात्र का था। ऐसे मामलों में अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी; राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत, अपने निर्णयानुसार अवकाश नियमों को अवहेलना करने के प्रयत्न को रोकने में असफल रहे तथा नियमों

+ (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या 1 (19) एक डी (व्यय-नियम) 67-1 दिनांक 21-3-67 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)

की मजदूरी करके उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों ने भर्वाछनीय नाम प्राप्त किए ।

2. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत करने वाला एक प्राधिकारी, एक कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छानुसार उपाजित अवकाश या बर्द वेतन अवकाश के लिए आवेदन किए गए विकल्प में दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखता है। इसलिए जब एक बार अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उन्हें लगातार दो प्रकार के अवकाशों के रूप में समझा जाकर एक-दूसरे में नहीं बदला जा सकता है। तथा राज्य कर्मचारी को नियमों द्वारा भर्वाछनीय लाभ उठाने से नहीं रोका जा सकता है। फिर भी सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकृत कर इस प्रकार अवकाश नियमों की मजदूरी करने के प्रयत्नों पर प्रतिबन्ध डाल सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य कर्मचारियों ने सेवा के अल्प-समय के बाद ही किसी नये प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया हो, वह सावधानी पूर्वक इस दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जाँच करे कि नियमों के पालन का पूर्ण ध्यान रखा गया है तथा, यदि किन्हीं कारणों से यह विश्वास हो जाए कि अवकाश नियमों का या उनके प्राप्ति का गलत ढंग से लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है, तो सक्षम प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अन्तर्गत अपने निर्णय के अधिकार का उपयोग कर, उसके अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है।

नियम 60—अवकाश का प्रारम्भ व अन्त—साधारणतया अवकाश उस दिन से प्रारम्भ होता है जिसकी कि कार्यभार का स्थानान्तरण होता है तथा चार्ज लेने के पहिले दिन अन्त होता है। जब भारत के बाहर विदेश से लौटकर आने वाले राज्य कर्मचारी को कार्यग्रहण करने का समय (रिपोर्टिंग टाइम) स्वीकृत किया जाता है तो उसके अवकाश का अन्तिम दिन वह होगा जिस दिन के पहिले कि वह अहाल, जिसमें वह यात्रा कर रहा है, अपने रवाना होने के स्थान या लंगर पर, उतरने के बन्दरगाह पर पहुँचे, यदि वह वायुयान द्वारा लौटता है तो वह दिन होगा, जिसकी वह उस वायुयान में लौटता है, भारत में अपने पहिले नियमित बन्दरगाह पर पहुँचे।

नियम 60—क. अवकाश के समय में पता—अवकाश पर रवाना होने वाले प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने अवकाश के प्रारम्भ व अन्त पर अपना पता लिखना चाहिये जिससे कि उस समय में उसके पास पत्र इत्यादि पहुँच सकें। (अवकाश काल में) पते में परिवर्तन होने पर, यदि कोई हो, उसकी सूचना, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय के अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के पास पहुँचा देनी चाहिए।

नियम 61—अवकाश के साथ अवकाशों (Holidays) का सम्बन्ध (combination)—जब राज्य कर्मचारी के अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व के दिन तथा अवकाश का समय समाप्त होने के बाद ही कोई सरकारी अवकाश (Holiday) या एक से अधिक अवकाश हों तो राज्य कर्मचारी पूरे दिन की समाप्ति पर अपने कार्यालय को छोड़ सकता है या आने वाली छुट्टी की या अधिक छुट्टियों में अन्तिम दिन को छुट्टी की छुट्टी कर सकता है, परन्तु शर्त यह है कि—

× वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1 (7) वित्त वि/ (न्यय नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा संशोधित।

(क) उसके स्थानान्तरण या कार्यभार के सम्भालने में इयाई एडवांटा के अनिश्चित जमानतों (Securities) या धन राशियों का कार्यभार सम्भालना या सम्भालना गारंटी न हो।

(ख) उसका शीघ्रतापूर्वक स्थानों में एक राज्य कर्मचारी को दूसरे स्टेशन से अपने गेवाओं को पूरा करने के लिए उस तरह शीघ्र स्थान न होना पड़ना हो।

(ग) उसके लौटने में विराम होने से ऐसे राज्य कर्मचारी के किसी दूसरे स्टेशन से स्थानान्तरण होने में देर नहीं हो रही हो जो कि वह उसकी अनुपस्थिति में कार्य कर रहा था उस पर अर्थात् वह नि नियुक्त किसी व्यक्ति को राज्यकीय सेवा से मुक्त करने में विराम नहीं होता हो।

नियम—62. मुक्त (Exempt) करने की शक्ति—इस शक्ति पर कि बिना होने वाला कर्मचारी अपने कामों की धनराशि का उत्तरदायी बना रहे, तो एक नक्षम प्राधिकारी घोषणा कर सकता है कि किसी विशेष मामले में नियम 61 के अन्तर्गत (क) भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

नियम—63. अवकाश के साथ छुट्टियों के सम्बन्ध होने पर अनुवर्ती व्यवस्थाओं का प्रभावशील होना (Consequential arrangements when effective, if holidays combined with leave)—कब तक सक्षम प्राधिकारी किसी एक मामले में अवकाश प्रकार से निर्देशित न करे—

(क) यदि छुट्टियाँ (Holidays) अवकाश में पूर्ववर्ती (prefix) हों तो अवकाश व केन व भर्ती की कोई अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव छुट्टियों के बाद प्रथम दिन में पड़ेगा।

+ (ख) यदि छुट्टियाँ अवकाश के समय से परवर्ती (suffix) हों तो छुट्टी का समय उस रोज समाप्त किया हुआ समझा जाता है तथा केन व भर्ती की किसी अनुवर्ती व्यवस्था पर प्रभाव उस दिन से पड़ता है जिसको कि अवकाश के समय का अन्त हो जाना, यदि उसके आगे कोई सरकारी छुट्टियाँ नहीं होती।

छू निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 के नीचे 'स्पष्टीकरण' के अन्त में प्रयुक्त वित्त विभाग के आदेश दिनांक 9-8-62 नियम 50 के अधीन प्रतिरिक्त केन को उन मामलों में विनियमित करता है जहाँ 30 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए दोहरी व्यवस्था की जाती है।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अवकाश में पूर्व एवं बाद की अवधि जो छुट्टी हो, उसे दोहरी व्यवस्था की अवधि के लिए बिना माना जायिये तथा तदनुसार प्रतिरिक्त केन दिया जाना चाहिये। वर्तमान प्रावधानों के अधीन छुट्टियों (होलीडेज) की ऐसी अवधि दोहरी व्यवस्था की अवधि में गिनने के लिए शामिल नहीं की जाती है तथा उसके लिए कोई अनिश्चित केन स्वीकार्य नहीं होता है।

मामले की राजस्थान सेवा नियमों के नियम 63 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच करली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि उक्त आदेशों के प्रयोजनार्थ अवकाश के पूर्ववर्ती एवं

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एक 1 (7) वित्त वि/ (व्यय नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा संशोधित

वित्त विभाग के आदेश सं० एक 1 (25) वित्त वि/ (व्यय नियम) 66 दि० 1-7-66 द्वारा निदिष्ट।

परचातवर्नी छुट्टियों को दोहरी व्यवस्था की अवधि गिनने में शामिल किया जा । चाहिये तथा तदनुसार प्रतिरिक्त वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिये ।

नियम-64 अवकाश (Leave) में नौकरी स्वीकार करना (1) एक राज्य कर्मचारी अवकाश काल में कोई भी सेवा या कोई नियुक्ति (जिसमें निज व्यवसाय की स्थापना, सेवाकार, सहायकार, कानूनी या चिकित्सा सम्बन्धी प्रेरितता भी शामिल है) सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकार नहीं कर सकता ।

(2) एक राज्य कर्मचारी जिसकी अवकाश काल में किसी सरकार या प्राइवेट नियोजक के अधीन नौकरी करने की आशा दे दी गई है, उसका अवकाश वेतन राज्यपाल के आदेशानुसार निर्धारित किए गए अनुसार होगा ।

टिप्पणी 1-यह नियम प्राकृतिक साहित्यिक कार्य या परीक्षक के रूप में सेवा या ऐसी समान सेवा पर लागू नहीं होगा तथा यह नियम उन विदेशी सेवा स्वीकार करने पर भी लागू नहीं होगा जो कि नियम 141 के अन्तर्गत आती है ।

2-यह नियम उन पर भी लागू नहीं होगा जहां राज्य कर्मचारियों को कुछ मर्यादित सीमा तक निज प्रेरितता करने को एवं उसको फौज प्राप्त करने को स्वीकृति, उसकी सेवा की शर्तों के अंग के रूप में दी गई है, उदाहरणार्थ जैसे एक चिकित्सक को निज चिकित्सा करने का अधिकार स्वीकृत किया गया है ।

स्पष्टीकरण—उत्तरा द्वारा सन्देश के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज-स्थान सेवा नियम 64 (2) के द्वारा अवकाश वेतन पर आभाषा गया प्रतिव्यय समान रूप से सम्पादित सेवा में नियुक्त ऐसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जो कि अवकाश के भीतर, या ऐसे अवकाश में, जिसके समाप्त होने पर उसके सेवा पर वापिस आने की आशा न हो, किसी राज्य सरकार या प्राइवेट नियोजक के अधीन नौकरी स्वीकृत कर लेता है या किसी स्थानीय निधि के दिए जाने वाले वेतन वाली नौकरी स्वीकार कर लेता है ।

यह धोर भी निर्णय किया गया है कि उपरोक्त प्रतिव्यय सविदा (Contract) अधिकारियों पर भी लागू होंगे ।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी जिसे निवृत्ति-पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) या अस्वीकृत अवकाश के भीतर किसी अन्य सरकार या एक पर-सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय किसी सेवा में नौकरी करने की स्वीकृति दे दी गई है, जो उसका वेतन पर वेतन अवकाश पर प्राप्य अवकाश वेतन की गति के बराबर होगा ।

नियम 65—निवृत्ति पूर्व अवकाश पर राज्य कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति—(1) जब कोई राज्य कर्मचारी जो कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश पर रवाना हो चुका हो, तथा उसे ऐसे अवकाश में सरकार के अधीन किसी पर पर पुनर्नियुक्त करने की जरूरत पड़ी हो तथा वह सेवा (ड्यूटी) पर आने के लिए रवाना हो तो उसे सेवा पर वापिस युक्त लिया जावेगा तथा सेवा पर उपस्थित होने के दिन से जो भी अवकाश का भाग देय रहेगा वह रद्द कर दिया जावेगा । इस प्रकार जो अवकाश रद्द किया जाएगा वह अस्वीकृत अवकाश (Refused leave) के रूप में समझा जावेगा तथा वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या पुनर्नियुक्ति

की तारीख समाप्त होने के बाद में स्वीकृत किया जायेगा यदि राज्य कर्मचारी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख तक या पूर्वोक्त तारीख के बाद तक, जैसी भी स्थिति हो, सेवा में घबरा रहे। एक राज्य कर्मचारी जितने अविवर्धित आय प्राप्त होने के पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश में किसी अन्य सरकार के तथोन् या गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्वतन्त्र निधि से देन सेवा के अधीन भोकरों करने की स्वीकृति दी गई है, उनका अवकाश वेतन, उनके अर्द्ध वेतन अवकाश के वेतन की राशि के बराबर होगा।

(2) विनियमित किया गया

टिप्पणी—वित्त विभाग के आदेश संख्या 35 (30) चार/52 दिनांक 12-7-52 के द्वारा नियम 65 का संशोधन दिनांक 1-4-51 में प्रभावशील होगा जिसकी कि राजस्थान सेवा नियम लागू हुये हैं।

नियम संख्या 1—विमोचनकरण (Integration) विभाग के आदेश संख्या 401 जी. डी./खण्ड 11/दिनांक 24-6-49 एवं संख्या 26 खण्ड 11 दिनांक 14-8-59 के अन्तर्गत बहुत से राज्य कर्मचारी, उनके बकाया अवकाश के पूर्ण या आंशिक रूप में उपयोग करने से पूर्व ही अस्थाई रूप से पुनर्नियुक्त कर लिये गए थे। उनके बकाया अवकाश के उपयोग तथा उसे वेतन के लिये योग्य सेवा में गिने जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को अवकाश पर के रूप में उस समय तक समझ जाने की स्वीकृति दी जाती है जब तक कि उस पर कार्य करते हुये उनका अवकाश समाप्त नहीं हो जाता है जिस पर वे पुनर्नियुक्त हुये हैं तथा उस मामले में उन्हें पुनर्नियुक्ति पर आधारित किये गये वेतन के प्रतिरिक्त भाषा अवकाश वेतन प्राप्त करने की तथा अवकाश के समय की वेतन के लिए गिने जाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि इस प्रकार पुनर्नियुक्त कर्मचारी इस रियायत का नाम उठाना नहीं चाहता हो तो वह पुनर्नियुक्ति की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे अवकाश में प्राप्य पूर्ण अवकाश वेतन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में उसकी सेवा निवृत्ति पुनर्नियुक्ति से पूर्व में मानी जायेगी तथा वह अवकाश का समय वेतन के लिये नहीं गिना जायेगा।

(2) किसी भी मामले में अवकाश की सीमा उस अधिकतम सीमा से ज्यादा न होगी जो कि सम्बन्धित इकाई के नियमों के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश में प्राप्त की जा सकती थी।

(विशेष—साधारण यह है कि इकाई राज्यों के नियम के अनुसार निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जितना अवकाश उसे मिल सकता हो, उससे ज्यादा अवकाश वह नहीं ले सकता है।)

(3) उपरोक्त अवतरण (1) के सम्बन्ध का विकल्प (आप्शन) वेतन के गिने जाने के पूर्व कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार के पास भिजवाया जाना चाहिये।

नियम संख्या 2—एक सन्देह उत्पन्न हो गया है कि क्या नियम 65 के खण्ड (2) के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को उसे नियम 89 के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए निवृत्ति पूर्व अवकाश पर जाने से रोका जा सकता है तथा, यदि आवश्यक हो तो, क्या उसकी सेवा में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उक्त खण्ड में दी गई इच्छा का भाव्य मामले में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में बाधा डालना नहीं है। जब एक राज्य कर्मचारी, जो कि नियम 89 के अन्तर्गत निवृत्ति

पूर्व अवकाश पर रवाना हो चुका है, यदि ऐसे अवकाश के बीच में सेवा पर वापिस बुला लिया जाता है तथा उसकी सेवा में वृद्धि स्वीकृत कर दी जाती है तो उसके अवकाश का बचा भाग रद्द कर दिया जावेगा तथा पूर्व में उपभोग किया गया अवकाश नियम 89 के प्रावधान के अन्तर्गत सेवा वृद्धि के समय में उपभोग किया गया अवकाश माना जावेगा ।

नियम संख्या 3—(1) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 65 के अवतरण 2 व 3 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी जिसको कि निवृत्ति पूर्व अवकाश काल में या नियम 89 के अन्तर्गत 'अस्वीकृत अवकाश' में किसी अन्य गैर सरकारी नियोजक के अधीन या स्थानीय निधि से देय सेवा में अन्य नोकरी करने की आज्ञा दे दी गई हो, उसका अवकाश वेतन निम्न तक सीमित होगा—

(i) एक राज्य कर्मचारी जो पेन्शन प्राप्त करने योग्य है, उसे उस पेन्शन की राशि के बराबर, जिसको कि सेवा निवृत्ति के समय उसके प्राप्त करने की आज्ञा है ।

(ii) यदि एक राज्य कर्मचारी पेन्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं है तो उस अवकाश वेतन की राशि के बराबर, जो उसे अर्द्धवेतन अवकाश पर मिलता हो ।

इस सम्बन्ध में यह विचार विमर्श किया जाता है कि अवकाश वेतन पर प्रतिबन्ध के विषय में दो विभिन्न सिद्धान्तों का लागू किया जाना, जैसे कि सम्बन्धित अधिकारी पेन्शन प्राप्त करने के योग्य है या नहीं, कुछ भ्रंश उत्पन्न करता है तथा विशेष तौर पर उन कर्मचारियों के साथ में इससे अनुचितता बसता है जो कि नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत साधारणतः अधिकतम पेन्शन से कम पेन्शन पर सेवा निवृत्त किया जाता है ।

चूंकि उक्त विचार में काफी शक्ति है तथा सभी प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में एक सा व्यवहार किया जाना वांछनीय है, इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 65 के अनुसूची (2) व (3) में वार्षिक संशोधन करते हुए आदेश दिया गया था कि ऐसे सभी मामलों में (पेन्शन प्राप्त करने योग्य कर्मचारियों को मिलाकर) अवकाश वेतन उनके अर्द्धवेतन पर मिलने वाली राशि तक सीमित होगा ।

ये आदेश जारी किये जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे तथा पुराने मामलों की पुनः प्रारम्भ नहीं किया जावेगा ।

नियम संख्या 4—(i) ऐसे मामलों में एक अधिकारी जो सेवा में निवृत्त (रिटायर) किये जाने के पूर्व राजस्थान सरकार की सेवा में था तथा जो अधिवापिकी प्राप्ति (superannuation) की तारीख से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृत किए जाने के कारण, उसके उपभोग करने के अवसर से पहले ही सेवा में पुनर्नियुक्त कर लिया गया हो तो वह ऐसे बकाया अवकाश का उपभोग पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कर सकता है ।

(ii) ऐसे अवकाश का अवकाश वेतन उतना ही हो जो कि उसे सामान्य रूप में मिलता लेकिन पुनर्नियुक्ति की जाने के कारण उससे से पेन्शन या उपदान के समान पेन्शन व अन्य सेवा निवृत्ति के लाभ की राशि काटी गई ।

(iii) अस्वीकृत अवकाश, जिसको कि पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उपभोग करने की स्वीकृति दी गई है, उसका अवकाश वेतन उस विभाग द्वारा दिया जावेगा जिसको कि

उसे यह ध्यय सहन करना पड़ता यदि वह कर्मचारी उसका उपयोग पुनर्निपुणता के पूर्व करता तथा उसे नहीं रोका जाता ।

(iv) पुनर्निपुणता काल में जितना अवकाश उपार्जित किया जाय तथा उतना अवकाश उस पुनर्निपुणता की अवधि में न दिया जाये तो उसका उपयोग, पुनर्निपुणता की अवधि समाप्त होने के बाद, करने की स्वीकृति दो या सफ़रों के बग़ैर कि उक्त अवतरण (1) के अन्तर्गत प्रस्तोहित किया गया अवकाश तथा इस अवधि में न कमाया गया अवकाश दोनों मिलाकर नियम 89 के अन्तर्गत एक समय में स्वीकृत किए जाने वाले अवकाश में ग्यारह नहीं होगा ।

(v) यदि एक राज्य कर्मचारी पुनर्निपुणता की तारीख को प्रस्तोहित अवकाश का कुछ भाग का उपयोग कर लेता है तो पुनर्निपुणता के बाद अन्तिम पद धारण करने पर जो अवकाश उसे मिलेगा वह ऐसे बचे अवकाश तथा पुनर्निपुणता काल में उपार्जित अवकाश को मिलाकर होगा तथा उस रूप में मिलाया जावेगा जैसा अधिकारी चाहे तथा प्रकार के अवकाश वेतन का भार दोनों प्रकार के अवकाशों को मिलाने के तरीके के अनुसार होगा । ऐसे अवकाश की औपचारिक स्वीकृति ऐसे समय अधिकारी द्वारा निहाने आनी चाहिए जैसे कि पुनर्निपुणता के पूर्व या उसमें स्वीकृत करने के लिए तथ्य है ।

(vi) पुनर्निपुणता में उपार्जित, उपार्जित अवकाश (Privilege leave) की अन्तिम अवकाश के रूप में उपयोग किये जाने की स्वीकृति दो जावेगी चाहे उसके लिए सार्वजनिक सेवा के आवश्यकता के समय में औपचारिक रूप से आवेदन न किया गया हो तथा प्रस्तोहित न किया गया हो ।

यह सटीकता 30-6-54 से प्रभावशील होगा ।

नियम 65. अवकाश में वापिस बुलाना—किसी राज्य कर्मचारी को, उसके अवकाश के समाप्त होने के पूर्व ही, सेवा में वापिस बुलाने के आदेश हैं यह कहा जाना चाहिए कि क्या अवकाश पर से सेवा में वापिस आना ऐच्छिक है या आवश्यक है । यदि वापिस आना ऐच्छिक हो तो राज्य कर्मचारी को कोई रिवाज या पाने का हक नहीं है । यदि यह आवश्यक है तो वह उस तारीख से सेवा पर उपस्थित माना जाने का हकदार है जिसकी ति वह उस स्थान के लिए रवाना होता है जिस पर पहुंचने के लिए आदेश दिया गया है तथा यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत वह यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन जब तक वह अपना पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह अवकाश वेतन ही प्राप्त करेगा ।

टिप्पणी—अवकाश से आवश्यक रूप से सेवा पर बुलाने पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की रिवाज राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार नियमित होगी ।

नियम 67. अवकाश के लिए आवेदन पत्र किये प्रस्तुत किया जाय—अवकाश या अवकाश में वृद्धि का आवेदन पत्र उनी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो ऐसे अवकाश या अवकाश की वृद्धि को स्वीकृत कर सकता है ।

नियम 68. विदेशी सेवा में स्थानान्तरित राज्य कर्मचारियों की पहिले अवकाश नियमों से अवगत कराना चाहिए—विदेशी सेवा में स्थानान्तरित एक राज्य कर्मचारी को, विदेशी सेवा में अपनी सेवा देने के पूर्व, उन सभी नियमों व प्रतिबन्धों से अवगत कराना चाहिए जिनसे कि ऐसी विदेशी सेवा में उसका अवकाश नियमित होगा ।

नियम 69. विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने—भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को, 120 दिन तक के उपरान्त अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों के सभी आवेदन पत्र महालेखाकार की रिपोर्ट के साथ, अपने नियोजक के द्वारा, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने चाहिए।

नियम 70 राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Medical certificates)—राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश या अवकाश की वृद्धि स्वीकृत करने से पूर्व, उसे निम्नलिखित कामों में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र

..... के मामले का विवरण

नाम

(सिविल सर्जन या सरकारी मेडिकल अटेंडेंट के सामने प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये)

नियुक्ति

उच्च

कुल सेवा

अवकाश का पूर्व समय यदि पहले चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अनुपस्थित रहा हो।

भावेत्त

बीमारी

मैं का सिविल सर्जन या का चिकित्सा अधिकारी मामले की श्रद्धापूर्वक रूप से सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री की हालत खराब दशा में है तथा मैं दृढ़तापूर्वक एवं गम्भीरतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार स्वस्थ होन के लिए सेवा से उसका अनुपस्थित रहना आवश्यक है तथा यह सिफारिश करता हूँ कि उसे माह का अवकाश दिनांक से स्वीकृत किया जावे। मेरी राय में अधिकारी के लिए मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना जरूरी है/जरूरी नहीं है।

दिनांक सिविल सर्जन या सरकारी चिकित्सा अधिकारी

टिप्पणी—यह वाक्य या लो प्रसम्बद्ध शब्दों को काट कर संशोधित किया जाना चाहिये या उसे शिक्कुन काट देना चाहिए, क्योंकि सिफारिश किया गया अवकाश 2 माह का है या उससे अधिक मात्र है।

टिप्पणियाँ—(1) इस प्रमाण पत्र में की गई सिफारिश से किसी ऐसे अवकाश का कलम नहीं किया जा सकेगा जो कि उसे अपनी संधिदा (Contract) के अनुसार या उस पर लागू होने के नियमों के अनुसार नहीं मिल सकता हो।

(2) इस फार्म को यथा सम्भव ज्यों का त्यों काम में लिया जाना चाहिये तथा इसे प्रार्थी के हस्ताक्षर करा लेने के बाद भरा जाना चाहिये। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने की स्वतन्त्रता नहीं होगी कि प्रार्थी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की

जम्बरत है या यह कि वह अनुक स्थान पर जाने के योग्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र केवल उनी समय दिए जाने चाहिये जबकि सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से जाह्रा गया हो। जब प्राचीं प्रशासनिक प्राधिकारी के पास इन आधार पर प्राथना पत्र देने के लिये उनके लिए यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी कि क्या प्राचीं की उसकी शारीरिक योग्यता की जांच के लिए मेडिकल कमेटी के सम्मुख जाना चाहिये या नहीं।

ऐसे मामले जिनमें प्रारम्भ में निवारित की गई अवकाश की अवधि या प्रारम्भ में निवारित किए गए तथा उसके बाद में और निवारित की गई अवधि अवकाश की अवधि, यदि 2 माह से ज्यादा नहीं हो तो चिह्नित अधिकारी को यह आवश्यकता है कि प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या उनकी राय में अधिकारी का मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना जरूरी है या नहीं।

नियम 71. मेडिकल समिति के सामने उपस्थित होना—ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर राज्य कर्मचारी को, केवल नियम 74 के अंतर्गत जाने वाले मामलों को छोड़ कर, मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, अपने कार्यालय के अध्यक्ष से या स्वयं ही कार्यालय के अध्यक्ष होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद उसे अपने मामले की दो प्रतियों के साथ कमेटी के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये। कमेटी का निर्णय शिष्टाचार एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से किया जावेगा। कमेटी या तो जयपुर या ऐसे अन्य स्थान पर बुलाई जावेगी जिसे सरकार तय करे।

नियम 72 मेडिकल कमेटी का प्रमाण पत्र—प्राचिन अवकाश या अवकाश वृद्धि स्वीकृत किए जाने के पहले राज्य कर्मचारी को कमेटी से निम्न प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए—

‘हम ऐतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम व्यवसायात्मक निर्णय के अनुसार मामले की स्थितिगत जांच करने के बाद हम थी ...’ के स्वास्थ्य को ऐसा समझते हैं कि उसकी स्वीकृति होने के लिए ... माह की अवधि तक का अनुसंधान का अवकाश स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

नियम 73. मरिचक मामलों में व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना—प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति करने के निर्णय से पूर्व, समिति, संविध्य मामले में 14 दिवस तक प्राचीं की व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोक सकता है। उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये—

‘...’ ने अवकाश स्वीकृत कराने के लिए बिक्रित प्रमाण-पत्र के लिए हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने या अस्वीकृत करने से पूर्व हम ... दिनों के लिए ... को व्यवसायात्मक परीक्षण के लिए रोकना जरूरी समझते हैं।

नियम 74. मेडिकल कमेटी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना—(1) यदि प्राचीं की हालत की बारे में सरकारी बिक्रित अधिकारी द्वारा या जिस बिक्रित अधिकारी पद से ऊपर के बिक्रित अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि वह कमेटी के सम्मुख किसी भी समय उपस्थित होने में असमर्थ है तो अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी नियम 72 में निर्धारित किए गए प्रमाण पत्र के बदले में निम्न में से किसी भी प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है।

(क) जिला चिकित्सा अधिकारी पद के या उसके ऊपर के दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र, या

(ख) यदि अधिकारी दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो जिला चिकित्सा अधिकारी के पद या उसके ऊपर के पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा जिलाबोध या डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया हुआ प्रमाण पत्र ।

(2) फिर भी उपनियम (1) में कुछ दिये गये अनुसार अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी नियम 71 व नियम 72 में दिये गये तरीके को समाप्त कर सकता है—

(1) जब प्राधिकृत मेडिकल एग्जैमिनेटर द्वारा सिफारिश किया गया अवकाश 2 माह से ज्यादा का न हो, या

(2) जब प्राणी का अस्पताल के भीतर (इनडोर) मरीज के रूप में इलाज चल रहा हो तथा उसके इलाज के समय तक के अवकाश की सिफारिश कम से कम जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के समकक्ष अस्पताल में उस मामले के मेडिकल आफीसर इन्चार्ज द्वारा की गई हो ।

परन्तु शर्त यह है कि, ऐसा चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में प्राणी को मेडिकल कमेटी के समक्ष उपस्थित किया जाना जरूरी नहीं है ।

नियम 75. चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार प्रदान नहीं करता है—नियम 72 या नियम 74 के अन्तर्गत प्रमाण दिये जाने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी किसी अवकाश का अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं करता है । प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकार करने वाले राज्य कर्मचारी को पेश किया जाना चाहिए तथा उन पर उन अधिकारी के आदेशों की इतना ही ध्यान देना चाहिए ।

नियम 76. अराजकचित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पत्र अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध का तरीका—(क) उच्च सेवा में नियुक्त प्रत्येक अराजकचित राज्य कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आवेदन दिये गये प्रत्येक अवकाश आवेदन पत्र के साथ इस नियम के मोक्षे निर्धारित प्रपत्र में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र सज्जन किया जाएगा । यह प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसने बीमारी की रकृति तथा उसकी अवधि को यथा सम्भव स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, या आवेदन पत्र के साथ अपनी किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग को धारणा संलग्न की जाएगी ।

(क) अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, अपनी इच्छा पर जिला चिकित्सा अधिकारी से प्राणी के स्वास्थ्य की जांच कर, दूसरी चिकित्सा सम्बन्धी राय भी प्राप्त कर सकता है । यह निर्णय लेने पर द्वारा जांच का प्रबन्ध प्रथम बार की गई जांच के बाद यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिए ।

(ग) जिला चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य बीमारी के तथ्यों तथा उसके लिए सिफारिश की गई अवकाश की अवधि दोनों के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करना होना तथा इसके लिए या तो वह अवकाश पर से राज्य कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है या उसके द्वारा मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है ।

(प्राणी के हस्ताक्षर)

अराजकपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

अवकाश या अवकाश वृद्धि या दान्तरित अवकाश की सिफारिश हेतु

मैं मामले की सावधानीपूर्वक स्थितिगत जांच करने के बाद ऐतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री..... जिनके हस्ताक्षर ऊपर किए हुए हैं, से पीड़ित हैं तथा मैं सोचता हूँ कि उनके स्वस्थ होने के लिए बिना..... से अवधि तक सेवा से उनका अनुपस्थित होना नितांत आवश्यक है।

दिनांक

सरकारी चिकित्सा अधिकारी या अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सक

टिप्पणी—इस नियम में निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी स्वयं ही अवकाश स्वीकृत कराने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है।

निर्णय—कुछ मन्देश उत्पन्न किए गए हैं कि क्या उच्च सेवा में नियुक्त अराजकपत्रित राज्य कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के आवेदन पत्र के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 76 (क) के प्रयोजन के लिए उनमें प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द में केवल रजिस्टर्ड ऐलोपैथिकल चिकित्सकों की ही माना जावेगा या उनमें आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति पर चिकित्सा करने वाले रजिस्टर्ड चिकित्सकों को भी माना जावेगा। मामले की जांच करती गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 76 (क) में प्रयुक्त 'रजिस्टर्ड चिकित्सक' शब्द का अर्थ इस रूप में लगाया जावे कि उनमें चिकित्सा आपार पर (नियम 76 (क) या नियम 83 के प्रयोजन के लिए) अवकाश के आवेदन पत्र के साथ आयुर्वेदिक या यूनानी रजिस्टर्ड चिकित्सकों के प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जा सकें, या

होमियोपैथिक चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र किन्हीं ऐसे कामों के लिए स्वीकृत नहीं किए जावेंगे जिसके लिए नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र पहिले चाहा गया हो।

नियम 77. अनुपं धेणी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश—एक अराजकपत्रित अनुपं धेणी कर्मचारी से चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के अथवा अवकाश वृद्धि के प्रार्थना के समर्पन में अवकाश स्वीकृत करने वाला तक्षम प्राधिकारी, जैसे उचित समझे, किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकार कर सकता है।

नियम 78. सेवा पर उपस्थित न हो सकने योग्य राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र—किसी एक ऐसे मामले में जिससे यह प्रतीत हो कि राज्य कर्मचारी के सेवा पर पुनः उपस्थित होने के समय का कोई आसार नहीं है, चिकित्सा अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिये। ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र में केवल यही राय लिखी जानी चाहिये कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थाई रूप से अयोग्य है।

नियम 79—मेडिकल कमेटी या चिकित्सा अधिकारी के किसी राज्य कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश के प्रत्येक प्रमाण पत्र में इस बात का एक प्रावधान किया जावेगा कि इस प्रमाण पत्र में की गई सिफारिश किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसे अवकाश प्रदान

कराने की सक्षी उपस्थित नहीं करेगी जो कि राज्य कर्मचारी को अपनी सेवा शर्तों के अधीन या उस पर लागू नियमों के अधीन नहीं मिल सकती हो ।

खण्ड 2

अवकाश की स्वीकृति (Grant of Leave)

नियम 80. अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकता (Priority of claims to leave)—ऐसे मामलों में जहाँ सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश में सभी प्रायना पक्षों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है, एक अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को, यह निर्णय करने में कि कौन से प्रायना पक्ष का अवकाश पहिले स्वीकृत किया जाना चाहिये, निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए—

(क) ये राज्य कर्मचारी जो, हाल किन्हाल, अच्छी तरह अवकाश पर जा सकते हैं ।

(ख) विभिन्न प्रायियों की बकाया अवकाश की अवधि ।

(ग) पिछले अवकाश से वापिस आने के बाद प्रत्येक प्रायों द्वारा की गई सेवा की अवधि व सेवा की किस्म ।

(घ) कोई ऐसा तथ्य जिसमें राज्य कर्मचारी को पहिले अन्तिम अवकाश से वापिस सेवा में आवश्यकीय रूप में बुलाया गया हो ।

(ङ) कोई ऐसा तथ्य जिसके अनुसार पहिले किसी राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक हित की दृष्टि से अवकाश की स्वीकृति नहीं दी हो ।

नियम 81. (1)—राज्य सेवा में वापिस लौटने के अयोग्य राज्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति—जब एक चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी हो कि ऐसा कोई उचित आसार नहीं है कि एक अनुप राज्य कर्मचारी कभी सेवा पर वापिस जा सकेगा तो ऐसे राज्य कर्मचारी का अवकाश आवश्यकीय रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये यदि उसका अवकाश बकाया हो तो उसे ससम प्राधिकारी निम्न शर्तों पर स्वीकृत कर सकता है—

(क) यदि चिकित्सा अधिकारी निश्चय पूर्वक यह कहने में असमर्थ हो कि राज्य कर्मचारी पुनः कभी सेवा में आने के योग्य न हो सकेगा, तो कुछ अवकाश अधिकतम 12 माह तक का स्वीकृत किया जा सकता है । इस प्रकार का अवकाश बिना चिकित्सा अधिकारी की राय के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) यदि एक राज्य कर्मचारी एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से व अस्थायी रूप से अग्रिम सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे अवकाश या अवकाश मुद्धि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्त कि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख के बाद, अवकाश की अवधि, जो उसके अवकाश खाते में जमा हो, व सेवा का समय 6 माह से ज्यादा का न हो ।

उप नियम (2) व (3) विलोपित

नियम 82. बर्खास्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी को अवकाश स्वीकार न करना—एक ऐसे राज्य कर्मचारीको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जो मुख्यवर्तार या सामान्ययोग्यता के आधार पर राजकीय सेवा से शीघ्र बर्खास्त किया जाने वाला हो या हटाया जाने वाला हो ।

+ नियम 82 क) —राजपत्रित अधिकारियों के लिए अवकाश—बैचल अथि प्रावश्यक मामलों को छोड़कर, या उपाजित अवकाश के सम्बन्ध में यह विदेशी सेवा में 120 दिन से अधिक का न हो, को छोड़कर, जिसमें कि अवकाश राज्य कर्मचारी की जिम्मेदारी पर जैसे अस्थायी अवकाश का परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, स्वीकृत किया जाएगा, एक राजपत्रित अधिकारी को अवकाश जब तक महा लेखाकार से उसके बचाया अवकाश की सूचना न आ जाए, तब तक स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार के अवकाश की सूचना अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महालेखाकार से मंगाने की जरूरत नहीं है जब तक कि वह विदेशी सेवा में नियुक्त न हो एवं जब वह उपाजित अवकाश के अलावा जो 120 दिन से अधिक न हो, अन्य प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन करता हो ।

— अवकाश संख्या 1—ऐसे मामले में जहाँ सरकारी कर्मचारी नियमित में यह प्रमाणित करता हो कि सेवा नियुक्ति पूर्व अवकाश, अस्वीकृत अवकाश एवं सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मोनन सीव , के अनिरिक्त अव्य अवकाश जिसके लिए उगने आदेशन किया हो, तथा जो नियमानुगत उसके लेवे में जाया हो, यह अवकाश स्वीकृत करने वाले मसम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार के पास से उसके अज्ञान के हक के बारे में रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत किया जा सकेगा । यदि इन प्रकार से स्वीकृत किया गया अवकाश, महा लेखाकार द्वारा सत्यापित किए जाने पर उसे देय नहीं पाया जाए तो उसे अन्य प्रकार के अज्ञान में जो उसे स्वीकार्य हो, बदला जा सकेगा । यदि अन्य प्रकार का कोई अवकाश बचाया एवं स्वीकार्य नहीं हो तो उन अवधि की अज्ञापायण अवकाश के रूप में समझा जा सकता है ।

× अवकाश संख्या 2—सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश (सीव रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट) के मामले में राज्य कर्मचारी अपना अवकाश का टाइल गीषा महालेखाकार से प्राप्त कर सकता है । अवकाश का टाइल प्राप्त करने पर वह उसे अपने प्राणना-पत्र के साथ स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के अवकाश के टाइल की रिपोर्ट करते समय महालेखाकार अपनी रिपोर्ट की एक प्रति स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पास भी भेजेगा ।

किर भी, जहाँ सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का समय पर महालेखाकार से अवकाश का टाइल प्राप्त न हो वहाँ पर स्वयं अधिकारी अपने आवेदन पर यह अधिलिखित करेगा कि उसके

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (17) एक० बी (व्यय-नियम) दिनांक 6-9-65 द्वारा संशोधित किया गया ।

— वित्त विभाग की अधिमूनना संख्या एक 1 (5) वित्त वि (व्यय-नियम) 16 दिनांक 24-3-66 द्वारा निविष्ट ।

× वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (22) एक० बी० (व्यय-नियम) 66 दिनांक 23 मिनम्बर, 1966 द्वारा नामित किया गया ।

सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर प्राविदन किया गया अवकाश का उसका समय बाकी है। ऐसे मामलों में वह इस सम्बन्ध का एक प्रतिवचन भी देगा कि यदि इस प्रकार स्वीकृत किया गया अवकाश बचाया नहीं पाया गया तो वह ऐसे अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है जो उसे स्वीकार्य हो। अन्य किसी भी मामले में अवकाश स्वीकार्य नहीं है तथा बचाया अवकाश के समय को प्रसाधारण अवकाश में सम्भ्रा आया।

टिप्पणी—एक सरकारी कर्मचारी जो राजपत्रित पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो, उसके अवकाश की प्राप्ति अकेलए अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

नियम 83. अवकाश से सेवा पर उपस्थित होते समय योग्यता का प्रमाण—एक राज्य कर्मचारी जिसने किरिस्ता प्रमाण पत्र पर अवकाश लिया हो, उसे सेवा पर उस समय तक नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि वह निम्न रूप में एक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है—

के सिविल सर्जन
हम मेडिकल कमेटी के सदस्य
के रजिस्टर्ड चिकित्सक
एतद्वारा यह प्रमाणित

करते हैं कि हमने/मैंने विभाग के श्री की सावधानी पूर्वक जांच करती है तथा यह पाया है कि वह अब पूर्ण स्वस्थ हो गया है तथा अब वह राजकीय सेवा में उपस्थित होने के योग्य है। हम/मैं यह निर्णय देने से पहले भी प्रमाणित करते हैं/करता हूँ कि हमने/मैंने मास्टर के उन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्रों व विवरणों की, या उनकी प्रमाणित प्रतियों की जांच की है जिन पर कि उसने अवकाश लिया है या अवकाश में मृद्धि कराई है तथा इस निर्णय को देने से हमने/मैंने इनको ध्यान में रखा है।

मामले के मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र व विवरण, जिस पर कि अवकाश मूल रूप में स्वीकृत किया गया था या अवकाश में मृद्धि की गई थी, उन्हें उक्त प्रमाण पत्र देने वाली अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए मामले के मूल प्रमाण पत्र व विवरण की प्रतियों में संशोधन किए जाने चाहिए तथा एक कापी सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा अपने पास रखनी चाहिए।

नियम 84. राजपत्रित कर्मचारियों की मेडिकल कमेटी से कब स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी है तो केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, उसे मेडिकल कमेटी से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए—

(क) वे मामले जिनमें अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक की न हो।

(ख) ऐसे मामले जिनमें अवकाश तीन माह से अधिक का हो या जिनमें तीन माह के अवकाश के बाद तीन माह या इससे कम का और अवकाश बढ़ाया गया हो तथा मूल प्रमाण पत्र या मृद्धि का प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाली मेडिकल कमेटी का यह कहना हो कि ऐसा प्रमाण पत्र देने के समय राज्य कर्मचारी की स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी अन्य मेडिकल कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

अपवाद स्वरूप मामलों में प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि अवकाश पर रहने वाला राज्य कर्मचारी, राजपत्रित अधिकारी नहीं हो तो सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय पर किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है।

निर्णय — राजस्थान सेवा नियमों के नियम 83 व 84 में दिया हुआ है कि एक अधिकारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश ले रखा है, उसे सेवा पर लौटने के पूर्व स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

महालेखाकार ने सरकार के ध्यान में लाया है कि राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश से सेवा पर पुनः उपस्थित होने के लिए आते हैं, उनके बारे में इन प्रकार की कोई सूचना उसके कार्यालय में इस समय प्राप्त नहीं हुई है कि क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों से उनके सेवा पर उपस्थित होने से पूर्व उचित चिकित्सा अधिकारियों से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं या नहीं एवं इसके फलस्वरूप उसके कार्यालय के लिए यह निगरानी रखना संभव नहीं हो सका है कि राजस्थान सेवा नियमों के सम्बन्धित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

नियमों का उचित पालन किए जाने की दृष्टि से तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश लेने वाले राजपत्रित कर्मचारियों के अवकाश से सेवा पर लौटने पर, उन्हें पे-रिचार्ज जारी करने में विलम्ब का दूर करने के लिए, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों से उनकी पुनः सेवा पर लेने की आज्ञा जारी करने समय, यह मुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया जाता है कि एक सूचना साथ में महालेखाकार को भी भिजवाई जानी चाहिए कि सेवा पर उपस्थित होने की आज्ञा देने से पहले नियमानुसार अधिकारी से उचित चिकित्सा अधिकारी का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। चूंकि इन प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर ही अवकाश पर लौटने पर उनकी पे-रिचार्ज महालेखाकार द्वारा जारी की जावेगी, इसलिए यह आवश्यक है कि उसे यह आवश्यक सूचना तथा सम्भव घोषित भिजवाई जानी चाहिए।

नियम 85 नियम निम्न से पूर्व अवकाश से लौटने — (क) (i) एक राज्य कर्मचारी, उसे स्वीकृति दिए गए अवकाश के समाप्त होने के पूर्व, सेवा पर उक्त समय तक पुनः नहीं लौट सकता है जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसे ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दे देता है।

(ii) फिर भी, उक्त धारा (1) में कुछ दिए गए अनुसार एक निश्चित पूर्व अवकाश पर गया हुआ राज्य कर्मचारी को, उस सेवा से निवृत्त करने की स्वीकृति की तथा, सेवा पर लौटने की प्रार्थना की उसे नियुक्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के अभाव, धारित लेने से रोका जा सकेगा।

(ख) अवकाश से लौटने वाला एक राज्य कर्मचारी, उस सम्बन्ध के आदेश की अनुपस्थिति में, उनी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है, तब पर से कि वह अवकाश पर गया था। उसे सेवा में उपस्थित होने की रिपोर्ट देनी चाहिए तथा नियुक्ति के आदेशों की इन्तजार करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण—नियम 85 के खण्ड(ख)की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें दिया हुआ है कि एक राज्य कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसी पद का कार्यभार सभलाया जावे जिसको कि वह अवकाश पर रवाना होने के पूर्व धारण कर रहा था। इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न किये गये हैं कि क्या अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश से लौटने पर उनका नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है। मामले का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है—

(1) एक अधिकारी जो अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम है, एक राजपत्रित अधिकारी की पुनर्नियुक्ति का आदेश उसी पद पर नियुक्त करने के लिए दे सकता है यदि वह पद उसके अवकाश काल में रिक्त रखा गया हो।

(2) जहाँ अवकाश एक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो तथा अन्य अधिकारी के आदेश से अवकाश काल में वह रिक्त स्थान भर लिया गया हो तो बाद का अधिकारी ही उस अधिकारी के अवकाश से लौटने पर पुनर्नियुक्ति (Reposting) के आदेश निकाल सकता है। चूँकि महालेखाकार, अधिकारी के अवकाश से लौटने पर उसके पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी किये बिना वे अनिरीखी जारी नहीं करेगा, इसलिये ऐसे आदेश अवकाश का समय समाप्त होने से पूर्व ही आवश्यक रूप से जारी कर दिये जाने चाहिये।

निर्णय—सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये गए हैं कि जब एक स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी को नियम 83 के अनुसार अवकाश समाप्त होने के पूर्व ही अवकाश से लौटने की आज्ञा देने में आदेश जारी नहीं करता है तथा महालेखाकार को उसकी प्रतिलिपि नहीं भेजता है जिसके फलस्वरूप जो अवकाश का उपयोग नहीं किया है, उसकी सेवा की तनखाह (Duty Pay) प्राप्त करने में अधिकारी को कठिनाई होती है।

यह आवश्यक है कि अवकाश के रद्द किए जाने के आदेश जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जानी चाहिए। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को अवकाश रद्द करने के सभी मामलों में इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

नियम 86. अवकाश समाप्त होने पर अनुपस्थिति—एक राज्य कर्मचारी जो अपना अवकाश समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहता है वह उस अनुपस्थिति के समय का कोई अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है तथा वह समय अर्द्धवेतन पर अवकाश के रूप में समझा जाएगा जब तक कि उसका अवकाश सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। अवकाश समाप्ति के बाद सेवा से ऐच्छिक रूप से अनुपस्थिति (Wilful absence) इस नियम के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार (Misbehavior) के रूप में समझी जानी चाहिये।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी अवकाश के बिना या अवकाश स्वीकृत किये जाने से पूर्व, सेवा से अनुपस्थित रहने के समय को किस रूप में समझा जाय, इस सम्बन्ध में एक सन्देह उठाया गया है।

स्थिति यह है कि सेवा से इच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना दुर्व्यवहार है तथा उसे इस ही रूप में समझा जाता है। अवकाश के बिना अनुपस्थिति उसकी पुरानी सेवाओं को समाप्त करते हुए उसकी सेवा के रूप में व्यवधान (Interruption) डालती है जब तक कि उनका संतोषजनक

कारण चाखिये न दिया जा सके तथा अनुसूचित का समय स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा धमाधोरण अवकाश में नहीं बढ़ा दिया जाता है ।

अध्याय ११ अवकाश (LEAVE)

खण्ड । —सामान्य

नियम 87. प्रयोग्यता (Applicability) —राज्य कर्मचारियों को प्राप्य अवकाश की प्रकृति व उसकी अवधि के सम्बन्ध में इस अध्याय के नियम (पद्धति सम्बन्धी नियमों को छोड़कर) केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो स्थाई रूप में स्थाई पद पर काम करते हैं, केवल उन्हीं स्थिति में ये नियम अस्थाई राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जहाँ यह स्पष्ट निश्चय हुआ है कि ये नियम उन पर लागू होंगे ।

नियम 87. (क) —अवकाश का लेखा (Leave Account) —प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट 2 (क) में दिए गए कार्य संकाय 1 में तैयार किया जावेगा ।

नियम 87. (ख) (1) राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा —राजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा राजस्थान के महालेखाकार द्वारा या उसके निर्देशन के अन्तर्गत तैयार किया जावेगा ।

(2) अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाशवेतन —अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उन्हीं कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है ।

नियम —एक अराजपत्रित कर्मचारी जो एक राजपत्रित पद पर कार्यरत रूप से काम कर रहा है, यदि वह अवकाश पर जाता है तो उसे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये जैसे प्रविष्टि जारी करने के लिए, अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के लिये, विरामा प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवकाश की वृद्धि की स्वीकृति आदि के लिए, अवकाश काल में उसे राजपत्रित पद को धारण किया हुआ ही समझा जाता चाहे कि तब वह ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए कि वह अवकाश 'वार्षिक वृद्धि' में गिना जाता चाहिए प्रत्यक्ष नहीं, वह उस राजपत्रित पद पर कार्य करता रहता या नहीं, लेकिन वह अवकाश पर चलता गया, एवं चाहे उसके अवकाश की समाप्ति पर वह अपने राजपत्रित पद पर लौटेगा या नहीं ।

(2) यदि ऐसा राज्य कर्मचारी किसी अराजपत्रित केडर पर अपना सीजन रखता है जिसमें अवकाश रिजर्व (Leave reserve) भी शामिल है तो, अवकाश लेने पर वह अवकाश उस केडर में लिया गया अवकाश गिना जाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की पहिले से ही राय ले लेनी चाहिए तथा उसे अवगत कराया जाना चाहिये ।

(3) यह नियम उस राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा जो एक राजस्थान सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार में या इसके विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया हो तथा अपने पैतृक कार्यालय में अपना सीजन (सक्रिय या निवृत्त) रखता हो, यदि वह उधार लेने वाले कार्यालय (Borrowing Office) में राजपत्रित पद पर

कार्यवाहक रूप में काम करते हुए अवकाश पर जाता हो। अवधि में ऐसे अधिकारियों के मामले में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए—

(क) उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा अवकाश एवं उसकी वृद्धि स्वीकृत की जानी चाहिए एवं प्रकाशित की जानी चाहिए; एवं

(ख) अवकाश वेतन प्रारम्भ में उधार लेने वाले कार्यालय द्वारा ही दिया जाना चाहिए, एवं अवकाश वेतन को नियमित करने वाले उचित नियमों के अनुसार अन्तिम रूप में समायोजित (Adjustment) किया जाना चाहिए।

नियम 88. विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय—किसी भी किस्म का अवकाश किसी भी अन्य किस्म के अवकाश के साथ में या कम में स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 89. अधिशासकी आयु की तिथि के बाद का अवकाश (Leave beyond date of Superannuation) उसे तारीख के बाद का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसकी कि एक राज्य कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त होना होगा।

यहाँ कि यदि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से अर्थात् समय पूर्व ही राज्य कर्मचारी को सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं के कारण पूर्ण या आंशिक ऐसे अवकाश के लेने में मना कर दिया गया हो जिसके लिए अपने निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अपने बकाया अवकाश के लिए आवेदन किया हो तो उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद उतने ही समय का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जो कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को उसका बकाया था। नियम 91 में निर्धारित किए गए अनुसार यह अवकाश अधिकतम 120 दिवस का (एवं जो अवकाश पर भारत के बाहर जा रहे हों उन्हें 180 दिन का) स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे स्वीकृत किए गए अवकाश में, वास्तव में प्रस्वीकृत किए गए निवृत्ति पूर्व अवकाश की तारीख के बीच में स्वीकृत किया गया अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश, यदि कोई हो, जिसके लिए कर्मचारी ने निवृत्ति पूर्व आवेदन किया हो, परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो, शामिल है तथा यह अर्द्धवेतन अवकाश उस सीमा तक उपाजित अवकाश में बदला जा सकता है बिना कि अपने निवृत्ति पूर्व अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख व अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बीच कमाया है।

यहाँ यह और भी है कि एक अधिकारी जिसकी सेवा अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से आगे सार्वजनिक सेवा में हित के कारण से बढ़ा दी गई है, उसे उपाजित अवकाश निम्न रूप में स्वीकृत किया जा सकता है—

(i) सेवा वृद्धि की अवधि में उस काल में कमाया गया उपाजित अवकाश तथा इसके बराबर उतना आवश्यक उपाजित अवकाश जो कि उसे पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार अनिवार्य निवृत्ति की तारीख को सेवा से निवृत्त होने पर स्वीकृत किया जा सकता था।

(ii) सेवा वृद्धि के समय के समाप्त होने के बाद—

(क) उपाजित अवकाश, जो कि उसे पूर्वोक्त प्रावधान के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को सेवा से निवृत्त करने पर स्वीकृत किया जा सकता था। परन्तु इसमें से जो उपाजित अवकाश सेवा वृद्धि में लिया जावेगा, उसे घटा दिया जावेगा।

(घ) सेवा वृद्धि की अवधि में कमाया गया अवकाश जिनके लिए उसने अपनी सेवा अवधि समाप्त होने के पर्याप्त समय पहिले आवेदन किया हो परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण मना कर दिया गया हो ।

(ii) नियम 91 के अन्तर्ग में सेवा वृद्धि के समय में कमाए गए उपाजित अवकाश की मात्रा निश्चित करने के लिए उसमें वह अवकाश भी गिना जावेगा जो कि उसे, यदि कोई हो, पूर्वोक्त प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है ।

+ टिप्पणी—(चित्तेपित की गई)

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत संपादकगुणों एक राज्य कर्मचारी को उससे अधिकारिकी धातु की तारीख के बाद, कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा । फिर भी, यदि उसने पर्याप्त समय पहिले उपाजित अवकाश के लिए निवेदन किया हो, परन्तु सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में वह स्वीकृत कर दिया गया हो, तो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को, उसकी अधिकारिकी धातु प्राप्ति की तारीख के बाद इस प्रकार का स्वीकृत किया गया अवकाश 120 दिवस तक की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

राजस्थान सेवा नियम 1-4-51 से प्रभावशील हुए हैं । वे राज्य कर्मचारी जिनकी 1-4-51 के बाद शीघ्र ही सेवा में नियुक्त होना है, वे इस धर्त के बारे में जान न सके थे इसलिए वे समय पर उपाजित अवकाश के लिए निवेदन करने का अवसर प्राप्त न कर सके । यदि नियम 89 की कठोरता से पालन किया जावे तो उनके साथ कठोरता का व्यवहार होगा । इसलिए सरकार उन राज्य कर्मचारियों के लिए, जो 31 दिसम्बर 1951 से पूर्व सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, निम्नलिखित रियायतें प्रदान करती है—

श्रेणी	अवकाश जो स्वीकृत किया जाना है चाहे नियम 89 की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं की गई हों, बशर्ते कि राज्य कर्मचारी का अवकाश बढ़ाया हो ।
30 दिसम्बर 1951 को या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिकारिकी धातु प्राप्ति की तारीख के बाद 120 दिन का उपाजित अवकाश ।
30 दिसम्बर 1951 के बाद परन्तु 31-10-51 को या उससे पूर्व तक सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिकारिकी धातु की तारीख के बाद 90 दिन का उपाजित अवकाश ।
31 दिसम्बर 1951 के बाद परन्तु 30 नवम्बर 51 को या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिकारिकी धातु की तारीख के बाद 60 दिन का उपाजित अवकाश ।
30 नवम्बर 51 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर 51 तक या उससे पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारी	अधिकारिकी धातु की तारीख के बाद 30 दिन का उपाजित अवकाश ।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एच 1 (48) वित्त विभाग (अध्य-नियम) 67 दिनांक 1-4-69 द्वारा विनियमित ।

31 दिसम्बर 1951 के बाद सेवा से निवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को उपाजित अवकाश उन्नीस महीने स्वीकृत किया जा सकता है जबकि नियम 89 की आवश्यकताओं को पहले पूर्ण कर दिया गया हो।

विभागाध्यक्षों से निवेदन किया जाता है कि वे इस आदेश को अपने विभाग के सभी राज्य कर्मचारियों के ध्यान में ला दें।

निर्णय संख्या 2—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के सही रूप में लागू होने के सम्बन्ध में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए हैं। स्थिति की जांच की गई तथा यह पाया गया कि नियम 89 के द्वितीय प्रावधान के अन्तर्गत अवकाश, सेवा की वृद्धि की अवधि की समाप्ति के बाद, केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि नियम के प्रथम प्रावधान की शर्तों का पालन किया जा चुका हो उदाहरणार्थ जैसे मानों अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो। यह शर्त दोनों पर लागू होती है (क) उपाजित अवकाश जो कि प्रथम प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता था, एवं (ख) उपाजित अवकाश जो सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में बताया हो। सेवा वृद्धि के समय में कमाया गया अवकाश इस तरह सेवा वृद्धि की अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही प्राप्त नहीं होता एवं केवल उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जब पहले उसे मना कर दिया गया हो। दोनों मामलों में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद अवकाश के मामले में या सेवा वृद्धि की अवधि समाप्त होने के बाद अवकाश के मामले में अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है, यदि राज्य कर्मचारी ने अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व या सेवा वृद्धि का समय समाप्त होने के पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो तथा वह अस्वीकृत कर दिया गया हो या स्वीकृति प्रदान करने वाले मध्यम अधिकारी ने लिखित में यह निश्चय करा दिया हो कि यदि अवकाश के लिए प्रार्थना की गई तो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में अस्वीकृत करने का आधार सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता होनी चाहिए।

+ निर्णय संख्या 3—सरकार को यह बतनाया गया है कि दिनांक 1 जुलाई 1967 से अनिवार्य सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष कर दिए जाने के फलस्वरूप बहुत से सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त की थी, इस तारीख के बाद शीघ्र ही पूर्ण या प्राप्ति रूप में सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करने से राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के प्रावधानों द्वारा रोक दिए गए थे।

मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर लिया गया है तथा यह आदेश दिया जाता है कि सभी मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी जो 2 जुलाई, 1967 एवं 31 दिसम्बर 1967 के बीच सेवा निवृत्त होते हैं/हो चुके हैं, उन्हें निम्न लिखित सीमा तक अस्वीकृत अवकाश (रिपयूज लीव) स्वीकार किया जाए— :

(1) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 2 जुलाई 1967 एवं 31 अगस्त 1967 के बीच सेवा निवृत्त हो गए हैं उन्हें सम्पूर्ण उपाजित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक न हो) जिसे वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख तक सामान्य रूप में उपाजित करता,

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम-) 67 दिनांक 5-10-67 द्वारा निविष्ट।

उसमें से उनके द्वारा वास्तव में उपभोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि को घाट कर शेष बचे अवकाश को अस्वीकृत अवकाश (रिप्यूज लीव) के रूप में सम्मत्ता जाना चाहिए।

(2) 1 सितम्बर 1967 एवं 31 दिसम्बर 1967 के बीच सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) के रूप में बकाया अवकाश जो (I) दिनांक 1-9-67 से सेवा निवृत्ति की तारीख से ठीक पूर्व की नागेल के बीच की अवधि (II) दिनांक 31-8-67 तक उपभोग की गई सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को निकाल कर बचे, उसे अस्वीकृत अवकाश के रूप में माना जाएगा।

उदाहरण

प्रकरण—क

जहाँ सरकारी कर्मचारी ने दिनांक 1-9-67 से पूर्व किसी प्रकार के सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश का उपभोग न किया हो—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख	1-10-67
सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया उपाजित अवकाश की संख्या (120 दिन से अधिक नहीं)	120 दिन
घटाइए—दिनांक 1-9-67 से 30-5-67 तक की अवधि	30 दिन
अस्वीकृत अवकाश के दिन	90 दिन

प्रकरण—ख

जहाँ सरकारी कर्मचारी ने दिनांक 1-9-67 से पूर्व उपाजित अवकाश का उपभोग किया हो—

अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख	15-11-67
सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में बकाया या उपाजित अवकाश की संख्या (120 दिन से अधिक नहीं)	120 दिन
घटाइए—दिनांक 1-9-67 से पूर्व/बाद के उपभोग किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि अर्थात् (18-8-67 से 14-11-67)	89 दिन
अस्वीकृत अवकाश के दिन	31 दिन

उपसुक्त पैरा 1 के पलस्वरूप द्वातानं योग्य क्षेत्र वित्त विभाग के ज्ञान संस्था एच 1 (48) दिनांक 15-7-67 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

÷ निर्णय संख्या 4—दिनांक 1-7-65 से सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष से 55 वर्ष करने के हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (42) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 I दिनांक 13-6-67 के जारी करने के फलस्वरूप कुछ सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1-7-67 से सेवा में वृद्धि स्वीकृत की गई थी। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे दिनांक 1-7-67 से सेवा में वृद्धि स्वीकार की गई है, उपाजित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) जो उसके सेले में जमा था, उसे वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13-6-67 (जो नियम 56 (क) (1) के नीचे राजस्थान सरकार के आदेश के रूप में समय समय पर यथा संशोधित कर रखा गया है) के पैरा 3 के उप पैरा 8 व 9 के अनुसार स्वतः ही अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि उपर्युक्त आदेश के प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू नहीं होते। फिर भी, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उनका उपाजित अवकाश (जो 120 दिन से अधिक का न हो) जो दिनांक 1-7-67 से पूर्व उनके सेले में जमा था, उसे अग्रणीत किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रकार से अग्रणीत उपाजित अवकाश सेवा में वृद्धि दिए गए समय में अजित उपाजित अवकाश के साथ मिलकर सेवा के अवधि समय में ही उपभोग किया जाएगा या यदि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अधीन अवकाश अस्वीकृत हो जाता है तो वह नियमानुसार सेवा में वृद्धि की गई अवधि के बाद भी उपभोग किया जा सकता है।

+ निर्णय संख्या 5—राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 के अधीन यह धारित किया गया था कि अवकाश, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के परन्तुक 2 के अधीन, उसके बढ़ाए जाने की अवधि के बाद केवल तब ही स्वीकृत किया जा सकता है जब कि अवकाश सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं की वजह से दोनों मामलों में अर्थात् (i) उपाजित अवकाश के मामले में जिसे प्रथम परन्तुक के अधीन स्वीकार किया जा सकता था (ii) तथा बढ़ाई गई अवधि के सम्बन्ध में बनाया उपाजित अवकाश के मामलों में अस्वीकृत कर दिया गया हो। उपर्युक्त संदर्भित दोनों प्रकार के मामलों में अर्थात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद अवकाश के मामलों में या बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के बाद अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जा सकता है जबकि सरकारी कर्मचारी ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या बढ़ाई गई अवधि के पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, औपचारिक रूप से अवकाश के लिए आवेदन किया हो तथा उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो या स्वीकृति अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि यदि अवकाश अस्वीकृत करने का आधार सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकता होगी।

उन सरकारी कर्मचारियों को जिनकी राजस्थान सेवा नियम भाग (II) के परिशिष्ट 9 के क्रम संख्या 19 (क) (i) पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिवापिकी आयु प्राप्त करने

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एफ 1 (31) वित्त वि (नियम) 68 दिनांक 3-8-68 द्वारा निविष्ट।

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० एफ 1 (12) वित्त वि (नियम) 70 दिनांक 7-3-70 द्वारा निविष्ट।

के बाद दि० 28-2-71 तक या उस तारीख तक, जिसको वे 58 वर्ष के होते हैं, इनमें से जो भी पहिले हो, सेवा वृद्धि की गई थी, उन्हें अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व प्रोत्साहक आवेदन करना था। मामले की जांच कर ली गई है तथा यह तय किया गया है कि चूंकि उनके मामले में सेवा की वृद्धि स्वतः ही 28-2-71 या वह तारीख जिसको कि वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, इनमें से जो भी पूर्व में हो, तक की हो, अतः अनिवार्यकी आयु की तारीख के पूर्व जितना भी उपाजित अवकाश वकाया हो, वह अधिनायिकी आयु की तारीख के बाद बढ़ाया जा सकता है तथा उसकी सेवा वृद्धि की अवधि कि सम्बन्ध में देय उपाजित अवकाश के साथ, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 के अन्वये निर्धारित की गई सीमा तक उन्नत किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार आगे ले जाया गया उपाजित अवकाश व सेवा वृद्धि की अवधि में अजित उपाजित अवकाश स्वतः ही सेवा वृद्धि की अवधि के समाप्त होने पर स्वीकार्य नहीं होगा लेकिन यह तभी दिया जाएगा जबकि इसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से मना किया गया हो।

अनुदेश—(क) राजपत्रित अधिकारियों की, जिनके कि अवकाश का स्थापन महालेखा-कार द्वारा कराता होता है, ऐसे अवकाश के प्रार्थना पत्र उस तारीख से कम से कम दो माह पूर्व देने चाहिए जिसको कि वे अवकाश पर प्रस्थान करना चाहते हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र महालेखाकार को उनके अवकाश की रिपोर्ट सौंप करने हेतु तथा उसे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पास अधिकतम 15 दिन की अवधि में लौटाने के लिए प्रार्थना करते हुए भेजे जाने चाहिए। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी लिखित में आदेश देगा कि उनका अवकाश स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं। ये आदेश महालेखाकार एवं सम्बन्धित अधिकारी के पास भेजे जाएंगे।

(ख) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में, चूंकि मृत्युवेवाहार से रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, इसलिए निवृत्ति पूर्व अवकाश का प्रार्थना पत्र कम से कम उस तारीख से एक माह पहिले भिजनाया जाना चाहिए जिसमें कि अवकाश के लिए प्रार्थना की गई है। उक्त तारीख से पूर्व अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लिखित में अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय देगा।

गत मामलों में जिनमें कि राज्य कर्मचारियों ने वर्षांत समर पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन किया था परन्तु उन्हें अवकाश अधिधिकी आयु प्राप्त करने की तारीख से पहिले या पुनर्नियुक्त होने से पूर्व या समय पर एक या अन्य कारणों से स्वीकृत नहीं किया गया था, कि राज्य कर्मचारियों द्वारा मन्ती करने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था। उनके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि उनके मामलों में प्रत्येक की योग्यता के अनुसार निर्णय किया जावेगा।

+ स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के नीचे दी गई शिष्टांगी संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें यह दिशा दिया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी, जिसको अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख के बाद या सेवा में की गई वृद्धि की संपादित के बाद, नियम 89 के अन्तर्गत अस्वीकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, उसे पेंशन सम्बन्धी मामलों के

+ वित्त विभाग की याज्ञा सं. एक 1 (48) एक डी (व्यय-नियम) 67 दिनांक 15-7-67 द्वारा शामिल किया गया।

प्रयोजनायं अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख को या सेवा में की गयी वृद्धि की समाप्ति की तारीख को, जैसी भी स्थिति हो, सेवा से निवृत्त किया हुआ समझा जाता है तथा वह उक्त तारीख से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। पूर्वोक्त प्रावधानों के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे तैयार गये हैं जिनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

उठाए गए मुद्दे

(1) क्या एक राज्य कर्मचारी जो अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गयी वृद्धि की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के ठीक बाद प्रस्थित अवकाश का उपयोग करता है, प्रस्थित अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से सेवा से निवृत्त होगा एवं क्या वह उक्त तिथि से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा।

स्पष्टीकरण

राज्य कर्मचारी जो अपनी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गई वृद्धि की समाप्ति के ठीक बाद पूर्ण वा / आंशिक रूप में उपाजित अवकाश का उपयोग करता है, उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से सेवा-निवृत्त हुआ समझा जायेगा या जहाँ सेवा में वृद्धि स्वीकृत की गई हो वहाँ उक्त वृद्धि की गयी अवधि की समाप्ति की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा वह उस तारीख से समस्त पेंशन सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने के योग्य होगा।

(2) प्रस्थित अवकाश की अवधि के अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) का भुगतान किस प्रकार विनियमित किया जाएगा—

(क) जब वह अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा में की गई वृद्धि की समाप्ति के, जैसी भी स्थिति हो, ठीक बाद लिया गया हो।

ऐसे मामले में स्वीकार्य अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) वही होगा जो उन्हें सामान्य रूप से स्वीकार्य है, लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को काट लिया जाएगा।

(ख) जब वह उस पद के कर्तव्यों को पूर्ण करने के साथ उपाजित की गई हो जिसमें कि व्यक्ति पुनर्नियुक्त किया गया हो।

अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) उस राशि तक सीमित होगी जो अवकाश, प्रदत्त वेतन अवकाश में उसे स्वीकार्य है, लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं या उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभ की राशि काटली जाएगी।

(ग) जब व्यक्ति ऐसे पद से, जिसमें वह पुनर्नियुक्त हुआ है, अवकाश पर रवाना हो जाता है तथा जो पुनर्नियुक्ति के दौरान या बाद में प्रस्थित अवकाश का उपयोग करता है।

अवकाश वेतन (लीव सेलेरी) वही होगा जो उसे पुनर्नियुक्ति को छोड़कर, सामान्य रूप से स्वीकार्य होता लेकिन उसमें से पेंशन की राशि एवं/या उपदान के बराबर की पेंशन या अन्य सेवा निवृत्ति लाभों को काट लिया जाएगा।

अन्तर्गत एक राज्य कर्मचारी को रूपान्तरित भवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा वह बाद में सेवा से निवृत्त होना चाहता है तो उसका रूपान्तरित भवकाश भर्द्ध-वेतन भवकाश में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए तथा रूपान्तरित भवकाश एवं भर्द्ध वेतन भवकाश के वेतन के अन्तर को अपने समूह करना चाहिए। इसलिए जो भी राज्य कर्मचारी इस प्रकार का रूपान्तरित भवकाश प्राप्त करता है उससे इस सम्बन्ध की प्रतिज्ञा करा लेनी चाहिए। लेकिन अन्य प्रश्न जैसे कि भवकाश वेतन के रूप में अधिक प्राप्त की गई राशि को लौटाना आदि प्रत्येक मामले के स्वभाव को देखकर तय किया जावेगा।

दूसरे शर्तों में यदि सेवा निवृत्ति कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से चाही गई हो तो उसे राशि लौटाने के लिए कहा जाएगा परन्तु यदि बीमारी आदि से सेवा करने में असमर्थ होने के कारण उसे आवश्यकतापूर्ण रूप से सेवा निवृत्त करने के लिए कहा जाए तो उससे कोई राशि लौटाने की नहीं कहा जावेगा।

(घ) बिना बकाया भवकाश कब स्वीकार किया जाता है (Leave not due when admissible):—निवृत्ति पूर्व भवकाश (Leave preparatory to retirement) के मामले के अतिरिक्त, स्थाई सेवा में नियुक्त एक अधिकारी को उसके पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन का बिना बकाया भवकाश स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन उसमें से एक साथ 90 दिन से अधिक का तथा कुल मिलाकर 180 दिन तक का बिना बकाया भवकाश चिरस्थायी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसा भवकाश उस अधिकारी के उसके द्वारा बाद में कमाए गए भर्द्ध वेतन भवकाश में से काटा जावेगा।

निर्णय—राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि क्या 'बिना बकाया भवकाश' (लीव नॉट ड्यू) उस राज्य कर्मचारी को भी स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि तैरिफ का इलाज करा रहा हो। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि 'बिना बकाया भवकाश' तैरिफ से पीड़ित स्थाई व भर्द्ध-स्थायी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि जब भवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी इसके पूर्णतया समुचित हो जाए कि (1) राज्य कर्मचारी के भवकाश की समाप्ति पर सेवा में लौटने के पर्याप्त उचित आधार हैं तथा (2) उसके बाद उसके द्वारा कमाया जाने वाला भवकाश उसके द्वारा उपभोग किए गए 'बिना बकाया भवकाश' की मात्रा से कम नहीं होगा। भवकाश की समाप्ति के बाद सेवा में लौटने के आधार को उचित चिकित्सा प्राधिकारी (Medical Authority) द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर माना जावेगा। 'बिना बकाया भवकाश' की मात्रा के बराबर, बाद में भवकाश कमाने के आधार हैं। इस बात को ध्यान में रखा जावेगा कि क्या साधारण रूप में राज्य कर्मचारी के सेवा से लौटने पर उसका सेवा काल इतना पर्याप्त होगा कि उसमें वह 'बिना बकाया भवकाश' की मात्रा के बराबर भवकाश उपार्जित कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि एक राज्य अधिकारी सेवा पर लौटकर आता है, एवं साधारण रूप में वह बाद में भवकाशिकी धातु (Superannuation) प्राप्त करने से पहिले केवल तीन साल तक सेवा करता है, तो 'बिना बकाया भवकाश', उतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि वह इस तीन साल की अवधि में भर्द्ध वेतन भवकाश कमा सकता है।

(2) उचित चिकित्सा प्राधिकारी निम्न को माना जावेगा:—

- (1) एक राज्य कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सक
- (2) यदि राज्य कर्मचारी किसी एक मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम में इलाज करा रहा हो तो उस मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम का इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी ।
- (3) यदि राज्य कर्मचारी अपने निवास स्थान पर इलाज करा रहा है तो सम्बन्धित राजकीय प्रशासनिक चिकित्सा प्राधिकारी (State Administrative Medical officer) द्वारा मान्यता दिया हुआ एक सपैदिक विशेषज्ञ (Tuberculosis Specialist); एवं
- (4) यदि राज्य कर्मचारी पल्मोनरी सपैदिक के अतिरिक्त अन्य तैदिक से पीड़ित हो रहा हो तो एक योग्य सपैदिक विशेषज्ञ या सिविल सर्जन ।

टिप्पणी—(1) 'बिना बकाया अवकाश' उसी समय स्वीकृत करना चाहिये यदि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि अवकाश की समाप्ति पर राज्य कर्मचारी के सेवा में वापिस आने के पर्याप्त उचित आसार हैं, यह 'बिना बकाया अवकाश' उसके द्वारा परवर्ती सेवा काल में कमाए गए 'अर्द्धवैतन अवकाश' की मात्रा के बराबर तक ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(2) यदि सेवा किसी एक साल में कुछ समय तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर तथा कुछ चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई हो तो उस पूर्ण वर्ष का 'अर्द्धवैतन अवकाश' निम्न प्रकार से लागू होगा—

'अर्द्धवैतन अवकाश' अनुपात की दर पर चतुर्थ श्रेणी के पद के समय का व चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य पद के समय का अलग अलग निकाला जावेगा तथा बाद में दोनों को जोड़ा जावेगा । यदि किसी विविष्ट साल के अर्द्धवैतन अवकाश का कोई भाग बचता है तथा यदि वह भाग से कम हो तो उसे छोड़ दिया जावेगा तथा यदि भाग या इससे ज्यादा है तो उसे पूरा एक अर्द्धवैतन अवकाश मान लिया जावेगा ।

नियम संख्या 1—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93 की धोर ध्यान आकषित किया जाता है । चूंकि इस नियम के शामिल करने से अर्द्धवैतन अवकाश के आधार में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यह माना जाता है कि राज्य कर्मचारियों के पूर्ण सेवा काल के सम्बन्ध में, पूर्ण प्रभाव से गणना की जावेगी । इसलिए राजस्थान सेवा नियमों के लागू होने की तिथि को जो 'अर्द्धवैतन अवकाश' बकाया निकलेगा वह सन् 1951 तक की गई सेवा अवधि के पूर्ण वर्षों के सम्बन्ध में निकाला जाकर तथा उस तिथि से पूर्व लिया गया 'निजी कार्यों के लिए अवकाश', एवं 'चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश' या किसी भी किस्म का अर्द्धवैतन अवकाश या अर्द्ध अर्द्धवैतन अवकाश आदि को उसमें से घटा कर, जो भेष रहेगा, वह माना जावेगा ।

(2) यदि इस प्रकार की गणना से उसका उपभोग किया गया 'अर्द्धवैतन अवकाश' उसके बकाया अर्द्धवैतन अवकाश से ज्यादा हो तो उसका शेष उपभोग किया गया अर्द्धवैतन अवकाश बाद में (1 अप्रैल 1951 से) कमाए गए अर्द्धवैतन अवकाश में से काट लिया जावेगा । इस अधिक

समय का 1/12 भाग माना जाना चाहिए। तथा इस प्रकार से निकाले गये अवकाश में से भाषा अवकाश उसके द्वारा लिया हुआ माना जाना चाहिए। तथा जो अवकाश क्षेप वने वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 91 (3) के प्रथम प्रावधान में वर्णित सीमा तक अधिकतम रूप में हो सकता है।

(ii) 1-4-51 को अर्द्धवेतन अवकाश निकालने में उक्त निर्णय संख्या 1 में दिए गए शरीके को काम में लिया जावेगा। जिन मामलों में अवकाश का अभिलेख (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं हो या अवकाश लेखा ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया हो, उसके सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि राज्य कर्मचारी ने कोई अर्द्धवेतन अवकाश नहीं लिया है।

(iii) जो राज्य कर्मचारी विधामकालीन विभागों (Vacation Departments) में हैं, जब तक विपरीत रूप का कोई प्रमाण उपलब्ध न हो, यह माना जाना चाहिए कि उनमें विधामकाल का पूर्ण उपयोग किया है।

+ 94 (क)—अस्थाई कर्मचारियों के लिए अवकाश—नियम 91, 92 व 93 के प्रावधान उस अधिकारी पर भी लागू होते हैं जो स्थाई सेवा में नहीं है। सिवाय इसके कि सेवा के प्रथम वर्ष में स्वीकार्य उपार्जित अवकाश।

(i) राजस्थान सहाय्य पुलिस में नियोजित तथा सीमा क्षेत्र पर परव्याप्त अधिकारी को राजकीय आदेश सं. एक 1 (21) जोए/ए/प्रुप 11/64 दिनांक 8-5-64 में परिभाषित किए गए अनुसार बिताई गई अवधि का 1/16 भाग होगा।

(ii) उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में बिताई गई अवधि का 1/22 भाग होगा।

[परन्तु—विलोपित किया गया]

परन्तु यह और भी है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में—

(क) कोई भी अर्द्ध वेतन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी सिवाय ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें कि एक राज्य कर्मचारी को किसी विनियमित अधिकारी ने पूर्ण व स्थाई रूप से सेवा करने में असमर्थ घोषित कर दिया हो, यह विश्वास न करे कि अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर सेवा में पुनः उपस्थित हो जावेगा।

(ख) कोई भी बिना बकाया अवकाश (Leave not due) स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

टिप्पणी—[देखिए नियम 94 क परिशिष्ट 2 (1) व (3)]

निर्णय—निम्नलिखित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त (Terminate) करने पर अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय पर, उनके बकाया तथा प्राप्य उपार्जित अवकाश की सीमा तक अन्तिम अवकाश (Terminal leave) स्वीकृत किया जा

+ वित्त विभाग की आज्ञा सं. एक 1 (32) वित्त विभाग (नियम) 65 दिनांक 17-7-68 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार तथा परन्तु आदेश सम संख्यक दिनांक 10-2-66 द्वारा विलोपित किया गया।

सकता है, चाहे उसके लिए प्रार्थना न की गई हो तथा चाहे वह सार्वजनिक दिन में स्वीकृत कर दिया गया हो—

(क) एक अस्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी जिनको कि सेवाएं सरकार द्वारा प्राधिकारों प्राप्ति करने के पूर्व ही पदों की कटौती करने के फलस्वरूप या पद की समाप्ति के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई है।

(ख) पुनर्नियुक्त किए गए पेंशनर (Pensioners) जो अवकाश के सम्बन्ध में नए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के समान इन शर्तों के साथ माने जाने हैं कि ऐसे पेंशनर बाने वाले व्यक्तियों को उनके अन्तिम अवकाश की अवधि में कोई पेंशन न हों मिलेगी यदि पुनर्नियुक्ति काल में उनकी पेंशन रोक ली गई हो।

(ग) वे व्यक्ति जो राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट (2) में दी गई शर्तों के आधार पर एक साल से अधिक के लिए किसी शर्त पर नियुक्त किये गए हों।

(घ) अयोग्य व्यक्ति जिनको कि करना अस्थाई पद योग्य उम्मीदवारों के लिए रिक्त करना है; एवं

(ङ) वे व्यक्ति जिनको सेवाएं, उनके विरुद्ध अनुशासनानुसार कार्यवाही करने के अन्तर्गत प्रशासनानुसार गुविना को ध्यान में रखते हुए समाप्त को जानी हों।

उक्त निर्णय निम्न पर लागू नहीं होगा—

(1) नव सिधुप्रा (Apprentices) एवं वे व्यक्ति जो सरकार की निरन्तर सेवा में नहीं है तथा जो उन पर लागू नियमों के अनुसार शासित होंगे, या

(2) जहां सम्बन्धित राज्य कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो अथवा हटाया गया हो, या

(3) जहां राज्य कर्मचारी की सेवाएं राष्ट्र विरोधी आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप समाप्त कर दी गई हों।

यदि एक अस्थाई राज्य कर्मचारी स्वयं की इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देना है, तो स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अपने नियम पर, उसके बचाया अवकाश से चाहे समय का सहायित अवकाश उसे स्वीकृत कर सकता है जिसको कि वह एक समय में उपयोग कर सकता है। जो मामले पहिले तय किए जा चुके हैं उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं होगी।

किसी अस्थाई पद या पुनर्नियुक्ति की अवधि को, राज्य कर्मचारी को उसकी स्थाई नियुक्ति के अन्त में या उसकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के अन्त में स्वीकृत किए गए अवकाश की अवधि तक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभी मामलों में जहां सम्बन्धित अस्थाई राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा समाप्त करने का नोटिस उसे दिया जाना हो तथा वह राज्य कर्मचारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सेवा से हटा दिया गया हो तो उस नोटिस के समय को या उसके बचे हुए समय को स्वीकृत किए गए समय के साथ साथ विताया हुआ समझना चाहिये।

× स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि प्राया सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनकी कि सेवाएँ राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 क के अधीन नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने पर समाप्त कर दी जाती हैं, उसके लेखे में जमा उपाजित भवकाश को सेवा समाप्ति भवकाश (टर्मोनल लीव) के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। तथा उसके भवकाश वेतन को किस प्रकार विनियमित किया जा सकता है। नियम के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएँ समाप्त की गई हैं, उनके लेखे में जमा उपाजित भवकाश की सीमा तक सेवा समाप्ति भवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, नोटिस की अवधि के लिए, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी द्वारा साथ साथ सेवा समाप्ति भवकाश भी लिया जाता है, केवल भवकाश वेतन ही दिया जाएगा। ऐतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जिनमें नोटिस के बदले वेतन दिया जाता है, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति भवकाश, उसके बकाया होने एवं स्वी-कार्य होने की सीमा तक, स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन उक्त भवकाश काल का भवकाश वेतन केवल भवकाश की अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिये इसमें वह अवधि शामिल नहीं की जानी चाहिये जिसके लिए कि नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं।

94. (ख) एक अधिकारी जो स्थायी नियुक्ति में नहीं है तथा जो किसी बेकेशन डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है, तो उसे उपाजित भवकाश उसके प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें कि उसे पूर्ण भवकाश (बेकेशन) की प्राप्त करने से रोका गया है, 17 दिनों के अनुपात से उतने दिनों के लिए प्राप्ति होगी जितने दिन का कि उसने भवकाश का उपयोग नहीं किया है।

+ निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 (ख) के नीचे दिया गया राजस्थान सरकार का निर्णय संख्या 2 बेकेशन डिपार्टमेंट के एक भ्रष्टाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा।

विधाम काल (Vacation)

नियम 94. क—जब तक विषय से अन्यथा प्रकार से मालूम न हो, विधाम काल सेवा के रूप में गिना जाता है न कि भवकाश के रूप में।

एक सक्षम प्राधिकारी विविध रूप से उन विभागों का या विभागों के कुछ भागों को निर्देशन दे सकता है जिनकी कि विधाम कालीन (Vacation) विभाग के रूप में माना जाना चाहिये तथा उन शर्तों का उल्लेख कर सकता है जिनमें कि एक राज्य कर्मचारी को विधाम काल का उपयोग किया हुआ समझा जावेगा।

निर्णय—राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन संस्थाओं को 'विधाम कालीन संस्थाओं' (Vacational Institution) के रूप में माना जावेगा।

× वित्त विभाग की आज्ञा सं. एक 1 (38) वित्त वि. (नियम) 69 दिनांक 26-9-69 द्वारा निविष्ट।

× (वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एक 1 (32) एक.डी. (व्यय-नियम) दिनांक 19-6-65 द्वारा शामिल किया गया)

परिशिष्ट (Annexure)

1- एक विधाम कालीन विभाग वह विभाग या विभाग का भाग होता है जिनमें नियमित रूप से विधाम स्वीकार किया जाता है तथा जिसमें उनमें सेवा करने वाले राज्य कर्मचारियों को सेवा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जाती है ।

2- (i) जब उक्त अवतरण (1) की घर्नों का पूर्णतया पालन हो जाए तो निम्नलिखित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को विधाम कालीन विभागों में कार्य करते हुए समझा जाना चाहिए-

(क) शिक्षा विभाग के संचालक, उप संचालकों एवं सहायक संचालकों तथा निरीक्षण अधिकारियों एवं उनके कर्मचारी वर्ग को छोड़कर शिक्षा अधिकारीगण ।

(ग) अन्य श्रेणी के राज्य कर्मचारी जिसे कि एक सक्षम प्राधिकारी विधाम कालीन विभाग के अन्तर्गत सेवा करता हुआ घोषित करे ।

(ii) सन्देह की स्थिति में एक सक्षम प्राधिकारी निर्णय कर सकता है कि प्रत्येक विधिष्ठ राज्य कर्मचारी एक विधाम कालीन विभाग में सेवा करता है या नहीं ।

3. जब तक किसी उच्च सत्ता द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा किसी राज्य कर्मचारी को पूर्ण विधाम काल या आंशिक विधाम काल का उपभोग करने से मना नहीं किया जाता है, वह अपने पूर्ण विधाम काल का उपभोग किया हुआ माना जावेगा । परन्तु तब यह है कि यदि वह आदेश द्वारा इस प्रकार के 15 दिन या उससे अधिक के विधाम काल का उपभोग करने में रोक दिया जाता है तो उसे विधाम काल के किसी भी भाग का उपभोग किया हुआ नहीं समझा जावेगा ।

+ अपवाद—आधुनिक कालेजों की निम्नलिखित विशेष शाखाओं (स्पेशिअलीटीज) को विधाम कालीन विभाग (डिपार्टमेन्ट) के रूप में नहीं समझा जाएगा—

- (1) काय चिकित्सा (2) शाल्य चिकित्सा (3) प्रसूती (4) स्त्री रोग (5) कोमार महम (6) अगततन्त्र (7) दृष्टिवृत्ति विज्ञान (8) शरीर श्रिया (9) रमभोग्य

टिप्पणियाँ—(1) एक राज्य कर्मचारी जिसे विधाम काल में अपना देनिक कार्य करना होता है तथा जिसके लिए उसे सेवा-स्थान पर उपस्थित रहना जरूरी नहीं होता है तथा जो कार्य उसके द्वारा अन्य स्थान पर पूरा किया जा सकता है या जो अन्य राज्य कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है तो उसे अपने पूर्ण विधाम काल या उसके भाग का उपभोग किया हुआ समझा जावेगा । एक राज्य कर्मचारी जो विधाम काल के किसी समय में सेवा स्थल से अनुपस्थित रहता है उससे सरकारी गृह के बिना अपना देनिक कार्य निमाने का प्रबन्ध करने या उसके प्रति उत्तरदायी रहने की आज्ञा दी जाती है । एक राज्य कर्मचारी जो अपने विधामकाल के किसी समय में सेवा के स्थान से अन्य स्थान पर हो और उसे वहाँ से सेवा पर बुलाया जाता है तो वह यात्रा भत्ता का उस समय तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि उसने विधाम काल के साथ साथ अवकाश नहीं लिया हो ।

+ वित्त विभाग की अधिमूचना संख्या एक 1 (62) वित्त वि (व्यय-नियम) 68 दिनांक 18-8-69 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 17-12-68 से प्रभावी ।

(2) इस अवतरण में प्रयुक्त किए गए “ उच्च सत्ता ” शब्दों का तात्पर्य एक कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष के सम्बन्ध में विभाग के अध्यक्ष से है तथा अन्य मामलों में कार्यालय या संस्था के अध्यक्ष से है ।

नियम 95. सेवा भंग किए बिना एक अस्थाई राज्य कर्मचारी की स्थाई रूप में नियुक्ति होने पर उनका अवकाश—एक राज्य कर्मचारी, जो स्थाई सेवा में नहीं हो, सेवा में व्यवधान किए बिना हो यदि स्थाई पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसकी सेवा को उपाजित अवकाश जमा किया जाएगा जो कि उसे प्राप्त होता। यदि उसकी पूर्व सेवा स्थाई नियुक्ति के कर्मचारी की सेवा के रूप में होती। इस उपाजित अवकाश में से जो उसने पूर्व में अवकाश से लिया है, वह घटा दिया जावेगा। इस नियम के लिए अवकाश सेवा में व्यवधान नहीं डालता है।

नियम 96. असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave)—(क) विशेष परिस्थितियों में राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(i) जब नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता हो।

(ii) जब अन्य अवकाश प्राप्त किया जा सकता हो लेकिन सम्बन्धित राज्य कर्मचारी लिखित में उसे असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र वेता हो।

(ख) स्थाई सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के मामलों को छोड़ कर असाधारण अवकाश का नवम दिनी भी एक सप्ताह पर तीन या अठारह माह से अधिक का नहीं होगा। अधिक लम्बे समय का असाधारण अवकाश सरकार द्वारा सामान्य या विशेष रूप से निकाले गए आदेश की शर्तों के अनुसार उसे समय स्वीकृत किया जाएगा जब कि राज्य कर्मचारी निम्न में से किसी एक बीमारी का इलाज करा रहा हो—

(i) एक मायता प्राप्त सेनेटोरियम में पहचानेरी तपेदिक का इलाज कराता हो।

(ii) शरीर के किसी अन्य भाग में हुई तपेदिक का एक योग्य तपेदिक विशेषज्ञ या एक तिविल सर्जन द्वारा इलाज करा रहा हो ; या

(iii) किसी मायता प्राप्त कुष्ठ विकसितालय संस्था (Leprosy Institution) में कुष्ठ रोग का किसी सम्बन्धित राज्यकीय प्रशासनात्मक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मायता प्राप्त कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ से अथवा एक तिविल सर्जन से इलाज करा रहा हो।

+ (ख) (क) जब तपेदिक (T. B.) का इलाज कराने वाले राज्य कर्मचारी के लिए असाधारण अवकाश उपनियम (ख) के अधीन स्वीकृत किया जाता है एवं वह अपना कार्य भार (ड्यूटी) उक्त अवकाश का उपयोग कर, ग्रहण करता है एवं उसके बाद में अद्वैत अवकाश उपाजित करता है तो उसके द्वारा इस प्रकार से प्राप्त किए गए असाधारण अवकाश को अद्वैत अवकाश में परिवर्तित किया जाएगा एवं अजित अद्वैत अवकाश में समायोजित कर लिया जाएगा।

टिप्पणियाँ—अठारह माह की अवधि तक के असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की रियायत

+ (वित्त विभाग की आज्ञा) सन् 1 (61) एफ० डी० (व्यव-नियम) / 65 दिनांक 17-11-65 द्वारा शामिल किया गया)

उस राज्य कर्मचारी को भी मिल सकेगी जो एल्मोनेरी तपेदिक से पीड़ित है तथा जो अपना इलाज घर पर ही ऐसे तपेदिक के विशेषज्ञ से कराता है जो कि राज्यकीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी से मान्यता प्राप्त किया हुआ है तथा उक्त विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है कि वह उमरे इलाज करवा रहा है तथा उसके लिए सिफारिश किए गए अवकाश की समाप्ति के बाद, उसके स्वस्थ हो जाने की पर्याप्त उचित सम्भावना है।

(2) (i) उपनियम के अन्तर्गत छठारह माह तक के असाधारण अवकाश की रियायत केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध की जाएगी जो एक मास से अधिक समय से लगातार राज्यकीय सेवा में खले पा रहे हैं।

(ii) जिस पद से राज्य कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करता हो, वह पद उसके सेवा से तोट कर जाने के समय तक, रखा जाना चाहिए, एवं

(iii) राज्य कर्मचारी ऐसे किसी सेनेटोरियम के मेडिकल अधिकारी, इन्चार्ज, या तपेदिक विशेषज्ञ, या निर्धारित पद के अन्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो, जिससे कि वह इलाज करा रहा हो। प्रमाण-पत्र में उस अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए कि अवकाश की सिफारिश की गई है।

अवकाश की सिफारिश करने वाला अधिकारी यह ध्यान रखेगा कि उसे किसी एक ऐसे मामले में अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिसमें कि राज्य कर्मचारी के पुनः सेवा में उपस्थित होने की कोई सम्भावना नहीं मालूम होती हो। ऐसे मामलों में उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र में अपनी यह राय लिख देनी चाहिए कि राज्य कर्मचारी राज्य सेवा करने में स्थाई रूप से अयोग्य है।

निर्णय :—ऐसे मामले प्राप्त किए जा रहे हैं जिनमें या तो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के लम्बी बीमारी के कारण या उसे सम्पन्न के विभिन्न पाठ्यक्रम पूरे करने हेतु उक्त नियम के प्रावधानों में रियायत करने के लिए निवेदन किया जाता है।

यह निर्णय दिया गया है कि भविष्य में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) में रियायत बरतते हुए असाधारण अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों द्वारा की गई सिफारिशों पर केवल उसी समय विचार किया जावेगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करती जावेंगी :—

(1) तीन माह के असाधारण अवकाश की समाप्ति की तारीख को सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ने तीन साल की सेवा पूरी करती हो (इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश सहित) जो कि साधारण रूप में एक स्थाई राज्य कर्मचारी को स्वीकृत की जाती है।

(ii) असाधारण अवकाश का कुल समय (इस नियम के अन्तर्गत प्राप्य तीन माह सहित) निम्न से ज्यादा न हो :—

(क) 6 माह, जहां अवकाश राज्य कर्मचारी की बीमारी के कारण चाहा गया हो तथा जहां नियमानुसार अवकाश की स्वीकृति के प्रायश्चित्त के साथ चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया हो।

(ख) 2 वर्ष अग्रपयन जारी रहने के लिए जहाँ यह सार्वजनिक हित में प्रमाणित किया गया हो ।

(ग) जहाँ एक राज्य कर्मचारी जो स्थायी सेवा में नहीं है, उसे स्वीकृत किए अधिकतम असाधारण अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा में उपस्थित होने में असफल रहता है या जहाँ एक राज्य कर्मचारी जिसको कि उसे प्राप्य अधिकतम असाधारण अवकाश के स्थान पर कम समय का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, वह किसी ऐसे समय तक सेवा से अनुपस्थित रहता है जो कि स्वीकृत किए गए असाधारण अवकाश को मिलाकर, उस अधिकतम सीमा से ज्यादा होता है और कि उसे उपनियम (ख) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता था, तो यह, जब तक कि राज्यपाल मामले की अपवादस्वरूप परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए अग्रपयन प्रकार से आदेश न दे, अपना नियुक्ति से स्थान पर बिया हुआ समझा जावेगा तथा उसके अनुसार राज्य सेवा में रहना बन्द कर देगा ।

(घ) अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम अधिकारी बिना अवकाश (Without Leave) की अनुपस्थिति के समय को पूर्व प्रभाव से क्यान्तरित अवकाश में बदल सकता है ।

निर्णय :—तपेदिक से पीडित राज्य कर्मचारियों के लिए सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निम्नलिखित अधिकारियों से शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये—

(1) एक अस्थाई राजपत्रित राज्य कर्मचारी जो परमोनरी तपेदिक या शरीर के अग्र किसी भाग में तपेदिक से पीडित हो उसे नियम 84 में वर्णित मेडिकल कमेटी का एक योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये चाहे इलाज सेनेटोरियम में कराया गया हो या घर पर । मेडिकल कमेटी में एक टी. बी. विशेषज्ञ का भी सदस्य के रूप में सहभाग किया जाना चाहिये ।

(2) परमोनरी तपेदिक से पीडित एक अस्थाई अराजपत्रित राज्य कर्मचारी के लिए या तो किसी एक योग्यता प्राप्त सेनेटोरियम के मेडिकल आफिसर इम्बार्ज का या राज्य सरकार द्वारा योग्यता प्राप्त एक तपेदिक विशेषज्ञ से प्राप्त शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । जब वह राज्य कर्मचारी शरीर के किसी भाग की तपेदिक से पीडित हो, तो उसे एक योग्यता प्राप्त तपेदिक विशेषज्ञ या सिविल एसिस्टेंट सर्जन क्लास I से प्राप्त शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये ।

नियम 97. (1) (i) प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए प्राप्य अवकाश वेतन की राशि—
(1) उपाजित अवकाश पर एक राजपत्रित कर्मचारी (क) या (ख) इनमें से जो कोई ज्यादा हो, के बराबर अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) जिस माह में अवकाश प्रारम्भ होता है उससे पूर्व के पूर्ण दस माह की अवधि में कमाया गया औसतन मासिक वेतन; एवं

(ख) स्थाई वेतन जिसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन, राज्य कर्मचारी प्राप्त करने का हकदार है ।

(ii) चतुर्थ खण्ड के अतिरिक्त अन्य एक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी को उपाजित अवकाश पर अवकाश वेतन (Leave Salary) निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकेगा—

(क) उस वेतन के बराबर जिसे वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन प्राप्त करने का हकदार है ।

परन्तु तब यह है कि यदि उन रोज यह अनिश्चित कार्य करने के कारण उसे स्वीकृत विशेष वेतन पा रहा हो या नियम 50 के अन्तर्गत अपने पद के कार्य के अनिश्चित अन्य पद का कार्यभार सम्भालने के कारण अनिश्चित वेतन प्राप्त कर रहा हो, तो अवकाश वेतन देने में ऐसा विशेष वेतन या अनिश्चित वेतन शामिल नहीं किया जावेगा ।

या

(ए) जैसा कि उपरिक्त (1) (क) में दिये गये अनुसार जो भी ज्यादा हो ।

(2) एक अधिकारी जो अर्द्ध वेतन अवकाश या बिना शर्तका अवकाश (Leave not due) पर हो तो उसे अवकाश वेतन उरर उररियन (1) में बर्णित आधी राति के बराबर मिलेगा परन्तु अधिनियम 75) ६० तक स्थापित किया जा सकेगा ।

परन्तु तब यह है कि यदि अवकाश चिरिस्ता प्रमाण-पत्र पर लिया गया हो या किसी अग्रपद के माध्य पाठ्यक्रम को पूरा करने के निरु अग्रपद अवकाश शर्तों के अनिश्चित अन्यथा प्रकार से लिया गया हो तो उस पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

(3) रुग्णान्वित अवकाश पर एक राज्य अधिकारी को अवकाश वेतन उसी तरह मिलेगा जो कि उसे उपार्जित अवकाश पर मिलता है ।

(4) एक राज्य कर्मचारी जो असाधारण अवकाश पर हो, उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलेगा ।

(5) एक अनुपुत्र श्रीणी राज्य कर्मचारी जो उपार्जित अवकाश या रुग्णान्वित अवकाश या अर्द्ध वेतन अवकाश पर है, वह अपना अवकाश वेतन, अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन, अपने विशेष वेतन तक्षित वेतन या ऐसे वेतन के माध्य के बराबर, जैसी भी स्थिति हो, पाने का हकदार होगा ।

+ निर्णय संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि सशम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन स्थापित पदों पर दि 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व स्तूनों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए सम्बाई रु से नियुक्त शक्ति को बेकेशन वेतन दिया जाएगा बगल कि अन्य कोई सरर री कर्मचारी उसी पद पर बेकेशन वेतन प्राप्त नहीं करता है तथा यह भी शीर है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी समले शिक्षण क्षेत्र के मुलने की तारीख से एक माह के भीतर अपनी स्तूटी पर टप'रदन होते हैं ।

समस्त ऐसे अध्यापी अध्यापकों की जो अवकाश काल में रिक्त पदों पर 1 जनवरी से पूर्व नियुक्त हुए हैं या ऐसे प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो ऐसी नियुक्तियां करने में सशम हैं तथा उन समस्त अध्यापी अध्यापकों की, जो 31 दिसम्बर के बाद नियुक्त हुए हैं, सेवाएं सन के अन्तिम कार्य दिवस को समाप्त करदी जाएंगी ।

+ वित्त विभाग की माता सं० एक 1 (50) वित्त वि० (नियम) 66 दिनांक 22-8-70 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

निर्णय संख्या 2—बिलोपित किया गया ।

निर्णय संख्या 3—एक सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) एवं पुनर्नियुक्त अधिकारी जो कि अपनी पुनर्नियुक्ति के समय में उपाजित अवकाश, भ्रष्ट वेतन अवकाश, रूपान्तरित अवकाश एवं भ्रष्टाचार अवकाश लेता है, उसके अवकाश वेतन या पेन्शन के सही निर्धारण में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं । स्थिति निम्न प्रकार है—

(2) पेन्शन योग्य (Pensionable) सेवा से निवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्त होने पर, एक अधिकारी को पेन्शन या तो स्थगित कर दी जाती है या भ्रष्टाचार से प्राप्त करने की उसे स्वीकृति दी जा सकती है जिसके लिए जहाँ आवश्यक हो, पुनर्नियुक्ति के वेतन से उचित कटौती की जा सकती है । एक अधिकारी जिसकी पेन्शन पुनर्नियुक्ति के समय में भ्रष्टाचार से प्राप्त की जाती है तथा जो उपाजित अवकाश या भ्रष्ट वेतन अवकाश या रूपान्तरित अवकाश पर रवाना होता है, तो वह पुनर्नियुक्ति के मूल वेतन पर आधारित अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा (भ्रष्टाचार से पेन्शन एवं/या प्रोव्यूटी के समान पेन्शन शामिल नहीं होगी) तथा इसके प्रतिरिक्त भ्रष्टाचार से पेन्शन प्राप्त करता रहेगा । एक अधिकारी जिसकी पेन्शन स्थगित कर रखी हो तो वह पुनर्नियुक्ति के मूल (नैट) वेतन पर आधारित अवकाश वेतन प्राप्त करेगा (भ्रष्टाचार, रूपान्तरित पेन्शन एवं/या प्रोव्यूटी के बराबर पेन्शन को घटाकर वेतन) तथा इसके साथ में स्थगित की गई पेन्शन के बराबर रकम प्राप्त करेगा । किसी भी मामले में अवकाश वेतन (पेन्शन या पेन्शन के बराबर की राशि जो स्थगित कर रखी हो उसे घटाकर एवं/या प्रोव्यूटी के बराबर की पेन्शन) जो कि भ्रष्ट वेतन अवकाश या रूपान्तरित अवकाश में मिल सकेंगे, वह क्रमशः 750) रु. एवं 1500) रु. की अधिकतम सीमा तक मिल सकेंगे ।

(3) भ्रष्टाचार अवकाश के समय में एक अधिकारी जिसकी कि पेन्शन को रोक लिया गया है, वह केवल रोक दी गई पेन्शन के बराबर की राशि प्राप्त करने का ही हकदार होगा । जहाँ पेन्शन भ्रष्टाचार से प्राप्त की जा रही हो, वह भ्रष्टाचार अवकाश के समय में भी प्राप्त किया जाता रहेगा ।

(4) जिन राज्याधिकारियों पर सेवा निवृत्ति से पूर्व कंट्रोलिंग ऑफिस पद प्रतिज्ञा थी, उनको अपने उपाजित अवकाश, भ्रष्ट वेतन अवकाश एवं रूपान्तरित अवकाश काल का अवकाश वेतन अपनी पुनर्नियुक्ति के मूल वेतन पर मिलेगा । वे भ्रष्टाचार अवकाश के समय में कोई अवकाश वेतन प्राप्त नहीं करेंगे ।

(5) पूर्व में जो मामले अन्य प्रकार से निपटाये गये हों, उन्हें पुनः दोहराने की जरूरत नहीं होगी ।

निर्णय संख्या 4—[बिलोपित किया गया]

टिप्पणी—भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर या विदेशी सेवा में बिताए गए समय के संबंध में, वेतन, जिसे अधिकारी भारत में सेवा पर प्राप्त करता, औसत वेतन गिने जाते समय वास्त-

+ राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 1-12-66 में प्रकाशित वित्त विभाग के आदेश संख्या-

एफ. 1 (50) एफ. सी. (व्यय नियम) 66 दि० 23-9-66 द्वारा परिवर्तित किया गया ।

विक्र प्राप्त किए गए वेतन में परिवर्तित कर दिया जावेगा ।

व्याख्या संख्या (1)—इस नियम के प्रयोजन के लिए मूल वेतन का तात्पर्य उस स्थाई पद के मूल वेतन से है जिसे अधिकारी स्थाई रूप से धारण करता है या जिस पर वह अपना नियत रखता है या जिस पर वह अपना नियत रखता यदि उसका नियत निश्चित नहीं किया गया होता । परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे राज्य कर्मचारी का अवकाश जो कि स्थाई सेवा में नियुक्त है तथा जो बीन साल से अधिक समय तक एक अन्य पद पर कार्यवाहक रूप में लगातार कार्य कर रहा है तो उसके अवकाश पर खाना होने पर उसका अवकाश वेतन इस रूप में गिना जावेगा जैसे कि मानों वह उस पद पर स्थाई रूप से कार्य कर रहा हो जिस पर कि वह इस प्रकार कार्य-वाहक रूप में कार्य कर रहा था या जिस पर वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता परन्तु उसकी उसके समान या उच्च पद पर नियुक्ति हो गई ।

तीन साल की अवधि में निम्नलिखित समय शामिल होगा—

(क) अवकाश की सभी अवधियाँ जिनमें कि राज्य कर्मचारी उस पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता पर वह ऐसे अवकाश पर बना गया; एवं

(ख) एक समान या उच्च पद पर कार्यवाहक रूप में की गई सेवाओं का कुल समय जिनमें वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता रहता परन्तु उसकी नियुक्ति होने के कारण नहीं कर सका ।

व्याख्या संख्या 2—एक राज्य कर्मचारी जो इस भाग के जारी होने की तारीख को अवकाश पर हो उसका अवकाश वेतन, ऐसे अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से उक्त संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्धारित (Recalculated) किया जावेगा ।

खण्ड 3

विशेष असमर्थता अवकाश (Special Disability Leave)

नियम 98. बिलोपित

नियम 99. विशेष असमर्थता अवकाश को स्वीकार किया जाना है—इन खण्ड में वर्णित शर्तों के आधार पर सरकार ऐसे राज्य कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत कर सकती है (जैसे अपनी सरकारी सेवा का उचित पाठन करते समय या अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी है या पहुँचाई गई है तथा जिसके कारण वह असमर्थ हो गया है)

(2) ऐसा अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जावेगा जब तक कि घटना में तीन माह के भीतर उस असमर्थता के कारण को, जिसमें बहु सम्बन्धित है, प्रकट न किया जावे तथा असमर्थ व्यक्ति स्वयं इसे यथाशीघ्र सरकार के ध्यान में लाने का प्रयत्न न करे । ऐसे मामलों में जहाँ असमर्थता का कारण स्वयं घटना के होने से तीन माह से अधिक समय में ज्ञान हो, यदि सरकार असमर्थता के कारणों से सन्तुष्ट हो जाए, तो उसे अवकाश स्वीकृत करने को आज्ञा दे सकती है ।

(3) विशेष असमर्थता अवकाश की अवधि—उनके ही समय का अवकाश स्वीकृत किया जावेगा जिनका कि चिकित्सा मण्डल (मेडिकल बोर्ड) द्वारा आवश्यक रूप में प्रमाणित किया गया हो ।

निर्णय—X राजस्थान सेवा नियमों के नियम 99 के खण्ड (3) में प्रावृष्टि किया गया है कि विशेष असमर्थता के लिए स्वीकृत किया गया अवकाश उतना ही होगा जितना कि चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रमाणित किया जाए।

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान के भीतर प्रतिस्थापित (पोस्टेड) राजस्थान सशस्त्र पुलिस बटालियन के मामले में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ मेडिकल बोर्ड निम्न का होगा—

(क) कमान्डेंट तथा अन्य ऊपर के पद वालों के लिए।

(1) अस्पताल का आफीसर इन्चार्ज जहाँ पर इलाज चल रहा है, एवं

(2) पी. एम. एच. ओ/तथा जिले का जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जहाँ पर कि वह भी उक्त (1) की भांति अस्पताल का इन्चार्ज हो तब पी. एम. एच. ओ/डी. एम.एच.ओ. द्वारा मनीनीत कोई अधिकारी, एवं

(3) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी।

(ख) अन्यो के लिए

(1) अस्पताल का एक चिकित्सा अधिकारी जिसका कि नाम उस अस्पताल के इन्चार्ज द्वारा लिया जाय जहाँ पर कि उसका इलाज चल रहा है, एवं

(2) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी।

राजस्थान के बाहर भार. ए. सी. बटालियन के प्रतिस्थापित किए जाने के मामले में निम्न के लिए मेडिकल बोर्ड इस प्रकार रहेगा—

(क) पराहन कमान्डर एवं अन्य उनसे नीचे के अधिकारी जिनको दो माह से अधिक का असमर्थता अवकाश नहीं चाहिये।

बटालियन का चिकित्सा अधिकारी ही मेडिकल बोर्ड होगा।

(ख) बटालियन के अन्य अधिकारी जो उपर्युक्त (क) द्वारा नियमित नहीं होते हो।

(1) अस्पताल का आफीसर इन्चार्ज जहाँ पर कि इलाज चल रहा है,

(2) बटालियन का चिकित्सा अधिकारी

(ये प्रादेश 5-9-65 से प्रभावशील होंगे)

(4) चिकित्सा मण्डल के प्रमाण पत्र के बिना यह अवकाश बढ़ाया नहीं जावेगा तथा किसी भी दशा में 24 माह से ज्यादा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसा अवकाश किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

X वित्त विभाग को भाजा संख्या एक1(57) एफ डी/(व्यय नियम) 65-II दिनांक 2-11-66 द्वारा शामिल किया गया।

(5) असमर्थता अवकाश एक से अधिक अवसरों पर भी स्वीकृत किया जा सकता है यदि बाद की तारीख में वह असमर्थता पुनः तेज हो जाती है या वैसी ही परिस्थितियों में पुनः उठ खड़ी होती है, परन्तु किसी एक प्रकार की असमर्थता के लिए 24 माह से ज्यादा ऐसा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(6) असमर्थता अवकाश पेंशन के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है—ऐसा अवकाश पेंशन निकालते समय सेवा के रूप में गिना जायेगा।

(7) असमर्थता अवकाश में अवकाश वेतन—ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन—

(क) किसी अवकाश के, जिसमें इस नियम के खण्ड (5) के अनुसार उच्च सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को, स्वीकृत अवकाश भी शामिल होगा, प्रथम 120 दिन के लिए नियम 97 के खण्ड (1) के अनुसार मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर होगा, एवं

(ख) उच्च सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए नियम 97 के (2) के प्रावधानों के अनुसार अर्द्धवेतन के बराबर होगा या राज्य कर्मचारी के विकल्प (Option) पर, उपाजित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, के औसतन वेतन के बराबर होगा। अन्त के मामले में ऐसे अवकाश का आधा समय उसके उपाजित अवकाश में नाम लिखा जायेगा।

अपवाद—यदि कोई पुलिस फोर्स का सदस्य जिसे कि डाकुओं के साथ मुकाबला करते समय चोट लग गई हो तथा वह चोट का इलाज कराने हेतु राज्यकीय अस्पताल में रहता है तो उसका अवकाश वेतन ऐसे अवकाश काल में अवतरण (क) व (ख) में रहे गए प्रावधानों के बावजूद भी, उस वेतन के बराबर होगा जो वह सेवा पर उपस्थित रहकर प्राप्त करता। ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए अवकाश वेतन इस खण्ड के अवतरण (क) व (ख) के अनुसार नियमित किया जाएगा।

(8) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों का अवकाश वेतन निम्न के बराबर होगा—

(क) इस नियम के खण्ड (5) के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये अवकाश को मिलाकर किसी ऐसे अवकाश के प्रथम 60 दिनों के लिए उसे अवकाश वेतन अपने उस वेतन के बराबर मिलेगा जो कि वह अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन प्राप्त कर रहा था।

(ख) ऐसे अवकाश के शेष समय के लिए उसे अवकाश वेतन अर्द्धवेतन के बराबर मिलेगा या राज्य कर्मचारी के विकल्प पर, उपाजित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए जो उसे अन्यथा रूप से स्वीकृत की जा सकती है, उस वेतन के बराबर मिलेगा जो कि उसे अवकाश प्रारम्भ होने के पूर्व दिन मिल रहा हो। बाद के मामले में ऐसे अवकाश का आधा समय उसके उपाजित अवकाश में नाम लिखा जायेगा।

अपवाद—+पुलिस कर्मचारी एवं पुलिस दल (Police force) के साथ सलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (राजस्थान सशस्त्र पुलिस एवं S. A. F. बटालियन् सहित) जो किसी विदेशी

+ वित्त विभाग की यात्रा सं० एक 1 (57) एफ.डी. (इ-गार) 65 दिनांक 3-11-65 द्वारा शामिल किया गया।

शक्ति द्वारा प्राकट्य किए जाने के परिणामस्वरूप खत हो गया है या चोट लग गई है, उन्हें इस नियम के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है एवं खण्ड 7 एवं खंड 8 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के होने हुए भी, ऐसे अवकाश के भीतर अपना वेतन उसके समकक्ष उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जिस रूप में कि वे अपना वेतन सेवा में रह कर प्राप्त करते ।

उक्त प्रकार के अवकाश की अवधि पंधान के लिए गिनी जाएगी एवं उसे वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ राजस्थान सेवा नियम के अधीन प्राप्य होंगे ।

यह संशोधन दिनांक 5-9-65 से प्रभाव में आया ।

नियम 100. अतमर्यता के लिए क्षतिपूर्ति (Compensation) स्वीकृत करने पर अवकाश वेतन में कटौती — यदि कोई राज्य कर्मचारी जो बर्तमान में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का हकदार है, जिनका कि प्रावधान इन अध्याय में किया गया है, तो उसे नियम 99 के अन्तर्गत दिए जाने वाले अवकाश वेतन की राशि में से उतनी ही क्षतिपूर्ति की रकम काट ली जायेगी जो कि उसे कानून के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है ।

नियम 101. सिविल कर्मचारियों पर विशेष अतमर्यता अवकाश नियमों का लागू होना — इस अध्याय के प्रावधान एक ऐसे सिविल कर्मचारी पर लागू होते हैं जो कि मिलेट्री फोर्स के साथ सेवा करने के फलस्वरूप अतमर्य हो गया हो तथा वह अपने भविष्य में मिलेट्री सेवा करने के लिए अयोग्य के रूप में हटा दिया जाता है लेकिन जो अग्रिम सिविल सेवा के लिए पूर्ण व स्थाई रूप से अयोग्य नहीं है । इसके अलावा यह प्रावधान ऐसे सिविल कर्मचारी पर भी लागू होता है जो इस तरह हटाया गया (डिस्चार्ज) नहीं हो परन्तु जो ऐसी अतमर्यता से पीड़ित हो, जिसके कि सम्बन्ध में, मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह अतमर्यता, कर्मचारी की मिलेट्री की सेवा के साथ हुई है । लेकिन किसी भी मामले में, उस अतमर्यता से सम्बन्धित मिलेट्री नियमों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत दिए जा सकने वाले अवकाश की अवधि को, अवकाश की स्वीकृत अवधि गिनने के लिए, इन नियम के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ।

नियम 102. सरकार इस खण्ड के प्रावधानों को उस राज्य कर्मचारी के लिए भी लागू कर सकती है जो कि अपनी सरकारी सेवा में दुर्घटना से पीड़ित हुआ हो या जिसे अपने सरकारी कर्तव्यों को पूर्ण करते समय चोट लगी हो अथवा जिसे अपनी सरकारी स्थिति में चोट लगी हो । या वह ऐंगो विनिष्ट सेवा करने के कारण बीमार हुआ हो जिसके कि पूरा करने से उसकी बीमारी बढ़ती हो या किसी ऐसे सिविल पद पर काम करते हुए पीड़ित हुआ हो जिस पर कि साधारण खतरे से अधिक खतरा रहता है । इस रियायत की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा सकेगी—

(i) यदि बीमारी के कारण अतमर्यता हुई हो तो एक मेडिकल बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह बीमारी किसी विनिष्ट सेवा करने के फलस्वरूप हुई है ।

(ii) यदि राज्य कर्मचारी की सेवा में ऐसी अतमर्यता, मिलेट्री फोर्स की सेवा के अलावा अन्यथा प्रकार से हुई हो, तो सरकार के विचार में यह अतमर्यता इतनी अपवाद स्वरूप तथा ऐसी

× **नियम 106.** अस्पताल अवकाश में अवकाश बेतन—अस्पताल अवकाश औसतन या अर्द्ध औसतन बेतन के बराबर तथा ऐसी अवधि के लिए, अवकाश बेतन पर जंझा अवकाश स्वीकृत करने वाला नक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, स्वीकृत किया जा सकता है ।

नियम 107. अस्पताल अवकाश की अवधि—(प्रिलोविन किया गया)

नियम 108. अस्पताल अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का सम्बन्ध—अस्पताल अवकाश अन्य प्रकार के अवकाशों के अनिश्चित है जो कि एक राज्य कर्मचारी को इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है ।

खण्ड (6)

अध्ययन अवकाश (STUDY LEAVE)

नियम—109. प्रयोग्यता (Applicability)—निम्नलिखित नियम केवल अध्ययन अवकाश से ही सम्बन्धित हैं । इनके द्वारा उन राज्य कर्मचारियों के मामलों को निपटाने की इच्छा नहीं है जो कि सरकार की प्रेरणा पर या तो उनको सौंपे गये विशेष कार्यों को पूरा करने हेतु या अपनी तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के अनुसंधान के लिए अन्य देशों में प्रतिनियुक्त किये हुए हैं । ऐसे मामले नियम 51 के अन्तर्गत उनके स्वयं पर विचार करते हुए निपटाये जायेंगे ।

+ **नियम 110.** अध्ययन अवकाश कितनी स्वीकृत किया जाय (Admissibility of study leave) अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी स्थायी राज्य कर्मचारी को स्वीकार किया जाएगा जो कि उस विभाग के लिए जिसमें वह नियुक्त है, कार्य करने के लिए सार्वजनिक हित में हो ।

÷ **अपवाद—**गिरा विभाग के अध्यापक चाहे वे छात्राधीन/स्थायी/स्थानापर नियुक्त हुए हैं लेकिन जो 1-7-65 को या उसके बाद व्यवसायात्मक प्रशिक्षण (प्रेसेन्सिंग ट्रेनिंग) में जाते हैं, इन नियम के अधीन अध्ययन अवकाश के पात्र होंगे परन्तु धर्त यह है कि उनकी नियुक्ति 31-3-63 से पूर्व हुई हो ।

(यह दिनांक 1-7-65 से प्रभावशील होगा ।)

निर्णय—नियम 110 के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों में अध्याय 11 के खण्ड 6 में दिए अध्ययन अवकाश सम्बन्धी नियम उच्च अध्ययन के लिए अनुमूचित जाति तथा अनुमूचित जन जाति के लोगों पर भी लागू होंगे ।

× वित्त विभाग की अधिमूचना संख्या एक 1 (52) वित्त वि (व्यय-नियम) 67 दिनांक 12-6-68 द्वारा नियम संख्या 106 प्रतिस्थापित तथा नियम नं० 107 विलोपित ।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (53) एक. डी. (ई-मार) दिनांक 18-10-65 ई० द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

÷ वित्त विभाग के आदेश सं० एक. 1 (56) एक. डी. (व्यय-नियम) 66 दिनांक 6-9-66 द्वारा शामिल किया गया ।

ॐ **नियम 111.** अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें—अध्ययन अवकाश उसी समय स्वीकृत किया जायेगा जब सहाय प्राधिकारी को यह राय हो कि अवकाश सामंजसिक हित में वैज्ञानिक या तकनीकी दृष्टि से अध्ययन या अनुसंधान के विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो राज्य कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी कर चुकेगा, उसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

टिप्पणियाँ—(1) राज्याधिकारियों पर जिन्होंने 20 साल की सेवायें पूरी करली हैं, उनके लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने में रियायत बरती जा सकती है बशर्ते कि यदि राज्य कर्मचारी अवकाश से लौटने के बाद 5 साल तक राज्य सेवा करने का या 5 साल की अवधि तक राज्य सरकार की सेवा करने में प्रसमर्थ होंगे के कारण अध्ययन अवकाश का समय लौटाने का प्रतिज्ञा पत्र भरता है।

(2) अध्ययन अवकाश प्राप्त करने में कम से कम 5 साल सेवा करने की जो योग्यता का प्रतिबन्ध रखा गया है वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के राज्य कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। वे तीन साल की सेवा पूरी करने पर अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के योग्य हो जावेंगे।

नियम 112. (1) अध्ययन कार्य के लिए अध्ययन अवकाश भारत में भारत के बाहर लिया जा सकता है। यह ऐसे अन्य अवकाशों के साथ मिलाया जा सकता है जितने राज्य कर्मचारी प्राप्त करने के योग्य हैं। किन्ती भी वंश में इस अवकाश की स्वीकृति में, असाधारण अवकाश या भिक्षिता प्रमाण पत्र के अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश की मिला कर, राज्य कर्मचारी की नियमित सेवा से अनुपस्थिति 24 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए या राज्य कर्मचारी की कुल सेवाधि में यह अनुपस्थिति 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। तथा इसे इस रूप में बार-बार स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य कर्मचारी अपने नियमित कार्य के सम्पर्क में न रहे या जिसके अवकाश पर अनुपस्थित रहने के कारण केडर की कठिनाई आवे। एक समय में 12 माह की अधिकतम अवधि साधारणतया उचित रूप से स्वीकृत की जानी चाहिये तथा अवकाश-स्वरूप मामलों को छोड़कर इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) अध्ययन अवकाश आधे वेतन पर अतिरिक्त (Extra) अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में अवकाश वेतन नियम 97 (2) के अनुसार नियमित होगा।

ॐ **नियम 113.** अन्य अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का समन्वय—एक राज्य कर्मचारी, जिसका अध्ययन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय पर लेना चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप वह पूर्ण में स्वीकृत किए गए अवकाश का इतना बकाया अवकाश अपने पास सुरक्षित रखे जो कि उसके सेवा पर लौटने तक के लिए पर्याप्त हो।

नियम 114. समय से कम के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में तरीका—जब एक राज्य कर्मचारी को किसी निश्चित अवधि तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तथा बाब

ॐ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (53) एन. डी. (अव-नियम) दिनांक 18-10-65 द्वारा शामिल किया गया।

में वह वह पाता है कि उनके अल्पजन का वाञ्छकम स्वीकृत अवकाश की अवधि के बाद जारी समय तक घटेगा तथा उनके वह सेवा से अनुसंस्थित रहेगा जो उसे अल्पजन अवकाश से अधिक समय के अल्पजन समय की कम करना पड़ेगा जब तक कि वह अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की, इसे साधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है।

नियम 115. अल्पजन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना—नियम 116 में दिए गए प्रावधानों के विषय, अल्पजन अवकाश के सभी प्रार्थना-पत्र आदिष्ट प्राधिकार के प्रमाण पत्र के साथ मजबूत प्राधिकारी को पेश किए जायें चाहिए तथा उनके त्रिगुणियों भी वाञ्छकम का वाञ्छकमों को वह पूरा करना चाहिए। तथा त्रिगुणियों परीक्षा में वह जाना चाहिए, उनका स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। भारत के बाहर अल्पजन अवकाश के मामले में यदि वह कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना चाहिए। त्रिगुणियों मजबूत प्राधिकारी से स्वीकृत कर लिया है, तो उसे स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन की सम्पूर्ण सूचना भेजनी चाहिए तथा, जब तक वह स्वयं पर निम्नोक्तों में से, उसे उन समय तक अल्पजन का वाञ्छकम प्रारम्भ नहीं करना चाहिए तथा न उनके सम्बन्ध में कोई धर्य हो करना चाहिए, जब तक कि वह इस सम्बन्ध की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता है।

नियम 116. अन्य अवकाश की अल्पजन अवकाश में परिवर्तन करना—राज्य कर्मचारी की अवकाश पर घोषण या अमेरिका में हों तथा अपने अवकाश के कुछ भाग को अल्पजन अवकाश में बदलना चाहते हों या जो अवकाश काल में अल्पजन का वाञ्छकम पूरा करना चाहते हों, उन्हें अल्पजन प्रारम्भ करने के पूर्व तथा उनके सम्बन्ध में कोई लक्ष्य करने के पूर्व, अपने प्रस्तावित अल्पजन के वाञ्छकम का कार्यक्रम पेश करना चाहिए। कार्यक्रम के साथ अल्पजन का सरकारी वाञ्छकम भी संलग्न किया जाना चाहिए, यदि प्राप्त हो, तो किसी विशेष वाञ्छकम के निम्न प्रमाण (Documentary evidence) भी संलग्न किए जाने चाहिए।

नियम 117 अल्पजन भत्ता (Study Allowance)—सरकार किसी मासिक प्राप्ति मंजूरी में अल्पजन के एक निश्चित वाञ्छकम को पूरा करने में अथवा विशिष्ट क्षेत्रों के कार्यों के निरीक्षण हेतु निश्चित क्षेत्रों में जाएँ गए समय तथा अल्पजन के वाञ्छकम के अन्त पर किसी परीक्षा के समय के लिए अल्पजन भत्ते की दर निश्चित कर सकती है।

नियम 118 विराम काल (Vacation) का अल्पजन भत्ता—किसी भी विराम काल की अवधि का अल्पजन भत्ता 14 रोज का स्वीकृत किया जा सकता है। एक समझौते की त्रिगुणियों राज्य कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए वाञ्छकम का कर सकता है, विराम काल नहीं मंजूर जा सकता है। सरकार अपने निर्णय पर एक समय में किसी भी 14 दिन तक की ऐसी अवधि का अल्पजन भत्ता स्वीकृत कर सकती है त्रिगुणियों कि अधिकारी को बीमारी के कारण अल्पजन का वाञ्छकम घातु रहने में रोक दिया जाता है। ऐसी बीमारी की अवधि के लिए विशिष्ट अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि कोई राज्य कर्मचारी अल्पजन अवकाश की अवधि के बाद सेवा पर पुनः उदात्त हुए बिना ही सेवा से निवृत्त किया जा रहा हो तो उसका अल्पजन भत्ता रोक लिया जावेगा। उसका अल्पजन अवकाश उनके अपने भेले में सेवा निवृत्ति के अन्तिम दिन तक बढ़ाया साधारण अवकाश की सीमा तक साधारण अवकाश (Ordinary leave) में बदल दिया जावेगा। यदि उपरोक्त वर्णन दिए गए

अध्ययन अवकाश का कुछ ऐसा भाग बचा हो जिसे इस प्रकार बदला नहीं जा सकता हो, तो उसे पेन्शन के लिए सेवा से निकाल दिया जावेगा ।

नियम 119. अध्ययन के पाठ्यक्रम का शुल्क (Fee for course of study)—जिन राज्य कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उन्हें साधारणतया अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए शुल्क आदि जमा करने के व्यय स्वयं को सहन करना है । केवल अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़ कर सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव रखने को तैयार होगी कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 1—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही थी कि क्या ऐसे राज्य कर्मचारी हों, जिसे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, अपने वेतन के प्रतिरिक्त कोई छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड, जो कि उसे सरकारी या गैर सरकारी स्त्रोतों से मिलती हो, स्वीकार करने तथा उसे अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती है ।

मामले पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद निम्न रूप से निर्णय किया गया है—

(i) एक राज्य कर्मचारी जिसे अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु व्यवसाय या तकनीकी विषय में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उसे अपने वेतन के प्रतिरिक्त किसी भी ऐसी छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड को प्राप्त करने तथा अपने पास रखने की स्वीकृति दी जा सकती है, जो कि उसे सरकारी या गैर सरकारी स्त्रोतों से मिलती हो ।

(ii) जहाँ राज्य कर्मचारी अध्ययन अवकाश में छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड (किसी भी स्रोत से हो) प्राप्त करता हो, वहाँ अध्ययन अवकाश के नियम 119 के अन्तर्गत अध्ययन पाठ्यक्रम के शुल्क आदि का व्यय नहीं दिया जाना चाहिए ।

निर्णय संख्या 2—वित्त विभाग के आदेश संख्या डी० 3942/59 एफ 7 ए (50) एफ. डी० (ए) नियम 59 दिनांक 13-1-60 द्वारा शामिल किए गए राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 1 के अन्तर् में यह आदेश दिया जाता है कि एक राज्य कर्मचारी जो अध्ययन अवकाश काल में छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड (किसी भी स्रोत से) प्राप्त करता है, उसे साधारणतया कोई अध्ययन भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए । लेकिन विशेष परिस्थितियों में जहाँ पर छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड की मूल राशि (अर्थात् छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड में से व्ययान फीस आदि की रकम काट कर बची राशि) स्वीकृत अध्ययन भत्ते की उस राशि से कम हो जो कि उसे प्राप्त होता परन्तु वह छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड प्राप्त करने के कारण नहीं पा सका, तो उसे छात्रवृत्ति या स्टाइफण्ड की मूल राशि तथा साधारण अध्ययन भत्ते की राशि का अन्तर सरकार की विनये स्वीकृति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है ।

नियम 120. पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र—किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को भेजा जावेगा जिसके साथ उत्तीर्ण की गई परीक्षा या विशेष अध्ययन के प्रमाण-पत्र संलग्न किए जावेंगे ।

नियम 121. उन्नति एवं पेन्शन के लिए अध्ययन अवकाश की गणना—अध्ययन अवकाश उन्नति या पेन्शन के लिए सेवा के रूप में समझा जावेगा लेकिन इसका प्रभाव कर्मचारी के बकाया किसी भी अवकाश पर नहीं पड़ेगा । यह अर्ध औसतन वेतन या अर्ध

औसतन मूल वेतन पर, जंसी भी स्थिति हो, अतिरिक्त अवकाश (Extra leave) के रूप में गिना जावेगा तथा खण्ड 2 के नियमों के अधीन स्वीकृत अधिकतम अवधि के अर्द्ध वेतन के अवकाश के गिनने में शामिल नहीं किया जावेगा ।

नियम 121 का—राज्य सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (Bond) भरा जाना—जो प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत प्राप्य अध्ययन अवकाश का उपयोग करते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण समाप्त होने पर नीचे दिखाए गए समय तक राज्यकीय सेवा करने का अनुबन्ध पत्र (बॉन्ड) भरना चाहिए ।

अध्ययन अवकाश का समय

समय, जितने के लिए अनुबन्ध पत्र भरना होगा ।

तीन माह

एक साल

छह माह

दो साल

एक साल

तीन साल

दो साल

पांच साल

अनुबन्ध पत्र (बॉन्ड) का फार्म परिशिष्ट 18 में दिए गए अनुसार होना चाहिए ।

नियम—जिन राज्य कर्मचारियों को अध्ययन के प्रयोजन के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा जो अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर बिना सौट ही सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं या सेवा से मुक्त हो जाते हैं या जो अपनी सेवा पर सौटने के बाद निर्धारित समय के भीतर ही किसी भी समय त्याग पत्र दे देते हैं या सेवा से निवृत्त कर दिए जाते हैं, उनसे दण्ड की राशि (Penalty) वसूल किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामले में वसूल की जाने वाली राशि, अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, तथा शुल्क, (फीस) यात्रा एवं ग्रन्थ भत्तों का व्यय जो कि राज्य कर्मचारी को उसके अध्ययन अवकाश की अवधि में दिया जावेगा या जो उस पर अन्यथा प्रकार से खर्च किया जावेगा, उसमें दूनी होगी, तथा उसे द्वाज सहित वसूल करना होगा । इस कार्य के लिए नियम 121 क के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश के लिए निर्धारित अनुबन्ध पत्र भरना होता है जो कि राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ट 18 में दिया हुआ है । यह अनुबन्ध पत्र इसके साथ (फार्म क व ख) के रूप में बरतना जावेगा ।

अध्ययन अवकाश नियमों में रियायत बरतते हुए यदि एक अस्थाई राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है तो उससे भी दण्ड की राशि वही वसूल की जावेगी जो उपरोक्त अवतरण (1) में दी हुई है ।

ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें अस्थाई राज्य कर्मचारियों को भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए ग्रन्थ नियमित अवकाश के साथ साथ नियमों में रियायत बरतते हुए विशेष प्रकार के मामले के रूप में, असाधारण अवकाश (Extra ordinary leave) उनमें लिखित में इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र भरने पर स्वीकृत किया जा सकता है कि उन्हें उनके अवकाश समाप्त होने के बाद प्रमुक्त निर्दिष्ट समय तक राज्यकीय सेवा करनी होगी । यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी से लिखित में एक प्रतिज्ञा पत्र (फार्म ग) अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व भरा लेना चाहिए । ऐसे मामलों में अनुबन्ध पत्र के फार्म में भरी जाने वाली दण्ड की राशि उपरोक्त अवतरण (1) में कहे गए अनुसार होगी ।

संश्लेषण 1—एक संदेश उत्पन्न किया गया है कि एक राज्य कर्मचारी जिसे भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए ग्रन्थ नियमित अवकाश के साथ साथ नियमों में रियायत बरतते

हुए, विशेष प्रकार के मामले के रूप में, प्रसाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा जो अवकाश के समय के बाद सेवा पर बिना लोटे ही त्याग पत्र दे देता है या सेवा निवृत्त हो जाता है या जो सेवा पर घाने के बाद निर्धारित समय में कभी भी त्याग पत्र दे देता है या सेवा निवृत्त हो जाता है, तो उसे दण्ड देने की राशि किम प्रकार निश्चित की जावेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में या विदेश में अध्ययन के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) में विधायित करते हुए जिन अस्थाई राज्य कर्मचारियों को प्रसाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, उनके जो (फार्म ग मे) अनुबन्ध पत्र में दण्ड की राशि भरी जाएगी वह अस्थाई राज्य कर्मचारी के उसके द्वारा लिए गए (यदि कोई हो) नियमित अवकाश के अवकाश वेतन की राशि तथा प्राप्ति के प्रसाधारण अवकाश पर चले जाने के कारण उसके अवकाश के समय में खाली पड़े स्थान पर कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति को नियुक्ति के व्यय की राशि की दूनी होगी।

स्पष्टीकरण सं० 2—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या नियम 121 का के नीचे दिए गए राजस्थान सरकार के नियंत्रण तथा तदधीन दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में या भारत के बाहर अध्ययन के लिए देय एवं स्वीकार्य, अन्य नियमित अवकाश यदि कोई हो, के क्रम में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) में विधिलता वरतते हुए लम्बी अवधि के लिए प्रसाधारण अवकाश के स्वीकृत करने पर प्रत्यायो सरकारी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रप्रेषित बन्धपत्र के साथ किसी एक व्यक्ति या एक से अधिक जामिन के साथ कान्ट्रेक्ट आफ गारण्टी भी इस हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से असफल रहा तो वे सरकारी दायित्व को पूरा करेंगे।

यह निश्चय किया गया है कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा बन्धपत्र के अधीन दायित्वो को पूरा करने हेतु निश्चय करने के लिए, बन्धपत्र के साथ दो स्थायी ऐसे सरकारी कर्मचारियों की जामिनें होनी चाहिए जो उस सरकारी कर्मचारी के, जिसे उक्त नियमों में डील देकर प्रसाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है, समकक्ष या उससे उच्चस्तर के हों। इस हेतु इस विभाग के आप दि. 28-4-61 द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट बन्ध पत्र को प्रतिक्रमित कर एक नया बन्धपत्र अध्याय 18 में शामिल कर दिया गया है।

+ स्पष्टीकरण सं० 3—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 121 का के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जिन्हें भारत में या बाहर अध्ययन के प्रयोजनार्थ अध्ययन अवकाश या प्रसाधारण अवकाश स्वीकृत हो गया है, उन्हें निर्दिष्ट अवधि तक राजस्थान सरकार की सेवा करने का एक बन्ध-पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। बन्ध पत्र के प्रपत्र राजस्थान सेवा नियम, भाग II के परिशिष्ट 18 व 18 क में दिए हुए हैं।

राजस्थान में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों के पास हस्तान्तरित कर देने के फलस्वरूप, अध्यापक वर्ग की सेवायें, जो महाविद्यालयों में सेवा कर रहे थे, विश्वविद्यालय को सौंप दी गयी थी। कुछ अध्यापक वर्ग अभी भी सरकार की सेवा करने के बन्ध-पत्र के अधीन थे। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा में वर्णित नियम की शर्तों के अनुसार निष्पादित बन्ध-पत्र के प्रयोजनार्थ, उक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजस्थान

+ वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 1 (87) वित्त वि/नियम/62 दि. 27-11-69 द्वारा शामिल किया गया।

वद्विद्यालय में की गई सेवायें, सरकार के अधीन की गयी सेवाओं के अंश के रूप में मानी जाएंगी ।

उपयुक्त पैरा 2 में अन्तर्विष्ट निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो अपनी स्वेच्छा से नती के लिए आवेदन करते हैं तथा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में या मालवीय प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर में प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए जाते हैं ।

खण्ड 7

परिषदाधीन व्यक्ति (Probationer) तथा नवमिषुओं (Apprentices) के लिए अवकाश

नियम 122. प्रोबेशनरों के लिए अवकाश :—एक परिषदाधीन व्यक्ति के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह उसे उन अवकाश नियमों के अन्तर्गत प्राप्य है जो कि उस पर लागू होते यदि वह परिवर्त्ताकाल के अतिरिक्त अन्यथा रूप से अपने स्थाई पद को धारण करता । यदि कसी कारण से प्रोबेशनर की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया हो तो उसे किसी भी रूप का स्वीकृत किया हुआ अवकाश उस नियम से आगे का नहीं होना चाहिए जिस तक कि उसका पूर्व में स्वीकृत किया गया या बढ़ाया गया परिषदाधीन (Probation) का समय समाप्त नहीं होता है । अथवा उनका स्वीकृत किया हुआ अवकाश ऐसी पूर्ण की तारीख से आगे का नहीं होना चाहिए जिसको कि उसकी सेवायें नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं ।

टिप्पणी--विश्राम कालीन (V cation) विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर इन सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम (92) (2) के नीचे दिया गया राजस्थान सरकार का निर्णय सख्या 2 लागू होगा ।

नियम 123. नवमिषुओं (Apprentices) के लिए अवकाश—एक नवमिषुआ (एप्रेन्टिस) को बिक्रिस्ता प्रमाण-पत्र या असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा जो कि स्थाई सेवा में नियुक्त नहीं किए गए एक सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है ।

खण्ड 8

अंशकालिक सेवा द्वारा उपार्जित अवकाश (Leave earned by part-time service)

नियम 124. शिक्षण संस्थाओं में पार्ट-टाइम प्राध्यापकों (Lecturers) एवं कानून अधिकारियों (Law officers) के लिए अवकाश—शिक्षण संस्थाओं में पार्ट टाइम प्राध्यापक एवं कानून अधिकारियों को, जो कि वेतन की निश्चित दर पर पद धारण किए हुए हों लेकिन जो पूर्ण समय के लिए सरकार की सेवा में नहीं रहे जाते हों, उन्हें अवकाश निम्न रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा—

(क) उस संस्था के विश्राम काल में जिनमें कि ऐसे प्राध्यापक कार्य करते हैं या उन अदालतों के विश्राम काल में जिनमें कि नियन्त्रण में कानून अधिकारी कार्य करते हैं, उन्हें अवकाश पूर्ण वेतन पर मिलेगा यद्यपि कि उसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़ता हो । ऐसा अवकाश, सेवा (Duty) के रूप में गिना जावेगा ।

(ख) छह साल की सेवा के बाद उसकी सेवा में अधिकतम तीन माह का अर्द्ध वेतन पर अवकाश ।

(ग) चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर, किसी एक समय में अधिकतम दो माह का अर्द्ध वेतन पर अवकाश, बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर पहिले लिए गए अवकाश तथा बाद में लिए जाने वाले अवकाश में दो वर्षों का समय व्यतीत हो चुका हो ।

(घ) नियम 96 में दो गई शर्तों पर असाधारण अवकाश ।

नियम 125. स्वीकृत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाशों का समन्वय—नियम 124 के किसी भी एक खण्ड के अन्तर्गत लिया गया अवकाश किसी दूसरे खण्ड के अन्तर्गत लिए गए अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है ।

खण्ड 9

पारिधमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिधमिक प्राप्त सेवा द्वारा उपाजित अवकाश

(Leave earned by service remunerated by honoraria or daily wages)

नियम 126. पारिधमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा पारिधमिक प्राप्त सेवा का अवकाश—एक राज्य कर्मचारी जो पारिधमिक या दैनिक मजदूरी द्वारा अपना पारिधमिक प्राप्त करता है, उसे अवकाश नियम 124 व 125 में दो गई शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि वह अपने कार्य को पूरा कराने का सन्तोषजनक प्रयत्न करदे तथा इसके कारण सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय न करना पड़े तथा यह कि नियम 124 के खण्ड (ख) में दिए गए किस्म के अवकाश में, उसका कुल पारिधमिक या दैनिक मजदूरी उस व्यक्ति को दी जावे, जो उसकी जगह पर काम करे ।

अध्याय १२

सेवा में कार्यग्रहण करने का समय (Joining Time)

नियम 127. कब स्वीकृत होगा (When admissible)—किसी भी राज्य कर्मचारी को निम्न के लिए ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत किया जा सकेगा—

(क) ऐसे नये पद पर कार्यग्रहण करने के लिए जिस पर कि वह अपने पुराने पद पर काम करते समय नियुक्त किया गया हो, या अपने उस पद का कार्यभार सम्भालकर सीधे उस पद पर कार्यग्रहण करने के लिए ।

(ख) (i) उपाजित अवकाश से लौटने पर नये पद पर उपस्थिति देने के लिए, या

(ii) उपखण्ड (1) में वर्णित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश से लौटने पर, अपनी नई नियुक्ति की पर्याप्त समय पूर्व सूचना प्राप्त न करने की स्थिति में, नए पद पर उपस्थिति देने के लिए ।

टिप्पणी संख्या 1—[विलोपित की गई]

टिप्पणी संख्या 2—प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कीछ ही यदि एक कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान में नियुक्ति के स्थान तक पहुँचने के लिए जो उचित समय आवश्यक हो, उसे प्रशिक्षण के समय का घंटा समझा जाना चाहिए । यह नियम 'प्रशिक्षण पदों' (Training posts) को धारण करने वाले प्रोबेशनरों पर लागू नहीं होता । उनको (पदों को) उनके स्थानान्तरण होने पर स्थानान्तरित किया हुआ समझा जावेगा । ऐसे प्रोबेशनरों को स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा ।

स्पष्टीकरण—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के नीचे दी गई टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है इसके अनुसार प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तथा समाप्त होने के बाद यदि एक कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से नियुक्ति के स्थान तक पहुँचने के लिए जो उचित समय आवश्यक हो, उसे प्रशिक्षण के समय का अंश समझा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न उत्तरित किये गये हैं कि क्या प्रत्येक मामले में परिवर्तन के वास्तविक समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में उसी मध्यम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है जो उसे प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति करने के लिए मस्य है।

प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा परिवर्तन के समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में समझे जाने के लिए बिल से आदेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु मध्यम प्राधिकारियों को व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति के आदेश में इस सम्बन्ध का एक खण्ड (Clause) और शामिल करना चाहिए कि अधिकारोंगण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 129 के प्रावधानों के अनुसार (तैयारी के समय को निकाल कर) वास्तविक यात्रा में लगने वाले समय के 'ज्वाइनिंग टाइम' का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का एक खण्ड शामिल करने से परिवर्तन का समय नियम 127 की टिप्पणी के अर्थ में प्रशिक्षण के रूप में समझा जावेगा।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के नीचे दी गई टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी यदि राज्य कर्मचारी किसी एक स्थान पर नियुक्त हो जाता है तो प्रशिक्षण के स्थान से नियुक्ति के स्थान तक पहुँचने के लिये आवश्यक उचित समय को प्रशिक्षण के भाग के रूप में माना जाता है तथा ऐसे मामलों में कोई भी ज्वाइनिंग समय नहीं दिया जाता है। एक प्रश्न उत्तरित हुआ है कि क्या पूर्वोक्त टिप्पणी उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ पर राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की समाप्ति पर ऐसे स्टेशन पर नियुक्त किया जाता है जो कि उसके प्रशिक्षण के लिये रवाना होने वाले स्टेशन से भिन्न हो।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि उक्त टिप्पणी उल्लेखित मामलों में लागू नहीं होगी। ऐसे समय में उसका पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम प्रशिक्षण के स्थान से उस स्थान तक लगाया जाना चाहिये जहाँ पर कि वह अन्तिम रूप से नियुक्त किया गया है न कि उस स्थान से लगाया चाहिये जिसमें कि वहिले यह प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ था।

टिप्पणी सं० 3—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने उपाधित अवकाश में एक ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जो कि अपने अवकाश पर रवाना होने वाले पद से भिन्न हो, तो वह नियम 129 के अन्तर्गत पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम प्राप्त करने का हकदार है चाहे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा स्थानान्तरण के आदेश किसी भी तारीख को क्यों न प्राप्त किये हों। यदि राज्य कर्मचारी को ऐसे अवकाश की समाप्ति के पूर्व एवं स्वीकृत ज्वाइनिंग टाइम के पूर्व अपने नये पद पर उदास्थित होना हो तो जितना भी समय कम बचेगा उसे अवकाश न प्राप्त किये गये समय के रूप में समझा जाना चाहिये तथा उसके बराबर के स्वीकृत समय के अवकाश की अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को बिल लिखे हुए रद्द (Cancel) कर देना चाहिये। यदि किसी मामले में, राज्य कर्मचारी उसे प्राप्त पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम का उपयोग नहीं करना चाहता हो तो ऐसे विकल्प (आप्शन) की स्थिति में अवकाश के समय तथा उपस्थिति के समय का समाबेज कर दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी सं० 4—यदि विधायक काल के साथ अवकाश लिया गया हो तथा विधायक काल व अवकाश का समय दोनों मिलाकर 4 माह से ज्यादा न हो तो ज्वाइनिंग टाइम नियम 127 के खण्ड (ख) (1) के अन्तर्गत नियमित किया जाना चाहिये ।

टिप्पणी सं० 5—प्रतिपक्ष के लिए रवाना होने के पूर्व या उनके बाद में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इसका मतलब राजस्थान सेवा नियम भाग 2 के परिशिष्ट 1 की आकस्मिक अवकाश के भाग 3 के पैरा (1) (II) के अर्थ में नियमों का उल्लंघन होगा ।

नियम संख्या 1—एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत एक अधिकारी को ज्वाइनिंग टाइम नये पद पर उपस्थित होने के लिए मिल सकता है जो कि अवकाश की समाप्ति पर या अन्यथा प्रकार से अपनी नियुक्ति के आदेशों का इन्तजार ऐसे स्थान पर करता है जहाँ पर कि अवकाश का उपयोग किया गया था या जो सेवा का प्रतिभूत स्थान हो एवं जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) (5) के अन्तर्गत 'सेवा' के रूप में माना जाता है ।

यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम तथा उक्त नियमों के नियम 138 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम का वेतन दोनों ही ऐसे मामलों में मिलेगा । ज्वाइनिंग टाइम 'नियुक्ति आदेश (Posting order)' के जारी होने की तारीख से गिना जाना चाहिये ।

आदेश जारी करते समय सलम प्राधिकारियों को बताना चाहिये कि क्या तैयारी के लिये पूर्ण ज्वाइनिंग टाइम पूरा अर्थात् ६ दिन का जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत प्राप्य है, स्वीकृत किया जाना चाहिये अथवा ६ दिन से कम या कोई निश्चित सीमा तक स्वीकृत किया जाना चाहिये । एक प्रकार के मामले जिनमें कि तैयारी के लिये ज्वाइनिंग टाइम में कमी करना ठीक हो, उनमें उक्त अधिकारी को पूर्व में ही सूचित कर देना चाहिये कि अपनी नियुक्ति दूसरे स्टेशन पर की जानी है ।

नियम संख्या 2—कुछ समय पूर्व से ही सरकार के विचाराधीन यह मामला चल रहा था कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप या साक्षात्कार (इंटरव्यू) के फलस्वरूप, जिनमें कि राज्य कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते थे, राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें कितना ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग टाइम का वेतन दिया जाना चाहिये । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में ज्वाइनिंग टाइम एवं ज्वाइनिंग टाइम का वेतन निम्न प्रकार से नियमित किया जावेगा ।

(क) ज्वाइनिंग टाइम सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों की साधारण रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिये, एवं यह कि

(ख) जब तक राज्य कर्मचारी सरकार के अधीन स्थाई पद पर स्थाई रूप में कार्य नहीं कर रहा हो उसे कोई ज्वाइनिंग टाइम वेतन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये ।

जहाँ उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत किया जाता है, वहाँ उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम 2६ के अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी स्वीकृत किया जाना चाहिये ।

निर्णय संख्या—3 वित्त विभाग के मीमो दिनांक 31-1-61 (उक्त निर्णय संख्या 2) के अतिप्रमाण में यह निर्णय किया गया है कि जो राज्य कर्मचारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप या साक्षात्कार (इंटरव्यू) के फलस्वरूप, जिनमें कि राज्य कर्मचारी व अन्य व्यक्ति सीधे भाग ले सकते हैं, राज्य सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्त किये जाते हैं, उन्हें ज्वाइनिंग टाइम का वेतन निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाना चाहिये।

(क) राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों के लिये साधारणतया ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत किया जाना चाहिये। इसके अलावा केन्द्रीय एवं अन्य राज्य के उन राज्य कर्मचारियों के लिये भी स्वीकृत किया जाना चाहिये जो कि स्थाई पदों पर स्थाई रूप में कार्य करने हैं, एवं यह कि

(ख) जब तक एक राज्य कर्मचारी सरकार के अधीन (केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों सहित) स्थाई रूप में स्थाई पद पर कार्य नहीं करना हो उसे कोई ज्वाइनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये।

जहां उपरोक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम का वेतन स्वीकृत किया जाता हो वही उन्हें राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत यात्रा भत्ता भी स्वीकृत करना चाहिये।

उक्त निर्णय दिनांक 1-11-56 को प्रभावशील समझा जावेगा।

निर्णय संख्या 4—जो अस्थाई राज्य कर्मचारी एक विभाग से स्थापन (Establishment) में कमी किए जाने के कारण हटा दिए (Discharge) गये हैं तथा ऐसे ही अन्य विभागों में पुनर्नियुक्त कर दिए हैं, उन्हें निम्नलिखित रियायतें स्वीकृत की जाती हैं—

(1) यदि नए पद पर नियुक्ति के आदेश सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ने उस समय प्राप्त किया हो जब कि वह अपने पुराने पद पर कार्य कर रहा हो या जब वह अन्तिम अवकाश (Terminal Leave) पर हो—

उन्हे स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम एवं यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जावेगा जहां पर यदि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उसका स्थानान्तरण सांख्यिक हिन की दृष्टि से है तथा सरकार के अधीन पूर्व में की गई उसकी सेवाएं उसके नये पद की नियुक्ति के लिए आवश्यक हैं। जहां इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता हो वहां कोई भी ज्वाइनिंग टाइम एवं भत्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा। परन्तु सेवा में, यदि कोई व्यवधान (Break) हो गया हो, तो उसे लगातार सेवा बनाने के उद्देश्य से कन्डोन किया जा सकता है बशर्ते कि व्यवधान का समय उसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा न हो।

(ii) यदि राज्य कर्मचारी अपने नियुक्ति के आदेश अपने पुराने पद से हटाये जाने के बाद या अन्तिम अवकाश की समाप्ति के बाद, शीघ्र ही अन्य ऐसे कार्यालय में प्राप्त करता है तथा अपने नये पद पर बिना किसी देर के उपस्थित हो जाता है तो—

उसे कोई भी ज्वाइनिंग टाइम या यात्रा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जावेगा परन्तु उसकी सेवा को निरन्तर गिने जाने के लिए उसकी सेवा के व्यवधान को कन्डोन किया जा सकता है बशर्ते कि

व्यवधान का समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत प्राप्य ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा न हो ।

(iii) उपरोक्त उप-अवतरणों (Sub-paras) के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत करने या ज्वाइनिंग टाइम के बराबर सेवा के व्यवधान को कन्डोन करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम प्राधिकारी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 135 व 136 के द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ज्वाइनिंग टाइम को 30 दिन तक बढ़ा सकता है । सभी मामले, जिनमें सेवा का व्यवधान 30 दिन से ज्यादा का हो एवं जिसमें कि व्यवधान को कन्डोन किया जाना हो प्रत्येक उस समय का ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत किया जाना हो, वित्त विभाग के पास उचित अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय हेतु भेजे जाने चाहिये ।

(iv) ऐसे सभी मामले जिनमें सेवा का व्यवधान कन्डोन किया गया हो तो उस सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (Service book) में व्यवधान को कन्डोन करने वाले प्राधिकारी का हवाला देते हुए इन्द्राज किया जावेगा ।

(V) जब कभी किया गया राज्य कर्मचारी पुनर्नियुक्त किया जाता है तथा उसकी सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, कन्डोन किया जाता है तो उसकी पूर्व की सेवाएँ (लेकिन इसमें स्वयं व्यवधान का समय शामिल नहीं होगा) नये कार्यालय में बरिष्ठता के निर्धारण में समग्र समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण नियमों या आदेशों के अनुसार गिनी जायेगी ।

व्यवधान को कन्डोन कर दिये जाने में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 138 क. की शर्तों के आधार पर कर्मचारी को पूर्व पश्चाद् सेवाएँ पे'जन् के लिये गिनी जायेगी ।

+ विषय—सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार संभालने में जानबूझ कर विलम्ब

सरकार के यह ध्यान में आया है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने पर कार्यभार संभालने वाला सरकारी कर्मचारी जिस पद पर वह स्थानान्तरित हुआ है, उस पद का कार्यभार संभालने के लिये ज्यों पर उपस्थित होता है लेकिन किसी न किसी कारण से कार्याभ्यास/विभागाध्यक्ष या कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी जानबूझ कर देरी करते हैं तथा कार्यभार संभालने से वकते हैं ।

मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह तय किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने पर कार्यभार, संभालने वाले कर्मचारी के आगमन पर सीधे ही सम्भाला जाना चाहिये । यदि कार्यभार संभालने में कोई जानबूझ कर देरी को जारी है तो कार्यभार संभालने वाला अधिकारी पद का कार्यभार संभाल लेगा तथा कार्यभार संभालने वाले कर्मचारी को उस समय तक अवधारण अवकाश पर सम्भाल जाएगा जब तक कि वह अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने को तारीख से, स्वीकृत नहीं कर दिया गया हो ।

नियम 128. स्थान का परिवर्तन न होने पर-ज्वाइनिंग टाइम (Joining time where

+ वित्त विभाग की आज्ञा संख्या एक 1 (72) वित्त वि (अध्य-नियम) 69 दिनांक 7-11-69 द्वारा निविष्ट ।

change of Station is not involved)—जहाँ एक पद से नये पद पर स्थानान्तरित होने में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में अपना निवास स्थान नहीं बदला जाना हो वहाँ पर नये पद पर उपस्थित होने के लिये एक दिन से अधिक का ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाना चाहिये। इस नियम के प्रयोजन के लिये एक पर्वकाश (Holiday) को भी एक दिन गिना जावेगा।

स्पष्टीकरण—एक मामला सरकार के पाम दम सम्बन्ध का भेजा गया कि जहाँ एक अधिकारी के द्वारा अपना वायमार समाप्त करने के बाद स्थानान्तरित अधिकारी भाने हैं तथा जहाँ नए पद की नियुक्ति में निवास स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो उनका ज्वाइनिंग टाइम किस प्रकार नियमित किया जावेगा। अधिकारी ने अपना चाज दोपहर बाद भोगा था।

मामले की जाँच की गई तथा यह स्पष्ट दिया जाता है कि प्रथम दिन का अधिकारी नियम 128 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है तथा इसके बाद के दोष अधिकारियों की नियम 61 के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम के पूर्ण भाग द्वारा अधिकारी समझा जाना चाहिये। बाद के अधिकारी भान का ध्यान एवं भत्ता नियम 63 (घ) के अनुसार नियमित किया जाना चाहिये।

जो मामले पहिले उपरोक्त तरीके के अन्तर्गत अधिकारी प्रकार में तय किए जा चुके हैं उन्हें पुनः दोहराने की जरूरत नहीं।

× 128 क.—जब कार्यग्रहण के समय (ज्वाइनिंग टाइम) के बाद छुट्टी या छुट्टियाँ आनी हों, तो सामान्यतः ज्वाइनिंग टाइम उक्त छुट्टी या छुट्टियों की सीमा तक बढ़ाया हुआ समझा जाएगा।

नियम 129. प्राप्ति ज्वाइनिंग टाइम की अवधि (period of joining time admissible)—तैयारी करने के लिए 6 दिन का समय तथा इसके साथ वास्तविक यात्रा का समय स्वीकृत किया जाता है जो निम्न प्रकार से गिना जाता है—

(क) एक राज्य कर्मचारी को निम्न दूरी तक यात्रा करने के लिए निम्न प्रारंभ मामले में एक रोज का समय दिया जाता है—

रेल द्वारा	500 किलो मीटर
समुद्री जहाज द्वारा	350 किलो मीटर
नदी के जहाज से (River Steamer)	150 किलो मीटर
सार्वजनिक किराये पर चलने वाली मोटर कार या बस द्वारा	150 किलो मीटर
चित्ती अन्य मार्ग द्वारा	25 किलो मीटर

(ख) सड़क (क) में वर्णित यात्रा के किसी अंश की दूरी के लिए एक रोज स्वीकृत किया गया है।

(ग) यात्रा के प्रारम्भ या अन्त में रेलवे स्टेशन तक या रेलवे स्टेशन से 8 किलो मीटर तक की यात्रा ज्वाइनिंग टाइम के लिए नहीं गिनी जाती है।

× वित्त विभाग के आदेश सं. एक 1 (7) एक ही (व्यय-नियम) 67 दिनांक 23-2-67 द्वारा शामिल किया गया।

(प्र) इस नियम में, गणना के प्रयोजन के लिए रविवार को एक दिन के समय के रूप में नहीं गिना जाएगा लेकिन रविवारों को 30 दिन की अधिकतम अवधि में शामिल किया जाएगा ।

अपवाद—स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, इस नियम के अन्तर्गत प्राप्त उपस्थिति (ज्वाइनिंग टाइम) के समय को कम कर सकता है ।

नियम 130. किस रास्ते द्वारा ज्वाइनिंग टाइम गिना जाएगा (Route by which joining time is calculated)—जहाँ राज्य कर्मचारी किसी भी मार्ग द्वारा यात्रा करता है लेकिन उसको ज्वाइनिंग टाइम, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशेष कारणों से अन्यथा प्रकार से आदेश न दे, उसी मार्ग द्वारा गिना जाएगा जिससे यात्री साधारणतया यात्रा करते रहते हैं ।

नियम 131. मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कार्यभार सम्भालने पर ज्वाइनिंग टाइम (Joining time where charge is made over at a place other than Head Quarters)—यदि कोई राज्य कर्मचारी अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पद का कार्यभार 'सम्भालने' के लिए 'अधिकृत' हो तो उसका ज्वाइनिंग टाइम उसी स्थान से गिना जाएगा जहाँ से उसने कार्यभार सम्भाला है ।

नियम 132 प्रस्थान समय में नए पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम (Joining time on appointment to a new post while in transit)—जब एक राज्य कर्मचारी एक पद से दूसरे नए पद पर, उसके प्रस्थान काल में, नियुक्त हो जाता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम नियुक्ति के आदेश प्राप्त करने की तारीख के पहले दिन से प्रारम्भ होता है ।

अथ निर्देशन—जब एक राज्य कर्मचारी अपने प्रस्थान काल में एक पद से दूसरे नए पद पर नियुक्त होता है तो उसे तैयारी करने के लिए दूसरे 6 दिन का और समय, ज्वाइनिंग टाइम गिनने में स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

नियम 133. एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान काल में अवकाश लेने पर राज्य कर्मचारी के लिए ज्वाइनिंग टाइम (Joining time for Government servant taking leave while in transit from one post to another)—यदि एक राज्य कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर प्रस्थान करते समय अवकाश लेता है तो अपने पुराने पद के कार्यभार सम्भालने से जितना समय व्यतीत होता है वह उसके अवकाश में शामिल किया जाना चाहिए ।

नियम 134. उपाजित अवकाश काल में नए पद पर नियुक्ति होने पर ज्वाइनिंग टाइम—यदि कोई राज्य कर्मचारी जब कि वह उपाजित अवकाश में हो, एक नए पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम उसके पुराने स्थान से या उस स्थान से गिना जाएगा वहाँ पर कि वह अपनी नियुक्ति के आदेश प्राप्त करता है । इन दोनों से गणना करने में जहाँ से भी ज्वाइनिंग टाइम कम प्राप्य होगा, वही गिना जाएगा ।

नियम 135. सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाया जाना—किसी भी मामले में सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने योग्य ज्वाइनिंग टाइम की अवधि को बढ़ा सकता है । परन्तु धर्त यह है कि नियमों की सामान्य भावना (General Spirit of the Rules) का पालन किया जाएगा ।

नियम 136. अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम जो स्वीकृत किया जा सकता है (Maximum joining time admissible)—30 दिन की अधिकतम सीमा के भीतर, एक सशम प्राधिकारी ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, एक राज्य कर्मचारी को निम्न लिखित परिस्थितियों में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने योग्य ज्वाइनिंग टाइम से अधिक समय का ज्वाइनिंग टाइम स्वीकृत कर सकता है—

(क) जब राज्य कर्मचारी यात्रा के साधारण साधन की उपयोग में लाने में असमर्थ रहा हो अथवा उसके द्वारा कठिन परिश्रम करने पर भी यात्रा में नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत समय से ज्यादा समय खर्च हो गया हो, या

(ख) जहाँ ऐसा विस्तार सार्वजनिक सुविधा के लिए आवश्यक समझा जाता हो अथवा अनावश्यक या शुद्ध औपचारिक स्थानान्तरण के कारण सार्वजनिक धन की बचाने के लिए आवश्यक समझा जाता हो ।

(ग) जब किसी ब्रिटिश भाषी में नियमों का कठोरता से प्रयोग किया गया हो । जैसे उदाहरण के लिए, जब एक राज्य कर्मचारी यात्रा में बिना कोई गलती किए हुए बीमार पड़ जाता है ।

नियम 137. अन्य सरकार में स्थानान्तरण पर ज्वाइनिंग टाइम का विनियमन (Regulation of joining time on transfer to other Government)—जब राजस्थान सरकार के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अधीन नियुक्त एक राज्य कर्मचारी दूसरी ऐसी सरकार के नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिसने कि ज्वाइनिंग टाइम निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में नियम बनाए हैं तो उस सरकार में पद पर उपस्थित होने का तथा उसने लौटने की यात्रा का ज्वाइनिंग टाइम उन नियमों द्वारा विनियमित किया जावेगा ।

नियम 138. ज्वाइनिंग टाइम सेवा के रूप में गिना जाता है (Joining time counts as duty)—कार्य ग्रहण काल (ज्वाइनिंग टाइम) में एक राज्य कर्मचारी सेवा के रूप में समझा जावेगा तथा उसका भुगतान निम्न प्रकार से प्राप्त करने का हकदार होगा—

(क) यदि नियम 127 के खण्ड (क) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम हो तो राज्य कर्मचारी वह वेतन प्राप्त करेगा जो कि, वह स्थानान्तरण न होने पर प्राप्त करता या जिसे वह नए पद पर कार्यभार सम्भालने पर प्राप्त करेगा । इनमें से जो भी कम होगा वही वेतन वह प्राप्त करेगा ।

(ख) यदि नियम 127 (ख) के अन्तर्गत ज्वाइनिंग टाइम हो तो वह, असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश से लौटने पर, ऐसा अवकाश वेतन प्राप्त करेगा जो कि वह भारत में अवकाश वेतन के भुगतान के लिए निर्धारित दर पर अवकाश में पहिले प्राप्त करता था । परन्तु यदि वह असाधारण अवकाश से लौटता हो तो उसे कुछ भी भुगतान नहीं मिलेगा ।

टिप्पणी—एक राज्य कर्मचारी के स्थानान्तरण के ज्वाइनिंग टाइम का भुगतान उस समय तक नहीं किया जावेगा जब तक कि वह सार्वजनिक हित की दृष्टि से स्थानान्तरित नहीं किया जाता है । परन्तु यदि राज्य कर्मचारी शर्पणा करे तथा मध्यम प्राधिकारी स्वीकृत करने के लिए इच्छुक हो तो अपने पुराने स्थान पर पद का कार्यभार सम्भालने तथा नए स्थान पर अपने पद का

कार्यभार सम्भालने के बीच में बिताए गए समय के लिए अवकाश नियमों के अनुसार उसे प्राप्य नियमित अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी को कोई बाधित नहीं होगी।

बाँच निर्देशन—(1) जब तक स्थानान्तरण पूर्ण न हो, किसी भी दशा में कार्यभार संभालने वाले राज्य कर्मचारी द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान (जहाँ स्थानान्तरण में अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति हो) प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। परन्तु जहाँ तक साधारण वेतन एवं भत्तों का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों में, इसके लिए सामान्य नियम का एक अपवाद बनाया जा सकता है, जिनमें कि हस्तान्तरित किए जाने वाले कार्यभार में कई बिखरे हुए काम हों जिन्हें कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार हस्तान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भालने वाले (Relieving) तथा कार्यभार सम्भालने वाले (Relieved) कर्मचारियों को साथ साथ देखा है। कार्यभार सम्भालने वाला राज्य कर्मचारी सेवा के रूप में समझा जावेगा यदि बिमागाध्यक्ष इन निरीक्षणों (Inspections) के समय को अधिक नहीं समझता हो। इस प्रकार कार्यभार सम्भालते समय एक राज्य कर्मचारी—

(क) यदि वह अपने द्वारा स्थाई रूप से धारण किए गए पद से स्थानान्तरित होता है तो वह उस पद पर धरना सम्भावी वेतन (Presumptive Pay) प्राप्त करेगा, तथा

(ख) यदि वह ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर वह कार्यवाहक रूप में कार्य करता हो तो वह उस पद पर प्राप्य कार्यवाहक वेतन प्राप्त करेगा यद्यपि कि वह उस वेतन से ज्यादा न हो जिसे वह स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद प्राप्त करता, अन्यथा स्थानान्तरण से पूर्व जिन पद पर उसका लीयन या उभरा सम्भावी वेतन प्राप्त करेगा, एवं

(ग) यदि वह अवकाश से लौटता है तो वह उन पद का सम्भावी वेतन प्राप्त करेगा जिन पर कि अवकाश काल में उसका लीयन रहता है।

(2) यदि उक्त बाँच निर्देशन में योजित बिदा होने वाले एवं बिदा करने वाले दोनों अधिकारी निशुल्क क्वार्टर प्राप्त करने के हकदार हैं या क्वार्टरों के बदले में भवना किराया प्राप्त करने के हकदार हैं, तो दोनों अधिकारी रियायतें पाने के हकदार होंगे।

नियम संख्या 1—यह निर्णय किया गया है कि जोधपुर एवं जयपुर जिला ट्रेजरियों में कार्यभार के हस्तान्तरण एक सप्ताह में पूर्ण हो जाने चाहिए तथा अन्य जिला ट्रेजरियों के कार्यभार का हस्तान्तरण तीन दिन में हो जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्धारित की गई समयवधि की सीमा अधिकतम है तथा जितना सम्भव हो सके जल्दी से जल्दी समय में कार्य को पूरा किया जाना चाहिये।

नियम संख्या 2—एक प्रश्न उत्पन्न किया गया है कि दोनों ज्वाइनिंग टाइम के समय नए धर्मात् नियम 133 के अन्तर्गत चिन्तिता प्रमाण पत्र पर अधिकतम चार माह तक के अग्रिम वेतन पर अवकाश के प्रारम्भ होने से पहले स्वीकृत किया गया ज्वाइनिंग टाइम तथा ऐसे अवकाश के समाप्त होने पर नये पद पर उपस्थित होने के लिए उन्मोघ किए गए समय का ज्वाइनिंग टाइम वेतन कैसे नियमित किया जावेगा। मामले की जाँच करती गई है तथा राज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि प्रथम प्रकार के ज्वाइनिंग टाइम जो कि नियम 133 के अन्तर्गत स्वीकृत किए जायें उसका ज्वाइनिंग टाइम वेतन नियम, 138 के अन्तर्गत विनियमित किया जा सकता है तथा दूसरे

प्रकार से बिताए गए ज्वाइनिंग टाइम का ज्वाइनिंग टाइम वेतन नियम 138 (ख) के अनुसार नियमित किया जा सकता है।

निर्णय संख्या 3—एक प्रदत्त उदाहरण दिया गया है कि (1) कार्यभार सम्भालने वाले राज्य अधिकारी द्वारा एक नए पद का कार्यभार सम्भालने के समय को किस रूप में समझा जावेगा तथा (2) उनका वेतन एवं भत्ता ऐसे समय में किम प्रकार नियमित किया जाना चाहिए, जहां पर कि हस्तान्तरित कार्यभार के कई स्टोर एवं/या बिपरे काम ऐसे शामिल हैं जिनका कि निरीक्षण, हस्तान्तरण पूर्ण करने से पूर्व कार्यभार सम्भालने वाले तथा कार्यभार सम्भालने वाले, दोनों राज्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना जरूरी है। यह निर्णय दिया गया है कि कार्यभार सम्भालने वाले अधिकारी को 'सेवा' (Duty) के रूप में समझा जाना चाहिए, यदि ऐसे निरीक्षणों में बिताया जाने वाला समय विभागाध्यक्ष के लिए चार्ज लेने में अधिक प्रतीत नहीं होता हो, कार्यभार सम्भालने वाला अधिकारी निम्न प्रकार से प्राप्त करेगा—

(क) (i) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होता है जिस पर उसने स्थाई रूप से कार्य किया हो, तो वह उस पद पर अपना सम्भाव्य वेतन (Presumptive Pay) प्राप्त करेगा। प्रत्यक्ष

(ii) यदि वह एक ऐसे पद से स्थानान्तरित होगा है, जिस पर उसने स्थाई रूप से कार्य-वाहक रूप में कार्य किया है तो वह उस पद पर प्राप्य कार्यवाहक वेतन प्राप्त करेगा या स्थानान्तरण पूर्ण होने के बाद जो वह वेतन प्राप्त करता, वह प्राप्त करेगा। परन्तु इनमें से जो भी कम हो, वह प्राप्त करेगा; एवं

(ख) उपरोक्त (1) या (2) के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त किए गए वेतन के आधार पर नए स्थान पर प्राप्य क्षतिपूर्क भत्ता/मकान किराया भत्ता वह प्राप्त करेगा।

निर्णय संख्या 4—अवकाश से लौटने पर एक पद पर स्थानान्तरित होने पर राज्य कर्मचारी का वेतन, कार्यभार सम्भालने की अवधि में निम्न प्रकार से नियमित किया जावेगा—

(1) यदि वह स्थाई रूप से धारण किये गए पद से अवकाश पर गया हो तो उस पद का सम्भाव्य वेतन वह प्राप्त करेगा, एवं

(2) यदि वह कार्यवाहक रूप से धारण किये गये पद से अवकाश पर गया हो तो उस पद का कार्यवाहक वेतन या उस नए पद में उसे प्राप्य वेतन, जिसे कि वह कार्यभार सम्भालने के बाद प्राप्त करता, इनमें से जो कम होगा, वही उसे मिलेगा।

नियम 139. ज्वाइनिंग टाइम के बाद दण्ड (Penalty for exceeding joining time)—एक राज्य कर्मचारी जो अपने उदासीनता के समय में अपने पद पर उदासीन नहीं होता है तो वह उस ज्वाइनिंग टाइम के समाप्त होने के बाद वेतन या अवकाश वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम के बाद सेवा से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना (wilful absence from duty) नियम 86 के अर्थ में दुर्व्यवहार (Misbehaviour) समझा जाएगा।

नियम 140. राज्यकीय सेवा में नियुक्त होने पर गैर सरकारी (Private) कर्मचारियों को ज्वाइनिंग टाइम—राज्यकीय सेवा के अतिरिक्त अन्य जगह पर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति या ऐसी नौकरी पर अवकाश स्वीकृत किया हुआ व्यक्ति, यदि सरकारी हित की दृष्टि से, सरकार के

अधीन किसी पद पर नियुक्त हो जाता है, तो सरकार अपने निर्णय पर उस समय को ज्वाइनिंग टाइम के रूप में समझ सकती है जब वह सरकार के अधीन पद पर कार्यभार संभालने के लिए तैयारी करता है तथा यात्रा करता है तथा जब वह वापिस सरकारी सेवा से अपने मूल नियोजक को स्थानान्तरित कर देने पर तैयारी करता है एवं यात्रा करता है। ऐसे ज्वाइनिंग टाइम में अथवा प्राइवेट नियोजन द्वारा स्वीकृत अवकाश के बाद ज्वाइनिंग टाइम में उसको ज्वाइनिंग टाइम वेतन उतना ही मिलेगा जो वह सरकारी सेवा में नियुक्त होने के पूर्व अपने नियोजक से प्राप्त कर रहा था अथवा राज्यकीय सेवा में पद के वेतन के बराबर, इनमें से जो कोई कम हो, वह प्राप्त करेगा।

भाग 5

अध्याय 13—विदेशीय सेवा (Foreign Service)

नियम 141. विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने पर कर्मचारी की सहमति आवश्यक—किसी भी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा। परन्तु धर्त यह है कि यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी कि-सेवाएं किसी ऐसे निगमित (Incorporated) या अनिगमित निकायों में स्थानान्तरित करनी होती है जिन पर सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप में है। अथवा जहाँ एक राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण ऐसी सेवा में करना होता है जिसका भुगतान राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम (1959 का अधिनियम संख्या 7) के अन्तर्गत गठित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् क्षेत्र से किया जाता है।

नियम 142. विदेशी सेवा में स्थानान्तरण कब स्वीकृत किया जा सकता है—विदेशी सेवा में स्थानान्तरण उस समय तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि—

(क) स्थानान्तरण के बाद की जाने वाली सेवायें ऐसी हों, जो कि सार्वजनिक कारणों से राज्य कर्मचारी द्वारा की जाती हों।

(ख) स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित राज्य कर्मचारी ऐसे पद पर कार्य करता है जिसका भुगतान संचित निधि से किया जाता है या ऐसे पद पर अपना लीयन रखता हो यदि उसका लीयन निलम्बित न किया जाय।

टिप्पणियाँ—(1) यदि किसी मामले में यह प्रस्ताव कर लिया जाता है कि राज्य कर्मचारी किसी गैर सरकारी उपक्रमों (Private undertakings) को संचार दिया जाना चाहिये, तो यह आवश्यक है कि इन नियमों का पालन सर्वाधिक कठोरता के किया जावे तथा सामान्य रूप में एक गैर सचकारी उपक्रम के लिए एक राज्य अधिकारी को तयार दिया जाना अपवाद स्वरूप मामलों (Exceptional cases) में ही होना चाहिये तथा उसमें उसके भेजने के लिये विशेष कारण उपस्थित होने चाहिये।

(2) इस नियम के अन्तर्गत अर्थवार्द्ध सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण भी विदेशी सेवा में स्वीकृत किया जा सकता है।

(3) जो राज्य सरकार राज्य कर्मचारी के विदेशी सेवा में उधार देने के कारण पेन्शन प्रभुत्व वसूल करने की हकदार होगी, उसे ही स्थानान्तरण की स्वीकृति करने में सक्षम सरकार के रूप में समझा जावेगा ।

निर्देशन—एक राज्य कर्मचारी को विदेशी सेवा में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश को एक प्रतिनिधि स्थानान्तरण करने वाले मध्यम प्राधिकारी द्वारा मन्त्रालयकार के पास भिजवाई जानी चाहिये । स्वयं राज्य कर्मचारी को बिना किसी प्रकार की देर किए उम कार्यवाय को एक प्रतिनिधि भेजनी चाहिये तथा अपने प्रदान (Contribution) को रकम के बारे में निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिये । उसे स्वयं को कार्यभार के सभी स्थानान्तरणों के समय एच दिनांक की सूचना उस अधिकारी को जिसके निये वह प्रस्थान करने समय एक पार्टी के रूप में होना है, अपने विदेशी सेवा काल में या उससे मोड़ने पर देनी चाहिये तथा उसे समय समय पर विदेशी सेवा काल में अपने वेतन, उद्योग दिए गए भत्ता, पत्र व्यवहार के पत्र के बारे में तथा अन्य ऐसी सूचनाएं भिजवाते रहना चाहिए जिन्हें वह अधिकारी मंगाता है ।

नियम 143. अवकाश काल में विदेशी सेवा में स्थानान्तरित करने के परिणाम—यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके अवकाश काल में ही विदेशी सेवा में हो जाता है, तो वह ऐसे स्थानान्तरण आदेश की तारीख से अवकाश पर रहना तथा अवकाश वेतन प्राप्त करना बन्द कर देगा ।

विदेशी सेवा के मध्य में राज्य कर्मचारी की पेरेन्ट केडर में स्थाई या कार्यवाहक उन्नति—विदेशी सेवा में स्थानान्तरित एक राज्य कर्मचारी उसी केडर या केडरों में रहेगा जिसमें कि वह अपने स्थानान्तरण के पूर्व शीर्ष ही स्थाई या कार्यवाहक रूप में शामिल किया गया था तथा उन केडरों में उसे स्थाई या कार्यवाहक रूप से ऐसी उन्नति हो जा सकती है जो उन्नति प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी उचित समझे । ऐसा प्राधिकारी उन्नति देते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगा ।

(क) विदेशी सेवा में किए जाने वाले काम की प्रकृति, एवं

(ख) जहाँ उन्नति का प्रदान पंदा होता हो वहाँ उससे निम्न केडर वालों की दो गई उन्नति ।

इस नियम के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को राज्यकीय सेवा में ऐसी अन्य उन्नति प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा जिसे कि उन्नति देने वाला ऐसा प्राधिकारी तय करे एवं जो कि उसे उन्नति प्रदान करने के लिए सक्षम होता यदि वह (अधिकारी) राज्यकीय सेवा में रहता ।

नियम 144. विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी द्वारा विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करने की तारीख—विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी उसी तारीख से विदेशी नियोजक से अपना वेतन प्राप्त करना शुरू कर देगा जिस दिन कि वह राज्यकीय सेवा में अपने पद का कार्यभार सम्भाल देगा । किसी भी प्रतिवन्ध की शर्त के अधीन जिसे राज्य सरकार, सामान्य आदेश द्वारा लागू करे, उसका स्थानान्तरण करने वाला सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक (Employer) को सलाह से राज्य कर्मचारी का वेतन, उसे सेवा पर उपस्थित होने के लिए स्वीकृत समय, तथा उस ज्वाइनिंग टाइम में वेतन आदि को तय कर सकता है ।

जांच निर्देशन—जब कोई राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा शर्तों के आधार पर उधार दिया जाता है तथा उस समय में वह विदेशी नियोजक द्वारा सेवा निवृत्त किए जाने से पूर्व ही राज्य सेवा से सेवा निवृत्त हो जाता है, तो महालेखाकार साधारण पद्धति द्वारा विदेशी नियोजक के पास एक स्टेटमेंट भेजेगा जिसमें उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख तथा सरकार से प्राप्त पेन्शन की राशि का उल्लेख करेगा ताकि विदेशी नियोजक के लिए निवृत्ति की शर्तों को दुहराने का, यदि वह इस तरह से इच्छुक हो तो, अवसर मिल सके।

नियम 144 क विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें—(Conditions of deputation on foreign service)—केन्द्रीय सरकार से/या 'ए' श्रेणी के राज्यों से 'बी' श्रेणी के राज्यों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट 21 में शामिल की गई शर्तों से शासित होगी।

नियम 145. अवकाश एवं वेतन में अंशदान (Contribution towards Leave and Pension)—(क) जब तक एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में है तब तक उसके पेन्शन की राशि का अंशदान उसके पक्ष में संचित निधि में जमा कराया जाना चाहिए—

(ख) यदि विदेशी सेवा भारत में हो तो अंशदान अवकाश वेतन की राशि के लिए भी दिया जाना चाहिए।

+ (खख) यदि राजः कर्मचारी पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं तो उनके अवकाश वेतन का अंशदान जमा नहीं किया जायेगा तथा प्रतिनियुक्ति काल में लिए गए अवकाश का अवकाश वेतन पंचायत समितियों द्वारा सहन किया जायेगा।

टिप्पणी यह संशोधन दिनांक 2-10-59 से प्रभाव में थाया हुआ समझा जाएगा।

(ग) उपरोक्त कण्ड (क) व (ख) के अन्तर्गत बकाया अंशदान स्वयं राज्य कर्मचारी द्वारा चुकाया जायेगा तब तक कि विदेशी नियोजक उसका भुगतान करने में अपनी सहमति न दे दे। विदेशी सेवा में अवकाश लेने पर उस समय का कोई अंशदान वेत नहीं होगा।

(घ) नियम 153 (ख) के अन्तर्गत किए गये विशेष प्रदण्य द्वारा अवकाश वेतन का अंशदान भारत के बाहर विदेशी सेवा के मामले में मांगा जा सकता है। जिसमें विदेशी नियोजक द्वारा अंशदान दिया जाना होगा।

टिप्पणी—इस अध्याय में पेन्शनों के साथ साथ राजकीय अंशदान, यदि कोई हो, शामिल है जो कि राज्य कर्मचारी के प्रोविडेंट फण्ड के खाते में जमा कराना चाहिए।

नियम 145. का-वेतन भत्ते आदि का भार (Incidence of Pay, allowances etc.)—राजस्थान सरकार एवं केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब, बिहार, मद्रास, मंसूर, मध्यभारत, हैदराबाद, (दकन), पेश्वा, सौराष्ट्र, ट्रायनकोर, कोचीन एवं मध्यप्रदेश सरकारों के बीच में राजस्थान सरकार से या उनसे राजस्थान सरकार में स्थानांतरण होने पर, अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेन्शन आदि के भार का नियमन इन नियमों के परिशिष्ट 13 में शामिल किए गये नियमों के अनुसार होगा।

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 7 ए (20) एफ डी (ए) नियम/60 दिनांक 6-2-61 तथा आदेश सं. एफ 7 ए (20) एफ डी (ए) 60 दिनांक 11-3-64 द्वारा शामिल किया गया।

नियम 145. ता-भारतीय राज्यों एवं श्री श्री के राज्यों के बीच में आपस में की गई सेवा की गणना—एक राज्य कर्मचारी जिसने एक भारतीय रियासत में सेवा की है, जो कि अब 'बी' श्रेणी के राज्यों का भाग बन चुकी है या 'बी' श्रेणी के अन्तर्गत आ चुकी है, यह सेवा उसके केन्द्रीय सेवा में स्थाई रूप से लिए जाने पर केन्द्रीय सरकार के पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के लिए गिनी जायेगी। इसी प्रकार का व्यवहार उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार से 'बी' श्रेणी के राज्यों के अन्तर्गत सेवा में पूर्णतः से लिये गये हैं तथा यहां से सेवा से नियुक्त किए जाते हैं, सम्बन्धित सरकारें प्रत्येक के अन्तर्गत की गई सेवाओं के संबंध में पेंशन की राशि के लिए उत्तरदायी बनी रहेंगी तथा प्रत्येक सरकार का उत्तरदायित्व इन नियमों के परिशिष्ट 13 में वर्णित तरीके से बांटा जायेगा।

नियम—146. अंशदान की दर (Rate of contribution)—पेंशन एवं अवकाश वेतन के लिए भुगतान किए जाने वाले अंशदान की दर यही होगी जो सरकार सामान्य आदेशों द्वारा निर्धारित करे।

जांच निर्देशन — (1) विदेश से लौटने के पूर्व नियम 127 के गण्ड (ग) के अन्तर्गत लिए गए अवकाश के साथ में राज्य कर्मचारी द्वारा लिये गये ज्वाइनिंग टाइम के समय के लिये अवकाश वेतन अंशदान सम वेतन की दर पर लगाया जाना चाहिए जिसे बट्ट अवकाश पर रवाना होने से पूर्व प्राप्त कर रहा था।

(2) जब एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में स्थानांतरित हो जाता है या जब एक राज्य कर्मचारी की सेवा का समय बढ़ा दिया जाता है तो यह माना जाना चाहिये कि पेंशन या अवकाश वेतन या केवल पेंशन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अंशदान राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार समय-समय पर प्रभावशील दरों के अनुसार बगून किये जाने योग्य होगा। इसी प्रकार यदि अधिकारी पेंशन प्राप्त करने वाला न हो तथा अंशदायी भविष्य निधि (न्याट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में राशि जमा करा रहा हो तो भी यह माना जाना चाहिये कि निधि में मासिक अंशदान तथा निधि लेने में सामयिक अंशदान, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, बमूल किया जायेगा।

निर्णय संस्था !—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 146 के अनुसार भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के अवकाश वेतन का अंशदान विदेशी नियोजक से वसूल करना होता है तथा ऐसे अंशदानों के बदले में राज्य सरकार विदेशी सेवा में या उसके अन्त में राज्य कर्मचारी द्वारा उपभोग किये गये अवकाश की किसी भी अवधि के अवकाश वेतन के व्यय को स्वीकार करती है। फिर भी ऐसे अवकाश के लिए भुगतान योग्य किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्क भत्ते का व्यय, विदेशी नियोजक द्वारा ही सट्टन किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या ऐसे मामलों में राज्य कर्मचारी को पहिले पहल विदेशी नियोजक द्वारा पूर्णतः समका अवकाश वेतन एवं भत्ते दिये जाने चाहिए तथा राज्यकीय हिस्सा वाद में वसूल किया जाना चाहिये या क्या पहिले पहल सरकार द्वारा अवकाश वेतन एवं भत्ते का भुगतान कर दिया जाना चाहिए तथा बाद में विदेशी नियोजक अपने दायित्व की रकम सरकार को वाद में चुकाता रहे या क्या सरकार एवं विदेशी नियोजक को अपने अपने हिस्से की भलग भलग रकम दे देनी चाहिये ताकि रकम के भावी सम-

योजन (Adjustment) की कोई समस्या खड़ी न हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में वर्तमान पद्धति एकरूपतात्मक नहीं है।

विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अब एक सा निम्न तरीका अपनाया जाना चाहिये—

(i) विदेशी सेवा में या उसके अन्त में राज्य कर्मचारी द्वारा उपभोग किये गए अवकाश के समय का भुगतान योग्य अवकाश वेतन एवं क्षतिपूर्क भत्ते के सम्बन्ध में सरकार के पैतृक विभाग (Parent Department) एवं विदेशी नियोजक को अपने अपने दायित्व की राशि सीधे सम्बन्धित कर्मचारी को विदेशी सेवा में स्थानान्तरण की शर्तों के आधार पर सौंप दी जानी चाहिए।

(ii) भाषित कोड के खण्ड 4 में अध्याय 2 के परिशिष्ट 'ख' के अवतरण 5 में दिये गए तरीके के अनुसार विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी का अवकाश महालेखाकार के द्वारा अवकाश की तादाद तथा अवकाश वेतन मय उसे प्राप्त क्षतिपूर्क भत्ते प्राप्ति के, प्रमाणित किये जाने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है यद्यः सिवाय इसके कि उपाधित अवकाश 120 दिन से अधिक न हो, उपरोक्त को प्रमाणित करते समय महालेखाकार को स्पष्ट रूप से सरकार एवं विदेशी नियोजक द्वारा दिये जाने वाले अवकाश वेतन एवं क्षतिपूर्क भत्तों का अलग अलग उल्लेख करना चाहिये जिससे कि उपरोक्त खण्ड (1) में वर्णित तरीके से उनके दायित्वों के अलग अलग भुगतान में उन्हें दिक्कत न पड़े।

(iii) सरकार या विदेशी नियोजक द्वारा सिवाय इसके कि उपाधित अवकाश 120 दिन से अधिक न हो, अवकाश स्वीकृत किए जाने के आदेश की एक प्रतिलिपि आवश्यक रूप से महालेखाकार को भिजवाई जानी चाहिये।

(iv) जब कोई राज्य कर्मचारी भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त होने पर अवकाश पर रवाना होता हो तो, सेवा अवधि का भुगतान करने के बाद विदेशी नियोजक के लिए सीधे ही एक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजना चाहिये जिसमें उसे स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिये कि नियमों के अन्तर्गत प्राप्त सीमा तक अवकाश काल में राज्य कर्मचारी को क्षतिपूर्क भत्ते उसके द्वारा दिये जाते रहेंगे। इसी प्रकार अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यालय के अध्यक्ष को तथा राजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में महालेखाकार को अवकाश वेतन का भुगतान करने के बाद अंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये यदि अवकाश समाप्त होने पर राज्य कर्मचारी वापिस विदेशी सेवा में उपस्थित होता है या उनके नियन्त्रण में बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(v) भारत में विदेशी सेवा में नियुक्त राजपत्रित कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के भुगतान का प्रबंध कोष (ट्रेजरी) द्वारा किया जावेगा जब कि अराजपत्रित कर्मचारियों का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जावेगा।

और भी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 82 (क) के अन्तर्गत महालेखाकार के कार्यालय से अवकाश-फैट्टाईल के प्राप्त किए बिना विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी को कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। महालेखाकार ने बतलाया है कि विदेशी नियोजक द्वारा, तरीके का पालन नहीं किया जा रहा है। यह निवेदन किया जाता है कि अब कोई राज्य

कर्मचारी विदेशी सेवा में नियुक्त किया जावे तो विदेशी नियोजक को इन नियमों के प्रावधानों से अवगत करा देना चाहिये ।

निर्णय संख्या 2—विदेशी सेवा काल में राज्य कर्मचारी को दिये जाने वाले क्षतिपूर्क भत्तों के भार के सम्बन्ध में सदेह व्यक्त किये गए हैं । वस्तु स्थिति की जांच की गई । विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में अवकाश वेतन का धंधदान विदेशी नियोजक से वसूल किया जाता है तथा धंधदान के बदले में सरकार उसको अवकाश वेतन देना स्वीकार करती है । इस प्रकार के धंधदान के लिए निर्धारित दरें राज्य कर्मचारी द्वारा अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के हिसाब से उपाजित किये गये पूर्ण वेतन एवं धर्द्धवेतन के अवकाश के आधार पर लगायी गई है तथा इसमें कोई ऐसा क्षतिपूर्क भत्ता शामिल नहीं किया गया है जो कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (16) में वर्णित अवकाश वेतन का भाग हो । इसी तरह विदेशी सेवा में या उसके अन्त में उपभोग किये गये अवकाश के सम्पूर्ण क्षतिपूर्क भत्ते का व्यय विदेशी नियोजक द्वारा किया जाना होगा जिससे कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रह सके । यह बांधनीय है कि इस प्रकार की बातों का उल्लेख, विदेशी सेवा में स्थानान्तरण करते समय अन्य बातों में शामिल कर देना चाहिये ।

निर्णय संख्या 3—केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों से राज्य सरकार में लिए गए सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय/अन्य राज्य सरकारों के अवकाश नियमों से शासित होते रहे तथा उनके अवकाश वेतन लेखा संहिता भाग I के परिलिप्ट 3 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार विनियमित होता है । राज्य सरकार के अधीन सेवा में अध्याई रूप से स्थानान्तरित किए गए सरकारी कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति एवं अवकाश वेतन के वितरण के सम्बन्ध में प्रवृत्ति देने वाली इस प्रक्रिया की महालेखाकार, राजस्थान के परामर्श पर जांच की गई है तथा तदनुसार निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाते हैं—

(1) यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन अपनी अध्याई सेवा की अवधि के दौरान अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे अवकाश राज्य सरकार के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो कि उसे अवकाश करने में सक्षम होगा । राजपत्रित सरकारी अधिकारी के मामले में अवकाश केवल उन्ही समय स्वीकार किया जाना चाहिए जबकि महालेखाकार द्वारा जो कि उनके वेतन की जांच करता है, उसकी स्वीकार्यता प्रमाणित हो जाए । इस प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रपत्र आवेदन पत्र अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की मार्फत दो प्रतियों में अधिकाधिक अधिकारी के पास भेजना चाहिए जो कि आवेदन पत्र पर आवश्यक प्रमाण-पत्र दर्ज कर उनकी एक प्रति सीधी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास भेजना तथा दूसरी प्रति अधिकाधिक अधिकारी (महालेखाकार, राजस्थान) को उसमें उन आचार्यों का उल्लेख करते हुए भेजना जिन पर कि अवकाश सम्पन्न किया जाना है तथा साथ ही साथ यदि ऐसे विशेष विवरण सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित वेतन आदि के बारे में पहले से ही प्रस्तुत नहीं किए गए हैं आवश्यक विशेष विवरण भी भेजना जो कि उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगे तथा जो बाद वाले अधिकाधिक अधिकारी के लिए अवकाश वेतन निकालने

हेतु आवश्यक हों। अवकाश हेतु आवेदन की दूसरी प्रति प्राप्त करने पर बाद वाला भेदभाषा अधिकारी स्वीकार्य अवकाश वेतन को संगणित करेगा तथा सामान्य रूप में छोटे सरकारी कर्मचारी को अवकाश वेतन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में अवकाश स्वीकृत करने में सशम प्राधिकारी जहाँ कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन भेजने वाले कार्यालय हैं केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकारों के अवकाश नियमों के अधीन अवकाश की प्राप्ति का प्रमाण पत्र माग सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन का भुगतान, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, कीर्णगार के मारफत प्राधिकृत किया जावेगा जबकि प्राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मामले में भुगतान सम्बन्धित विभाग या कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) यदि सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन करता है तथा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अधीन तथा ऐसे अवकाश के समकक्ष केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकारों के नियमों के अधीन राजकीय प्रत्यावर्तन के आधार पर उक्त अवकाश स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्बन्धित केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार से सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के मना करने से पूर्व अनिवार्य रूप से परामर्श ले लिया गया है। यदि केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार ऐसे अवकाश को मना करने से सहमत न हो या उसके द्वारा प्रस्तावित होने वाली प्रतिरिक्त पेंशन सम्बन्धित देवता को वर्दाश्त करने से मना करती हो तो उचित तरीका यही होगा कि पहले आवेदन किए गए सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश को स्वीकृत किया जाए तथा बाद में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद पर राजस्थान सेवा नियमों के सम्बन्धित अवकाशों के अधीन पुनर्नियोजित किया जाए। ऐसे सरकारी कर्मचारी का अवकाश वेतन ऐसे प्रतिवर्षों के अधीन रहेगा जैसा कि सम्बन्धित केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार आरोपित करना चाहे।

(4) यदि सरकारी कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन राज्य सरकार के अधीन अपनी पुनर्नियोजन की अवधि के अन्त में किन्तु सम्बन्धित केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार के अधीन वास्तव में क्यूटी पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व करता है तो राज्य सरकार सम्बन्धित केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार से परामर्श करेगी तथा केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार यह निर्णय करेगी कि प्राया अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है या नहीं। यदि अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार में प्रत्यावर्तन अवकाश प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होना चाहिए तथा अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी औपचारिक आदेश/प्रतिसूचनाएं केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकारों द्वारा जारी की जानी चाहिए। सम्बन्धित केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार के साथ परामर्श राज्य सरकार के अधीन क्यूटी की सूचना से तथा अवकाश के प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय/ग्रन्थ राज्य सरकार यह निर्णय कर सके कि क्या अवकाश स्वीकृत करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक रहेगा या नहीं।

नियम 147. अंशदान किस प्रकार निकाला जाता है (How contribution is calculated)—नियम 146 के अन्तर्गत निर्धारित की गई पेंशन, अंशदान की दर, राज्य कर्मचारी के

लिये पेंशन प्राप्त कराने के लिये वही होगी जो कि वह सरकार के अन्तर्गत प्राप्त करता यदि वह विदेशी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाता ।

अवकाश वेतन के लिये अंशदान की दरें, राज्य कर्मचारी को उस पर लागू होने वाली श्रृंखला में उस पर लागू होने वाली एवं अन्य शर्तों के अनुसार, अवकाश वेतन दिलाने के लिये होगी । प्राप्य अवकाश वेतन गिने जायेगे, विदेशी सेवा में प्राप्त किया गया वेतन, नियम 7, (24) के प्रयोजनों के लिये, वेतन के रूप में गिना जायेगा । इस विदेशी सेवा में प्राप्य वेतन भी, उन राज्य कर्मचारियों से, जो अंशदान दे रहे हैं, उसी ही राशि काट ली जायेगी जो कि उसी अंशदान के रूप में हो जाती है ।

टिप्पणी इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई अंशदान की दरें तथा उन्हें निशाने के तरीके का उल्लेख इन नियमों के परिशिष्ट 5 में किया हुआ है । यह निर्णय किया गया है कि विदेशी सेवा में प्रस्थान करते समय नियम 127 (ब) के अधीन उपभोग किए गए उवाइनिंग टाइम के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के अंशदान की बसूनी उस वेतन के अनुसार की जानी चाहिए जो कि राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में कार्य का भार लेने पर प्राप्त करता है ।

निर्णय—राजस्थान सरकार के कर्मचारी का जो विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हों, अवकाश वेतन का अंशदान विदेशी सेवा में प्राप्त किये जाने वाले वेतन पर दिया जायेगा, जहां पर कि वे स्वयं अंशदान दे रहे हों । इससे अंशदान की राशि काट ली जायेगी ।

नियम 148. अंशदान माफ करना (remission of contribution)-राज्य सरकार विदेशी सेवा में स्थानांतरण करते समय—

(क) किसी विशिष्ट मामले में या मामलों की श्रेणी में बकाया अंशदानों को छोड़ सकती है, एवं

(ख) अधिक बकाया अंशदानों पर, यदि कोई हो, व्याज की दर निर्धारित करने के लिए नियम बना सकती है ।

निर्णय—राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो कि झूठान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे, उनके पेन्शन अंशदान की बसूनी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 148 (क) के अन्तर्गत समाप्त की जाती है ।

नियम 149. बकाया अंशदानों पर व्याज (Interest on arrear contributions)-यदि विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के अवकाश वेतन या पेंशन का बकाया अंशदान उस माह के अन्त से 15 दिन के भीतर नहीं दिया जाता है जिसका कि वेतन, जिस पर यह अंशदान आधारित है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी प्राप्त कर चुका है, तो नहीं चुकाये जाने वाले अंशदान पर, जब तक सरकार द्वारा उसे विशेष रूप से मारु न कर दिया गया हो, 2 पैसे प्रति 100) रु. प्रतिदिन के हिमाय से 15 दिन की अवधि के बाद से भुगतान करने की तिथि तक व्याज लगातार पूर्ण रूप में अंशदान लिया जाना चाहिये । व्याज या तो राज्य कर्मचारी या विदेशी नियोजक से, इनमें से जो कोई भी अंशदान जमा कराता है, वसूल किया जायेगा ।

निर्देशन—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 149 के अनुसार यदि विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके अवकाश वेतन या पेंशन का बकाया अंशदान उस माह के

अन्त 15 दिन के भीतर नहीं दिया जाता जिसका कि वेतन, जिस पर कि यह भ्रंशदान आधारित है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी प्राप्त कर चुका है, तो नहीं चुकाये जाने वाले भ्रंशदान पर, जब तक उसे सरकार द्वारा विशेष रूप से माफ न कर दिया गया हो, सरकार के लिए दण्ड के रूप में व्याज (Penal interest) देना होता है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्त राज्य कर्मचारियों के अवकाश वेतन या पेंशन अनुदान की दरें महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा उपार लेने वाले अधिकारी के पास भेजी जाती हैं। यह देखा गया है कि विदेशी निकायों को विदेशी सेवा भ्रंशदान की दरों की सूचना भेजने में देर लग जाती है। क्योंकि महालेखाकार को कुछ सूचनाएँ नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों से मंगानी होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय में भ्रंशदान नहीं चुकाए जाते हैं तथा उन्हें सरकार को व्याज माफ (Remit) करने के लिए लिखना पड़ता है।

अनुदान वसूल करने में देरी को बचाने के लिए भविष्य में अवकाश वेतन तथा पेंशन/भ्रंशदायी भविष्य निधि भ्रंशदान (कान्ट्रीव्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड कान्ट्रीव्यूदान) की दरें राजस्थान सेवा नियम (खण्ड 2) के परिशिष्ट 5 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी नियोजक उपार लेने वाले अधिकारी द्वारा निकाली जावेगी तथा वह उन दरें (Provisional rates) को महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के पास भेजेगा। विदेशी सेवा में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्य कर्मचारी के स्थानान्तरण को स्वीकृति के आदेश में एक निम्न अतिरिक्त शर्त और शामिल करेगा :—

विदेशी नियोजक राज्य कर्मचारी राजस्थान सेवा नियम (खण्ड 2) के परिशिष्ट 5 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रपत्र में अवकाश वेतन एवं/या पेंशन/भ्रंशदायी भविष्य निधि की दरें के अनुसार राशि जमा कराएगा तथा उसके द्वारा निश्चित की गई दरों के हिसाब से भ्रंशदान की राशि उस माह के अन्त से 15 दिन के भीतर जमा कराएगा जिसमें कि वेतन, जिस पर यह आधारित है, राज्य कर्मचारी ने प्राप्त कर लिया है। दरें की निकालने में सहायक प्रपत्र संलग्न किया गया है।

भ्रंशदान की राशि लेखों के निम्नलिखित मदों में जमा की जानी है—

(1) अवकाश वेतन भ्रंशदान प्राय शीपक (Receipt Head) में जमा होगा जो कि लेख के सेवा शीपक (Service Head of Account) के समान होगा जिसमें कि पैतृक विभाग में अधिकारी का वेतन नाम लिखा जाता है अथवा जहाँ इस प्रकार का समान मुख्य शीपक (Major Head) न हो वहाँ यह 'शीपक LII मिसलेनियस' में जमा होगा।

(2) पेंशन/भ्रंशदायी भविष्य निधि भ्रंशदान XLVIII भ्रंशदान पेंशन के लिए एवं पेंशन के लिए सेवा निवृत्ति लाभ भ्रंशदान तथा पेंशन/भ्रंशदायी भविष्य निधि के लिए " ग्रेज्युटी-भ्रंशदान की वसूलियाँ " शीपक के अन्तर्गत जमा कराया जावेगा।

विदेश नियोजक द्वारा निश्चित की गई दरों की दरें (Provisional) समझा जावेगा तथा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा निश्चित किए जाने के समय तक वह विचाराधीन रखी जावेगी एवं पूर्ण प्रभाव से समायोजन किए जाने की शर्त पर होगी। यदि विदेशी नियोजक द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय में अवकाश वेतन/पेंशन/भ्रंशदायी भविष्य निधि

अनुदान की राशि सरकार को नहीं दी जाती है तो विदेशी नियोजक से भुगतान न की गई राशि पर दिनांक 1-4-64 से दण्ड स्वल्प व्याज की रकम वसूल की जावेगी ।

× स्पष्टीकरण—(नियम 149 के नीचे राजस्थान सरकार के अनुदेश के रूप में प्रदर्शित) वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 11-6-64 के अन्तिम पैरा के सही स्कोप के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न किए गए हैं जो विदेशी नियोजक से भुगतान न किए गए अनुदान पर दिनांक 1-4-64 से दण्डित व्याज की दर पर वसूली के लिए प्रावधान करते हैं ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहाँ विदेशी नियोजक निर्धारित अवधि के भीतर अनुदान का भुगतान नहीं करता है, वहाँ भुगतान न किए गए अनुदानों पर दण्डित व्याज की दर दिनांक 1-4-64 से या उस तारीख के बाद की ऐसी तारीख में, जिसकी कि अनुदान भुगतान किया जाएगा या / है, जो भी बाद में हो, में वसूली की जाएगी ।

नियम 150. विदेशी सेवा में अनुदान राज्य कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता—विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी अनुदानों को रोकने तथा विदेशी सेवा में वित्तिये गये समय की राजस्वीय सेवा के रूप में न गिने जाने के लिए नहीं कह सकता है । उसके पक्ष में अनुदान के भुगतान से यह उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार वेतन या वेतन एवं अवकाश वेतन, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान करने का हक्कदार होता है । न तो वह और न विदेशी नियोजक भुगतान किए गए अनुदान में से कुछ प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उसके लोटाये जाने या कोई दावा (क्लेम) स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

नियम—151. विदेशी नियोजक से वेतन या प्रेच्युटी स्वीकार करने में स्वीकृति लेना आवश्यक—एक राज्य कर्मचारी जो विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, वह सरकार की स्वीकृति के बिना अपनी सेवा के सम्बन्ध में विदेशी नियोजक से कोई वेतन या प्रेच्युटी स्वीकार नहीं कर सकता ।

नियम—152. विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश—विदेश सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के तरीकों के अतिरिक्त अन्यथा प्रकार से कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है तथा वह सरकार से अवकाश या अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वास्तव में वह सेवा को नहीं छोड़ देता है तथा अवकाश पर नहीं चला जाता है ।

नियम—153. भारत के बाहर विदेशी सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियंत्रित करने के विशेष प्रावधान—(क) भारत के बाहर विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए विदेशी नियोजक द्वारा ऐसी शर्तों पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें नियोजक निश्चित करे । किसी अतिरिक्त मामले में स्थानान्तरण स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी विदेशी नियोजक को सलाह से पूर्व में ही ऐसी शर्तें वापस कर सकता है जिन पर विदेशी नियोजक द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा । नियोजक द्वारा स्वीकृत किए गए अवकाश के अवकाश वेतन का भुगतान

नियोजक द्वारा किया जावेगा तथा वह अवकाश राज्य कर्मचारी के अवकाश लेख में नाम नहीं लिखा जावेगा ।

(ख) विशेष परिस्थितियों में भारत के बाहर विदेशी सेवा में स्थानांतरण करने में तत्सम प्राधिकारी विदेशी नियोजक के साथ ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जिसके अन्तर्गत किसी भी राज्य कर्मचारी को, उस पर राज्य कर्मचारी के रूप में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि विदेशी नियोजक नियम 146 के अन्तर्गत निर्धारित दर पर अवकाश अंशदान सञ्चित निधि में जमा कराता है ।

टिप्पणी—पेंशन के प्रयोजन के लिए भारत से बाहर विदेशी नियोजक द्वारा उसे उधार दिये गये राज्य कर्मचारी के लिए स्वीकृत किए गए अवकाश की अवधि को 'अवकाश' के रूप में समझा जाता चाहिए एवं 'सेवा' (Duty) के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए । ऐसा कोई अवकाश यदि पूर्ण वेतन या उसके समान अन्य शर्तों पर लिया गया हो तो उसे, एक समय में अधिकतम चार माह की सीमा तक, नियम 91 के प्रयोजन के लिए उपाधित अवकाश के रूप में समझा जाना चाहिए तथा अन्य गन अवकाश व ऐसे अवकाश भत्तों, नियम 92 से 98 अनुसार निपटारे जाने चाहिए ।

नियम 154. राजकीय सेवा में कार्यवाहक उन्नति हो जाने पर विदेशी सेवा में राज्य कर्मचारी के वेतन का निर्धारण—विदेशी सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारी, यदि राज्य सेवा में किसी पद पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपना वेतन राज्य सेवा में उस पद के वेतन के अनुसार प्राप्त करेगा जिस पर कि वह लीयन रखता है या जिस पर वह अरना लीयन रखता यदि उसका लीयन निलम्बित नहीं किया जाता तथा उस पद का वेतन लेता जिस पर कार्यवाहक कार्य करता है । उनका वेतन निश्चित करने में विदेशी सेवा में प्राप्त किए गए वेतन को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

नियम 155. विदेशी सेवा से लौटने की तारीख—एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा से राज्यकीय सेवा में उतरी तारीख को लौटा हुआ समझा जाता है जिसको कि वह राज्यकीय सेवा में अरने पद का कार्यभार संभालता है । परन्तु शर्त यह है कि यदि वह अपने पद पर पुनः उपस्थित होने से पूर्व विदेशी सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका परिवर्तन (Reversion) उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसे कि सरकार, जिसके स्थापन में वह नियुक्त है, तय करे ।

टिप्पणी (1)—वे मामले जहाँ एक राज्य कर्मचारी, जो पहले से ही भारत के भीतर या बाहर विदेशी सेवा में, सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित एक निषिद्ध निकाय के अन्तर्गत नियुक्त है, तथा वह निवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए प्रार्थना करे ।

प्रार्थना किया हुआ अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित निषिद्ध निकाय (Corporate body) उसे अपनी सेवा से अवकाश का उपभोग करने हेतु मुक्त करने की तैयार हो । यदि वह, इस प्रकार से मुक्त न किया जाय तो अवकाश सार्वजनिक हित की दृष्टि से स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए तथा वह अवकाश राज्य कर्मचारी द्वारा बाद में अपनी सेवा त्यागने पर, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के अन्तर्गत प्राप्य सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) वे मामले जहाँ एक राज्य कर्मचारी, सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियमित नियमित निकाय के प्रतिष्ठित अन्य निकाय के अधीन भारत में भारत के बाहर विदेशी सेवा में नियुक्त है, तथा वह नियुक्ति पूर्व अवकाश के लिए प्राप्ति करते—

ऐसे मामलों में अवकाश सभी प्राप्त किया जा सकेगा जब राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा को छोड़ देगा। पहले मामले में, नियुक्ति पूर्व अवकाश के समय में उसे विदेशी नियोजन के अधीन सेवा करने करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। विदेशी सेवा में विदेशी नियोजन के अधीन सेवा के कम-अधिक नियुक्ति पूर्व अवकाश स्वीकृत किए जाने की सम्भावना को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 89 के प्रयोजन के लिये सम्बोधित किया गया अवकाश नहीं सम्माना जाएगा। यदि उसे प्रतिस्थापित घातु (Superannuation) प्राप्त करने की तारीख के बाद विदेशी संगठन में सेवा करने की स्वीकृत दे दी जाती है, तो वह युक्त है तो और सरकारों नियुक्ति के रूप में सम्माना जाएगा।

(3) वे मामले जहाँ राज्य कर्मचारी सम्बोधित अवकाश व नियमित निकाय के अधीन पुनर्नियुक्ति प्राप्त करना चाहता है—यदि सम्बोधित किए गए समय में एक राज्य कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियमित नियमित निकाय के अधीन पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो बिना प्राधिकारी से उसका अवकाश सम्बोधित किया जा, उसे उस कर्मचारी का सम्बोधन न किया गया अवकाश वह कर देना चाहिए तथा इन हुए अवकाश का सम्बोधन पुनर्नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद उन लोगों के आधार पर किया जाना चाहिए जिनका सम्बोधन वित्त विभाग के आदेश गहरा एक. सी. 1760/59, एक. (1) (16) एक. सी. ए./नियम/57 निर्दिष्ट 30-10-59 द्वारा सम्मिलित निम्न राजस्थान सरकार के निर्णय में किया गया है।

निरा श्री यदि सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या उनके द्वारा नियमित नियमित निकाय के प्रतिष्ठित अन्य संगठन के अधीन पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह पुनर्नियुक्ति की शर्तों के आधार पर अपने सम्बोधित अवकाश के समय का पुनः उपयोग नहीं कर सकता है। वह या तो सेवा में उसी समय नियुक्त किए जाने का विचार कर सकता है या ऐसे संगठन के अधीन सम्बोधित अवकाश प्राप्त करने में सेवा में इन शर्तों के साथ बने रहने का विचार कर सकता है कि उसे उस काम में अवकाश केवल अन्य केवल पर अवकाश की सीमा तक मिलेगा।

निर्णय—एक राज्य कर्मचारी जो एक संभाव्य मिति की विदेशी सेवा के सम्पन्न होने पर प्रत्यावर्तित (Revert) होता है वह उस तारीख से प्रत्यावर्तित माना जाएगा जिसकी कि वह संभाव्य मिति में वह का कार्यभार सम्भालता है।

स्पष्टीकरण—विषय—भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए राज्य कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति-राजस्थान सेवा नियमों का नियम 155

एक प्रदान उपपन्न किया गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए राज्य कर्मचारी को उसका प्रतिनियुक्ति का समय बीत जाने पर अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/अन्य राज्य सरकार उस राज्य कर्मचारी को आवेदन किए गए अवकाश की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वीकृत

— वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 7 ए (43) एक सी (ए) नियम 58 दि० 28-10-66 द्वारा सम्मिलित किया गया।

कर सकती है। उस राज्य कर्मचारी का राजस्थान सरकार को प्रत्यावर्तन किया जाना उसी तारीख से प्रभावी माना जाय। उस सरकार के अधीन सेवान्वेष्ट पुनः उपस्थित होता है।

नियम 156. विदेशी नियोजक द्वारा वेतन एवं अंशदान बन्द कर देने की तारीख—जब एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा से राजकीय सेवा में वापिस लौट आता है तो उसका वेतन विदेशी नियोजक द्वारा दिया जाना बन्द कर दिया जावेगा तथा उसका अंशदान, परिवर्तन की तारीख से, बन्द कर दिया जावेगा।

नियम 157. नियमित स्थापन जिसका कि व्यय सरकार को देय है, के सम्बन्ध में अंशदान की वसूली (Recovery of contribution in case of regular establishment of which the cost is payable to Government)—जब किसी नियमित स्थापन में इस शर्त पर अतिरिक्त वृद्धि की जानी हो कि अतिरिक्त वृद्धि का पूर्ण या आंशिक भय उन लोगों से वसूल किया जावेगा, जिसके हित के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ा, तो उनके सम्बन्ध में वसूलियों निम्नलिखित नियमों के अनुसार होंगे—

(क) वसूल की जाने वाली घटराशि सेवा के लिए स्वीकृत कुल भय अपवादा सेवा के भाग के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, होगी तथा किसी भी भाह के वास्तविक व्यय के अनुसार नहीं बढ़ेगी।

(ख) सेवा के भय में नियम 146 में की गई वरों के अनुसार अंशदान की रकम शामिल होगी एवं अंशदान स्थापन वर्ग के सदस्यों के वेतन की स्वीकृत वरों के आधार पर गिना जाएगा।

(ग) सरकार वसूलियों की राशि में कमी भी कर सकती है या उन्हें छोड़ भी सकती है।

अध्याय १४

स्थानीय निधियों के अधीन सेवा (Service under Local Funds)

नियम 158—सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि से भुगतान की जाने वाली सेवायें किस प्रकार नियमित होती हैं—जिन राज्य कर्मचारियों का भुगतान सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों से किया जाता है वे इन नियमों के अध्याय 1 से 12 तक के प्रावधानों के आधार पर शासित होंगे।

टिप्पणियाँ—(1) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों के कर्मचारी जिनका कि भुगतान राज्य की सञ्चित निधि से नहीं किया जाता है एवं, इसलिए, जो राज्य कर्मचारी नहीं हैं, उनका नियमन अध्याय 1 से 12 तक में दिए गए नियमों के अनुसार होता है।

(2) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों का तात्पर्य उन निधियों से है जो निकायों द्वारा प्रशासित होती हैं और जो कानून या नियम द्वारा कानून का प्रभाव रखते हुए, सामान्य रूप से प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सरकार के नियन्त्रण में आते हैं, बल्कि बजट की स्वीकृति तथा कुछ विशिष्ट खाती जंगहों को भरने के लिए स्थानों का सृजन कराना, या भवकाश या पेंशन या अन्य समान नियमों का विधानीकरण करना आदि मामलों में भी सरकार के नियन्त्रण में आते हैं।

(क) जब वह सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है या 30 वर्ष की प्रहंकारी सेवा (जिसमें सरकार की अधीन की गई सेवा भी शामिल है) पूरी करता है; या

(ख) जब वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन समय में पूर्व सेवा निवृत्त होता है जो कि यदि वह सेवामें बना रहना तो पेंशन सम्बन्धी लाभों को समाप्त करने वाली नहीं होती ।

(III) अस्थाई सरकारी कर्मचारी—अस्थाई सरकारी कर्मचारियों की सेवायें स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण की तारीख में समाप्त की हुई समझी जायेंगी तथा उन्हें ऐसे उपदान का भुगतान किया जाएगा जो उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के अधीन स्वीकार्य हों ।

(2) सरकारी बकायों की बमूली—भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम में उनके स्थानान्तरण के समय सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे तथा ऐसे निकाय/नियम सरकार की ओर से उनकी बमूली करते रहेंगे ।

(3) सरकारी सेवा से मुक्ति (डिस्चार्ज)—यदि स्थायी सरकारी कर्मचारी, जिसकी कि सेवायें किसी स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम आदि द्वारा उसे उच्च विभाग का, जिसमें वह सीपन रखता था, कार्य सौंप दिए जाने के फलस्वरूप ले भी गई है, उक्त निकाय/नियम में सेवा करने हेतु विकल्प देता है तो यह वहां से मुक्त होने की तारीख से उसके स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवा मुक्ति (डिस्चार्ज) के लिए बचन स्थि गये सरकारी कर्मचारी के रूप में समझा जाएगा ।

(4) कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू न होना—ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे—

(1) सरकारी कर्मचारी जिन्होंने राजस्थान सेवा नियमों के अधीन निर्धारित प्रतिनिधुक्ति की मानक शर्तों पर किसी विनिश्चित अवधि के लिए स्वतन्त्र निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के नियम की सेवा में रहने हेतु विकल्प दिया है ।

(ii) सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इन आदेश द्वारा अधिग्रहित शर्तों के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम की सेवा में बने रहने के लिए पहिले से ही विकल्प दे रखा है तथा जो इन नियमों द्वारा शासित होने हेतु नया विकल्प नहीं देते हैं ।

(iii) सरकारी कर्मचारी जो सरकारी विभाग या संस्था के स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के नियम में स्थानान्तरित या परिवर्तित होने के फलस्वरूप के अतिरिक्त अन्य प्रकार से, मानवीय रीबनल इन्जिनियरिंग कालेज को छोड़कर उपर्युक्त किसी अन्य निकाय द्वारा सीधे भरती किए गए हैं । ऐसे सीधे भरती किए गए व्यक्तियों के मामले सरकारी आदेश सं. एफ 7ए(43) वित्त वि (नियम) 70 दि. 18-4-62 द्वारा विनियमित होंगे ।

(iv) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी ।

5. विकल्प—(1) इस प्रादेश के अधीन उपलब्ध विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित अवधि के भीतर किया जाना चाहिये—

(क) पैराग्राफ 1 के खण्ड I के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम के अधीन सेवाकाल में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।

(ख) पैराग्राफ 1 के मुख्य खण्ड II के अधीन स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के निगम में सेवा के स्थानान्तरण से तीन माह के भीतर या स्वतन्त्र निकाय/निगम द्वारा उनके अधीन/नियोजन की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के बनाए जाने से तीन माह के भीतर या इस प्रादेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर, जो भी बाद में हो।

(ग) पैराग्राफ 1 के खण्ड II के उप-खण्ड (ग)(1) के अधीन 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किसी भी समय।

(घ) पैराग्राफ 4 के खण्ड (ii) के अधीन 31 दिसम्बर 1968 तक।

(2) सभी विकल्प उस विभाग/विभाग की जहाँ वह भन्त में सेवा कर रहा था, सम्बोधित लिखित में प्रावेदन पत्र के जरिए भरे जाने चाहिए तथा उसकी एक प्रति स्वतन्त्र निकाय/निगम जहाँ वह सेवा कर रहा है, के प्रशासनिक अध्यक्ष को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए। हाँ विभागाध्यक्ष ने काम करना बन्द कर दिया हो वही प्रतिलिपि निकाय/निगम को संबोधित करने वाले प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव को भेजी जानी चाहिए। राजपत्रित अधिकारियों मामले में, प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव तथा महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

विश. वि. के प्रादेश III, एक 1 (II) वित्त वि. (व्यय-नियम)/66 दि. 23-7-68 द्वारा निविष्ट)

नियम सं. 5—1-वित्त विभाग के प्रादेश दि. 23-7-68 निर्णय सं. 4 की धोर ध्यान प्राकटित किया जाता है जो स्वतन्त्र निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानान्तरण की शर्त निर्धारित करता है। एक प्रश्न उठाया गया है कि उक्त सरकारी कर्मचारियों को किस रूप में सम्मिलित जाए जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सीधी भरती के लिए आवेदन किया था तथा जो नियुक्त हो चुके थे एवं जो प्रारम्भ में अपनी स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पर गए थे तथा जिन्हें बाद में नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गई या जो बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वतन्त्र निकायों में सीधी भरती या सेवा के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मामले पर विचार कर लिया गया है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर उपर्युक्त प्रादेश के प्रावधान लागू नहीं होते।

2-फिर भी, स्थानान्तरणों के मा. पूर्व में सीधी भरती द्वारा की गई नियुक्तियों के समस्त मामलों को तर्पण बोर्ड में सम्मिलित होने वाले मामलों को निपटाने हेतु राज्यपाल ने प्रादेश दिया है

कि उन स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में जिनकी कि नियुक्तियाँ भारत के विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन प्रस्थापित भरती, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या राजस्थान लोक सेवा आयोग या विभागीय चयन समिति की नियुक्तियों के आधार पर की गई थी तथा स्वतन्त्र निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण के समय जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष की थी, वहाँ उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण को राजकीय हित में समझा जाना चाहिए तथा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ नीचे दिए गए पैरा 3 या पैरा 4 में दिए गये प्रावधानों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अधिनियम 'राजकीय हित में स्थानान्तरण' का तात्पर्य इन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निम्न में से होगा—

(क) राजस्थान में स्थित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में स्थानान्तरण जिसमें कि राजस्थान सरकार की राशि हिस्से या ऋण के रूप में लगी हुई हो।

(ख) राजस्थान में स्थित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में स्थानान्तरण जिसमें चाहे राजस्थान सरकार की चाहे राशि न लगी हुई हो लेकिन ऐसे उपक्रम/निकाय का बना रहना राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए हो। यह भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन किन्तु राजस्थान में स्थित स्वतन्त्र निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों पर भी लागू होगा।

(ग) राजस्थान में स्थित विश्वविद्यालयों में या मातृशाला रीजनल इंजिनियरिंग कालेज जयपुर में या राजस्थान राज्य में प्रशासनिक कार्य करने वाली अन्य स्वतन्त्र प्रशासनिक संस्था में स्थानान्तरण।

4. सेवा निवृत्ति लाभ—(क) जहाँ सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन हैं वहाँ वेदान्त सम्बन्धी लाभों के बदले ऐसी राशि जिसे सरकारी कर्मचारी प्रदान में देता यदि वह अधिकारी जोधपुर प्रदायी भविष्य निधि योजना के अधीन होता एवं समय-समय पर प्रयोग द्रों पर साधारण व्याज व सरकार के अधीन उसकी पेंशन सम्बन्धी सेवा के सम्बन्ध में जोधपुर प्रदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा प्राप्ति कर्मचारियों को +[विशेष प्रदान, यदि स्वीकार्य हो,] के बराबर की राशि जो स्वतन्त्र निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के नियम में उसके स्थानान्तरण के समय विद्यमान हो, उसे अधिकारी के अधिकारिकी आय प्राप्त करने पर निकाय के अधीन उसके भविष्य निधि लेख में जमा करायी जाएगी।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो जोधपुर प्रदायी भविष्य निधि योजना के अधीन हो, उसके लेख में सरकारी प्रदान सहित जमा राशि एवं उस पर व्याज तथा +[विशेष प्रदान यदि स्वीकार्य हो] जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वतन्त्र निकाय में उसके स्थानान्तरण के समय विद्यमान हो, उसके अधिकारिकी आय प्राप्त करने पर उसे भुगतान योग्य होगा।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अधीन भुगतान योग्य राशि पर भी उसके सेवा में स्थानान्तरण की तारीख से ऐसे समय तक वह भुगतान योग्य हो जाए, 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण व्याज दिया जाएगा।

+ (रित्त विभाग के आदेश सं.एफ1(48) वित्त वि (व्यय-नियम)68 दि. 27-11-69 द्वारा निर्दिष्ट

(ii) अवकाश—अग्रणी सेवा के स्थानान्तरण की तारीख को सरकारी कर्मचारी के लेख में जमा उपाजित अवकाश उसके द्वारा स्वतन्त्र निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के नियम की सेवा के अधीन रहते हुए भी लिया जा सकता है। जब इस प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन किया जाए तथा वह नए नियोजक के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो तो सरकार की ओर से कोई अवकाश वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर भी, जब कभी इस प्रकार के अवकाश के लिए किसी ऐसे विशिष्ट अवसर पर आवेदन किया जाए जो नए नियोजक के अधीन देय अवकाश से ज्यादा हो तथा ऐसा अधिक अवकाश सरकारी सेवा से स्थानान्तरण के समय देय अवकाश में जमा करने हेतु स्वीकृत किया गया हो तो सरकार स्वतन्त्र निकाय/नियम को इस प्रकार उपभोग किये गये अधिक अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन की राशि का भुगतान, स्वतन्त्र निकाय/नियम में उसके स्थानान्तरण की तारीख को विद्यमान राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार करेगी।

5. इन हकों के लिए बलेम अविवार के रूप में नहीं किया जा सकता है लेकिन इन्हें व्यक्तिगत मामलों में सरकार द्वारा वहाँ स्वीकृत किया जा सकता है जहाँ वे लाभदायक हों। वैयक्तिक मामले वित्त विभाग के परामर्श से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा संव्यवहृत किए जाएंगे।

6. पूर्वोक्त पैरों में अन्तर्विष्ट निर्णय केवल वही लागू होंगे जहाँ स्वतन्त्र निकाय/या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी की सेवा स्थायी रूप से स्थानान्तरित की गई है तथा वे गैर सरकारी संस्था या सरकारी क्षेत्र के नियम में स्थानान्तरण के मामलों पर लागू नहीं होंगे।

(वित्त विभाग के शाप सं. एक 1(48) वित्तवि (अग्र-नियम) 68 दि. 10-4-69 द्वारा निविष्ट)

भाग ६

अध्याय १५ सेवा के अभिलेख (Records of Service)

नियम 159. राजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख—एक राजपत्रित राज्य कर्मचारी की सेवाओं का अभिलेख महालेखाकार द्वारा रखा जाएगा।

नियम 160. अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की सेवा का अभिलेख—निम्नलिखित अवसरों को छोड़कर प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी की, जो कि स्थाई स्थापन में स्थाई पद को धारण किए हुए हो या एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या एक अस्थाई पद पर कार्य कर रहा हो, एक सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) ऐसे कार्यों में तैयार की जानी चाहिए जो कि भारत के नियंत्रक (कम्पट्रोलर) एवं महाधिवक्ता द्वारा तय किया जावे।

[क] वे राज्य कर्मचारी जिनकी सेवा का विवरण हिस्ट्री आफ सर्विस में या महालेखाकार द्वारा रखे गए रजिस्टर में किया जाता है।

[ख] पदों पर कार्यवाहक रूप में या अस्थाई पदों पर कार्य करने वाले राज्य कर्मचारी जो कि योद्धे समय के लिए शून्य अस्थाई या कार्यवाहक स्थानों पर नियुक्त किए गए हैं तथा जो स्थाई नियुक्ति के योग्य नहीं हैं।

[ग] पुलिस मेन जिसका पद एक हेड कांस्टेबल के पद से उच्च हो।

[घ] चतुर्थ थैली कर्मचारी।

टिप्पणी—सभी मामलों में जिनमें कि नियम 160 के अन्तर्गत सर्विस बुक रखना जरूरी है, ऐसी पुस्तिका एक राज्य कर्मचारी के लिए उस तारीख से तैयार की जावेगी जिसकी उसकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उस कार्यालय के अध्यक्ष की मुरादा में रखी जानी चाहिए जहाँ पर कि वह सेवा करता है तथा उसे उसके स्थानान्तरण के साथ साथ हस्तान्तरित कर देना चाहिए।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 की टिप्पणी के संशोधित प्रथम अवतरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संशोधित टिप्पणी में दिया हुआ है कि सभी मामलों में, जिनमें कि नियम 60 के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका रखना जरूरी है, वही हर राज्य कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका उसी तारीख से तैयार की जावेगी जिसकी उसकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति प्रारम्भ होती है। यह उसी कार्यालय के अध्यक्ष के नियन्त्रण में रखी जानी चाहिए जहाँ पर कि यह सेवा कर रहा है। तथा उसके साथ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। जहाँ उपरोक्त संशोधन हुआ है, कुछ निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं—

(1) क्या यह वांछनीय है कि सर्विस बुक की कीमत अब राज्य सरकार द्वारा सहन की जावेगी।

(2) क्या सेवा पुस्तिका राज्य कर्मचारी को, उसके त्याग पत्र देने पर या बिना गलती के उसे हटाये जाने पर, लौटाई जावेगी (यदि नहीं लौटाई जावेगी) तो क्या सेवा पुस्तिका को सेवा निवृत्ति के बाद राज्य कर्मचारी को लौटाई जा सकती है, यदि वह इसके लिए माग करता हो।

पुराने नियम के साथ परिवर्तित किए हुए नियम की तुलना से स्पष्ट है कि इसमें से 'सेवा पुस्तिका' को राज्य कर्मचारी द्वारा कीमत देने पर दिया जावेगा, इस सम्बन्ध का प्रमाण हटा दिया गया है तथा उसमें राज्य कर्मचारी को, अपने पद से त्याग पत्र देने तथा सेवा से हटाने पर, सेवा पुस्तिका लौटाने का भी कहीं वर्णन नहीं किया हुआ है। केवल वर्णन यह किया हुआ है कि प्रत्येक मामले में सेवा पुस्तिका का खर्च सरकार द्वारा सहन किया जावेगा तथा यह राज्य कर्मचारी को उसके त्यागपत्र देने, हटाने या सेवा निवृत्त होने पर नहीं लौटाई जावेगी चाहे उन्होंने पहिले सेवा पुस्तिका की कीमत क्यों न चुकाई हो।

† निर्णय संख्या 2—यह देखा गया है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण (Pay fixation) एवं पेन्शन के मामले, या तो राज्य कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड न होने से या उनका सर्विस रिकार्ड भ्रष्टा होने के कारण, बहुत समय तक तय नहीं हो पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने अब सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की दूसरी प्रतिनिधि बनाने का निर्णय किया है जो कि राज्य कर्मचारी के पास रहेगी तथा उसका यह ध्यान रखने का कर्त्तव्य होगा कि विभाग

+ वित्त विभाग के आदेश संख्या एक 1 (12) वित्त (अवध-नियम) 65 दिनांक 9-3-65 द्वारा शामिल किया गया।

में तैयार की गई सेवा पुस्तिका में जो इन्द्राज किये जाते हैं वे इन्द्राज समय समय पर उसकी सेवा पुस्तिका में भी करा लिए जावें तथा उन्हें कार्यालय के अध्यक्ष/या विभागाध्यक्ष से प्रमाणित करा लिया जावे।

राज्य कर्मचारियों को जो प्रत्येक सेवा पुस्तिका मिलेगी उसका फार्म निर्धारित कर दिया गया है जो कि उचित समय में राजकीय मुद्रणालय से उपलब्ध हो सकेगा। इतने समय में सेवा पुस्तिका के वर्तमान इन्द्राजों की, वर्तमान में चालू सेवा पुस्तिका में नकल की जा सकती है।

जो सेवा पुस्तिका विभाग में तैयार की जावेगी वही प्रमाणिक प्रमाण होगी लेकिन सेवा पुस्तिका के न मिलने पर या मूल सेवा पुस्तिका किन्हीं स्पष्ट एवं आवश्यक कारणों से भ्रष्ट हो तो वेतन निर्धारण तथा पेन्शन तय करने के मामलों में सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति, जो कि राज्य कर्मचारी के पास रहेगी, की सहायता ली जा सकती है बशर्ते कि उसमें सारे इन्द्राज सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों के साथ प्रमाणित किए गए हों। जहां वेतन निर्धारण एवं पेन्शन के मामलों को तय करने के उद्देश्य से सेवा पुस्तिका की दूसरी प्रति तैयार करनी हों, वहां सम्बन्धित राज्य कर्मचारी से इस बात का प्रतिज्ञा पत्र अवश्य लिखवा लेना चाहिए कि राज्य कर्मचारी वेतन एवं भत्तों को उस अधिक प्राप्त की गई राशि को लौटाएगा जो कि (सेवा पुस्तिका की) दूसरी प्रति में इन्द्राजों के आधार पर वेतन निर्धारण या पेन्शन स्वीकृत करने में बाधी जावेगी।

+ निर्णय संख्या 3-(उपयुक्त राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 2 के रूप में प्रयुक्त) वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 9 3 65 की ओर ध्यान आकषित किया जाता है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि 'सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन स्थिरीकरण एवं पेन्शन मामलों से निपटाने की सुविधा हेतु सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कापी दी जाए। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या सेवा पुस्तिकाएं सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क दी जाए या भुगतान करने पर ही दी जाए।

मामले को जांच कर ली गई है तथा यह निश्चय किया गया है कि सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट कापी प्रत्येक अराजपणित सरकारी कर्मचारी को केवल 25 नए पैसे के भुगतान पर की जाएगी।

नियम 161. (i) सेवा पुस्तिका में इन्द्राज (Entries in Service Book)--(1) सेवा पुस्तिका में राज्य कर्मचारी के सेवा काल में प्रत्येक घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष है तो उससे उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाना चाहिए। कार्यालय के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि सभी इन्द्राज ठीक तरह से किये गए हैं तथा उनको अनुप्रमाणित (Attested) किया जा चुका है तथा पुस्तिका में कोई खुरचन (erasure) या उपरिलेखन (over-writing) नहीं है। सभी सुद्धियां साफ तीर पर की जानी चाहिए तथा उचित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए।

नू. वित्त विभाग की आज्ञा सं० एफ 1 (12) वित्त वि (अर्थ-नियम) 65 दिनांक 25-3-66 द्वारा निविष्ट।

टिप्पणी—एक विभागाध्यक्ष अपने निम्नलिखित अधिकारियों के सम्बन्ध में, इस अधिकार को एक उचित राजपत्रित अधिकारी के लिए सौंप सकता है ।

(ii) नियुक्ति में नितम्बित किए जाने के प्रत्येक समय का तथा सेवा के प्रत्येक अन्य व्यवधान का सेवा पुस्तिका में धार पार पृष्ठों पर इन्द्राज किया जाना चाहिए, जिसमें उसकी अवधि का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए तथा उसकी प्रमाणित करने वाले अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना चाहिए । प्रमाणित करने वाले अधिकारी का यह देवना कर्तव्य है कि इन्द्राज ठीक प्रकार से किया गया है ।

(iii) सेवा पुस्तिका में, जब तक विभागाध्यक्ष इस प्रकार का आदेश न दे, चरित्र सम्बन्धी व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों का इन्द्राज नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु यदि एक राज्य कर्मचारी एक निम्न अस्थाई पद पर भ्रवण कर दिया जाता है तो उसमें भ्रवणत किए जाने के कारणों का संक्षेप में वर्णन किया जाना चाहिए ।

निर्देशन—जब कभी एक अस्थाई पद स्थाई कर दिया जाता है जिसमें कि कर्मचारी की पद पर की गई सेवाएं पेंशन के योग्य हो जानी हैं, तो उसके लिए इस सम्बन्ध का इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आर्वाइट आफीसर से करा लेना चाहिए । चूंकि आर्वाइट आफीसर केवल राजपत्रित अधिकारियों का ही सेवा इतिहास सँभार करता है इसलिए उनके मामले में उन कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी । अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिकाएं तथा स्थापन वर्ग को विवरणिकाएं (return) कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा सँभार की जाती हैं, इसलिए इन कार्यालय को उपरोक्त विवृति में वर्णित प्रारम्भिक इन्द्राज, उनके द्वारा, आवश्यकतानुसार रूप से किए जाने चाहिए ।

निर्णय—एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या एक राज्य कर्मचारी द्वारा राजकीय सेवा में प्रविष्ट होने के बाद प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता को उसकी सेवा पुस्तिका में लिखा जाना चाहिये प्रपक्ष नहीं चाहें वर्तमान सेवा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की योग्यताओं को लिखे जाने के लिए कोई स्थान नहीं दिया हो ।

(2) सेवा पुस्तिका का प्रश्न अभी भारत सरकार द्वारा परिवर्तित किया गया है तथा उसके पृष्ठ संख्या । पर राज्य कर्मचारी की शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं को लिखे जाने के लिए, जगह दी गई है, जहाँ ऐसा करना चाहा गया हो उसके द्वारा सेवा में प्रविष्ट होने के बाद में प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जा सकती है । फिर भी, नया फार्म तब तक उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब तक कि पुराना पड़ा हुआ स्टाक समाप्त न हो जाए । इसलिए यः निर्णय किया गया है कि इस बीच की अवधि में राज्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा सम्बन्धी योग्यता जिसका कि उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया जाना जरूरी है, उसे सेवा पुस्तिका में टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है ।

+ निर्णय संख्या 3—यह निर्णय किया गया है कि सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी में जन्म की तारीख की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से गर्वों एवं अंकों दोनों में की जानी चाहिए ।

+ 162.—सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा पुस्तिका की जांच—यह प्रत्येक कार्यालयध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष सेवा पुस्तिकाएं लिखाएँ तथा उस पर उनके हस्ताक्षर इस बात की साक्ष्य में कराएँ कि उन्होंने सेवा पुस्तिकाएं देखली हैं। इस सम्बन्ध का एक प्रमाण पत्र कि पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उसने उचित प्रकार से कार्य कर दिया है, हर वर्ष सितम्बर के अन्त तक अपने धरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी अन्य बातों के साथ साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सेवाएं उचित प्रकार से सत्यापित की गई हैं तथा उचित रूप में प्रमाणित कर दी गई हैं। सरकारी कर्मचारी यदि राज्येतर सेवा (फोरेन सेवा) में हो तो सेवा पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर उसी समय कराए जाएंगे जब कि राज्येतर सेवा के सम्बन्ध में जो अंकेक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक इन्द्राज उसमें कर दिए गए हों।

निर्देशन—सेवा निवृत्त हो जाने के बाद राज्य कर्मचारियों के पेन्शन के दावे निश्चित करने में देर होने के बड़े कारणों में से एक कारण यह है कि उनका सेवा अभिलेख अधूरा रहता है। (सेवा अभिलेख) के आधार पर द्रष्टता आदि के प्रश्न पर भी विचार करना होता है। इसलिए यह देखा जाना स्वयं सरकार के हित में होगा कि उनकी सेवा पुस्तिकाओं आदि ठीक प्रकार से तैयार कर दी जावे तथा उन्हें अन्तिम तारीख तक तैयार रखा जावे। उन्हें समय समय पर उस कार्यालय से जिसमें कि उसका सेवा अभिलेख तैयार किया गया है, यह भी जांच करनी चाहिए कि सेवा पुस्तिका आदि में कर्मचारी के सरकारी जीवन सम्बन्धी प्रत्येक घटना का उल्लेख कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा अभिलेख तैयार किया जा चुका है तथा वह बाकिरी तारीख तक का है।

निर्णय—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 में यह दिया हुआ है कि निर्धारित कार्य में एक सेवा पुस्तिका ऐसे प्रत्येक भ्राजपत्रित राज्य कर्मचारी के लिए तैयार की जानी चाहिए जो कि एक स्थाई स्थापन पर स्थाई पद को धारण किए हुए हो या एक पद पर कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहा हो या अस्थायी पद पर कार्य कर रहा हो। इसमें प्रत्येक राज्य कर्मचारी एवं नियम में उल्लिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जावेगी। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 161 के अनुसार, सरकारी जीवन की प्रत्येक घटना का सेवा पुस्तिका में उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक इन्द्राज का प्रमाणिकरण कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए या यदि वह स्वयं कार्यालय का अध्यक्ष हो तो अपने निकटतम उच्च अधिकारी से प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यालय के अध्यक्ष के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा पुस्तिका में सभी इन्द्राज ठीक प्रकार से किए गए हैं तथा उन्हें प्रमाणित कर दिया गया है। इस प्राथमिक आवश्यक कर्तव्य का पालन न किए जाने से राज्य कर्मचारी के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तथा यह पाया जाता है कि पेन्शन के मामलों में देर होने के उत्तरदायित्व में एक सबसे बड़ा मूल तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख अधूरा होते हैं। नियम 162 प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के लिए यह देखने का कर्तव्य बतलाता है कि उनकी अपनी सेवा पुस्तिका नियम 161 में निर्धारित किए गए अनुसार उचित रूप से तैयार

करनी गई है ताकि पेन्शन के लिए सेवा के मायानु कराने में कोई दिक्कत न पड़े। विभिन्न संस्था-एक० 21 (2) वित्त II/53 दिनांक 19-2-53 में वित्त विभाग ने सभी राज्य कर्मचारियों को समय समय पर यह जांच करने की गन्ताह दी थी कि उनकी सेवा प्रतिष्ठान पूर्ण तैयार है तथा यह अन्तिम तारीख तक है। फिर भी सरकार के पास कई कारण ऐसे विद्यमान करने योग्य हैं कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान दिए जाने के कवचबन्ध भी गया उनके द्वारा निर्देशन जारी करने पर भी, नियमों की आवश्यकताओं का ठीक तरह पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 162 की आवश्यकताओं आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी चाहिए। सेवा का प्रतिष्ठान प्रवेश कर 31 मार्च तक तैयार किया जावेगा तथा 30 जून तक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को दिखनाया जावेगा। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सीधे सरकार के पास एक इन सम्बन्ध का अनुमानना प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए। यह अधिकतम अगले माह 15 जुलाई तक पहुँच जाना चाहिए तथा एक प्रतिनिधि साथ ही अपने उच्च अधिकारी के पास भिजवाई जानी चाहिए। प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए कि कार्यालय में काम कर रहे विभिन्न अयोग्य कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं गान के 31 मार्च तक की तैयारी की गई है तथा प्रत्येक सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा उनकी जांच कर ली गई है। बिन राज्य कर्मचारियों ने अपनी सेवा पुस्तिकाओं की जांच करनी है उनके नामों तथा सेवा प्रतिष्ठान की पूर्णता के बारे में उनके द्वारा दिए गए विवेक विवरणों के माध्यम का उल्लेख प्रतिवेदन (Report) में किया जाना चाहिए। बिन राज्य कर्मचारियों की किन्हीं कारणों से सेवा पुस्तिका नहीं दिखाई गई हो उनके नामों का उल्लेख अगले से एक विवरण के साथ दिया जाना चाहिए कि उनकी सेवा पुस्तिका बिन कारणों में नहीं दिखाई गई।

(2) यदि इन प्रादों के अनुसार कार्य करने में कोई कठिनाई महसूस हो, तथा वह समय से पहिले न पाती हो तो अपना गीघ स्पष्टीकरण करा लेना चाहिए।

नियम 163. आर्टि आर्टि द्वारा विदेशी सेवा में स्थानान्तरण पर इन्तान किया जाना—यदि एक राज्य कर्मचारी विदेशी सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष को उनकी सेवा पुस्तिका आर्टि आर्टीनर के पास भेजनी चाहिए। आर्टि आर्टीनर इनमें अपने हस्ताक्षरों में स्थानान्तरण स्वीकृत करने के आदेश का उन्नेय कर उसे लौटा देगा। वह इनमें विदेशी सेवा में प्राप्त अवकाश के सम्बन्ध में स्थानान्तरण के प्रभाव एवं अन्य ऐसी विवेक बातों का इन्तान करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। राज्य कर्मचारी के गानधीय सेवा में वापिस कर दिए जाने पर उनकी सेवा पुस्तिका फिर से आर्टि आर्टीनर के पास भिजवाई जानी चाहिए जो कि इनमें अपने हस्ताक्षरों के साथ उनकी विदेशी सेवा के सम्बन्ध में, जैसा वह आवश्यक समझे, विवरण निवेगा। आर्टि आर्टीनर के अनिवार्य अन्य कोई भी अधिकारी विदेशी सेवा में बिनाए गर समय के सम्बन्ध में इन्तान नहीं करेगा।

नियम 164. सेवा सूचियां (सर्विस रोल)—एक पुलिस मेन के प्रादों में जो कि एक हेड, वांस्टेबिल के पद से उच्च न हो, हर एक पुलिस के ज़िन्दाअधीन (District Super-intendant of Police) द्वारा एक सर्विस रोल तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक पुलिस कर्म-चारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवेक बातों का इन्तान किया जाना चाहिए जो कि स्थाई पद पर कार्य कर रहे हों एवं जो इस कान्टेन्गुलरी में पद पर कार्य बाहक रूप में कार्य कर रहे हों या अस्थाई

रूप से पद पर कार्य कर रहे हों, लेकिन जो किसी छोड़े समय के लिए शब्द अस्थाई रूप में या कार्य-वाहक रूप में रिक्त स्थान पर नियुक्त न किया गया हो तथा जो स्थाई सेवा के लिये योग्य हो—

(क) उसके प्रवेश होने की तारीख

(ख) प्राप्त, ध्यापु, ऊँचाई तथा पहिचाने जाने के चिह्न

(ग) पद जिसे उसने समय समय पर धारण किया है, उसकी उन्नतियाँ, अवतियाँ एवं अन्य दण्ड,

(घ) अवकाश सहित या अवकाश रहित सेवा से उसकी अनुपस्थिति ।

(ङ) उसकी सेवा में ध्यवधान

(च) उसकी सेवा में अन्य कोई घटना ऐसी हुई हो जिसमें उसका कुछ हिस्सा समाप्त कर दिया गया हो या जिसका पेशन पर प्रभाव पड़ता हो ।

सूची (रोल) की गाँध आदेश पुस्तिका, दण्ड रजिस्टर एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों से की जानी चाहिए तथा इसमें प्रत्येक इन्द्राज पर जिला अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

नियम 164. (का) नियम 164 में वर्णन किए गए अनुसार सविन रोल ऐसे अन्य श्रेणी के प्रत्येक स्थाई, अस्थाई या कार्यवाहक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के लिये भी तैयार किया जावेगा जिसके लिए सेवा पुस्तिका को कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

राजस्थान सरकार

सेवा पुस्तिका

1-नाम.....

2-पद.....

3-विभाग.....

1-नाम.....

2-निवास स्थान

3-पिता का नाम

4-जन्म तिथि

5-पहिचान के निशान

6-प्रथम नियुक्ति की तिथि और विभाग का नाम

7-स्थाई होने की तारीख व पद, आज्ञा की संख्या व तारीख सहित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर या निशान राज्य कर्मचारी

सेवाकाल का विवरण

1 नाम व पद

2 स्थाई या अस्थाई

3 नियुक्ति किये जाने की तारीख

4 नियुक्ति/पद समाप्ति की तारीख

- 5 समाप्ति का कारण जैसे स्थानान्तरण इत्यादि
- 6 वेतन एवं वेतन-मान (वे-स्केल)
- 7 स्थानापन्न वेतन व वेतन-मान
- 8 अन्य परित्याग्यता जो वेतन में शामिल हों जैसे विनिष्ट वेतन एवं स्थितिगत वेतन
- 9 अवकाश दिवस व अवधि और वर अवकाश वेतन
- 10 यदि निलम्बित हो तो, क्या वह निलम्बित काल सेवा में गिने जाने योग्य है या नहीं
- 11 सेवाकाल में अन्य बाधाएँ, यदि कोई हों
- 12 आता की सरपा एवं दिनांक
- 13 अधिकारी के हस्ताक्षर
- 14 विशेष विवरण

भाग 7

अध्याय 16-शक्तियों का प्रदत्तीकरण (Delegations)

नियम 165. अधीनस्थ अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का उपभोग करते हैं—
(क) परिशिष्ट 9 में राज्य सरकार के अधीनस्थ उन अधिकारियों की सूची दी गई है जो विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का उपभोग करते हैं।

(ख) प्रसंग की सुविधा के लिए, वे मामले भी शक्तियों के प्रदत्तीकरण के रूप में परिशिष्ट में शामिल कर लिए गए हैं जिनमें कि वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत यह घोषित कर दिया है कि सरकार के एक विभाग द्वारा, उन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग करने की स्वीकृति में उनकी अनुमति दी हुई समझी जावेगी।

नियम 166. जिन अधिकारियों की शक्तियाँ सौंपी गई हैं उनके उपभोग करने में वित्त विभाग की अनुमति दी हुई मानी जावेगी—वित्त विभाग ने नियम 3 के अन्तर्गत घोषित किया है कि उन अधिकारियों द्वारा शक्तियों के उपभोग में उसकी सहमति प्राप्त की हुई समझी जावेगी जिनको कि परिशिष्ट 9 में वर्णित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

नियम 167. प्रदत्त शक्तियों के उपभोग के नियमन सम्बन्धी सामान्य शर्तें—परिशिष्ट 9 में प्रदत्त शक्तियाँ निम्न शर्तों के साथ हैं—

(क) केवल उसके अतिरिक्त अर्थात् सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा सरकार से निर्देश करे, शक्ति का प्रयोग एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसको कि यह शक्ति सौंपी गई है। यह शक्ति का उपयोग केवल उन्हीं राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया जा सकता है जो कि उस अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

(ख) परिशिष्ट के कालम सं० 3 में प्रत्येक प्रदत्त शक्ति के रूप का वर्णन किया गया है। शक्ति का प्रदत्तीकरण, बतलाई गई शक्ति तक ही सीमित है। उसका विस्तार कालम दो में वर्णित नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति तक नहीं होगा।